राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तेरहवां दिवस [संख्या: 06

सोमवार,

15 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री भागचन्द टांकड़ा।

बांदीकुई के कोलाना औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार

62. **श्री भागचन्द टांकड़ा** (बांदीकुई): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कोलाना औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त औद्योगिक क्षेत्र में कितने भूखण्ड खाली हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में रीको द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जायेगा? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई): (1) बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में स्थित कोलाना औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु उपयुक्त भूमि का आवंटन प्रक्रियाधीन है।

(2) बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, कोलाना में 02 औद्योगिक भूखण्ड, 01 संस्थानिक भू-खण्ड एवं 27 वाणिज्यिक भू-खण्ड रिक्त हैं। रिक्त भू-खण्ड की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) बांदीकुई विधान सभा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि का आवंटन प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय मंत्री महोदय, कोलाना औद्योगिक क्षेत्र का भूमि आवंटन का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

दूसरा प्रश्न है, माननीय मंत्री महोदय, क्या सरकार कोलाना औद्योगिक क्षेत्र में स्टोन व्यवसाय हेतु पृथक् से जोन बनाने पर विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): कोलाना औद्योगिक क्षेत्र में कुल 71.31 एकड़ भूमि के कुल 144 औद्योगिक भू-खण्ड एक संस्थानिक व 53 व्यावसायिक दुकान नियोजित किये हुए हैं। इनमें 142 औद्योगिक भू-खण्ड एवं 26 व्यावसायिक भू-खण्ड/दुकानें आवंटित हैं और जैसा कि बताया है कि यह प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया चल रही है, तो जल्द से जल्द इसका प्रयत्न है। यहां पर कोरोगेटेड बॉक्स, आटा मील, सीमेंट जाली उद्योग, सैंड स्टोन कटिंग इत्यादि प्रकार की इकाइयां पहले से ही लगी हुई हैं, तो स्टोन का कार्य वहां पहले से ही चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन।

सीकर मुख्यालय पर अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रावास

63. श्री गोरधन (धोद): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार सीकर मुख्यालय पर अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) नवीन छात्रावास खोलने के संबंध में राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता एवं छात्रावास की आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। वर्तमान में सीकर मुख्यालय पर नवीन छात्रावास खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। नियम की प्रति परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री गोरधन (धोद): अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह हायर एजुकेशन से सम्बन्धित है, लेकिन मैं आपकी अनुमति से यह पूछना चाहता हूं कि पिछली

(श्री गोरधन)

सरकार में कॉलेज छात्रावास के लिये जमीन आवंटन के लिये इनके पास प्रस्ताव आया था, इन्हीं के द्वारा तो आवंटन किया गया और इन्हीं के द्वारा वापस निरस्त कर दिया गया। मंत्री महोदय, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? है, तो वह बताएं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के मूल प्रश्न में मैंने जानकारी दे दी। चूंकि यह उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय वहां सरकार ने एक जमीन आवंटन की और उसके बाद उसी जमीन को वापस निरस्त कर दिया गया। यह दर्शाता है कि सरकार दलित समाज के साथ न्याय नहीं करना चाहती है। उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिये, हॉस्टल के रूप में, कॉलेज के रूप में या किसी इंस्टीट्यूट के रूप में, वह करना नहीं चाहती है। यह गत सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो दलित समाज के साथ अन्याय हुआ था, अब आप नये सिरे से प्रस्ताव दें, उच्च शिक्षा विभाग और हमारा विभाग, दोनों मिल कर आपके इस प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जिनका प्रश्न है, वे पूछेंगे।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जहां आप कहेंगे, आपके कहे अनुसार हम नवीन स्वीकृति दिला देंगे।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी सोच बढ़िया है। हम जब भी एससी और एस.टी. के छात्रावास के लिये जमीन आवंटन के लिये प्रस्ताव भिजवाएं तो कृपया आप उसमें जरूर गौर करें। चूंकि सीकर जिला संभाग स्तर हो गया है, इसलिए वहां बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यह कह रहे हैं कि हम हितैषी हैं.. (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री गोरधन (धोद): आज तक इन्होंने कॉलेज के लिये हॉस्टल नहीं खोला है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जब भी हमारा प्रस्ताव आये तो उस पर विचार करें।

प्रश्न संख्या 64

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचन्द मीणा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

चित्तौड़गढ़ में टाडा-माडा योजना के स्वीकृत कार्य

65. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ एवं भदेसर में किन-किन ग्राम पंचायतों के कौन-कौनसे ग्राम टाडा-माडा योजना में सम्मिलित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत चार वर्षों में उक्त योजना के अन्तर्गत कितने कार्य स्वीकृत कर कितनी राशि का व्यय किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विगत चार वर्षों में पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ एवं भदेसर के टाडा-माडा योजना में सम्मिलित 41 गांवों में एक भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त गांवों में नवीन कार्य स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराडी): (1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौडगढ़ की पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ एवं पंचायत समिति भदेसर में अनुसूचित क्षेत्र में कोई गांव नहीं आता है। पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में परावर्तित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले 41 गांवों तथा बिखरी क्षेत्र में आने वाले 228 गांवों की सूची परिशिष्ट-अ पर सलग्न है। पंचायत समिति भदेसर के 169 गांव बिखरी क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित हैं। गांवों की सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(2) विगत चार वर्षों में विभाग द्वारा संचालित बिखरी योजना में किए गए स्वीकृत कार्य की सूची परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(3) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा पचायत समिति चित्तौड़गढ़ में बिखरी क्षेत्र अंतर्गत आश्रम छात्रावास विजयपुर घाटा का निर्माण कराया गया है। उल्लिखित 41 गांवों के स्थानीय प्रशासन स्तर से उपयुक्त पात्र प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से कार्य स्वीकृत नहीं हो पाए हैं।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(4) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में माडा तथा बिखरी क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले गांवों का विकास करने के उद्देश्य से उक्त क्षेत्र में जनजाति जनसंख्या, ससाधनों तथा बजट उपलब्धता एवं अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष मांग को ध्यान में रखते हुए नवीन कार्यों की स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाता है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माडा एरिया में मेरे 42 गांव आते हैं और मंत्री महोदय फरमा रहे हैं कि आपने प्रस्ताव नहीं दिये। मैंने कंटीन्यू पिछले पांच साल में भी प्रस्ताव दिये हैं और उससे पहले भी मैंने दिये हैं, हो सकता है कि पिछले छह महीनों में नहीं दिये हों। मेरी वहां की 19 परसेंट आबादी एस.टी. है और वास्तव में वहां पर काफी जरूरत है। मैं तो मंत्री महोदय से यही कहना चाहता हूं कि जिस ऐरिये से आप आते हैं वह भी मेवाड़ का एरिया है और मेरे वहां भी 19 परसेंट एस.टी. आबादी है। बजट डूंगरपुर जाता है, बांसवाड़ा जाता है, वहां जाना भी चाहिये, दूसरे एरिये में भी जाता है। मेरे एरिये में अब की बार आप कितना बजट देंगे, प्रस्ताव तो आज ही मैं आपको दे दूंगा, आप आश्वस्त करें कि प्रस्ताव देने के बाद मैं आपको अच्छा बजट दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य की चिंता सही है। आपकी भावना के अनुसार अब तक तो प्रस्ताव आये नहीं, अगर आपके प्रस्ताव कहीं पड़े हैं तो मुझे आप दे दें। अब भी आप प्रस्ताव देंगे तो प्राथमिकता के आधार पर जितना संभव होगा, उतना देंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जहां पर बिखरी आबादी है, वहां पर भी विकास होना चाहिये। उनका विकास इसलिए नहीं हो पाता है, क्योंकि उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि निश्चित रूप से जो भी आप प्रस्ताव लायेंगे, उन प्रस्तावों को स्वीकार करके काम को पूरा करेंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): मैं आज ही आपको प्रस्ताव दे दूंगा और आपको धन्यवाद है कि आपने मेरे प्रस्ताव को माना है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप लाल भील।

संपरिवर्तन भूमि का नामान्तरण

66. श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री प्रताप लाल भील)

क्या प्रदेश में संपरिवर्तन भूमि के बेचान पर नामान्तरण की कार्यवाही की जाती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त भूमि के बेचान पर नामान्तरण खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): जी नहीं। संपरिवर्तन भूमि के बेचान पर नामान्तरण के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 12(4) एवं नियम 12(5) में प्रावधान किये गये हैं। नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि संपरिवर्तन भूमि के नामान्तरण खोलने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी? संपरिवर्तन भूमि के नामान्तरण नहीं खुलने के कितने प्रकरण प्रदेश में दर्ज हुए?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विभाग में संपरिवर्तन भूमि का नामान्तरण खोलने का प्रावधान नहीं है। इसलिए इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं और राजस्थान भू-राजस्व नियम 12(4) के अनुसार गैर खातेदारी अभिधारी द्वारा संवर्तित भूमि के अंतरण की दशा में वह तहसीलदार को ऐसे अंतरण के बारे में सूचित करेगा। विलेख के अंतरण के आधार पर तहसीलदार राजस्थान भू-राजस्व नियम 1957 के प्रारूप- P(21) में नामान्तरण खोलेगा। यह नियम है।

दूसरा, 12(5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति या उसका अंतरिती, जो इन नियमों या किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि संपरिवर्तन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तत्समय प्रवर्त नियमों के अधीन अपनी कृषि भूमि का संपरिवर्तन करा लेता है तो संपरिवर्तित आदेश और उसके पक्ष में भूमि के अंतरण विलेख के साथ नामान्तरण रजिस्टर में..

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इनको नियमों की कॉपी भेज देना।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): ठीक है, साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द में वन विभाग के कार्यालयों में रिक्त पद

67. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के आसीन्द व बदनोर में जंगली जानवरों को पकड़ने हेतु पिंजरे नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभाग में कितने पद स्वीकृत व कितने रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) जी नहीं। वन मण्डल की रेंज आसीन्द अधीन जंगली जानवरों को पकड़ने हेतु 02 सुरक्षा पिंजरे उपलब्ध हैं।

(2) विभाग अन्तर्गत अधीनस्थ संवर्ग के पद वन मण्डल स्तर पर ही स्वीकृत हैं।

वर्तमान में वन मण्डल की रेंज आसीन्द अधीन पदस्थापित अधिकारी कर्मचारी की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**पदनाम**	**संख्या**
1	क्षेत्रीय वन अधिकारी	01
2	वनपाल	01
3	सहायक वनपाल	04
4	वनरक्षक	10

राजकीय विभाग में रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। विभाग अन्तर्गत वर्तमान में वनपाल के 11 एवं वनरक्षक के 937 पदों हेतु नियुक्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा वाहन चालक, सर्वेयर, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रयोगशाला सहायक व ट्रैक्टर गार्ड के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं, लेकिन मेरा एक छोटा-सा निवेदन है कि आप अधिकारियों को आदेशित करें कि आसीन्द के पास कटार गांव है, उसके पास माइनिंग एरिया है, बहुत माइंस हैं और बड़े-बड़े पत्थरों का ढेर लगा हुआ है, वहां आये

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

दिन पैंथर दिखते हैं, वहां एक पिंजरे की व्यवस्था करायें, बाकी व्यवस्था बढ़िया है।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने पैंथर से सम्बन्धित जो चिन्ता व्यक्त की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि वहां अधिकारियों से कह कर पिंजरे की व्यवस्था की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मण।

बस्सी में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम

68. श्री लक्ष्मण (बस्सी): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर ग्रामीण में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने के क्या मानदण्ड है? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोली जानी प्रस्तावित है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र की कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम बने हुए हैं तथा शेष समितियों के गोदाम कब तक बना दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) जिला जयपुर ग्रामीण में 377 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने के मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

1. न्यूनतम सदस्य संख्या - 300
2. न्यूनतम हिस्सा राशि - 3 लाख रुपये
3. न्यूनतम अमानत - 1 लाख रुपये

मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, सहकारिता)

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित 07 ग्राम पंचायत मुख्यालयों (सूची परिशिष्ट-3) में जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जावेगी।

(4) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 27 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्मित हैं। शेष 22 गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम निर्माण हेतु वैध स्वामित्व की भूमि उपलब्ध होने तथा संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी। सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण, प्रति व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्री लक्ष्मण (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। मैं सप्लीमेंट्री पूछ लूं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यहां 19 को-ऑपरेटिव सोसाइटी हैं, पंचायतों ने कहा कि भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि उपलब्ध कराने का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है और आबादी भूमि है तो ग्राम पंचायत का। मंत्री जी यह बतायें कि क्या इन्होंने रेवेन्यू आफिसर से मिलकर प्रयास किया कि उनको जमीन मिल जाये? क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है, मेरे को मालूम है कि वहां पर जमीन की कोई कमी नहीं है। अगर उनको जमीन नहीं मिलती है तो इनके डिपार्टमेंट के लोग मेरे से सम्पर्क कर लें। 19 की 19 में मैं जमीन उपलब्ध करवा दूंगा।

मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री यह है कि 07 ग्राम पंचायतें हैं। उनमें को-ऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं हैं। राज्य सरकार चाहती है कि हर एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर को-ऑपरेटिव सोसाइटी हो। जिला स्तरीय कमेटी जिसका अध्यक्ष कलक्टर होता है, तो क्या आपके अधिकारी सम्बन्धित कलक्टर से संपर्क करके उनकी अभिशंसा करेंगे, ताकि वहां भी को-ऑपरेटिव सोसाइटी बन सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि कलक्टर से हमें कोई प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जिला स्तरीय कमेटी में अगर वे पंचायतें उन मानदण्डों को पूरा करती हैं तो निश्चित

(श्री गोतम कुमार)

रूप से वहां उन पंचायतों, सातों पंचायतों में जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त होंगे, हम ग्राम सेवा सहकारी समिति खोल देंगे।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर को-ऑपरेटिव सोसाइटीज का बजट ही कम कर दिया है। क्या राज्य सरकार इस वजह से बाकी में नहीं करना चाह रही है?

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): राज्य सरकार निश्चित रूप से को-ऑपरेटिव मूवमेंट को और मजबूत करना चाहती है।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): आपने तो बजट कम दिया।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): आप जो फसली ऋण की बात कर रहे हैं, उसमें भी सरकार ने पांच लाख नये कृषकों को ऋण देने की घोषणा इस बजट में की है, बजट कम करने की बात आप कैसे कर सकते हैं? पाचं लाख नये किसानों को हम ऋण उपलब्ध करायेंगे और हम उनको राजस्थान सरकार के माध्यम से किसान सम्मान निधि देने का काम करेंगे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बजट ही आधा कर दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि जहां जमीन नहीं है वहां सोसाइटी की बिल्डिंग नहीं बन पा रही है, उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया, उसके लिए मंत्री जी क्या प्रयास करेंगे, यह बता दें।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): वैसे वहां की सोसाइटी को जमीन के लिए प्रयास करना चाहिए, फिर भी बस्सी से आने वाले माननीय विधायक और नेता, प्रतिपक्ष ने बताया है, तो वहां की समितियों के प्रयास से नहीं हो पा रहा है तो हम 19 समितियां जिनमें उपलब्ध नहीं है और तीन सोसाइटी जिनमें उपलब्ध है, उनके प्रस्ताव मंगवाकर गोदाम बनवाने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: सरकार भी मदद करे।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): बिलकुल।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित मीना।

किशनगंज के केलवाड़ा में 220 के वी जी एस एस का निर्माण

69. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ललित मीना)

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में निर्माणाधीन 220 केवी जीएसएस केलवाड़ा का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मागंरोल में 132 केवी जीएसएस पर 20/25 एमवीएए 132/33 केवी उच्च क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में रामगढ़-रेलावन व सैमली फाटक तथा तलहटी क्षेत्र कस्बा थाना में 132 केवी के नये जीएसएस तथा पंचायत समिति शाहाबाद व किशनगंज के गांव सन्दोकडा, धुंवा, सुवांस, छीनोद, बांसथूनी, सिमलोद, दुर्जनपुरा में 33/11 केवी के नये जीएसएस स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में प्रस्तावित 220 केवी जीएसएस केलवाड़ा के निर्माण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोली जा चुकी है तथा कार्यादेश का कार्य प्रक्रियाधीन है। इससे सम्बन्धित लाइनों का कार्यादेश दिनांक 04.10.2023 को जारी किया जा चुका है, जिसको पूर्ण करने की दिनांक 04.10.2025 निर्धारित है।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद के 132 केवी जीएसएस मांगरोल पर 132/33 केवी, 20/25 एमवीए क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर वर्ष 2024-25 की क्षमता आवर्धन योजना में प्रस्तावित है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में रामगढ़-रेलावन व सैमली फाटक क्षेत्र में 132 केवी जीएसएस हेतु प्रस्ताव प्रारम्भिक स्तर पर तकनीकी साध्यता का परीक्षण किया जा रहा है। साध्य होने पर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। तलहटी क्षेत्र कस्बा थाना के समीप देवरी में 132 केवी जीएसएस दिनांक 13.06.2023 को स्वीकृत कर निर्माण हेतु दिनांक 14.03.2024 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। उक्त जीएसएस को मार्च, 2026 तक स्थापित किया जाना लक्षित है। अत: तलहटी कस्बा थाना में नये जीएसएस निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

उक्त विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की पंचायत समिति शाहबाद व किशनगंज के ग्राम सन्दोकडा, धुंवा में 33/11 केवी सब-स्टेशन बनाया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

गांव सुवांस, छीनोद, बांसथूनी, सिमलोद, दुर्जनपुरा में 33/11 केवी के सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव का प्रारंभिक स्तर पर तकनीकी साध्यता का परीक्षण किया जा रहा है। साध्य होने पर प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि आपने इसी बजट में मुझे सैमली फाटक और रेलावन, दो 132 जीएसएस की घोषणा की है, आपका बहुत-बहुत आभार।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि 220 जीएसएस 2018 में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय स्वीकृत हुआ। पिछले छह साल से वर्तमान में केवल सिविल वर्क, केवल बाउंड्री हुई है। यह बारां 220 केवी जीएसएस से जुड़ना है, जिसकी दूरी लगभग 58 किलोमीटर है। केवल 15 किलोमीटर का ही उसमें अप्रूल अभी तक वर्तमान में हुआ है। 43 किलोमीटर अभी तक बाकी है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री ललित मीना (किशनगंज): अभी तक उसमें एक भी पिल्लर, कोई काम वहां पर नहीं गढ़ा गया है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि दस माह तो गुजर गये और आपने इसमें कहा है कि 04/10/2023 से 04/10/2025, दो साल में हम इसको पूरा कर देंगे। पिछले पांच साल में कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। अभी दस महीने गुजर गये हैं, 14 महीने शेष बचे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मेरा निवेदन है कि किसानों को तकलीफ हो रही है, 132 की सिंगल लाइन है। हम इसको 14 महीने में कम्प्लीट कर देंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: बैठिए, हो गया। माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बताया 220 जीएसएस के लिए काफी धीमी गति से काम चल रहा है। इसको पूरा करने की जो दिनांक 04/10/2025 निर्धारित है, इसमें सदस्य ने जो पूछा है, इसमें 57 किलोमीटर की लाइन है, 170 टॉवर लगने हैं। अभी तक कोई भी टॉवर नहीं लगा है। संवेदक को निर्देशित किया गया है कि वह जल्दी काम करे। फिर भी संवेदक ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करके, उसका कांट्रेक्ट निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। मैं सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि निर्धारित तारीख 04/10/2025 तक इसको पूरा करने का सरकार प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका। उत्तर आ गया है। श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मेरा दूसरा है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ललित मीना (किशनगंज): 000

शेरगढ़ में शहीदों के नाम पर संस्थानों का नामकरण

70. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में शहीद के नाम पर विद्यालय व चिकित्सा संस्थान आदि के नामकरण के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कितने व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण (श्री विजय सिंह): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में (बेटल केजुअल्टी फेटल एवं ऑपरेशनल केजुअल्टी) सैनिकों/कार्मिकों के नाम पर विद्यालय नामकरण करने के 12 प्रकरण वर्ष 2017-2024 से विचाराधीन चल रहे हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विद्यालय नामकरण करने की एक सतत प्रक्रिया है, जिसके

(राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण)

अनुसार लम्बित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही कर नामकरण की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नामकरण के लिए क्या मानदंड है? मानदंड में प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद कितनी समय सीमा में ये प्रस्ताव स्वीकृत किए जाते हैं?

श्री विजय सिंह (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यालय नामकरण करने की एक सतत प्रक्रिया है, जिसके अनुसार लंबित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही कर नामकरण की कार्यवाही की जा रही है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी पंचायत और जो भी विभाग हैं, उनकी एनओसी और प्रस्ताव बनकर आ जायेंगे तो जल्दी से नामकरण करवा दिया जायेगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने तो मानदंड के बारे में पूछा है। आप फरमा रहे हैं कि सतत प्रकिया है। पूरे मानदंड तो बता दीजिए, क्या हैं? बता सकें तो ठीक है। मेरा तो यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि दो-तीन साल हो गये हैं, शहीदों के नाम से, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से नामकरण करना है, दो-दो, तीन-तीन साल से पेंडिंग पड़े हैं, विचाराधीन हैं। अब तो कम से कम बता दीजिए कि किस समय सीमा में इनको आप कर देंगे?

श्री विजय सिंह (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बेटल केजुअल्टी फेटल एवं ऑपरेशनल केजुअल्टी सैनिक/कार्मिकों के नामकरण के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा जारी नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार नामांकन की कार्यवाही की जाती है। विभागाध्यक्ष द्वारा प्रेषित किए जाने वाले नामांकन के प्रस्तावों में स्वयं की स्पष्ट अभिशंसा व समस्त दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। यथा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, संस्था प्रधान एवं ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अभिशंसा प्रपत्र 7 के बेटल केजुअल्टी फेटल एवं ऑपरेशनल केजुअल्टी प्रमाण पत्र, गेलेन्ट्री अवार्ड प्रमाण पत्र संलग्न करने के उपरांत परीक्षण कर शिक्षा विभाग के स्तर पर नामांकन की कार्यवाही की जायेगी।

(श्री विजय सिंह)

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कार्यवाही पूर्ण होते ही, इनको करवा दिया जायेगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय, कार्यवाही पूर्ण है। हमारा प्रस्ताव तो आपके पास विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इस पर जल्दी कार्यवाही करें।

श्री विजय सिंह (राज्य मंत्री, राजस्व): बिलकुल साहब, जल्दी कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर जसवंत सिंह यादव।

बहरोड़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी

71. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में विगत तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कुल कितने वृद्धजन पात्र पाए गए? उक्त में से कितनों को पेंशन दी जा रही है एवं कितने वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में पात्र वृद्धजनों के आधार कार्ड से मोबाइल नम्बर नहीं जुड़ने तथा बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं होने के कारण योजना से वंचितों को लाभ देने हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत तीन वर्षों में पालनहार योजना के तहत कुल कितने व्यक्ति पात्र पाये गये? उक्त में से कितनों को योजना का लाभ दिया जा रहा है एवं कितने लाभ से वंचित है? सरकार की लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु क्या कार्ययोजना है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत कुल 23,068 वृद्धजन पेंशनर्स पात्र पाए गए हैं। इनमें से 22,619 पेंशनरों को पेंशन दी जा रही है तथा 449 पेंशनरों के प्रकरण निम्नलिखित कारणों से लंबित हैं:-

पेंशनरों का ई-मित्र द्वारा गलत सत्यापन- 21

पेंशनरों की मृत्यु हो जाने के कारण- 407

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

बैंक विवरण गलत होने के कारण- 04

वर्ष 2023 में भौतिक सत्यापन नहीं कराने के कारण- 17

संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना में पात्र वृद्धजनों के आधार कार्ड से मोबाइल नम्बर नहीं जुड़ने तथा बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं होने के कारण योजना से वंचितों को लाभ देने हेतु सरकार द्वारा पेंशन पोर्टल पर एक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसके द्वारा संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी उपलब्ध करवाकर पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में विगत तीन वर्षों में पालनहार योजनान्तर्गत पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल पात्र आवेदनों का विवरण वर्षवार निम्नानुसार हैः-

वर्ष	**कुल पात्र**		**लाभान्वित**		**लंबित प्रकरण**
	पालनहार	**बच्चे**	**पालनहार**	**बच्चे**	
2021-22	230	406	230	406	0
2022-23	198	354	198	354	0
2023-24	165	285	156	276	09

लंबित प्रकरणः- आवेदक द्वारा योजनान्तर्गत श्रेणीवार निर्धारित दस्तावेज जैसे बच्चों के अध्ययन प्रमाणपत्र, माता/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि संलग्न नहीं होना है। जो प्रकरण लंबित हैं, उनका कारण।

निस्तारण की योजनाः- पालनहार योजना के नियम 9 उपनियम 6 के तहत ऐसे आवेदन पत्रों में आक्षेपों की पूर्ति कराने के लिए सिस्टम आधारित मैसेज के माध्यम से पालनहार के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर आक्षेप लगाये जाने के दिनांक से आक्षेप पूर्ति हेतु 30 दिवस, 45 दिवस एवं 60 दिवस में सूचित किया जाता है तथा इसके उपरान्त भी आक्षेप पूर्ति नहीं होने की स्थिति में 30 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर जिला अधिकारियों व ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पालनहार से समन्व स्थापित कर आवेदनों में कमी की पूर्ति कराई जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो बहुत बुजुर्ग हो गये हैं उनका बॉयोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो सकता, उनके हाथों की रेखाएं मिट जाती हैं। उनके पास मोबाइल होता नहीं है और वह जाने के अन्दर बेसहारा हैं, उनको अधिकारी के पास ले जाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि अधिकारी का मिलना भी कोई आसान काम नहीं है। ऐसे लोग जो पेंशन से वंचित हैं, क्या सरकार इन लोगों का सहारा बनने के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए आप कोई नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहते हैं, जो उनके पास जाकर ये सारा काम कर लें। बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, वे जाएं कैसे? उनको ले जाने वाला कोई होता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है, वाकई में राजस्थान के उन वृद्धजनों के लिए है जो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण न तो वेरिफिकेशन करा पाते हैं और न उनको पेंशन का लाभ मिल पाता है। मैं इसके लिए माननीय सदस्य को सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि पेंशन सत्यापन हेतु बॉयोमैट्रिक ई-मित्र पर मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। यदि सम्बन्धित पेंशनर का मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो या अंगूठा न तो हो तो उस स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ, शहरी क्षेत्र में एसडीओ के मोबाइल से सत्यापन किया जाता है।

माननीय विधायक महोदय के क्षेत्र में यदि कोई पेंशनर का सत्यापन उनके शारीरिक रूप से अक्षम या ई-मित्र पर नहीं जा पाने के कारण नहीं हो रहा है तो ई-मित्र संचालक को उनके निवास पर भी भेजा जा सकता है। राज्य सरकार सभी ई-मित्र संचालकों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ, शहरी क्षेत्र में एसडीओ के माध्यम से ऐसे प्रकरणों में मानवीय संवेदना का ध्यान रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेगी। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि हम हमारी सरकार के माध्यम से नोडल अधिकारी, वैसे तो मैंने बता दिया, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, ग्राम पंचायत में जो स्वीकृत ई-मित्र होते हैं, उनके माध्यम से स्वीकृत होने के बाद वेरिफिकेशन होता है प्रत्येक साल में, लेकिन कुछ वास्तव में ऐसे होते हैं जो वहां नहीं पहुंच पाते, तो हम बीडीओ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम सेवक हैं, उनको परमानेंटली एक सर्कुलर जारी करेंगे, ताकि वे ई-मित्र के

(श्री अविनाश गहलोत)

माध्यम से वहां जाएं और उन बुजुर्गों का, वृद्धजनों का, जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा, उनके माध्यम से वह कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: हो गया समाधान।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष जी, एक सैकण्ड। आपके जवाब में आया है, जवाब अच्छा दिया है, अभी आपने नोडल अधिकारी की बात भी कह दी है, परंतु कोई आदमी, बुजुर्ग आदमी बड़ी मुश्किल से ई-मित्र के यहां चला गया। जो भी ई-मित्र ने मांगा आधार कार्ड, राशन कार्ड, उसने दे दिया। ई-मित्र के द्वारा गलती हो गयी, कोई गलती कर दी तो उस बुजुर्ग की गलती तो है नहीं, ऐसे में ई-मित्र वाले अपनी काफी फीस लेकर लापरवाही करने लग गये हैं, जो आपने जवाब में भी दिया है। ऐसे ई-मित्र के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की योजना रखते हैं? आज तक कोई कार्यवाही की है?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी बिलकुल सच बात है कि ई-मित्र होता है कहीं, उसकी गलती के कारण पेंशन के लाभार्थी को पेंशन नहीं मिल पाती है। यह आईटी का डिपार्टमेंट का काम है कि ई-मित्र का लाइसेंस है वह आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से मिलता है, लेकिन फिर भी अगर किसी ई-मित्र के प्रकरण का हमारे पास आता है, हम उसकी जांच बनाकर आईटी डिपार्टमेंट को भेज देंगे और उसका जो लाइसेंस है, उसको रद्द करने के लिए उसके प्रकरण को बनाकर हम आईटी विभाग को भेज देंगे।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्री जी, आपके पास तो आ गए हैं कि इतने लोगों को ई-मित्र की गलती से पेंशन नहीं मिल पाई, तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो और सब सही हो जाएंगे।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बिलकुल। निश्चित ही, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकरण में हमारे पास रिपोर्ट आ गई ई-मित्र की गलती के कारण अगर किसी व्यक्ति को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, आज ही सर्कुलर जारी करके उनका आधार निरस्त करने की कार्यवाही आईटी डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी।

प्रश्न संख्या 72

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री अमृतलाल मीणा।

होम गार्डों को विराम भत्ता देने की कार्ययोजना

73. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में होम गार्ड के जवानों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया जाता है?

(2) क्या सरकार होम गार्ड को विभागों में रिक्त पदों पर स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उदयपुर संभाग में विभाग में कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि होम गार्ड के जवानों को देय विराम भत्ता बंद है? क्या सरकार उक्त भत्ता पुन: देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) जी हां। राजस्थान होम गार्ड नियम 1962 एवं राजस्थान होम गार्ड अधिनियम 1963 के तहत मांग प्राप्त होने पर विभिन्न विभागों में होम गार्ड जवानों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए नियोजित किया जाता है।

(2) जी नहीं। राजस्थान होम गार्ड नियम 1962 एवं राजस्थान होम गार्ड अधिनियम 1963 में प्रावधान नहीं होने के कारण होम गार्ड स्वयंसेवकों को रिक्त पदों पर स्थायी करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) का (1) निदेशालय गृह रक्षा के उदयपुर संभाग में स्थायी स्टाफ का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	समादेष्टा	1	1	0
2.	उप समादेष्टा	5	4	1
3.	कम्पनी कमाण्डर	2	0	2
4.	प्लाटून कमाण्डर	11	3	8
5.	मुख्य आरक्षी	11	3	8
6.	आरक्षी	13	12	1
7.	अतिरिक्त प्रशा.अधि.	1	0	1
8.	सहायक प्रशा.अधि	2	2	0

(गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री)

क्र. स.	**पदनाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
9.	वरिष्ठ सहायक	5	3	2
10.	कनिष्ठ सहायक	6	6	0
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/चौकीदार/कुक	3	1	2
	कुल योग	**60**	**35**	**25**

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया।

श्री अध्यक्ष: सदस्य कहें ना। सदस्य कहें तो मैं मानूं। सदस्य बुलवा रहे हैं तो मैं कैसे कह दूं कि आ गया?

गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी) : (II) निदेशालय गृह रक्षा के उदयपुर संभाग में स्वयंसेवकों की नफरी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	**स्वयंसेवकों की स्वीकृति नफरी**	**स्वयंसेवकों की ऑनरोल नफरी**	**रिक्त**
1.	3,880	3,159	721

(4) जी नहीं। वर्तमान में होम गार्ड स्वयंसेवकों को विराम भत्ता दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि निदेशालय के 721 पद तो रिक्त हैं, इधर 25 रिक्त हैं। नफरी वैसे बहुत कम है सरकार उसको भरने की इच्छा रखती है? दूसरा, होम गार्ड में वेतन बढ़ोतरी करने का सरकार विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष जी, आपने पूछा है होम गार्ड के रिक्त की भर्तियां, प्रक्रियाधीन है, जो विवरण इस प्रकार है। जो स्थायी हैं उनकी भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और जो अस्थायी श्रम सेवक हैं, उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का फैसला होने के बाद हम उनकी भर्तियां जारी करेंगे। अस्थायी हैं इसलिए हम भर्ती नहीं मान सकते हैं।

दूसरा, आपने हम से विराम भत्ते के सम्बन्ध में पूछा। अध्यक्ष महोदयजी, मैं कहना चाहूंगा कि होम गार्ड्स को विराम भत्ता दिया जा रहा

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

था, लेकिन कांग्रेस के शासन में दिनांक 06.05.2022 को विराम भत्ता स्थगित कर दिया गया था। अब 27.02.2024 को नीति निर्धारण करते हुए नियमानुसार विराम भत्ता दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: चलिए, हो गया।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या होम गार्ड जवानों को पूरे वर्ष ड्यूटी पर लिया जाता है या कितने दिन इनको ड्यूटी पर ले रहे हैं? मंत्री जी से निवेदन है कि शेष समय में उनके परिवार को गुजारा करने हेतु क्या सरकार कोई पारिश्रमिक देती है, यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उनको पारिश्रमिक देने का विचार रखती है?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, ये हमारे श्रम सेवक हैं। सरकारी उपक्रम और सेमी गवर्नमेंट के जो उपक्रम हैं, उनमें मांग आने के बाद हम उनको वहां भेजते हैं। आपने कहा कि इनको स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए। जैसे-जैसे मांग आती है, हमारे पास श्रम सेवक हैं उनको भेजते हैं। मांग नहीं आने पर उनको 12 महीने का रोजगार अभी तक सरकार नहीं दे पाती।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन पटेल कोलाना।

पीपल्दा के ग्रामों का राजस्व रिकार्ड

74. श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्रामों के राजस्व रिकार्ड को ऑनलाइन किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की दीगोद तहसील के कुछ गांवों के राजस्व रिकार्ड ऑनलाइन नहीं हुए? यदि हां, तो शेष को कब तक ऑनलाइन करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में तहसील पीपल्दा के 174 ग्राम एवं तहसील दीगोद के 86 ग्राम शामिल हैं, जिनमें से तहसील पीपल्दा के समस्त 174 ग्रामों एवं तहसील दीगोद के 63 ग्रामों के राजस्व रिकार्ड को ऑनलाइन किया जा चुका हैं।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में शामिल तहसील दीगोद के 23 ग्राम का रिकार्ड एवं मौका स्थिति में काफी भिन्नता होने के कारण ऑनलाइन अधिसूचित होने से शेष रहे हैं। उक्त ग्रामों में सर्वे-रिसर्वे की कार्यवाही के पश्चात् ऑनलाइन करवाया जा सकेगा। कोटा जिले में सर्वे-रिसर्वे का कार्य प्रगतिरत है, जिसे पूर्ण किये जाने की समयावधि वर्ष 2026-27 तक निर्धारित हैं।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): मुझे जवाब मिल चुका है, मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहता हूं।

मुझे जवाब मिला है, 2026-27 तक गलती को दुरुस्त कर दिया जाएगा। मेरा निवेदन है कि ऑनलाइन का कार्य चलते हुए पांच वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, ऑनलाइन के अभाव में किसानों को एमएसपी पर खरीद के समय जमाबंदी पर पटवारी के साइन करवाने हेतु चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि 2026-27 तक गलती को दुरुस्त करने की जगह तत्काल सर्वे-रिसर्वे कराकर सैटलमेंट व कैचमेंट में हुई गलतियों का सुधार करने पर विचार रखते हैं? हां, या नहीं? नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय का प्रश्न है, क्योंकि यह सर्वे-रिसर्वे का काम 2016-17 में आरम्भ हुआ था। इस विधान सभा क्षेत्र में पीपल्दा और दीगोद, जो इन्होंने प्रश्न किए हैं, पीपल्दा के 174 गांव हैं, 174 में से पूरे ऑनलाइन हो गए हैं। दीगोद के 86 गाँवों में से 63 हो चुके हैं। चूंकि दीगोद के 23 गांव बाकी रह गए हैं। 23 गांव रिकार्ड एवं मौका स्थिति में काफी भिन्नता होने के कारण ऑनलाइन अधिसूचित होना शेष हैं। यह सीकोन कम्पनी के माध्यम से सर्वे-रिसर्वे का काम हो रहा है। कोटा जिला रिसर्वे के दूसरे चरण में आ रहा है। इसको 2026-27 तक पूरा करने का टारगेट है।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): सर, मेरा यह प्रश्न था कि पांच साल पहले ही इस कार्य को चलते हुए हो गए हैं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि इसको तत्काल सर्वे-रिसर्वे कराकर सैटलमेंट, कैचमेंट में गलतियों को सुधार करने का आप विचार रखते हैं क्या? किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी है पटवारी के चक्कर लगाने में।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय सदस्य महोदय, फील्ड सर्वे

(श्री हेमन्त मीणा)

कार्य के समय, 2017-18 से चला था और इसमें 3-4 कारण रहे हैं, जिससे यह डिले हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी, क्योंकि पूरे राजस्थान में कुल 426 तहसीलें हैं जिसमें से 416 तहसीलें ऑनलाइन अधिसूचित हो चुकी हैं, बाकी रही इन दस तहसीलों के काम भी जल्दी ही पूरा करके आपको सूचित कर दिया जायेगा, सदन को सूचित कर दिया जायेगा और जो पटवारी और तहसीलदार के पास जनता चक्कर काट रही है, उस चक्कर को समाप्त कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो बताया है वैसे तो यह एक काफी गम्भीर समस्या है, काफी लम्बे समय से यह चल रही है और ज्यादातर पंचायतें ऐसी हैं जिनमें पांच परसेंट, दस परसेंट, बीस परसेंट ही काम बाकी है, ऐसी कुछ तहसीलें हमारी पेंडिंग हैं, तो क्या आप समयबद्ध तरीके से इनको पूरा करने का कोई विचार रखते हैं? अभी आपने जैसे वर्ष 2026-27 बताया है तो क्या 2026-27 तक यह काम पूरा हो जायेगा? क्या सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है? जो इनको टास्क दिया हुआ है, क्या उसकी मंथली या तिमाही रूप से सरकार समीक्षा करती है?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): इसको वर्ष 2026-27 तक तो निर्धारित किया गया है, तब तक तो हो ही जायेगा परंतु उससे पहले करने का हम प्रयास करेंगे, यह मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द में स्थापित औद्योगिक इकाइयां

75. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला राजसमन्द में लाल, नारंगी, हरी एवं श्वेत श्रेणी की कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिला में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं परिचालन हेतु कितने आवेदन विगत तीन वर्षों में प्राप्त हुए तथा उक्त में से कितने आवेदनों को स्वीकृत किया गया व कितने शेष हैं? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला राजसमन्द में उक्त अवधि में पर्यावरण सहमति के

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

मानदण्डों का उल्लंघन करने पर किस-किस इकाई के विरुद्ध कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्री संजय शर्मा): (1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध अभिलेखानुसार, राजसमंद जिले में लाल श्रेणी की 09, नारंगी श्रेणी की 1062, हरी श्रेणी की 193 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। यहां यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि श्वेत श्रेणी की इकाइयों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से सम्मति प्राप्त करने की प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है।

(2) राजसमन्द जिले विगत तीन वर्षों में पर्यावरणीय स्वीकृति (ई.सी.) हेतु परिवेश पोर्टल के अनुसार 164 ई.सी. जारी की गई है तथा पांच ई.सी. प्रस्ताव निरस्त किये गये हैं।

राजसमन्द जिले में परिचालन हेतु विगत तीन वर्षों में प्राप्त हुए आवेदनों की वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) पर्यावरण नियमों एवं निर्धारित मांपदण्डों का उल्लंघन करने पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इकाइयों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है एवं पर्यावरण मापदण्डों में सुधार नहीं करने पर दोषी इकाई के विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 (A) एवं अथवा वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31 (A) के तहत उद्योग को बन्द करने के निर्देश जारी किये जाते हैं।

जिले में विगत 03 वर्षों में पर्यावरण नियमों एंव मापदण्डों के उल्लंघन करने वाली 03 इकाइयों के विरुद्ध जल एवं अथवा वायु अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग को बन्द कराने के निर्देश जारी किये गये, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उद्योगों की समय-समय पर जांच कर गुण दोष के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रदूषण नियंत्रण मानकों में सुधार करवाये जाते हैं जो कि एक सतत प्रक्रिया है। इसी क्रम में गत 03 वर्षों में 145 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूंगी कि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आती हूं, वहां पर स्लरी डम्पिंग, मार्बल स्लरी डम्पिंग, अन्य वेस्ट डम्पिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। चुनावों में ही नहीं आप कभी नया दरीबा या इसके आसपास के गांवों में पानी पीने जाएंगे तो आप एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते, वहां की स्थिति तो यह है। लेड की वजह से आये दिन वहां के लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां, लीवर डैमेज हो रहे हैं। इसको मैंने 295 के माध्यम से भी सदन में बहुत बार रखने की कोशिश की है।

माननीय मंत्री महोदय, यह जो डम्पिंग हो रही है, कहीं भी मन करता है, किसी भी तरीके से चरागाह भूमि को कब्जा करते हैं और उसके ऊपर डम्पिंग करते हैं और आये दिन हमने भी प्रशासन को बहुत बार बताकर हटवाया भी है और आज भी हम उस समस्या से लड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हम इस डम्पिंग को रेगुलराइज्ड करें, ऐसा कुछ क्या सरकार सोच रही है कि नियमानुसार ही यह डम्पिंग हो?

दूसरा प्रश्न भी मैं यह पूछूंगी कि आपने जो परिशिष्ट-स में यह दिया है कि हमने इनके बारे में अलग-अलग कार्यवाही की है। इसमें आप अगर खुद देखेंगे तो हिन्दुस्तान जिंक, जो एक बहुत बड़ी स्लरी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये। आप सीधे प्रश्न पर आएं।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सर, मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं। मैं यह बता रही हूं कि आपने इतनी बार डिफरेंटडिफरेंट टाइम पर उनको नोटिस दिया है। पहले 2021 में दो नोटिस पेश किये गये, 2022 में दो नोटिस पेश किये गये, 2023 में दो नोटिस पेश किये गये, तो इतनी बार नोटिस पेश करने के बावजूद भी आज भी समस्या वही की वही है कि कोटड़ी में टेलिंग डैम में बड़े-बड़े पहाड़ क्रिएट कर दिये हैं। आप अगर स्वयं आएंगे और वहां पर देखेंगे तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण नहीं। आप प्रश्न पूछिये। इतनी भूमिका की जरूरत नहीं है।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं पर मुझे वहां की परिस्थिति तो बतानी ही पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: परिस्थिति पर अलग से आइये। आप परिस्थिति मत बताइये, सीधा प्रश्न पूछिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मंत्री महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करती हूं कि इस स्लरी वेस्ट डम्पिंग के लिए आप रेगुलराइज्ड करें। हम कुछ ऐसे कड़े नियम लाएं कि वहां पर पानी में भी सुधार हो सके। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: निवेदन नहीं, आप सीधा प्रश्न करें। आप सुझाव बाद में देना।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इस पर क्या कार्यवाही हम कर रहे हैं?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने जो विषय सदन के अन्दर रखा है, यह निश्चित रूप से चिंताजनक है क्योंकि किसी भी उद्योग को यह छूट नहीं है कि वह अपने वेस्ट के माध्यम से आसपास के रहने वाले किसानों को परेशान करे, पीड़ा हो या दूषित जल उसको मिले, यह किसी भी उद्योग को छूट नहीं दी जा सकती है।

जहां तक माननीय सदस्या ने इस सदन में यह विषय रखा है कि जो क्षेत्र में स्लरी के माध्यम से जो इधर-उधर डम्पिंग की जाती है, उसके लिए सर्वे करवा लिया जायेगा और उनको यह निर्देशित किया जायेगा कि डम्पिंग यार्ड में ही उनको शिफ्ट करवाया जाये। साथ ही साथ, भविष्य में निगरानी एवं सतत प्रक्रिया जारी करते हुए जिला प्रशासन व राज्य प्रदूषण मंडल के अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित भी करवाया जायेगा कि निर्धारित डम्पिंग यार्ड के अलावा कहीं भी मार्बल स्लरी को डम्प नहीं किया जाये। साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक के अपशिष्ट के बारे में माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, तो यह निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में भी यह विषय आया है और आने वाले समय में उद्योग कोई भी हो यदि वह विभाग के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह आश्वस्त करता हूं कि कठोर से कठोर कार्यवाही उस उद्योग के खिलाफ की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

बाडसा ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा फसली ऋण का वितरण

76. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति, बाडसा द्वारा माह अक्टूबर, 2019 में किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना फसली ऋण दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों द्वारा ऋण चुकाने के बाद भी उनके खाते में बकाया बताया जा रहा है? यदि हां, तो कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त के संबंध में जिला कलेक्टर एवं प्रबंध निदेशक को शिकायत की गई है? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) ग्राम सेवा सहकारी समिति बाडसा द्वारा अक्टूबर, 2019 में किसी भी सदस्य को ऋण वितरण नहीं किया गया।

(2) चूंकि ग्राम सेवा सहकारी समिति बाडसा द्वारा अक्टूबर, 2019 में किसी भी सदस्य को ऋण वितरण नहीं किया गया। अत: उक्तानुसार लागू नहीं है।

(3) चूंकि ग्राम सेवा सहकारी समिति बाडसा द्वारा अक्टूबर, 2019 में किसी भी सदस्य को ऋण वितरण नहीं किया गया। अत: उक्तानुसार लागू नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया मैं सीधा पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछना है? चलिये, सीधा पूरक प्रश्न आ रहा है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि अक्टूबर की जगह सितम्बर में किन-किन लोगों ने लोन लिये और उन लोगों के लोन अभी तक बाकी हैं या भुगतान हो गया? बस।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्टूबर का जो प्रश्न मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था, तो अक्टूबर में तो इस प्रकार का कोई लोन लिया नहीं गया था लेकिन सितम्बर में, आपने जब प्रश्न किया तो उसकी जानकारी हमने ली है, तो

(श्री गोतम कुमार)

इसमें यह जानकारी में आया है कि आठ किसानों द्वारा इस बाडसा ग्राम सेवा सहकारी समिति में शिकायत की गयी थी डी.आर. को और डी.आर. को शिकायत करने के बाद पता किया गया तो यह संज्ञान में आया कि 11 किसानों को, जिनको सितम्बर, 2019 बाडसा ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऋण दिया गया था, उन किसानों द्वारा समिति के तत्कालीन व्यवस्थापक को 19.01.2020 से 30.06.2022 तक की अवधि में राशि 3 लाख 28 हजार रुपये जमा करवा दी गयी थी परंतु व्यवस्थापक ने वह राशि ऋण खाते में जमा नहीं करवाई। जैसे ही सी.सी.बी., पाली को इस प्रकरण में संज्ञान हुआ तो समिति के संचालक मण्डल द्वारा सम्बन्धित व्यवस्थापक को समिति की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया। तत्कालीन समिति व्यवस्थापक द्वारा उक्त 11 किसानों की राशि मय ब्याज खातों में जमा करवा दी गयी है और उस व्यवस्थापक के खिलाफ विभाग द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के निर्देश जारी कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

रामगढ़ में स्वीकृत 33 के वी जी एस एस

77. श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम पंचायत पिपरोली, सैंथली, नंगला बन्जीरका व रघुनाथ में स्वीकृत 33 केवी जीएसएस अभी तक चालू नहीं हुए हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त जीएसएस को कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): जी हां। विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम पिपरोली, सैंथली, नंगला बन्जीरका, रघुनाथगढ़ ग्रामों में 33/11 सब-स्टेशन स्वीकृत हुए हैं तथा सभी सब्स्टेशन चालू नहीं हुए हैं। उक्त चारों 33/11 सब-स्टेशन का कार्य माह जुलाई, 2024 के अन्त तक पूर्ण कर चालू किया जाना लक्षित है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्रीजी, मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यह उत्तर दिया है कि 31 जुलाई तक सब चालू हो जाएंगे, इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद और एक तो आज चालू भी हो गया है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि रामगढ़ जीएसएस 132 और गोविंदगढ़ जीएसएस

(श्री जुबेर खान)

132, दोनों ही एक लाइन पर हैं और वह रेलवे लाइन का भार भी जीएसएस 132 रामगढ़ पर ही है। अब इसमें दो प्रस्ताव हैं। एक तो मुबारिकपुर में 132 जीएसएस मंजूर हो गया, आपके विभाग ने जमीन के पैसे भी जमा करवा दिये, तो उसको चालू करवा दीजिए और एक गोविंदगढ़ का प्रस्ताव है कि सीकरी में नया 220 जीएसएस बना है जो गोविंदगढ़ से मुश्किल से आठ-दस किलोमीटर ही है। अगर गोविन्दगढ़ को वहां से जोड़ दें, जो प्रस्तावित है, प्रस्ताव आया पड़ा है, तो गोविन्दगढ़ वहां से हो जायेगा। इससे रामगढ़ क्षेत्र में बिजली की सुविधा हो जायेगी। मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, बताना है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गोविन्दगढ़ को जोड़ने के लिए प्रस्ताव का जो आग्रह किया है, इसका हम तकनीकी आधार पर परीक्षण कराकर के, उसको जोड़ सकते हैं तो निश्चित रूप से जोड़ने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विपक्ष के नेता, जूली जी। प्रश्न, आपका प्रश्न है।

बामनवास के बौंली व बाटोदा में खेल स्टेडियम का निर्माण

78. श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष) (श्रीमती इन्द्रा (बामनवास) के स्थान पर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बामनवास के बौंली व बाटौदा में खेल स्टेडियम हेतु बजट आवंटित किया गया था? यदि हां, तो सरकार बौंली व बाटौदा में खेल स्टेडियम का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दो हो गये, दो खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष: हां, आप बोलिये। 2-2 तैयार हैं। माननीय मंत्री जी, बोलिये। शुरू करो आप।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई): जी हां। बामनवास विधान सभा क्षेत्र के बौंली एवं बाटौदा में विभाग द्वारा कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रमश: राशि रुपये 150 लाख एवं 80 लाख की स्वीकृति वर्ष 2023-24 में जारी की गयी है। स्वीकृति की प्रतियां परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध हैं।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

बौंली व बाटौदा में भूमि आवंटित नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाये हैं। भूमि आवंटन होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, पैसे तो हमने हमारे समय में दे ही दिये, आपको सिर्फ भूमि आवंटित करनी थी, आप आठ महीनों में भूमि आवंटित नहीं कर पाये। बौंली में तो भूमि आवंटन का बनाकर के भी भेज दिया है। जमीन दे दी है। बाटौदा में दो स्कूल हैं, एक मॉडल स्कूल है, एक दूसरा स्कूल है, दोनों का जो ग्राउंड है, उसको मिलाकर वहां पर स्टेडियम बन सकता है। आप इन दोनों जगह पर कब तक काम प्रारंभ करा देंगे?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि पैसे तो इनके समय पर आवंटित कर दिये गये, लेकिन इनके कार्यकाल में जिले भी इन्होंने खूब बनाकर के दे दिये थे। यह दो जिलों के अन्दर काम है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जिलों की तो छोड़ो, आप स्टेडियम तो बनवा दो।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): चूंकि यह बाटौदा सवाई माधोपुर में है और बामनवास गंगापुर सिटी में चला गया। यह प्रक्रियाधीन है और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने, कलेक्टर ने भी इसके लैटर लिख दिये हैं। जमीन के आवंटन की प्रक्रिया अधूरी है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह जिम्मेदारी विभाग की है कि वह दूसरे विभाग, राजस्व से कॉआर्डिनेट करके जमीन उपलब्ध करवाये। अब यह कहना कि जमीन मिलेगी तभी हम बनायेंगे, पैसे अलॉट हो गये, टेंडर हो गये, वर्क ऑर्डर हो गये उसके बावजूद आप काम शुरू नहीं करा पा रहे।

श्री अध्यक्ष: जिले दो हो गये, तो कर रहे हैं कार्यवाही।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): अध्यक्ष महोदय, इसमें बीच में आचार संहिता भी थी।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती धारीवाल। आपका प्रश्न है।

पन्ना धाय जीवन अमृत योजना

79. श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में पन्ना धाय जीवन अमृत योजना को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): जी हां। प्रदेश में बी.पी.एल एवं आस्था कार्ड धारी परिवारों हेतु दिनांक 14.08.2006 से संचालित पन्ना धाय जीवन अमृत योजना को दिनांक 14.05.2024 से बन्द कर दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम को भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा कोष एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय परिवार लाभ योजनान्तर्गत प्रति व्यक्ति कुल रुपये 200/- की प्रीमियम राशि आवंटित नहीं किये जाने के कारण नवीनीकरण के अभाव में संचालन बन्द किया गया है। निरस्तीकरण के आदेश (परिशिष्ट अ) संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जवाब आ गया, पढ़ लिया मैंने जवाब।

श्री अध्यक्ष: चलिये, चलिये, पूरक प्रश्न पूछिये। आप पूरक प्रश्न पूछें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि विगत वर्षों में इस योजना पर कितनी राशि खर्च की गयी और केन्द्र सरकार से कितनी राशि मिली? योजना के बंद करने के बाद राज्य पर वित्तीय भार कितना कम हुआ और इस योजना में क्या-क्या लाभ दिये जाते थे? मेरा पहला प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है, मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो योजना है वित्तीय वर्ष 2006-07 में बीपीएल एवं आस्था कार्ड धारी परिवारों के पन्ना धाय जीवन अमृत योजना की घोषणा की गयी। भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना और दिनांक 14.08.2006 से प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के

(श्री अविनाश गहलोत)

अंतर्गत चयनित बीपीएल परिवारों के मुखिया, कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर एकमुश्त निम्नांकित सहायता राशि का प्रावधान किया गया है।

मानीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रीमियम राशि, उसमें सामान्य मृत्यु पर 30 हजार, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार, स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता पर 75 हजार, 2 आंख और 2 हाथ-पैर की क्षति होने पर 75 हजार, 1 आंख या 1 हाथ-पैर की क्षति होने पर 37,500 रुपये दिया जाता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना पीएमजेजेवाई एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई का संचालन 1.06.2017 से प्रारंभ हुआ। इसमें 18 से 50 साल की आयु वर्ग के लिए प्रीमियम राशि 330 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रखी गयी। मृत्यु होने पर बीमित राशि दो लाख रुपये का प्रावधान था। पीएमएसबीवाई में 12 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष और दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमित राशि दो लाख रुपये थी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं पूछा।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं एक मिनट में बता रहा हूं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैंने जो पूछा उसका जवाब चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: वह भी मिलेगा। उत्तर आने दीजिये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं आपको राशि वाइज बता रहा हूं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप इधर-उधर की बात कर रहे हो। मैंने स्पष्ट तौर पर यह पूछा है कि इस पर कितनी राशि केन्द्र सरकार के द्वारा विगत वर्ष में दी गयी?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पन्ना धाय जीवन अमृत योजना जनश्री योजना के माध्यम से वर्ष 2006-07 में चालू की गयी। मैं बता रहा हूं, आप सुनिये तो सही।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैं विगत वर्ष की पूछ रहा हूं और आप 2006-07 की बात कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: उत्तर बता रहे हैं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 2016-17 तक यह बीमित राशि इसमें मिली।

श्री अध्यक्ष: सुनो तो सही, बता रहे हैं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 2006-07 में 22 करोड़ 23 लाख रुपये, 2007-08 में 26 करोड़ 48 लाख रुपये ...(व्यवधान)

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पिछले साल का बताओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लास्ट ईयर की पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: धारीवाल जी आपसे सीनियर हैं। उनको अनुभव है, पूछें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लास्ट ईयर की वे बता दें।

श्री अध्यक्ष: उनको सहायता की आवश्यकता नहीं है। हो गया?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): कहां हो गया। मेरा उत्तर तो नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: हो गया ना आपका। 26 करोड़ बता दिया ना।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 2016-17 में 27,70,820 बीमित परिवारों की संख्या थी। इसमें 27 करोड़ और 71 लाख रुपये की प्रीमियम राशि दी गयी।

श्री अध्यक्ष: श्री गणेश घोगरा।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, बताइये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरा स्पष्ट सवाल यह है कि विगत वर्ष में इस योजना पर कितनी राशि खर्च की गयी और केन्द्र सरकार के द्वारा कितनी राशि दी गयी? मैं तो पिछले साल का आपसे मांग रहा हूं। आप 2016-17 की बात कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: सुनिये, उत्तर आ रहा है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पन्ना धाय जीवन अमृत योजना है, लास्ट 2016-17 तक इसका प्रीमियम भुगतान किया गया। उसके बाद में किसी भी सरकार ने ...(व्यवधान) इसमें 5 साल आपकी भी सरकार रही। 5 साल आपकी

(श्री अविनाश गहलोत)

भी सरकार रही। मैं 2016-17 का बता रहा हूं। 2018 में आपकी सरकार आ गयी ...(व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है ...(व्यवधान) बीपीएल से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये। श्री गणेश घोगरा, प्रश्न पूछो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जवाब दिलवाओ।

श्री अध्यक्ष: आपका हो गया। श्री गणेश घोगरा।

डूंगरपुर में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की कार्ययोजना

80. श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने हेतु अपीलीय अधिकार उप खण्ड अधिकारी को दिया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के उप खण्ड बिछीवाड़ा व डूंगरपुर में वर्ष 2019 से दिसम्बर, 2023 तक कितनी अपीलें दर्ज हुईं? अपील के निर्णय अनुसार कितने नाम जोड़े गये तथा कितनी अपीलें अस्वीकार की गयीं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर विगत पांच वर्षों से नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर नये नाम कब तक जोड़े जायेंगे? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर दीजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, उधर से जवाब ही नहीं आया। जवाब ही नहीं आया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आ गया। आपकी सरकार थी, आप भी देने वाले थे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, आप जवाब दिलवाओ।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जवाब दिलवायें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर दीजिये। आप उत्तर दीजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब तो दो। मंत्री जी, बीपीएल से जुड़ा हुआ मामला है बीपीएल से ...(व्यवधान)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के उप खण्ड बिछीवाड़ा एवं उप खण्ड डूंगरपुर के पास वर्ष 2019-22 से दिसम्बर, 2023 तक दर्ज स्वीकार एवं अस्वीकार अपीलों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्रम संख्या	नाम उप खण्ड	प्राप्त अपील	स्वीकृत अपील	अस्वीकृत अपील
1	डूंगरपुर	8,387	3,215	140
2	बिछीवाड़ा	4,841	2,056	121

(2) जी नहीं। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की क्रियान्विति के क्रम में 5,32,441 अपीलें स्वीकृत कर 20,61,314 नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े गये हैं।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वह योजना बंद कर दी, आप जवाब नहीं दे रहे ...(व्यवधान)

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जवाब दिलवाइये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गया ...(व्यवधान) दूसरा प्रश्न आ गया। बैठिये, बैठिये। गणेश घोगरा, पूरक प्रश्न ...(व्यवधान) श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा में संचालित जनजाति छात्रावास

81. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में माडा योजना में किन-किन स्थानों पर अनुसूचित जनजाति के छात्रावास व राजकीय आवासीय छात्रावास संचालित हैं तथा उक्त में कितनी-कितनी छात्र क्षमता निर्धारित है व वर्तमान में उनमें कितने-कितने छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सुविधाओं का निरन्तर निरीक्षण किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2022 से वर्ष 2024 में कब-कब निरीक्षण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कल्पना देवी)

(4) क्या उक्त छात्रावासों में सुविधाओं से संबंधित वार्डनों के विरुद्ध अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। उनका उत्तर दो ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उनका उत्तर दो।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा (कोटा) में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा माडा क्षेत्र अन्तर्गत मण्डाना में राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास संचालित है, जिसकी क्षमता 50 छात्राओं की है तथा वर्तमान में 50 छात्राएं लाभान्वित हो रही हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में अनुसूचित जनजाति के दो छात्रावास एवं अनुसूचित जाति के दो छात्रावास, इस प्रकार कुल 04 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विभागीय नियमानुसार छात्रावास में आवासित छात्राओं को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नि:शुल्क आवास, पलंग, गद्दा, तकिया, खेस, दरी, कंबल, बेडशीट, तकिया कवर प्रति छात्रा, दो समय नाश्ता, दोपहर का लंच व डिनर दिया जाता है। रहवास, भोजन, कपड़े व अन्य सुविधाओं हेतु प्रत्येक छात्रानुसार 2,500 रु. प्रतिमाह के हिसाब से प्रदान किए जाते हैं। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभागीय नियमानुसार छात्रावास में आवासित छात्र-छात्राओं को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नि:शुल्क आवास के साथ-साथ प्रति आवासी बिस्तर-पलंग, गद्दा, तकिया, 01 खेस, 01 दरी, 01 कम्बल, 02 बेडशीट, 02 तकिया कवर सामग्री के रूप में व 02 स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूते, मोजे, तौलिये व गर्म जर्सी हेतु 2,660/- रुपये प्रति छात्र एकमुश्त डीबीटी के माध्यम से आवासी को उपलब्ध करवाये जाते हैं। साथ ही दोनों समय का भोजन, नाश्ता, प्रत्येक सप्ताह विशेष भोजन एवं प्रतिमाह हेयर ऑयल, नहाने व कपडे धोने का साबुन एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र-पत्रिकाए की सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

(3) उक्त सुविधाओं की निरन्तर समुचित उपलब्धता के निरीक्षण हेतु

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्‍वारा एवं जिला परिषद् के द्‍वारा निरीक्षण किये जाते हैं। वर्ष 2022 से 2024 तक किये गये निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्‍वारा संचालित छात्रावासों का समय-समय पर निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। विगत तीन वर्षों में उक्त छात्रावासों के निरीक्षण किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(4) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्‍वारा संचालित छात्रावासों में सम्बन्धित वार्डनों के विरुद्ध अनियमितता किये जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्‍वारा संचालित छात्रावासों में सम्बन्धित वार्डनों के विरुद्ध अनियमितता किये जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): मंत्री जी, मैंने आपका जवाब पढ़ लिया। मंत्री जी, पूरक प्रश्न।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्‍वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: उधर जाओ, उधर जाओ। वैल में नहीं ...(व्यवधान)

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): मैं सीधा पूरक प्रश्न पूछ लूं। अध्यक्ष जी, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं। प्रश्न (2) के जवाब में आपने दिया है कि दो स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूते, मोजे, तौलिये व गर्म जर्सी हेतु 2,660 रुपये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। माननीय सदस्य, ...(व्यवधान)..

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: दे दिया। आप अपनी सीटों पर चले जायें। दूसरे की सीट से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यहां आकर बोलते हैं। ...(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये आप। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्या कर रहे हो? बैठिये। ..(व्यवधान)....सब लोग। माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(समय: 12.00 बजे)

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

घोषणा

माननीय सदस्यों के उद्बोधनों के वीडियो अंशों की विधान सभा की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्धता

मुझे माननीय सदस्यगण को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि उनके सदन में उद्बोधनों के वीडियो अंश, जो वर्तमान में बजट सत्र की समाप्ति पर पैन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते रहे हैं, तत्काल प्रभाव से उन्हें राजस्थान विधान सभा की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवश्यक नियमानुकूल एडिटिंग के पश्चात् एक दिवस पश्चात् से ही उपलब्ध कराये जायेंगे।

आशा है, इस नवाचार से न केवल वे स्वयं लाभान्वित होंगे, अपितु उनके क्षेत्र व समस्त राजस्थानवासी भी अपने क्षेत्रीय विधायक की सक्रियता से परिचित हो सकेंगे।

सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री अमीन कागजी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशन पोल के चारदीवारी क्षेत्र में आवारा पशुओं से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से दिनांक 08 जुलाई, 2024 को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर घटित घटना के फलस्वरूप कानून व्यवस्था बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से जयपुर शहर के जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनाये जाने की योजना के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री टीकाराम जूली एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण स्थानीय विधायक की अनुशंसा से न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री अमित चाचाण एवं 05 अन्य सदस्यों की ओर से भादरा

(श्री अध्यक्ष)

नगरपालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव के दिन निर्वाचन अधिकारी के अवकाश पर जाने के कारण चुनाव स्थगित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) डा. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना का पोर्टल बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विगत 03 वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री टीकाराम जूली, श्री अमित चाचाण, डा. ऋतु बनावत एवं श्री थावर चन्द को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो- दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में विद्युत लाइनों को व्यवस्थित किये के संबंध में।

(2) डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से नगर परिषद् बाड़मेर के सीमा क्षेत्र की समीक्षा कर वंचित आबादी क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

(3) श्री राधेश्याम बैरवा, सदस्य की ओर से बारां शहर के निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री कैलाश चन्द वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बगरू के मुख्यालय बगरू पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय स्थापित किये जाने के संबंध में।

(5) श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा की ग्राम पंचायत तिगरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाये जाने के संबंध में।

(6) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा जमाबन्दी की अशुद्धियों को कैम्प लगाकर दूर किये जाने के संबंध में।

(7) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से श्री प्रेमसिंह सिंघवी

(श्री अध्यक्ष)

राजकीय महाविद्यालय, छीपाबड़ौद में कार्यरत निजी कार्मिकों को राजकीय सेवा में समायोजित किये जाने के संबंध में।

(8) श्री भागचन्द टांकड़ा, सदस्य की ओर से बांदीकुई को जिला बनाये जाने के संबंध में।

(9) श्री अंशुमान सिंह भाटी, सदस्य की ओर से पश्चिमी राजस्थान में आगजनी से पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता राशि नहीं दिये जाने के संबंध में।

(10) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में पैरिफेरी क्षेत्रों में वर्षों से निवासरत परिवारों को पट्टे दिये जाने के संबंध में।

(11) श्री कान्ति प्रसाद, सदस्य की ओर से प्रदेश में नरेगा योजना के अन्तर्गत स्थायी परिसम्पतियों का निर्माण कार्य करवाये जाने के संबंध में।

(12) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के समरोल में 132 केवी. जी.एस.एस. स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

(13) श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से डूंगरपुर शहर के आस-पास भूमाफियाओं द्वारा राजकीय तथा आदिवासियों की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री बालमुकुन्दाचार्य, सदस्य की ओर से जयपुर शहर स्थित मन्दिरों को दक्षिण भारत के मन्दिरों के अनुरूप विकसित किये जाने के संबंध में।

(15) श्री लादु लाल पितलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में चंबल के पानी की आपूर्ति को बढ़ाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 15/07/2024 को शून्य काल में बोलने हेतु 38 पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें से शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	**पर्ची संख्या**	**माननीय सदस्य का नाम**	**विषय**
1.	15	श्री शंकरसिंह रावत	पंचायत समिति जवाजा में चल रहे फर्जी पट्टी के गौरख धंधे को उजागर करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

क्र. सं.	पर्ची संख्या	माननीय सदस्य का नाम	विषय
2.	2	श्री पूसाराम गोदारा	विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ की नवीन क्रमोन्नत रा.उ.मा.वि. में विभिन्न पदों को सृजित करवाकर रिक्त पदों पर शिक्षक लगवाने एवं राजकीय महाविद्यालय, राजलदेसर में कला संकाय में सीट बढ़वाने व विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू करवाने बाबत।
3.	29	श्री भीमराज भाटी	पाली विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में।
4.	31	श्री चन्द्रभान सिंह चौहान	चित्तौड़गढ़ को डार्क जोन हटाने के संबंध में।

श्री टीकाराम जूली।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

विधान सभा क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्थानीय विधायक की अनुशंसा से न किया जाना

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धित नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत आपने जो मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट घोषणा 2020-21 में 5 करोड़, 2022-23 में 10 करोड़, 2023-24 में 10 करोड़ और अब 2024-25 में 5 करोड़ प्लस 3 करोड़ की घोषणा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खड़े होकर बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह देखो, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा एक बार देख लो आप। ..(व्यवधान)... कितने आप लोग संजीदा हो इस विधान सभा में, यह नजर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी-अपनी सीटों पर विराजें। 1.00 से 2.00 लंच इसलिये किया है कि उस समय मंत्रियों से भी मिल लें। बैठिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट घोषणा हमारे समय में होती रही और यह विधायकों का अधिकार रहा कि विधायक अपने क्षेत्र के अन्दर संबंधित प्रस्ताव दें और उस पर PWD उस क्षेत्र की सड़कें बनायें और यह बनती आयी हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, मुझे कहते हुए खेद है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार की तरफ से एक लैटर निकाला गया है जिसमें यह इंगित किया गया है कि क्षेत्र के जो जन-प्रतिनिधि हैं उनसे इन सड़कों के प्रस्ताव लिये जायें। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि क्षेत्र के जन-प्रतिनिधि विधान सभा के सबसे प्रथम विधायक होता है और ज्यादातर जगह पर ऐसा नजर में आया है कि जो लोग बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वह लोग चुनाव हार गये, जनता ने जिनको नकार दिया, उनसे प्रस्ताव लेकर यहां पर भेजे गये और स्वीकृत किये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति चुनाव हार गया वो व्यक्ति जन-प्रतिनिधि की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? सरकार उसको जन-प्रतिनिधि मानती है या नहीं मानती है?

दूसरा, मैं आपसे यह संरक्षण चाहूंगा कि जिन लोगों को जनता ने जिताकर भेजा है और आपके इस सदन की जो बैठक है, जिसमें हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, हम लोग बजट पास करते हैं और बजट में यह प्रावधान किया जाता है विधान सभा क्षेत्र में सड़कें दी जायेंगी और उसके बाद जो हारे हुए लोग हैं, उनसे प्रस्ताव लेकर, सड़कों के प्रस्ताव करा दिये जाते हैं तो मैं समझता हूं यह सरकार नियमों का खुला उल्लंघन कर रही है। इस सरकार को आप पाबन्द करें कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं, ...(व्यवधान)

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में 2019 से 2023 के बीच में आपने भी ऐसा किया था। ...(व्यवधान) जो हारे हुए प्रत्याशी थे, उनसे प्रस्ताव लिया था। हमने इसी सदन में कहा था कि चुने हुए एमएलए जन प्रतिनिधि हैं, उनसे प्रस्ताव लीजिये। ...(व्यवधान) उस समय के विधान सभा अध्यक्ष श्री सी.पी. जोशी जी ने कहा, चुने हुए एमएलए जन प्रतिनिधि होते हैं उनसे प्रस्ताव लीजिये, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। आपने कांग्रेस के जो हारे हुए एमएलए थे, उनसे प्रस्ताव लेकर सड़कें बनायी हैं। ...(व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं। अपनी सीट से बात करें। अपनी सीट पर जाएं। श्री अमित चाचाण। ...(व्यवधान) यह पुरानी परम्परा है यहां की। ये आपके समय भी थी। पहले भी यही हुआ है। श्री अमित चाचाण। ...(व्यवधान) आपके सदस्य बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) जो आप कर रहे थे, वही ये कर रहे हैं। श्री अमित चाचाण।

भादरा नगरपालिका अध्यक्ष पद के उप-चुनाव के दिन निर्वाचन अधिकारी के अवकाश पर जाने के कारण चुनाव का स्थगन

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की जो हमारी वर्तमान राज्य सरकार है वह लोकतंत्र की रक्षा करने की बड़ी-बड़ी बातें करती है, संविधान के अनुसार चलने की बातें करती है, लेकिन हम सबने और पूरे राजस्थान की जनता ने 8 जुलाई को लोकतंत्र के उस काले दिन को भी देखा, जब भादरा नगरपालिका का उप-चुनाव करवाया जा रहा था, जहां कांग्रेस पार्टी का पहले बोर्ड था, कांग्रेस पार्टी की नगरपालिका अध्यक्ष की मृत्यु होने के बाद वहां उप-चुनाव घोषित किया गया, लेकिन जिस दिन मतदान दिवस था, कांग्रेस पार्टी के पार्षद मतदान करने के लिए नगरपालिका भवन में पहुंचे तो 70 सालों के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि मतदान दिवस के दिन अचानक वहां के निर्वाचन अधिकारी छुट्टी पर चले गये। चार घंटे तक कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को नगरपालिका भवन में बैठाया गया। चार घंटे के बाद उन्हें यह सूचना दी गयी कि आपका यह चुनाव स्थगित कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा करने वाली, संविधान की दुहाई देने वाली इस सरकार के राज में 8 दिन गुजरने के बाद भी आज दिनांक तक यह पता नहीं चला कि वहां का निर्वाचन अधिकारी किस बीमारी के कारण छुट्टी पर चला गया। आज तक यह नहीं बताया गया कि इनके बोर्ड के द्वारा उनका परीक्षण करवाया गया या नहीं। मतदान दिवस के दिन निर्वाचन आयोग दूसरा विकल्प रखता है, चुनाव कभी स्थगित नहीं किया जाता, लेकिन ऊपरी दबाव के कारण इस चुनाव को स्थगित किया गया है और आज दिनांक तक उस चुनाव की तारीख घोषित नहीं की गयी।

हम इसकी निन्दा करते हैं। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। अगर सही मायने में ये संविधान की रक्षा करने वाले हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हैं

(श्री अमित चाचाण)

तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सदन के पटल पर रखा जाये कि उस अधिकारी को उस दिन क्या समस्या थी। हम आपसे यह मांग करते हैं कि तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई की जाये। आप लोकतंत्र की रक्षा कीजिये, आप संविधान की रक्षा कीजिये। ...(व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं नारे।)

श्री अध्यक्ष: डा. ऋतु बनावत।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, हमने पहले भी इस बात को उठाया था, राजस्थान को चंडीगढ़ मत बनने दें। अध्यक्ष जी, राजस्थान को चंडीगढ़ मत बनने दें। यहां जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं, यहां चंड़ीगढ़ क्यों बनाना चाहते हैं? सरकार चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती है? आप लोग डरते हैं, इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहते। अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिये। आप चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते?

श्री अध्यक्ष: आपका विषय आ गया। हाउस के रिकॉर्ड पर आपका विषय आ गया।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के पोर्टल के बन्द होने से आमजन को समस्या

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 50 के तहत बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद।

बिजली आधारभूत संरचना का हिस्सा है। बजट में भी यह कहा गया कि बेहतर कल के लिए आधारभूत संरचना में निवेश किया जायेगा।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलिये न, नहीं तो अगला नाम पुकारूं।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): बेहतर कल के लिए आधारभूत संरचना पर निवेश की बात इस बजट में कही गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने एक योजना लागू की, ''मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना'', जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की गयी। यद्यपि यह पूरे प्रदेश को विदित है कि उस समय बिजली की आधारभूत संरचना की कोई भी व्यवस्था किये बिना यह योजना लागू की गयी और जो भुगतान होना चाहिये था, उपभोक्ताओं को जो सुविधाएं उस बिजली की योजना से मिलनी चाहिये थीं, वे नहीं मिलीं।

(डा. ऋतु बनावत)

समस्त जनता में एक परसेप्शन बना हुआ है कि जब-जब भाजपा की सरकार आती है, तब-तब बिजली की व्यवस्था अच्छी हो जाती है। इस परसेप्शन को देखते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो "नि:शुल्क बिजली योजना" का पोर्टल बन्द है, उसे चालू किया जाये और नये कनेक्शंस को भी इसमें सुविधा दी जाये ताकि जो आम जनता है, उसे सहयोग मिल सके, 200 यूनिट फ्री मिल सके और जो तकनीकी समस्याएं इस पोर्टल के बन्द होने में आ रही हैं, उन समस्याओं का निदान आम जनता के सामने हो।

जब भी भाजपा की सरकार रहती है तब बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। मैं यह कहना चाहती हूं कि आज के समय में जो बिजली की व्यवस्था खराब चल रही है, उसे ठीक किया जाये। बिजली के बिना न पानी है, न तरक्की है, न पढ़ाई है और न ही और कुछ है। इस समय व्यवस्था को सम्भालकर, बिजली की व्यवस्था को ठीक कर नये कनेक्शंस को भी इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाये और उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्रदान किया जाये। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री थावर चन्द। ...(व्यवधान)

श्री थावर चन्द (धरियावद): जूली साहब, जूली साहब। विपक्ष के सदस्यों, दो मिनट, बहुत जरूरी बात करना चाह रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सब अपनी सीटों पर जाएं। ...(व्यवधान) पहले सीटों पर जाएं, फिर सुनूंगा। पहले सब सीटों पर जाएं। सीटों पर जाएंगे तो जरूर सुनूंगा।

जनजाति क्षेत्रों के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का लम्बित छात्रवृत्ति भुगतान

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के जो नौजवान हैं, उनकी पीड़ा को व्यक्त करने जा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज करीब तीन वर्ष हो गये हैं, नौजवानों की पीड़ा यह है कि वे हताश और परेशान हैं कि उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ...(व्यवधान)

सदन कूप में

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे।)

श्री अध्यक्ष: सीटों पर जाइये। No, No, No, I will name You.

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ट्राइबल क्षेत्र में हम लोग आर्थिक रूप से बिलकुल कमजोर हो चुके हैं। हमारे पास फीस भरने के नाम पर पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें छात्रवृत्ति की बहुत बड़ी आशा और उम्मीद रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में तीन वर्षों से छात्रवृत्ति अटकी हुई है। मैं पक्ष और विपक्ष, दोनों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि वे नौजवानों की पीड़ा को समझें। नौजवानों का क्या दोष है? आज हम लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं कि ट्राइबल और अनुसूचित क्षेत्रों के नौजवानों को फीस भरने के लिए अहमदाबाद, मुम्बई, गुजरात तक जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उन्हें अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ती हैं, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं। तीन वर्षों से छात्रवृत्ति लम्बित पड़ी है। मैं पक्ष और विपक्ष से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि नौजवानों को छात्रवृत्ति दिलवाएं।

साथ ही, मैं यह कहना चाहता हूं, इस बार मैं पक्ष से उम्मीद करता हूं कि तीन वर्षों की नौजवानों की छात्रवृत्तियां डालकर इस छात्रवृत्ति का रगड़ा ही निकाल दें आप। मैं उम्मीद करता हूं कि नौजवानों के बारे में तीन वर्ष पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो नौजवानों को उपचारात्मक शिक्षा के नाम पर उन्हें तीन महीने तक रोजगार देने के लिए कहा गया था, उनका पैसा आज भी खाते में नहीं डाला गया है। आज उन नौजवानों की क्या गलती है? सत्ता आती है, जाती है। पक्ष और विपक्ष बदलता रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी पीड़ा को समझना होगा, हमारी स्थिति को समझना होगा। मैं पुन: सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों से कहना चाहता हूं कि उनकी स्थिति को समझें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जय जोहार। जय भील प्रदेश। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपनी सीटों पर जाएं।

नियम 295, श्रीमती शोभा चौहान।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी...

श्री अध्यक्ष: पहले अपनी सीटों पर जाइये। आसन पैरों पर है। No, No, कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सोजत में विद्युत लाइनों का व्यवस्थीकरण

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं

(श्रीमती शोभा चौहान)

आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे नियम 295 के तहत सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप दोनों के नाम अभी मैं पुकारूंगा, बाहर भेज दूंगा अभी। अनुशासन में रहिये। ...(व्यवधान)

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): महोदय, 29 मई, 2024 को मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड रायपुर जिला ब्यावर देवलीकलां रोड नोख के पास दुपहिया वाहन से गुजर रहे देवलीकलां के बेरा कतीरिया निवासी सुरेश कुमावत व उनकी पत्नी पाचुन्डी देवी जमीन पर गिरे, बिजली के तार से उलझ जाने के कारण सुरेश कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी और पाचुन्डी देवी को गम्भीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैंने विधायक कोष से एक लाख रुपये, डिस्कॉम से पांच लाख रुपये, पांच लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष, पांच लाख रुपये कर्मचारी संगठन कोष व पांच लाख रुपये अन्य एनजीओ कारपोरेट के सहयोग से, कुल इक्कीस लाख रुपये की घोषणा करवायी।

मैं इस सदन के माध्यम से आपसे एवं ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि सोजत विधान सभा क्षेत्र की सभी लाइनों एवं आड़े-तिरछे, क्षतिग्रस्त पोलों एवं उनके उपर जो झाड़ियां हैं, उनको साफ कराते हुए क्षेत्र की समस्त जनता को सूचित करते हुए मरम्मत के स्थान पर बैरियर लगाये जायें ताकि माननीय, इस तरह की घटना मेरे विधान सभा क्षेत्र में भविष्य में न हो तथा आमजन ऐसी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें। बस यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देती हूं। पुनः धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: डॉ. प्रियंका चौधरी। (व्यवधान) पहले सीटों पर जायें। बिना सीटों पर जायें कोई सुनवाई नहीं होगी।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

बाड़मेर नगर परिषद् के सीमा क्षेत्र की समीक्षा एवं वंचित आबादी क्षेत्र का सम्मिलन

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के तहत अपनी बात रखने का अवसर दिया।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के विशेष

(डॉ. प्रियंका चौधरी)

उल्लेख के तहत नगर परिषद्, बाड़मेर के सीमा क्षेत्र की समीक्षा कर वंचित आबादी क्षेत्र को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि जिला बाड़मेर में बाड़मेर नगर के विकास हेतु जनहित में 1932 में नगरपालिका बाड़मेर को घोषित किया और 2012 में नगर परिषद् में क्रमोन्नत किया। वर्तमान में इसमें 55 वार्ड हैं और जनसंख्या लगभग दो लाख है। जिला मुख्यालय के साथ ही शिक्षा एवं रोजगार का केन्द्र होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहां आकर बसने लगे और आबादी बढ़ती रही। नगर परिषद्, बाड़मेर की सीमा क्षेत्र एवं उसके लगते खसरों में बढ़ी इन आवासीय कॉलोनियों एवं उनके पट्टे, भवन निर्माण आदि कार्य नगर परिषद् में माध्यम से किये जिससे नगर परिषद् को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की आय हुई। विडम्बना यह रही की उक्त बस्तियां नगर परिषद् की सीमा में नहीं होने से आज भी सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित हैं।

नगरपलिका अधिनियम, 2009 के तहत 31 अगस्त, 2018 को स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर ने आदेश जारी कर बाड़मेर ग्रामीण, बाड़मेर आगोर, बाड़मेर गादान तथा बाड़मेर मगरा राजस्व ग्राम को वर्तमान सीमाओं में सम्मिलित किया परन्तु राजनैतिक एवं अन्य कारणों से उक्त आदेशों को निरस्त कर विभाग ने 31 मार्च, 2023 को आदेश जारी कर बाड़मेर ग्रामीण एवं बीदासर के सम्पूर्ण क्षेत्र बाड़मेर मगरा में बाड़मेर मगरा, बाड़मेर आगोर में बाड़मेर आगोर एवं गादान में से बाड़मेर गादान को सीमा में सम्मिलित कर दिया, जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण था। उक्त परिसीमन में कई घनी आबादी वाले क्षेत्रों को द्वेषतापूर्ण छोड़कर स्थानीय निवासियों के हितों के साथ कुठाराघात ही नहीं किया बल्कि उनको संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों से भी वंचित रखा गया हैं, जो न्यायोचित नहीं है।

मेरा माननीय मुख्य मंत्री एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री से आग्रह है कि जन मांग एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए उक्त सभी आदेशों की समीक्षा और पुनर्विचार कर वंचित खसरों एवं क्षेत्रों को नगर परिषद्, बाड़मेर की वर्तमान सीमा से सम्मिलित किया जाये। धन्यवाद। (व्यवधान)

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: सभी सदस्यों से कह रहा हूं, अपनी-अपनी सीटों पर जायें। विराजमान हो जायें। श्री राधेश्याम बैरवा। विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अपनी सीटों पर जायें, सदन की कार्यवाही चलने दें।

(श्री अध्यक्ष)

श्री राधेश्याम बैरवा, बोलिये। मेरे चैम्बर में आकर बात करिये। यहां व्यवस्था की बात है। जिसको बात करनी है, बाद में मेरे चैम्बर में आइये। इस कार्यवाही के बाद लंच में आप कमरे में आइये। हम बात करेंगे, अभी नहीं।

बारां शहर में निर्माणाधीन आर.ओ.बी का शीघ्र निर्माण

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): सर, बोल रहा हूं। बारां शहर में निर्माणाधीन आर.ओ.बी. (तेल फैक्टरी) का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से जनता को होने वाली परेशानियों के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव कर निवेदन है कि बारां शहर में आर.ओ.बी. तेल फैक्टरी का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसका समस्त खामियाजा स्थानीय जनता को उठाना पड़ रहा है। आर.ओ.बी. निर्माण कार्य समय पर नहीं होने से रहवासियों को गन्तव्य स्थान तक पहुंचने हेतु काफी लम्बा चक्कर लगाना पड़ रहा हैं। साथ ही, निर्माण कार्य नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक कच्चा रोड जनता के लिए खाज में कोढ़ का काम कर रहा हैं। इस वैकल्पिक रोड पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसका प्रभाव स्थानीय दुकानदारों पर भी आर्थिक नुकसान उठाकर पड़ रहा है।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन है कि बारां शहर में निर्माणाधीन आर.ओ.बी. (तेल फैक्टरी) का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण करा कर आम जनता को राहत प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: डॉ. कैलाश वर्मा।

बगरू उप खण्ड मुख्यालय पर अधिकारी कार्यालय की स्थापना

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष प्रस्ताव। विधान सभा क्षेत्र बगरू में पृथक् से उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने के क्रम में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू के अन्तर्गत कुल 30 ग्राम पंचायत एवं दो नगरपालिकाएं तथा जयपुर नगर निगम के 21 वार्ड आते हैं। वर्तमान में राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आमजन को उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर आना पड़ता है, जो कि आमजन के लिए काफी ज्यादा समय एवं श्रम खर्च कराने वाला है। उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर में कार्य की अधिकता के चलते बगरू क्षेत्र विकास कार्यों में पिछड़ रहा है। आमजन से सम्पर्क एवं जनसुनवाई के

(श्री कैलाश चन्द वर्मा)

दौरान बगरूवासियों के द्वारा बार-बार बगरू के लिए पृथक् से उपखण्ड कार्यालय खोलने की मांग की जा रही है।

अतः उपर्युक्त लोकहित के विषय को ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी एवं राजस्व मंत्री जी से आग्रह है कि बगरू मुख्यालय पर उपखण्ड कार्यालय की स्वीकृति प्रदान कर अनुगृहीत करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मनीष यादव।

तिगरिया ग्राम पंचायत (शाहपुरा) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा की ग्राम पंचायत तिगरिया (पंचायत समिति गोविन्दगढ़), जो कि धानोता से चौमूं मुख्य रोड पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1828.98 हेक्टेयर है। इस ग्राम पंचायत की जनसंख्या लगभग 15 हजार है तथा इसमें लगभग 8,500 वोटर हैं। उक्त ग्राम पंचायत में तीन राजस्व ग्राम (कालू का बास, तिगरिया व बावडी) स्थित है। उक्त ग्राम पंचायत में वर्तमान में 17 वार्ड हैं तथा 9 राजकीय विद्यालय, 5 निजी विद्यालय, दो निजी महाविद्यालय तथा एक पुलिस चौकी संचालित हैं तथा उक्त ग्राम पंचायत आस-पास के गांवों के व्यापार का मुख्य केन्द्र है। उक्त ग्राम पंचायत में धानोता से चौमूं मुख्य रोड गुजरने के कारण लोगों का आवागमन बहुतायत में होता है।

उक्त ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति व आबादी की दृष्टि से यहां स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त नहीं होने के कारण यहां के निवासियों को उपचार के लिए भी यहां से 20 किलोमीटर दूर चौमूं जाना पड़ता है। मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण कई बार उनके साथ अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं।

अतः, श्रीमान जी, आपसे आग्रह है कि उक्त ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की कृपा करें, जिससे लोगों को समय पर इलाज मुहैया हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

राजस्व जमाबन्दी रिकार्ड का कैम्प लगा कर दुरुस्तीकरण

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मान्यवर, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव कर निवेदन है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकाड्स मोडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के तहत राजस्व रिकॉर्ड में सेग्रीग्रेशन और वन टू वन मैचिंग करते हुए जमाबन्दी में हिस्सा किस्सी खोलने के प्रोग्राम के तहत केन्द्र सरकार से पैसा आया था। राजस्थान सरकार द्वारा जमाबन्दी में जितने खसरे जमाबन्दी में हैं, उतने के उतने खसरे नक्शे में तरमीम करते हुए खसरों का मिलान किया गया।

सेग्रीगेशन की प्रक्रिया के तहत राजस्व जमाबन्दी में काश्तकारों के हिस्से खोले गये, उसमें बड़ी मात्रा मे अशुद्धियां कर्मचारियों की गलती के कारण हो गयीं। किसानों को अपना हिस्सा शुद्धिकरण कराने के लिए तहसील एवं उपखण्ड कार्यालयों में भटकना पड़ता है। चूंकि, हिस्से का शुद्धिकरण एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसके लिए किसानों को वकील के मार्फत 136 का दावा करना पड़ता है। उक्त अशुद्धियों के लिये किसान का कोई दोष नहीं लेकिन कर्मचारी की गलती का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे एक नहीं हजारों किसानों के नाम या रकबा हिस्से में अशुद्धियां हैं।

अतः आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि इसमें कैम्प लगाकर पूर्ण रूप से रिकार्ड को दुरुस्त करने के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कि जाये कि अब रिकॉर्ड में किसी तरह की कोई अशुद्धि नहीं रहे। किसान को जमाबन्दी शुद्ध करके उसकी एक प्रति उसको दिलाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपका हो गया। श्री प्रताप सिंह सिंघवी। इसको पढ़ना है, भाषण नहीं होता है। आप पुराने हैं, तीन बार के विधायक हैं, विराजिये।

छीपाबड़ौद स्थित श्री प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत निजी कार्मिकों का राजकीय सेवा में समायोजन

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, छीपाबड़ौद, जिला बारां में श्री प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय संचालित है। बजट घोषणा वर्ष 2019 की पालना में श्री प्रेम सिंह सिंघवी महाविद्यालय, छीपाबड़ौद को राजकीय किया गया है। इस राजकीय महाविद्यालय में वर्षों से कार्यरत शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों को राजकीय सेवा में समायोजन

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

की प्रक्रिया वर्ष 2019 से चल रही है, किन्तु अभी तक इन निजी कार्मिकों को राजकीय सेवा में समायोजन नहीं किया गया है। ये कर्मचारी राजकीय सेवा देते हुए संपूर्ण राजकीय दायित्व निभा रहे हैं। इन कर्मचारियों का पिछले 33 माह से अधिक समय का वेतन बकाया है जिससे महाविद्यालय के कर्मचारियों को अपने परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। इन कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वेतन समय पर नहीं मिलने की वजह से दैनिक खर्चों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों को लगातार प्रत्येक महीने कर्ज लेना पड़ता है। महाविद्यालय के कार्मिकों द्वारा संबंधित विभाग को समस्या का समाधान करने हेतु कई बार लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गया, किन्तु विभाग द्वारा कोई उचित समाधान नहीं किया गया है।

आपसे निवेदन है कि श्री प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय, छीपाबड़ौद में कार्यरत निजी कार्मिकों का बकाया वेतन देने एवं राजकीय सेवा में समायोजित किए जाने हेतु समुचित कार्रवाई कराने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री भागचन्द टांकडा।

बांदीकुई को जिला बनाया जाना

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव बांदीकुई को जिला बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई को लम्बे समय से जिला बनाए जाने की मांग की जाती रही है, जिला बनाए जाने की समस्त योग्यताओं के बावजूद भी गत सरकार ने बांदीकुई को जिला नहीं बनाया जिससे क्षेत्र की जनता में अत्यन्त निराशा व्याप्त है।

महोदय, बांदीकुई दौसा जिले में दौसा के बाद सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। बांदीकुई रेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जो दौसा जिले के मध्य में स्थित है। सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से प्रमुख केन्द्र है। 20 अप्रैल, 1874 को आगरा फोर्ट से बांदीकुई के लिए पहली ट्रेन भी चली जो कि आज भी एक विशेष उपलब्धि है। जिले की प्रथम अनाज मण्डी माधोगंज मण्डी है। राजस्थान की सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी बांदीकुई में है। आरपीएफ ट्रेनिंग सेन्टर भी है। बांदीकुई में यातायात सुविधाओं की पर्याप्तता है। रेल मार्ग,

(श्री भागचन्द टांकडा)

सड़क मार्ग के माध्यम से बांदीकुई दौसा, जयपुर, अलवर, दिल्ली, आगरा से जुड़ा हुआ है। देशभर में प्रमुख आस्था केन्द्र मेहन्दीपुर बालाजी के दर्शन हेतु लाखों श्रद्धालु रेल मार्ग से बांदीकुई आते हैं। राणा सांगा की छतरी, चांद बावड़ी, हर्षद माता का मन्दिर, झाझीरामपुरा, ब्रिटिशकालीन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च हेतु देश-विदेश से पर्यटक निरन्तर आते रहते हैं।

अतः मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि बांदीकुई को आमजन की मांग के मद्देनजर जिले का दर्जा दिलवाया जाये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अब तो इनके पक्ष वाले भी जिला मांग रहे हैं, सरकार पुरानों को बन्द करेगी या नये और भी बनायेगी?

श्री अध्यक्ष: आपका ध्यान आ गया। श्री अंशुमान सिंह भाटी।

पश्चिमी राजस्थान में आगजनी से पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता राशि का भुगतान

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख - पश्चिमी राजस्थान में आगजनी से पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता राशि नहीं मिलने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में सादर अनुरोध है कि राजस्थान प्रदेश के पश्चिमी भू-भाग में ग्रामीणों का गांव तथा खेत की ढाणियों में निवास करने पर गर्मियों में विशेष तौर से आगजनी की बहुत घटनाएं होती रहती हैं जो कि क्षेत्रीय पुलिस थानों में दर्ज है। पश्चिमी राजस्थान में कच्चा झोंपड़ा निर्माण में स्थानीय झाड़ियां खींप, सनिया का इस्तेमाल किया जाता है और गर्मियों में इनका तापमान बढ़ कर 50 से 53 डिग्री तक हो जाने एवं आपस में खींप का हवा आंधी में रगड़ खाने से आग लग जाती है।

झोंपड़े-छपरे में तेज हवा एवं पानी के अभाव में आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है और उससे ग्रामीण का अनाज, गहने, कपड़े, चारपाई, बिस्तर यहां तक कि भेड़-बकरी, गाय भी कई बार जल जाती है। पीड़ित परिवार के तन पर कपड़ों के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचता है।

प्रदेश में प्राकृतिक आपदा विभाग भी है लेकिन पुलिस व पटवारी की जांच प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है और परिवार खुले आकाश के नीचे भूखा-प्यासा, तेज गर्मी में आंखें पथराये बैठा रहता है और आपदा विभाग की

(श्री अंशुमान सिंह भाटी)

अपनी कार्यशैली से छह माह से एक वर्ष तक पीड़ित द्वारा चक्कर लगाने पर मात्र 4,100/- रुपये अथवा पूरा घर जलने या पशु जलने पर एक लाख रुपये या अधिक राशि मिल जाती है तथा कई पीड़ित तो थक हार के बिना किसी राजकीय सहायता के निराश होकर घर पकड़ लेते हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत में वर्ष 2015 की गर्मियों में ग्राम भलूरी में आगजनी से 40 परिवारों के पूरे झोंपड़े, घर आग में स्वाहा हो गये थे। इसकी सूचना मिलने पर पूर्व सिंचाई मंत्री श्री देवी सिंह भाटी मौका देखने पहुंचे परन्तु हालात देखकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जन सहयोग से 14 दिन में प्रत्येक पीड़ित परिवार को पक्का कमरा, रसोई, स्नानघर, शौचालय, जल कुंड, गैस चूल्हा, अलमारी, सिलाई मशीन, बिजली पंखे, दो महीने की खाद्य सामग्री, चारपाई बिस्तर आदि उपलब्ध करवा दिये। जन समूह के भारी संख्या में आने-जाने पर तत्कालीन प्रभारी मंत्री जी एवं संभागीय आयुक्त ने पांच दिन बाद सहायता राशि के नाम पर प्रत्येक परिवार को 99,000/- हजार रुपये के चैक दिए।

मेरा सुझाव है कि आगजनी की घटना होने पर पीड़ित परिवार के पास तन के कपड़ों के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचता है, ऐसी परिस्थिति में जब मौके पर पुलिस, राजस्व पटवारी सभी जांच कर लेते हैं तो उसी दिन पीड़ित को सहायता राशि दे देनी चाहिए, जो छह माह या एक वर्ष बाद देने का कोई महत्व नहीं रह जाता है और आपदा विभाग एक ढकोसला लगता है।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

पैरिफेरी क्षेत्रों में निवासित परिवारों को पट्टा

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान राज्य में पैरिफेरी एरिया में वर्षो से निवासरत आमजन बिलानाम चरागाह भूमि देवस्थान विभाग, वन विभाग, कृषि भूमि में निवासरत हैं। बसी हुई आबादी जिनको आज तक पट्टे नहीं मिले। वर्षों से जब भी चुनाव आते हैं हर पार्टी आश्वासन देती है, हम जीत कर आयेंगे, आप को पट्टा देंगे। आज तक किसी पार्टी ने इनकी नहीं सुनी। पूर्व सरकार ने भी वादा करके, सरकार बनाने के लिए पूरे राजस्थान की जनता ने इनको सरकार में आने का मौका दिया, चार वर्षों में

(श्री फूल सिंह मीणा)

सरकार ने कुछ भी नहीं किया एवं एक साल छह माह पूर्व एक आदेश सरकार ने निकाला की 30 नवम्बर, 2011 से पहले कोई भी रहने का प्रूफ देकर यूआईटी में पेश करोगे तो पट्टा दिया जाएगा। इनको पट्टे देने ही नहीं थे, केवल चार साल पहले वादा किया। पूर्व सरकार ने आदेश निकाल कर जनता से वोट लेने का प्रयास किया, मगर जनता ने पूर्व सरकार के असत्य वादे को समझ लिया और पूर्व सरकार को बहुमत नहीं देकर सत्ता से बाहर कर दिया। आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके वर्तमान में सरकार बनवा दी। पैरिफेरी एरिया में आज तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चूंकि इनके पास पट्टा नहीं है और इस योजना के लाभ से वंचित हैं और सरकार में सांसद व विधायक के फण्ड से आधारभूत सुविधा के लिए भी यूडीए के चक्कर काटना पड़ता है, जब तक यूडीए की परमिशन नहीं मिलती तब तक विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार एक कमेटी बनाकर हर जिले में जांच करवाकर प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टा दिलवाने की कृपा करावें, जिससे आमजन को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री कान्ति प्रसाद।

नरेगा के अन्तर्गत स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जब से नरेगा (महात्मा गांधी गांरटी योजना) लागू की गई तब से गांवों में अधिकतर कच्चे कार्य ही स्वीकृत होते आये हैं, जिसमें जोहड़ खुदाई, पटरी सफाई कार्य तथा अन्य इसी प्रकार के कार्य होते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों में जो भी सरकारी भूमि खाली थी उस पर या तो जोहड़ बना दिये गये हैं या फिर नरेगा से वृक्षारोपण करवा दिया गया है। आज अधिकतर गांवों में सरकारी भूमि खाली नहीं होने के कारण नरेगा के कार्य स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं तथा जो पहले जोहड़ खोद दिये गये हैं वे इतने गहरे हो गये हैं कि उनको अब सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा गहरा नहीं किया जा सकता है।

(श्री कान्ति प्रसाद)

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी गारंटी योजना (नरेगा) में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कार्य, जिसमें 60 प्रतिशत सामग्री एवं 40 प्रतिशत लेबर कार्य तथा जोहड़ पिचिंग कार्य, गांव के क्षेत्र में सी.सी सड़क कार्य करवाये जावें। सादर।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना के समरोल में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्वीकृति

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में 132 अकलेरा, मनोहर थाना के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में ऊर्जा प्रसारण एवं वितरण की स्थिति अत्यंत दयनीय है। घरेलू बिजली में रात के समय 7 से 2 बजे तक लगातार कट लगते है। एल.टी. मेसेज आते रहते हैं। और तो और भगवान की संध्या आरती के समय भी बिजली चली जाती है। गांव के लोगों के बहुत फोन आते हैं। लम्बे समय से क्षेत्र में मैंटिनेंस का कार्य भी नहीं हुआ है। 11 के.वी. लाइन जो कई गांवों जैसे समरोल, बिन्दायका, देवली बटूखेड़ी, भूलनखेड़ी के अन्दर से लाइन गुजर रही है, उस लाइन को गांव से बाहर की जाये। 132 के.वी. समरोल में नया खोला जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोड अधिक होने की वजह से बार-बार ट्रिपिंग होती है व नया 33 के.वी. जी.एस. एस. टोडरी जग्गनाथ, मनपसर, गेंहुखेड़ी, तुरकाड़िया में खोलने से क्षेत्र में काफी समस्या का समाधान होगा।

कई जगह हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, कभी भी हादसा हो सकता है। क्षेत्र में बिजली से काफी मौतें हुई हैं, उनको मुआवजा दिया जावे। कोई अनहोनी घटना ना हो सके, इसके लिए स्थायी समाधान किया जावे। मैंने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है कि बिजली की बहुत विकट समस्या है, उसका समाधान किया जावे।

आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि कालीसिंध सुपर थर्मल प्लांट की इकाई बारबार खराब होने की वजह से क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था बिगड़ जाती है। 132 के.वी ग्रिड सब स्टेशन समरोल में स्वीकृत किया जावे, ताकि क्षेत्र के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शोर नहीं। श्री गणेश घोगरा।

डूंगरपुर में भू-माफिया द्वारा राजकीय एवं आदिवासियों की भूमि पर अवैध कब्जा

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि डूंगरपुर शहर के आस-पास गेपसागर के जल आवक मार्ग जो सागवाडा रोड पर है तथा जिनकी संख्या 6 है, को भू-माफिया द्वारा नालों पर निर्माण कर गेपसागर के जल भराव मार्गों को रोक लिया है, इस कारण गेपसागर में पानी नहीं आ रहा है। गेपसागर के कैचमेन्ट एरिया में भू-माफिया द्वारा अवैध निर्माण कर लिया गया है। भू-माफिया आदिवासियों की जमीन हड़प रहा है। भू-माफिया ने आस-पास की सारी पहाड़ियों को काट कर डूंगरपुर शहर का पर्यावरण खराब कर दिया है तथा भू-माफिया ने धनमाता पहाड़ी के पीछे की पहाड़ियां जो सेफियाह विद्यालय की साइड खरीदी गई है तथा उसके अलावा 300 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है एवं वहां काबिज आदिवासियों को जबरन हटाया जा रहा है तथा उक्त सारा काम प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है तथा आदिवासियों को असत्य मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जिस कारण आदिवासियों में भारी रोष है एवं आदिवासियों के द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। भू-माफिया द्वारा माण्डवा खापरडा में भी 100 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर प्लाट काट दिये गये हैं।

भू-माफिया द्वारा अपने नाम से ग्राम भण्डारिया में स्थित खातेदारी भूमि के खसरा नं. 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1304/1135, 1306/1137, 1308/1139, 1310/1140, 1312/1141, 1314/661, 1316/666, 1322/669, 1324/671, 1326/672, 656 से 600 तक 663, 664 एवं 670 कुल रकबा 5 हैक्टेयर भूमि को आवासीय परियोजना में आवेदन किया गया है, जिस पर पहले से ही आदिवासी लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं।

अतः मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि भू-माफिया द्वारा जिन आदिवासी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है उसे निरस्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री बालमुकुन्दाचार्य जी।

जयपुर स्थित मंदिरों का दक्षिण भारत के मंदिरों के अनुरूप विकास

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत जयपुर स्थित मन्दिरों को दक्षिण भारत के मन्दिरों की तरह विकसित करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर को हिन्दुस्तान में छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और धार्मिक आस्था की नगरी है। यहां के मन्दिर अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, परन्तु इन मन्दिरों का वैभव बढ़ाने एवं इनका विकास करने की दिशा में सरकारों द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। भारत के दक्षिण में स्थित मंदिरों की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा जयपुर के मन्दिरों का भी विकास किया जाए तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त मन्दिरों में पुस्तकालय बनाया जाए, जहां आध्यात्मिक पुस्तकें रखी जाएं। इसके अलावा एल.ई.डी. के माध्यम से डिजिटल रूप में मंदिरों के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाए जिसमें मंदिरों का इतिहास, निर्माण कराने वालों के बारे में बताया जाए, ताकि जनता को इन मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त हो।

इसके साथ ही मंदिरों में टोकन सिस्टम के आधार पर भोजनशालाएं शुरू की जाएं, जहां पर सस्ती दर पर लोगों को खाना उपलब्ध हो। साथ ही, मंदिरों के अधीन गौशालाओं का संचालन किया जाए जिससे गौमाता की सुरक्षा हो। मंदिरों में समय निश्चित कर आध्यात्म की शिक्षा एवं संत महात्माओं के प्रवचन कराये जाएं, जिससे भारतीय संस्कृति को संरक्षण मिले।

अतः प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत यह विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि जयपुर के विख्यात मंदिरों का दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह देवस्थान विभाग की तरफ से विकास किया जाए, ताकि भारतीय संस्कृति की रक्षा हो।

श्री अध्यक्ष: जो लिखा हुआ है केवल वही पढ़ें। श्री लादु लाल पितलिया।

सहाड़ा में चंबल के पानी की आपूर्ति में वृद्धि

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा

(श्री लादु लाल पितलिया)

क्षेत्र सहाड़ा में चंबल के पानी की आपूर्ति होती है जो अंतिम छोर (जमसस) पर होने के कारण सबसे अंतिम मेरी ही विधान सभा क्षेत्र में पानी पहुंचता है। सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र को 25 एम.एल.डी. पानी निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में 22 एम.एल.डी. पानी की सप्लाई हो रही है, जो सामरिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही कम है। अगर इसमें चार या पांच एम.एल.डी. पानी और बढ़ा दें तो क्षेत्रवासियों को कुछ राहत मिल सकती है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र सबसे अंतिम छोर पर रहने के कारण पानी का प्रेशर भी कम हो जाता है। गांव और ढाणियां, मजरों में पानी की बहुत किल्लत है। इस भयंकर गर्मी को देखते हुए पानी की समय पर जलापूर्ति होना अति आवश्यक है। मैंने कई बार उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत करवाया है कि जान निकाल देने वाली इस गर्मी में जहां पानी ही सब कुछ है, समय पर नहीं मिलना बहुत ही तकलीफदायक है।

अतः प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत यह विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन है कि अधिकारियों को निर्देशित कर मेरे विधान सभा क्षेत्र में 25 एम.एल.डी. की जगह 30 एम.एल.डी. पानी की जलापूर्ति की जाए और समय पर जलापूर्ति करने के निर्देश प्रदान करावें।

श्री अध्यक्ष: पर्ची।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जवाजा में चल रहे फर्जी पट्टों के प्रकरण

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान और ब्यावर जिले में पंचायती राज के जो पट्टे काटे गये हैं, उसमें पंचायत समिति जवाजा में फर्जी पट्टे एक गिरोह के द्वारा काटे जा रहे हैं। एक व्यक्ति सरपंच की सील, ग्राम सेवक की सील, विकास अधिकारी की सील फर्जी एवं फर्जी पट्टा बुक लेकर एक ही बैग में रखकर वह चल रहा है। जो पट्टा लेना चाहे, उसकी रकम तय करके फर्जी पट्टा भी दिया जा रहा है। और तो और उसका रजिस्ट्रेशन भी तहसील में हो रहा है। उसके बाद उस फर्जी पट्टे के ऊपर बैंकों के द्वारा लोन भी दिया जा रहा है। उसमें खसरा नंबर भी अंकित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब बैंक अपना लोन नहीं चुकाने पर वसूल करेगी और फर्जी पट्टों को जब्त किया जायेगा तो बैंक वसूली किससे करेगी, यह समझ में नहीं

(श्री शंकरसिंह रावत)

आ रहा है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करते हुए, ऐसे मामलों में तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। पिछली सरकार के टाइम पर सरकार ने यह फैसला लिया था कि पंचायतों के अन्दर अनाप-शनाप पट्टे, जितने चाहें पट्टे ले जायें। पिछली सरकार में दो साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा हाथ में बैग लेकर और हजारों पट्टे काटे गये। उसमें उनके लगाये हुए आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी लिप्त हैं। गैंगों को बचाने में लगी हुई कांग्रेस के टाइम पर ही ऐसे अधिकारियों को लगाया गया।

हमने उस मामले को उठाया, मुकदमे दर्ज कराये। तारागढ़ थाने में मुकदमा दर्ज है, जवाजा में दर्ज है, भीम में दर्ज है, सैंदड़ा में दर्ज है। कहां-कहां दर्ज नहीं है? ब्यावर में दर्ज है, लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। आपसे आग्रह है कि इनके किये हुए कारनामों पर थोड़ा विराम दिलायें। जैसे कोई 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज करने जा रही है, यह इस मामले में उजागर हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि निश्चित कार्यवाही करते हुए..

श्री अध्यक्ष: श्री पूसाराम। अंकित नहीं हो।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): 000

रतनगढ़ के रा.उ.मा.वि. में पदों का सृजन, रिक्त पदों पर पदस्थापन एवं राजलदेसर महाविद्यालय में सीटों में वृद्धि व विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों का प्रारम्भ

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में 35 नव क्रमोन्नत विद्यालय सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत हुए हैं उनमें आज तक व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं, क्रिएट नहीं गये। इसके अलावा जो सैकण्ड ग्रेड के पद क्रिएट किये गये हैं, वे सारे पद खाली हैं। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां दो ऐसी स्कूलें हैं सीनियर सैकण्डरी बालिका देसूंसर, सीनियर सैकण्डरी बालक, पालसर, जिनमें आज तक, तीसरा सत्र चल रहा है। इनमें कोई भी पद सेकण्ड ग्रेड और लेक्चरर्स के स्वीकृत नहीं किये गये हैं। माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, वहां पर तत्काल स्टाफ की व्यवस्था की जाये और पद सृजित किये जायें।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में राजलदेसर तहसील है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। उसमें चार साल से महाविद्यालय खुला हुआ है बिल्डिंग बन चुकी है, कॉलेज चलती है। बच्चों के

(श्री पूसाराम गोदारा)

लिए 200 सीटें हैं, 438 आवेदन आये हुए हैं। बच्चे लगातार चक्कर काट रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कहां जायें? इसलिए वहां 200 सीटें और कायम की जाएं, जिससे बच्चों को एडमिशन दिया जा सके है। वहां मात्र आर्ट्स है, वहां पर विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोला जाये, ताकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों और कस्बे के छात्रों को दूरदराज में नहीं जाना पड़े।

मैं पुन: शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कार्यवाही तत्काल की जाये। वहां रोज-रोज तालेबन्दी होती है, वहां झगड़े होते हैं और प्रशासन का समय खराब होता है। इसलिए व्यवस्था के कार्यादेश एक सप्ताह में जारी किये जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री भीम राज भाटी।

पाली में पीने के पानी की समस्या

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में न तो कुओं में पीने योग्य पानी है न तालाबों में पीने योग्य पानी है। ऐसे इलाके में जहां पानी की इतनी किल्लत है, वहां हालत यह है कि टैंकरों से पानी सप्लाई होता है। टैंकरों के लिए राज्य सरकार में तो मात्र 133 रुपये जमा होते हैं और वे टैंकर 800 रुपये से लगाकर दो हजार रुपये-बाइस सौ रुपये तक बिकते हैं। पीने योग्य पानी का टैंकर वाटरवर्क्स से 133 रुपये में भरकर 2,200 रुपये तक बिकता है, दूरी के हिसाब से बिकता है। बड़ी दयनीय स्थिति है। मेन लाइनों पर अवैध कनेक्शन हैं। मेन लाइनों पर जो अवैध कनेक्शन हैं, वे कनेक्शन बड़े-बड़े लोग जो अप्रोच वाले लोग हैं, उनके तो नहीं काटे जाते, गरीब लोगों के, शिड्यूल्ड कास्ट के और गायों के जो ग्वाले हैं, उन ग्वालों के कनेक्शन काटे जाते हैं। जो प्रोटेक्शन मिलता है, जिनके कनेक्शन नहीं काटे जाते हैं, वे उन अफसरों को पैसे देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पीएचईडी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अफसरों की हालत यह है कि वही आदमी जेईएन, उसी जगह पर वही आदमी एईएन उसी जगह है, वही आदमी एक्सईएन उसी जगह है। कोई भी गवर्नमेंट आयी, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट आयी तो भी यही हाल है, बीजेपी की गवर्नमेंट आयी तो भी यही हाल है। यह क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था समझ में तो आनी चाहिए कि जेईएन भी वहीं पर, एईएन भी वहीं पर, एक्सईएन भी वहीं पर। कोई भी पार्टी की सरकार आयी तो वह आदमी वहीं पर है।

(श्री भीम राज भाटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर से रोहट पाइपलाइन बिछी हुई है, वह पाइपलाइन 25-27 साल तक जमीन में गढ़ी रही, वह पाइपलाइन फिर पाली जोधपुर से रोहट के लिए। वह पाइपलाइन इतनी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी कि वह पाइपलाइन रिपेयर नहीं हो सकती थी, लेकिन उस पाइपलाइन को रिपेयर कराने के लिए करीब एक करोड़ रुपये राज्य सरकार से लिया गया और एक करोड़ रुपये के बाद भी वह जीर्ण-शीर्ण पाइपलाइन सही नहीं हुई। लोगों को जोधपुर जिले से, कुड़ी से, बाड़मेर, जालौर जिले से, भादरा की ढाणी से पानी लाना पड़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जो अवैध कनेक्शन हैं, उन अवैध कनेक्शनों को काटने के लिए कोई पॉलिसी बनायी जाये।

मेरा दूसरा निवेदन है कि जितनी जनसंख्या इंसानों की है, उससे कुछ कम जनसंख्या जानवरों की है। जानवरों के पीने के पानी के लिए कोई मात्रा सुनिश्चित नहीं है। जानवरों के पीने के पानी के लिए कोई मात्रा सुनिश्चित की जाये, ताकि उस हिसाब से जानवरों को पीने का पानी मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

चित्तौड़गढ़ को डार्क जोन से बाहर किया जाना

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिला डार्क जोन में रख रखा है। वहां काफी उद्योग भी हैं सीमेंट फैक्ट्रियों का हब है, हिन्दुस्तान जिंक है, मार्बल इंडस्ट्री का काफी लंबा-चौड़ा एरिया है और पहले पानी की कमी थी और डार्क जोन में था, कोई दिक्कत नहीं पर आज चित्तौड़गढ़ जिले में काफी पानी है और काफी नये उद्योग भी लगाना चाह रहे हैं, पर डार्क जोन होने के कारण नये उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। आज वहां अगर कोई बोर करता है तो उसके लिए अधिकारियों से सेंक्शन लेनी पड़ती है। ट्यूबवैल का बोर 300 फीट तक करना पड़ता है, हैंडपम्प का 200 फीट तक ही होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मंत्री जी से जवाब दिलायें और इसका रिव्यू भी करवायेंगे, क्योंकि वहां का वॉटर लेवल काफी बढ़ गया है। उसको रिव्यू करवाने की कृपा करायें। भौगोलिक कारणों से वॉटर लेवल शिफ्ट हो गया है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पूर्व, दक्षिण-पश्चिम में शिफ्ट हो गया है।

(श्री चन्द्रभान सिंह चौहान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका चित्तौड़गढ़ जिले में डार्क जोन की वजह से काफी नुकसान उद्योगपतियों को हो रहा है, वहां के किसानों को भी हो रहा है और वहां सब लोगों को हो रहा है। इसलिए मंत्री जी से जवाब दिलायें और इसको रिव्यू कराने की कृपा करायें। धन्यवाद।

साहब, रिव्यू का जवाब दिला दें, एक मिनट का समय बाकी है।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की जो चिन्ता है कि गणना में कुछ कमी खामी रही तो वापस करवा लेंगे। रिव्यू करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: हो गया चारों। और कोई बोलना है आपको?

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, रिव्यू भी करवायें और आपका संरक्षण चाहता हूं। अगर आप इसको रिव्यू करवा देंगे तो वास्तव में चित्तौड़गढ़ जिले के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे श्रीचन्द जी कृपलानी, गोतम जी, सुरेश जी धाकड़ साहब, सब इस बात को उठाना चाह रहे हैं कि इसको डार्क जोन से निकालें और हम आपके चैम्बर में आकर अलग से मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी आपकी बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद करूं कि उन्होंने मान लिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठकर बात करिये।

सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री कालीचरण सराफ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

रामबाग गोल्फ क्लब संचालन में व्याप्त भ्रष्टाचार

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण की संपत्ति पर स्थित रामबाग

(श्री कालीचरण सराफ)

गोल्फ क्लब संचालन के दौरान किये गये भ्रष्टाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। आ गये। ये बोल चुके हैं।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): साहब, रिप्लाई दे दूं?

श्री अध्यक्ष: रिप्लाई दे दीजिए। कोई भयभीत नहीं, निर्भय रहो, लेकिन नियमों में रहो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): भयभीत होते तो आप यहां से नहीं बोलते।

श्री अध्यक्ष: सीट पर नहीं हैं आप। चलिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य, जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है, उनको और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि रामबाग गोल्फ क्लब के लिए 322 बीघा 8 बिस्वा जमीन जो थी वह 1973 में अधिग्रहित हुई थी। उसमें से एक हिस्सा सेन्ट्रल पार्क चला गया, कुछ दूसरे कामों में आ गया और अधिग्रहण के बाद, इस प्रकरण को लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में बहुत-सी रिट याचिकाएं दायर हुई। दायर होते-होते खंडपीठ का एक फैसला आया, उस खंडपीठ के फैसले के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका पेश हुई। उसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर रोक लगा दी गयी और तब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वह रिट पेंडिंग है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रामबाग गोल्फ क्लब जेडीए की जमीन पर बना हुआ है। आज की तारीख तक इसका कोई एम.ओ.यू. नहीं हुआ है। एम.ओ.यू. के लिए कई बार मीटिंग्स हुई, लेकिन आज की तारीख तक एम.ओ.यू. नहीं हो पाया। इसी दौरान मेरे संज्ञान में ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगने के बाद जो जानकारी मैंने जुटाई, उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नवीन सदस्यता पर रोक भी लगायी गयी थी और अभी पिछले दिनों, चूंकि इस गोल्फ क्लब में हमारे विभाग के शासन सचिव अध्यक्ष हैं और हमारे जे डी सी इसके उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इसकी जो प्रबन्ध समिति है और जो कार्यकारी समिति है, उसमें सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। दोनों में निजी व्यक्तियों का समावेश है, जो सदस्य हैं। पिछले दिनों इन्होंने एक एजेंडा नोट

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

जारी करवाया लगभग 117 पेज का, जिसमें इन्होंने संपूर्ण इनका जो विधान था, उसको बदलने के प्रस्ताव थे। कुछ नागरिकों द्वारा ये प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया और संज्ञान में लाने के बाद जब मैंने प्रमुख शासन सचिव से बात की और उन्हें निर्देशित किया कि क्या आपकी अनुमति से ये सभा बुलायी गयी है? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, मुझसे कोई अनुमति नहीं ली गयी। मैंने उन्हें इस सभा को स्थगित करने के लिए निर्देशित किया। प्रमुख शासन सचिव ने इस सभा को स्थगित कर दिया।

चूंकि एम.ओ.यू. नहीं हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सदस्यता पर रोक लगी हुई है। इस बीच इन्होंने एक हिस्से पर कुछ निर्माण कार्य किए थे। उस निर्माण कार्य की जैसे ही हमें शिकायत मिली तो जे.डी.ए. द्वारा उस निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया।

इस प्रकार मैं सदन को बताना चाहूंगा कि रामबाग गोल्फ क्लब हेतु सदस्यता राशि में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। नये सदस्य बनाने तथा टर्मिनेट किए जाने सम्बन्धी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। गोल्फ क्लब द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि पर बिना अनुमति किये गये निर्माण को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09/02/2024 को ध्वस्त किया जा चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्लब के मौजूदा विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन आज की दिनांक तक नहीं किया गया है।

क्लब द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति के आहूत की गयी आम-सभा को विभागीय पत्र दिनांक 28/06/2024 से आगामी आदेश तक स्थगित किया जा चुका है। अब माननीय वरिष्ठ सदस्य की जो भी कोई शिकायत है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी शिकायत प्रस्तुत करें, उस पर हम यथोचित कार्यवाही करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात बिलकुल सही है कि अवैध रूप से बिना अध्यक्ष की अनुमति लिए वह जो मीटिंग करके कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते थे, आपके निर्देश से उसको उन्होंने रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया। यह बात भी सही है कि वहां अवैध निर्माण जो हुआ, जे.डी.सी. ने उसको भी ध्वस्त कर दिया।

इसके साथ-साथ मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब न्यायालय की रोक है कि 2017 के बाद कोई मेम्बर नहीं बनेंगे, इसके बाद भी सदस्य बन रहे हैं।

(श्री कालीचरण सराफ)

एक लाख रुपये आपका साधारण सदस्यता का शुल्क है, ढ़ाई लाख रुपये आजीवन सदस्यता का शुल्क है और पांच लाख रुपये संस्थागत सदस्यता का शुल्क है। यानी 19 लाख रुपये, 29 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, इस प्रकार से बिना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की जानकारी के, वहां के जो मिस्टर कैप्टन हैं और जो सेक्रेटरी हैं, वह लोगों से ले रहे हैं तो वह किस आधार पर ले रहे हैं? ये मेरी समझ में नहीं आया।

इसी प्रकार जब इस जमीन का कोई एम.ओ.यू. नहीं हुआ, जे.डी.ए. को वह कोई किराया नहीं दे रहे तो वह कैसे तो उसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जब कोई लीज मनी नहीं ले रहे, जब कोई किराया नहीं ले रहे तो क्या आपने वहां उनको शराब के लिए बार की सेंक्शन की हुई है? क्या वहां रेस्टोरेंट चलाए जाने की परमिशन आपने दी है?

मैं यह चाहूंगा कि ये जो वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं इसके लिए मैं, मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये एक लाख की जगह 5-5 लाख, 50-50 लाख, 25 लाख, 29 लाख, इस प्रकार की सूची मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, अगर आप कहेंगे। इसकी जांच आप निश्चित रूप से, निष्पक्ष एजेंसी और मेरा तो कहना है कि एस.ओ.जी. से इसकी जांच करवाइए, जिससे जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं जो लूट मचा रखी है, मनचाहा खर्चा, यानी आप देखिए कि 15 लाख से ज्यादा का खर्चा वहां बिना एग्जीक्यूटिव की परमिशन के कर नहीं सकते और ये करोड़ों रुपये का खर्चा कर रहे हैं। इन पर कोई रोक नहीं है। अध्यक्ष को पता नहीं, जैसा आपने कहा, उपाध्यक्ष को पता नहीं। आप ये देखिए की पांच साल में जितने भी यू.डी.एच. सेक्रेटरी बने, जितने जे.डी.सी. बने, उनको सबको मेम्बर बना दिया। बिना प्रायोरिटी के मेम्बर बना दिया, जिससे कि वे बोले नहीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन-कौन हमारे आई.ए.एस. ऑफिसर थे, हमारे प्रशासिनक अधिकारी, जो वहां पर मेम्बर बन गये। जो भी राजनेता बोलता था, पिछली बार, सत्ताधारी पार्टी के लोग, उनको मेम्बर बना दिया। किसी विधायक के लड़के को मेम्बर बना दिया। आखिर ये क्या गोरखधंधा है? जे.डी.ए. की जमीन, सरकारी जमीन, इस पर इस प्रकार से मनमानी चल रही है। मैं चाहूंगा कि इसकी एसओ.जी. से जांच करवाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को तथा सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

कि सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट याचिका पेंडिंग है, हम हमारे यहां के महाधिवक्ता जी से राय लेकर, सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी करवाकर उसका निस्तारण करवाने का प्रयास करेंगे।

नम्बर दो, हम इस गोल्फ क्लब को दिल्ली में जिस तरह देहली विकास प्राधिकरण द्वारा एक गोल्फ क्लब का संचालन किया जा रहा है, उसी तर्ज पर करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

नम्बर तीन, इसमें जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं, विधान के विरुद्ध जाकर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और आपकी मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी गड़बड़झाला किया है, आर्थिक अराजकता की है, आर्थिक अनियमितता की है, मैं इन सबकी जांच एस.ओ.जी. से करवाने की घोषणा करता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस पर और कोई नहीं बोलेगा। श्री जेठानंद व्यास।... (व्यवधान) इस पर चर्चा नहीं होती। बात कह दी, जिन्होंने मांगा ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का मैंने ध्यानाकर्षण करवाया, आपने ध्यान दिया, एस.ओ.जी. की जांच, आपने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर, कुतुब गोल्फ क्लब की तर्ज पर इसको करेंगे, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: हो गया, बैठिए। ...(व्यवधान) इस पर हो गया।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): एस.ओ.जी. जांच करेगी तो सारे नाम सामने आ जाएंगे। जिस-जिसने गड़बड़ी की है, उसके खिलाफ हम प्रभावी कानूनी कार्यवाही करवाएंगे। ...(व्यवधान)

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम-131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव..

श्री अध्यक्ष: एक सैकण्ड।

व्यवस्था का प्रश्न

अधिकारी दीर्घा में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की गैर मौजूदगी

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। मंत्री का बहुत शानदार जवाब है लेकिन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मेरा इसमें व्यवस्था का प्रश्न है। इतना महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और इतना शानदार जवाब लेकिन इस अधिकारी दीर्घा के अन्दर कोई सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं है, इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है। आप बताइये कि मंत्री इतना अच्छा जवाब दे रहा है, यह इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कोई सुन ही नहीं रहे ...(व्यवधान) आप अधिकारियों का बचाव कर रहे हो क्या ...(व्यवधान) अधिकारियों का बचाव कर रहे हो क्या? यह व्यवस्था की बात है। सदन की गरिमा के खिलाफ है।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ...(व्यवधान)

व्यवस्था

प्रक्रिया नियमों में उठाये गये विषयों के समय विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये

श्री अध्यक्ष: एक सैकण्ड। माननीय संसदीय मंत्री जी, सदन की यह व्यवस्था दे रहा हूं कि आगे से जब कभी आपके स्थगन, पर्चियां, ध्यानाकर्षण हो, उस विभाग के समुचित अधिकारी यहां बने रहें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपका आदेश शिरोधार्य है, इसकी पूर्ण रूप से पालना होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री जेठानन्द व्यास।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पंजीकृत समितियों को आवंटित भूखण्डों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों को राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूखंडों पर भूमाफियाओं द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने के लिए फर्जी पदाधिकारी बनकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सोसाइटी पर कब्जा कर ज़मीनें हड़पने के क्रम में।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण करना है आपको, मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): जवाब मुझे मिल गया है।

श्री अध्यक्ष: आपका ध्यान आकर्षित हो गया ना।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): लेकिन मैं उसे ...

श्री अध्यक्ष: बाद में, बाद में आता है। माननीय मंत्री जी। ध्यानाकर्षण की कुछ व्यवस्थाएं हैं। सदस्य केवल ध्यानाकर्षण करेगा, मंत्री जवाब देगा, उसके बाद आप बोलेंगे। मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राज्य में "राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत संस्थाओं का पंजीकरण किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 2,70,257 संस्थाएं पंजीकृत हैं। अधिनियम में धारा 4 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार, संस्थाएं कार्यालय में वार्षिक सूची दाखिल की जानी अपेक्षित होती है, जिसमें परिषद् समिति या अन्य शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों के जिनको सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध तत्समय सौंपा हुआ हो, नाम, पते और उपजीविकाएं प्रमाणित ही भिजवाने का प्रावधान है।

साथ ही अधिनियम की धारा 4-क (1) के अंतर्गत इन्हीं संस्थाओं द्वारा उस वर्ष किये गये समस्त परिवर्तन दर्शित करने होते हैं, तथा संस्था के नियमों और उप नियमों की एक शुद्ध अद्यतन सूची भी भिजवानी होती है जो कि शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित ही भिजवाने का प्रावधान है।

धारा 4-क (2) के अंतर्गत संस्थाओं के नियमों और विनियमों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रति, जो पूर्वोक्त रीति से सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, ऐसे प्रमाणित करने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजे जाने का प्रावधान है।

कार्यालय में संस्था द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई अधिनियम की धारा 4 (क) (1) में पदाधिकारियों की सूची में से ही किसी भी पदाधिकारी द्वारा संस्था के आवेदन करने पर मूल दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जाती है। आवेदन के साथ संस्था द्वारा मूल दस्तावेज खोने के संबंध में दर्ज एफ.आई.आर. की प्रति, शपथ पत्र एवं दैनिक समाचार पत्रों में खोए-पाए की सूचना की प्रति रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त समिति के पंजीकरण से संबंधित मूल दस्तावेजों की प्रति रजिस्ट्रार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

(श्री गोतम कुमार)

किसी भी समिति के सदस्य द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने पर भी संबंधित पत्रादि की प्रति उपलब्ध कराने के प्रावधान हैं। समिति के पदाधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की कार्यालय प्रणाली से बन्द पड़ी संस्थाओं की भूमि पर कब्जा करने के प्रकरण या प्रयास की संभावना बहुत कम रह जाती है। किसी भी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर संस्थाओं के फर्जी पदाधिकारी बनकर बन्द पड़ी संस्थाओं की भूमि पर कब्जा करने आदि गैरकानूनी कार्य करने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार द्वारा सक्षम न्यायालयों/संबंधित पुलिस थानों में परिवाद प्रस्तुत किया जाता है तत्पश्चात् दोषी व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी संस्थाएं जो पांच वर्ष से पुरानी हैं, उनका कोई कार्य आज तक नहीं हो रहा है, वहां के कर्मचारियों की मिलीभगत से भूमाफिया, पिछले पांच साल में ऐसे कई प्रकरण बीकानेर में हुए, राजस्थान में अन्य जगह भी हुए होंगे, वह पुरानी संस्थाएं जो बंद पड़ी हैं वह नाम लेकर फिर फर्जी शपथ पत्र, फर्जी साइन करके आवेदन करते हैं, वहां से वह रिकार्ड लेते हैं और फिर नये सिरे से कार्यकारिणी बनाकर उसको एप्रूव्ड कराते हैं। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि जांच की जाए कि जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है, वह व्यक्ति संसार में ही नहीं है और उसने आवेदन किया है। वापस कार्यकारिणी बनाई है, जिसने उसका रिकार्ड मांगा, उस कार्यकारिणी में नाम ही नहीं है। ऐसे जितने भी प्रकरण हैं, उनकी समिति बनाकर जांच की जाए। मेरा निवेदन है कि जितने भी अधिनियम होते हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए नियम बने होते हैं, लेकिन राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1958 के सम्बन्ध में कोई प्रक्रियागत नियम नहीं है। विभाग इस सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए क्या विचार रखता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): वैसे समिति का संचालन पंजीकृत विधान के अनुसार होता है। समिति में नये सदस्य हो, निष्कासन हो, विधान अनुसार समिति का आंतरिक मसला होता है जिसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। समिति को राजकीय भूमि आवंटित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। अगर उस उद्देश्य से वह इधर-उधर होते हैं तो निश्चित रूप

(श्री गोतम कुमार)

से नियमों व शर्तों का वह उल्लंघन करते हैं तो सम्बन्धित विभाग उस पर कार्यवाही करता है। भूमि का आवंटन भी निरस्त होता है। किसी भी फर्जी दस्तावेज से अगर किसी भू-माफिया ने अनधिकृत कब्जा या जमीन हड़पने का कोई काम किया है तो निश्चित रूप से भारतीय न्याय संहिता के तहत उस पर कार्यवाही की जायेगी। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बात आ गई।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसी जो संस्थाएं हैं, यह जो हुआ है, तो जो पांच वर्ष पुरानी संस्थाएं थीं उनका एकदम जीवित होना, तो ऐसी संस्थाओं की जांच करवायी जाए। इसके लिए समिति बनाकर जांच करवाने का विचार है या नहीं है?

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो बात आपके माध्यम से कही जा रही है, निश्चित रूप से जो भी कोई प्रकरण इस तरह के हैं आप अगर बताएंगे तो उन पर निश्चित रूप से कमेटी बनाकर, जैसा कि अभी नगरीय विकास मंत्री महोदय ने भी जिस प्रकार से कहा है, चाहे एस.ओ.जी. से हो या चाहे पुलिस से हो, किसी भी एजेंसी द्वारा जांच करवाकर ऐसे अपराधियों पर कार्यवाही कराने का काम विभाग करेगा।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री ओटा राम देवासी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ8(11)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/गिरदावरी/2023, दिनांक 11.03.2024 जिसके द्वारा बाढ़ से 33 प्रतिशत या इससे अधिक

(श्री ओटा राम देवासी)

फसल खराबा होने के कारण जिला जालोर एवं नागौर के कतिपय कुल 238 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.1(2)आ.प्र.एवं सहा./ओ.वृ. व पा.शी./ गि.रि./ 2023/1298-332, दिनांक 21.02.2024 जिसके द्वारा ओलावृष्टि से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने के कारण जिला श्रीगंगानगर के कतिपय 10 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है; एवं

(3) अधिसूचना संख्या: एफ1(5)आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/2023/2297-2324, दिनांक 17.05.2024 जिसके द्वारा खरीफ फसल वर्ष 2023 (संवत 2080) में सूखाग्रस्त तहसीलों को अधिसूचना क्रमांक एफ1(5)आ.प्र.एवं सहा./ सामान्य/2023/5576 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया है, जिसकी अवधि को दिनांक 31.07.2024 तक बढ़ाया गया।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री सुरेश सिंह रावत।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना अधिनियम, 2015 की धारा-15 के अन्तर्गत राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक। गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024, श्री सुमित गोदारा। ...(व्यवधान) इस पर नहीं। विधेयक रख रहे हैं, आप विधेयक पर बोलना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विधेयक तो रखा जा सकता है। कोई भी विधेयक लाया जा सकता है। आप विधेयक पर बोलना। विधेयक पर आपको बोलने का अधिकार होगा। ...(व्यवधान) विधेयक पर बोलने का अधिकार होगा।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024,

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं आपकी अनुमति से गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप विधेयक पर बोलना। आपको अनुमति होगी बोलने की। ...(व्यवधान)

घोषणा

परिवर्तित आय-व्ययक वर्ष 2024-25 पर विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों को बोलने के लिए शेष समय का विवरण

माननीय सदस्यों, जब बजट पर चर्चा होनी शुरू होनी थी तो हमने दलों का समय का विभाजन किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी 9 घंटे 26 मिनट, इण्डियन नेशनल कांग्रेस 5 घंटे 25 मिनट, भारत आदिवासी पार्टी 15 मिनट, बहुजन समाज पार्टी 10 मिनट, राष्ट्रीय लोक दल 5 मिनट, निर्दलीय 39 मिनट और अब तक जो समय लिया गया है 11 और 12.07.2024 तक, दो दिन बहस हुई है और अब आज तीसरे दिन का जो शेष समय है और यह कल का और आज का मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पास 3 घंटे 16 मिनट है, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 1.30 घंटा है, भारत आदिवासी पार्टी के 8 मिनट बचे हैं, एक मिनट बहुजन समाज पार्टी का बचा है, राष्ट्रीय लोक दल के 5 मिनट और निर्दलियों के 14 मिनट बचे हैं, इसलिए समय सीमा है।

(श्री अध्यक्ष)

आज जो मेरे पास दोनों दलों की सूचियां आई हैं वे इतनी लम्बी हैं और समय जो निर्धारित करके भेजा है, उस हिसाब से दोनों दिन और कल विपक्ष के नेता भी बोलेंगे और वित्त मंत्री का जवाब भी आयेगा इसलिए समय सीमा को देखते हुए दोनों सचेतक महोदय इस सूची को कम करें या समय कम करें, ताकि हम समय पर यह बहस करवा सकें, इसलिए आप दोनों थोड़ी देर में यह व्यवस्था करके मुझे दे दें। यह इतनी लम्बी लिस्ट है, इसमें आज 45 लोगों को बोलने का समय दिया है। अब एक-एक को कितने-कितने मिनट दिये जाएं, यह आप लोगों पर है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सदन का समय बढ़ा लीजिए।

श्री अध्यक्ष: समय तो एक सीमा तक ही बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता है। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज आपने परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 08 फरवरी, 2024 को 50 पेज का बजट आपने प्रस्तुत किया जिसमें लेखानुदान प्रस्ताव शामिल थे, अभी आपने 10 जुलाई, 2024 को जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट पेश किया वह 125 पेज का है। इस प्रकार 175 पेज हो गये जिसमें सरकार ने अपनी बात कही है। जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसकी योजनाओं को उन्होंने गलत बताया है, नीतियों को गलत बताया है और जो भी अपने से बन पड़ा वह काम, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट है, वह हमारी सरकार के बजट को री-पॉलिश किया गया बजट है क्योंकि आपका बजट, केन्द्र का बजट अभी आया नहीं है। आपके पास देने को कुछ नहीं है। सर, वे ही अधिकारी, वह ही लैपटॉप, वह ही टाइप, वह ही कम्प्यूटर, वह ही सोच, कहां से ले आये आप नया बजट? कहां से लेकर आये? आपने केवल एक परिवर्तन किया इस बजट में जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि श्रीमती दिया कुमारी, उप मुख्य मंत्री (वित्त), राजस्थान

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

का बजट भाषण। यह कोई पोस्ट होती ही नहीं है, सर। उप मुख्य मंत्री (वित्त) कोई पोस्ट ही नहीं होती है। जब मुख्य मंत्री होता है या मंत्री होते हैं तो उसके डिप्टी सैक्रेटरी होते हैं कि वह वित्त देखेगा, क्या देखेगा, सी.एम.ओ. में ओ.एस.डी. होते हैं, वे होते हैं ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सचिन पायलट क्या थे? इसीलिए उनको हटाया था क्या? ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तय कर लीजिए कि अगर कोई गलत बात बोलूं तो ये बोलें। आप ऐसे ही बोलोगे तो कौन नम्बर दे रहा है। आपके बाबू नहीं लगते आपके कहने से। काहे के लिए चिल्ला रहे हो? ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके भरोसे नहीं हैं। आपकी तरह हमारे मुख्य मंत्री अपने प्रदेश के अध्यक्ष को निकम्मा नहीं कहते हैं। हम आपकी मौजूदगी में यह नहीं कहलवाते कि कौन-कौन रिश्वत लेता है। हम नहीं कहलवाते हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आगे बढ़िये, यह हो गया। आपके संसदीय मंत्री ने बोल दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों, आप सुनोगे तो आपको मजा आयेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ खट्टा होगा, कुछ मीठा होगा। ...(व्यवधान)

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पिछली बार आपके मुख्य मंत्री ने पिछली बार का बजट इस सदन में पढ़ा, हमने यह सीखा था पिछली बार। ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको हल्ला करना है या सुनना है? आप तय कर लो। आपके मुख्य मंत्री को एक शब्द नहीं बोलने देंगे। आप शांति से रहो। शांति से रहो। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इस तरह धमकाओ मत। इस धमकी से मत डराओ। आप बजट पर बोलो, कोई इंटरफीयर नहीं करेगा। आप बजट पर बोलो। ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप कह रहे हो कि इस बजट में यह कर दिया। 2047 बार-बार यानी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

2047 का विजन, किसने देखा है 2047 को? पांच साल बाद में 70-80 परसेंट तो पूर्व विधायक की पेंशन लेते मिलेंगे, यह मैं आपको बता रहा हूं। किसने देखा है? 2047 किसने देखा है? सवाल यह है कि आप 2047 का विजन दिखा रहे हो तो आप अपना वर्तमान विजन ठीक करो। जिस दिन हमने सदन में देखा वह सदन की गरिमा को तार-तार कर रहा था। मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री के बीच में जो संवादहीनता थी, वह हमने देखी है, साहब। सबने देखी है, पूरे प्रदेश ने देखी है। मैं यह समझता हूं कि इन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अशोक गहलोतजी और सचिन पायलट के बीच में जो संवादहीनता थी उसको आपने बखूबी देखा है। ...(व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात गलत है। यह बात गलत है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को आर्डर में लाइये। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर में है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं है। इनके डर है और ये सुनना नहीं चाहते हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं करवा रहा हूं। आप भी डिस्टर्ब कर रहे हो। माननीय सदस्य, पिछले बारह दिनों में आपने जितना डिस्टर्ब किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। माननीय सदस्य, इनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको इनका नमूना देता हूं कि आर्थिक नीतियों की हमारी आलोचना की। आर्थिक नीतियों का पैमाना क्या होता है? पैमाना यह है कि 2023-24 में जब हमारी सरकार थी तो राजकोषीय घाटे का अनुमान 62,772 करोड़ रुपये का था और इनका 70 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2018-19 में जब बीजेपी की सरकार थी तो जो पूंजीगत परिव्यय है वह 16,638 करोड़ रुपये था और हमारा 2023-24

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

में 38,062 करोड़ पूंजीगत परिव्यय प्रस्तावित किया गया, 2018-19 से दुगुना। आर्थिक नीतियों की केवल बातों में आलोचना करना और यह कहना कि मुख्य मंत्री जी तो कह रहे हैं कि 45 परसेंट हमारे वादे ही पूरे कर दिये हमने तो, अब क्या करोगे, और उप मुख्य मंत्री जी कह रही हैं कि केवल 45 किये हैं। सामंजस्य बैठा लो, नमस्ते-वमस्ते कर लो। बात कर लो, बैठकर चर्चा कर लो।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आप देखिये 2018-19 में, यह जो आंकड़े हैं, वही तो प्रमाणित करेंगे कि आप लोगों ने अच्छे काम किये या हम लोगों ने अच्छे काम किये। कोई आकाश से तो आकाशवाणी होगी नहीं। जो आंकड़े हैं वह समझ लो, आपके काम में आयेंगे। बहुत से मेरे वरिष्ठ भी हैं, बहुत से कनिष्ठ भी हैं। पहली बार आये हैं और आखिरी बार, आगे आयें भी नहीं, हो सकता है। यह मौका आप ले लो।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2018-19 में 2,12,275 करोड़ रुपये का बजट था, 2023-24 में 3,90,856, यानी 84 परसेंट की बढ़ोतरी। फिर आप जीएसडीपी का देख लीजिये 2018-19 में 9,11,519, करोड़ रुपये और इनका देख लीजिये 2023-24 में हमने जो छोड़ा, 15,76,186 यानी 73 परसेंट बढ़ोतरी। आर्थिक विकास दर 2018 में जब इनकी सरकार थी 2.37 प्रतिशत और 2021-22 में हम 11.04 से देश में नंबर टू पर पहुंच गये थे। यह आंकड़े बोलते हैं मैं नहीं बोलता। मैं कोई पर्ची से नहीं बना। मैं तो जो हकीकत है वह रखूंगा।

2017-18 में प्रति व्यक्ति आय 98,698 रुपये बढ़ोतरी वाला राज्य 30वें स्थान पर था बीजेपी की सरकार में। आज, 2023-24 में जब हम थे तो 1,56,149 रुपये, यानी बढ़ोतरी वाले राज्यों में हम 9वें स्थान पर थे। यह आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। इन्होंने बहुत हल्ले किये, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान। पता नहीं कितने हम पर आरोप लगाये। अपराध बढ़ गये, यह हो गया, पेपर लीक हो गया। जो बोला, सो बोला। रुक जाओ, मुश्किल से आये हो बहुत पसीना बहा-बहा कर, सुन लो, काम आयेगा। जब आपको लगे कि यह काम की चीज नहीं है तो कान बंद कर लेना। आपको मना कौन कर रहा है लेकिन मेरी बात तो सुनो।

अध्यक्ष महोदय, अब देखिये, जो इनका पांच महीने के अपराध का आलम है, पांच महीने का, कुल आईपीसी के अपराध 87,311, अब दुष्कर्म बालिग के साथ 1994, नाबालिग के साथ 576, कुल 2,570 और महिलाओं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

के, जिन महिलाओं की यह बात कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार के 14,835 केवल पांच महीनों के हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो नहीं सहेगा राजस्थान, आपका फेल हो गया। छह महीने में केवल मुख्य मंत्री जी ने और इन्होंने, आप सुन लो, आप तो मेरी जगह भी बोल लो तो भी मेरे को आनंद आ जायेगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप भी जवाब देना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तो शिक्षा मंत्री जी को डिमांड पर रिप्लाई देने के लायक ही नहीं समझा। फिर भी बीच-बीच में बोल रहे हैं। आप डिमांड रखवाओ, फिर आप बोलना।

श्री अध्यक्ष: आप बजट पर बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर मैं बोलूंगा। पता लग जायेगा। अच्छा, चलो मुद्दे पर आ जाता हूं। सर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री सुझाव प्राप्त करेंगे, वित्त मंत्री बजट का अंतिम रूप देंगी, फिर मुख्य मंत्री प्रेस कान्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वित्त मंत्री नहीं बोलेंगी। फिर बजट की क्रियान्विति में वित्त मंत्री नहीं जायेंगी और बजट पारित होने से पहले मंत्री जा-जा करके वहां कहेंगे, बजट को लागू करो, जिला कलेक्टर कह रहे थे कि क्या लागू करें, बजट पारित कराकर के तो लाओ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी के प्रदेश समझ में नहीं आ रहा। मंत्री के विभाग और एस.ए. समझ में नहीं आ रहे हैं। सी.एस.के.सी.एम.ओ. समझ में नहीं आ रहा है। सी.एम.ओ. के दिल्ली समझ में नहीं आ रही है। जन-प्रतिनिधियों का काम कौन करेगा, यह समझ में नहीं आ रहा है। यह इनकी सरकार का छह महीने का नमूना है। यह इनकी हालत है। कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। किलों की बातें करेंगे, महलों की बातें करेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यही बजट पर है, बस। यही बजट पर है? यही बजट पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष: समय सीमित है, मैं बैठा दूंगा। समय पूरा होते ही बैठा दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजस्थान के इतिहास में इस सदन की परंपरा रही है कि जब मुख्य मंत्री का विभाग होता है तो मुख्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्री से जवाब दिलवाता है। यह पहली बार है, जब काबिल

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

संसदीय मंत्री होकर के भी इनसे जवाब नहीं दिलवाये जा रहे हैं। यह क्या चीज है, समझ में नहीं आ रहा है।

इस सदन में बजट के माध्यम से एक गरीब की बात नहीं, दलित की बात नहीं, पिछड़ों की बात नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, सुशासन की बात नहीं, कृषि पर डिमांड पर चर्चा नहीं होगी, शिक्षा पर नहीं होगी, गृह पर नहीं होगी, बिजली पर नहीं होगी, पानी पर नहीं होगी, तो क्या करोगे? मेज ही थपथपाओ क्या?

सवाल यह है कि यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है कि क्यों नहीं हो रही है। इसका मायना यह हुआ कि जो पर्चियां आ रही हैं वह ना मुख्य मंत्री की और ना मंत्रियों की सही आई हैं। उसके बाद में इनको जो एस.ए. मिले हैं, वह भी 360 डिग्री परीक्षण के बाद मिले हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अब एस.ए. पर कौनसी बात हो गयी? अभी आप सब बोल रहे थे एस ए पर, हमें कौनसा एस ए मिला, नहीं मिला, यह कौनसा बजट है? हमारे यहां यह नहीं होता है, हमारे यहां शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में मुख्य मंत्री यह नहीं पूछता है कि शिक्षा विभाग में रिश्वत चलती है कि नहीं चलती है? हमारे यहां नहीं पूछते हैं। हमारे यहां नहीं पूछते हैं कि कौन-कौन से नेता हैं। हमारे यहां मुख्य मंत्री यह नहीं कहता है कि प्रदेश अध्यक्ष निकम्मा है, निठल्ला है, फलां, फलां। हम नहीं कहते हैं। हमारी यह परंपरा नहीं है। आप बजट पर बोलें महाशय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चलिये, बजट पर बोलता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी जब जोधपुर गये और यही संसदीय कार्य मंत्री जी को अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया तो यह कह रहे थे कि थैली देने वाला मिलता है। एक-एक लाख की थैली देने वाले को मुख्य मंत्री मिलते हैं। हमसे नहीं मिलते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह असत्य है। सब को प्रवेश करने दिया है। आप बजट पर एक शब्द बोलकर बताओ। हिन्दुस्तान के इतिहास में, राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में ऐसा ऐतिहासिक बजट आया हो तो आप बता दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह डिबेट नहीं है। मेरे अच्छे मित्र हैं। इनकी बेइज्जती हुई है इसलिए मैंने यह दो बात कह दी। आपको बुरा लगा तो मैं मेरे शब्द वापस ले लेता हूं ...(व्यवधान) चलिये, वह शुरू करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप कंटीन्यू करिये। आपका टाइम हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बजट पर कर देंगे। यह कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, डबल इंजन की नहीं है, यह चार इंजनों की सरकार है। चौबल इंजन की सरकार है। चौबल इंजन की ऐसे है, एक मुख्य मंत्री जी, मंत्री, एक इंजन वह हो गया। एक आपका ब्यूरोक्रेसी का इंजन हो गया। एक आपका पूर्व मुख्य मंत्री का जो खेमा है, उसका हो गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): फिर वही बात।

श्री अध्यक्ष: यह बजट तो नहीं है। आपके 10 मिनट बाकी हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक +++ का हो गया। यह चार इंजन हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह कौनसी बजट स्पीच हो रही है?

श्री अध्यक्ष: यहां राजनीतिक दल की बात हो रही है। यह शब्द हटा दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): शान्ती धारीवाल जी, आप जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कृपया सिखाइये कि बजट पर कैसे बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष: यह शब्द अंकित नहीं होगा। चलिये ...(व्यवधान) 10 मिनट हो चुके हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह बजट पर बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नाम आते ही यह कृपलानी ही खड़े हो जाते हैं। पूर्व मुख्य मंत्री जी का नाम लेते ही खड़े हो जाते हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या बात कर रहे हो? बजट पर बोल रहे हैं यह?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जो बजट है, इसमें किसने कहा था, हमने कहा था कि डबल इंजन लिख दो? जब डबल इंजन लिख दिया और हमको चार इंजन नजर आ रहे हैं तो हम तो राजस्थान की जनता जो कहती है वह बात सदन में रख रहे हैं। आपको तकलीफ होनी ही नहीं चाहिये। आपको तो चार इंजन बना दिये, चारों चार दिशा में खींच रहे हैं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इंजन बैठने वाला है। धूं-धूं कर रहा है और आप चारों दिशाओं में खिंचे हुए हो, कोई काम आपका होने वाला नहीं है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): चार इंजनों में भी एक तो इलेक्ट्रिक का है। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय धारीवालजी, आप सीनियर आदमी हो, विराजो। फिर आपको भी नहीं बोलने देंगे। ..(व्यवधान) धारीवाल जी, मैं कह रहा हूं कि आप बोलोगे तो फिर आपको भी नहीं बोलने देंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ..(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुद्दे पर आता हूं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि महंगाई के ऊपर खूब हल्ला होता है। एक भी योजना, जो महंगाई राहत केन्द्र में हमारी सरकार ने शुरू की थी, उसके लिये आपने एक भी वर्ड नहीं बोला। देश के प्रधान मंत्रीजी यह कहकर गये थे कि जो जनहित की योजनाएं हैं, वह हम बंद नहीं करेंगे। आप फ्री बिजली पर नहीं बोल रहे, आप कृषि के ऊपर जो बिजली दे रहे हैं, उस पर नहीं बोल रहे। जो इंदिरा रोजगार योजना हमने शहरों में लागू की, उस पर नहीं बोल रहे। आप ओ.पी.एस. कर्मचारियों पर आप नहीं बोल रहे हो। आप नौकरियों का हल्ला करते थे, वह करते थे, अभी कह रहे थे न मुख्य मंत्रीजी कल-परसों राधे-राधे का बैल्ट लगाकर गये थे और कह रहे थे 70 हजार नौकरियां दे दी। ...(व्यवधान).. बुरा है क्या?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। इनको पूरा करने दो। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बजट पर बोलें। ..(व्यवधान)... इनको पूरा करने दो। ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने तो अच्छा ही बताया है। ..(व्यवधान)... गोठवालजी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। ...(भारी व्यवधान)..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गोठवाल जी मेरे छोटे भाई हैं। बहुत अच्छे मित्र हैं। अगर यह सरकार बनते ही सी.एस. से नहीं लड़ते तो आज मंत्री होते। मेरी गारंटी है, लेकिन इन्होंने रोंग नंबर डायल कर लिया, मैं क्या कर सकता हूं इसमें?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो योजनाएं थीं, उनके लिये आपने क्या किया? आज 27 हजार की नौकरियां बता रहे हो न, एक नौकरी की विज्ञप्ति आपकी निकाली हुई नहीं है। हमारी जो डिग्रियों की जांच हो रही

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

थी या जो कोर्ट में पेंडिंग थी, स्टे की वजह से पेंडिंग थी, वह नौकरी देकर यहां हाथ से थपथपा रहे थे। एक लाख, चार लाख, माननीय सदस्य, सर्कस थोड़े ही है। हर चीज यहां पर नोट होती है। अगर आप चार लाख सरकारी नौकरी दे दो न तो मैं सार्वजनिक मंच से आपको धन्यवाद दूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देना। चार लाख नौकरी देंगे और आप धन्यवाद दे देना।

एक माननीय सदस्य: चार लाख का मतलब समझते हो क्या? ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: इनको बोलने दो। इनका समय मत बर्बाद करो। ..(व्यवधान).. आपका समय क्यों खराब कर रहे हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो नई शिक्षा नीति शिक्षा मंत्रीजी लागू कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनना, बहुत गंभीर है। आपके भी काम आयेगी। शिक्षा मंत्रीजी जिस नई शिक्षा पॉलिसी की बात कर रहे हैं न, मैं कहना चाहता हूं उस नई पॉलिसी में शिक्षा विभाग में एक भी सरकारी नौकरी आगे से नहीं होगी, इस बात का प्रावधान है। सारी की सारी नौकरियां संविदा पर होंगी। इन्होंने एक यह चैंज कर दिया कि छह साल का बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेगा। अब की बार एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया। हमने एक करोड़ तक नामांकन पहुंचा दिया था। यह 70 हजार पर आ गये और इसका परिणाम बताऊं? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो शिक्षा मंत्री रहे हो और इतने शानदार रहे हैं। आपके निर्णय आज भी पूरे देश में गूंजते हैं। स्मृति जी ईरानी भी इनको बुलाती थी। इनको राय लेने के लिये माननीय केन्द्रीय मंत्री स्मृति जी ईरानी बुलाती थी और पूरे देश के मंत्रियों का समूह बनाया, उसका चेयरमैन हमारे माननीय स्पीकर साहब को बनाया था। एक यह शिक्षा मंत्री,...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप बोलें, आपके छह मिनट बाकी हैं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): पूर्व शिक्षा मंत्री ने कितने पैसे खाये? ..(व्यवधान)... गोविन्द सिंह डोटासरा जी ने कितने पैसे खाये? यह गहलोत जी पूछ रहे थे वहां। ...(व्यवधान)..गहलोत जी पूछ रहे थे कि डोटासरा जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए कितने पैसे खाये? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके पूरे लोग ही खड़े होकर बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप एक भी मत खड़े होओ, मैं अकेला सक्षम हूं। मैं अगर गलत बोलूं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आप तुरंत उसको एक्सपंज कर दें। लेकिन यह जो मेढ़क की तरह उछल रहे हैं न, यह आपके ही घाटे का सौदा है, मेरे नहीं है। आपके मंत्री मिलते नहीं, मंत्री से मुख्य मंत्री नहीं मिलता, मुख्य मंत्री से प्रधान मंत्री नहीं मिलता। क्या बात कर रहे हो आप? ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): गई बार में आप अधूरा छोड़कर भागे थे...(व्यवधान)..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चिरंजीवी योजना का क्या होगा, इन्होंने बताया नहीं।

श्री अध्यक्ष: आपके पांच मिनट बाकी हैं, जो बोलना है, वह बोल लीजिये। ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेडिकल कॉलेजों का काम, जो पैसे हमने दिये थे, वह रुक गये। यह ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बना रहे हैं। हमने 10-10 करोड़ रुपये दिये थे...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। पांच मिनट इनको दिये हैं, आप बैठिये। ..(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप पूरा करिये। पांच मिनट बाकी हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कर रहा हूं न। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनायेंगे। हमने 10 करोड़ की सड़कें दी थीं, आप तो पांच में ही निपट गये। क्या बात कर रहे हो? ...(व्यवधान)

यह जो बजट है न, माननीय अध्यक्ष महोदय, खाटूश्याम जी मेरे जिले में है, 100 करोड़ देने की घोषणा की है, काम पहले से चल रहा है। 32 करोड़ रुपये हमने पहले ही दे दिये। गोविन्द देवजी के मन्दिर में हमारी सरकार ने 100 करोड़ दिये, यह दोबारा बजट में लेकर आ गये।

पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव एक साथ 'वन स्टेट वन इलेक्शन', भरतपुर के जिला प्रमुख के चुनाव तो आज तक नहीं करा पाये मुख्य मंत्रीजी। आपने भादरा में क्या किया? क्या तमाशा लगा रखा है 12, 13 और 14 जगहों पर उप चुनाव हैं, आपने उप चुनाव रोक दिये। यह सरकार

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जन प्रतिनिधियों की खिल्ली उड़ाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला, उप जिला प्रमुख मौजूद, जिला प्रमुख एम.एल.ए. बन गया और जिला कलेक्टर उसका चार्ज लिये बैठा है। यह काहे के पंचायती राज के चुनाव करवायेंगे। आप भट्ठा बैठाओगे। इन जन प्रतिनिधियों का, नगर निकाय और पंचायती राज का भट्ठा बैठाओगे। मोदीजी की लाइनें लिखना बंद करो। आपके बस में ही नहीं है कि पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव आप करवा दो। आप एक भादरा का चुनाव तक तो नहीं करवा सके। एस.डी.एम. को छुट्टी पर भेजना पडा, क्योंकि वहां पर आप हार रहे थे। भरतपुर में आप हार रहे हो।

श्री संजीव कुमार (भादरा): भादरा में हार क्या रहे थे, आप हारने वाली बात कैसे कह सकते हो? क्या हार रहे थे भादरा में?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजीव गांधी स्कॉलरशिप के लिये मैं कहना चाहूंगा, विदेश में हमारे प्रदेश के गरीब के बच्चे पढ़ने जा रहे थे। मंत्रीजी ने एक जवाब दिया था, उस दिन मुझे अफसोस हुआ कि थोड़े बहुत तैयारी करके आते नहीं है। यह कहना कि आठ लाख बच्चों के बराबर का बजट है। फरवरी और मार्च के अन्दर विदेशों में सलेक्शन हो जाता है। आपने आज तक आवेदन ही नहीं लिये। हम मार्च से पहले आवेदन ले लेते थे। उसके बाद में जिसका सलेक्शन हो जाता था, उसको पैसे मिल जाते थे तो वह चला जाता था। आज सारे के सारे बच्चे या तो घर से पैसे देकर जा रहे हैं वरना उनका एक साल बर्बाद कर दिया आपने। आप नाम चेंज कर देते, लेकिन आज तक फार्म नहीं ले पाये। इससे ज्यादा आप और क्या करोगे? आप तुलना कर रहे हो, विदेश में हमारा गरीब का बेटा नहीं पढ़े। इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद कर रहे हो, तमाशा लगा रखा है। गरीब के सवा सात लाख बच्चे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जान चली जाये इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद नहीं करने देंगे, क्या बात कर रहे हो?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मोदीजी ने कहा था कि कोई भी जनहित की योजना बंद नहीं होगी। किसी भी योजना के ऊपर उन्होंने बजटरी कोई बात नहीं की है। दूसरी बात, मोदीजी ने कहा था कि मेरी गारंटी है कि हरियाणा और राजस्थान में दिसम्बर के अन्दर सरकार बनते ही पेट्रोल का भाव बराबर कर दूंगा। आज भी 10 रुपये का अंतर है। मोदीजी ने कहा था कि ERCP मैं लागू कर दूंगा। इस बजट में लेकर आये हैं। आप

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

देखना सीकर, शेखावाटी के लिये पानी की जो योजना है, उसका बजट में नाम पढ़ा है इंदिरा गांधी योजना, अगर यह हमारी योजना नहीं होती, हमने इसकी वित्तीय स्वीकृति 7 हजार समथिंग की कर दी थी, नहीं होती तो यह दीन दयाल उपाध्याय योजना होती, यह इंदिरा गांधी के नाम से योजना आप बजट के अन्दर पढ़ते। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ERCP के अन्दर 10 हजार करोड़ की वित्तीय स्वीकृति करके हमने टेंडर करके काम चालू कर दिया। आपके मुख्य मंत्री जाकर अवलोकन करके आये और इस बजट के अन्दर ठकाठक-ठकाठक ठोक दिया, क्योंकि टाइप करने वाले वही थे। इनको तो समझ में ही नहीं आया, इनके तो फोटो का चक्कर था कि वित्त मंत्रीजी की फोटो अधिकारियों के साथ आनी चाहिये या मुख्य मंत्रीजी के साथ में आनी चाहिये। फोटो तो सबकी एक साथ ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बजट एक बहुत सेंसेटिव डॉकूमेंट होता है। इस तरीके से केवल फोटो के लिये, एक मैसेज देने के लिये आपस में नूरा-कुश्ती ठीक नहीं रहता है।

मैं कहना चाहता हूं, एक बात मैं कहना चाहता हूं। लास्ट में मेरी बात एण्ड करूंगा, क्योंकि आप मुझे समय कम दें, इनकी सबकी भावना यही है। एक मुख्य मंत्री जी ने लास्ट में जब पहले सत्र था, उसमें एक बात मेरी ओर इंगित करके कही थी, चाहे नाम नहीं लिया हो, मैं उसका जवाब आज देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, ''डोटासरा जी, कौन-सी चक्की का आटा बच्चे खाते हैं कि इंटरव्यू में बराबर नम्बर हो जाते हैं।'' मैं उसके जवाब में कहना चाहता हूं, क्योंकि उस दिन मेरा मौका नहीं था, उनका ही मौका था, अब वे जवाब देंगे कि नहीं, वे ही जानें। मैं यह कहना चाहता हूं कि, मुख्य मंत्री जी, आप ही बता दीजिये कि आपने किस-किसको कौन-सी चक्की का आटा खिलाया कि दिल्ली से पर्ची आपकी आयी? किस-किसको कौन-कौन सी चक्की का आटा खिलाया कि पहली बार के एमएलए की पर्ची आयी?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ता की पहचान होती है। आपके यहां तो विभाग को बीच में ही छीन लिया जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ता की कद्र होती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट की कविता पढ़ना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में वाइंड-अप करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। एक कविता है सर। मैंने बनायी है।

नाकाम दावे लगातार, जनता करे हाहाकार,
सिर्फ झूठ का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार।
अपराध हुआ सीमापार, बच्चियों से बलात्कार,
बढ़ता महिलाओं पर अत्याचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार।
नौकरी की आस में युवा लाचार, भत्ते को तरसे बेरोजगार,
कांग्रेस की भर्तियों पर वाह-वाही लूट का प्रचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार।
बिना एमएसपी किसान लाचार, टैक्स के कर्ज से हुआ बेजार,
हर ओर बिजली-पानी का इन्तजार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार।
मिली महंगाई अबकी बार, हुई कीमतें पहुंच के बाहर,
आम आदमी पर बढ़ता भार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार।
25 लाख के इलाज की पुकार, बिना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमार,
अस्पतालों में गन्दगी अपार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार।
मोदी मित्रों को दे व्यापार, भ्रष्टाचार पर करे करार,
पैट्रोल-डीजल से लूट का करोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार।
नफरत को बनाया हथियार, मंत्री करे दुष्प्रचार,
बालाजी से पानी की गुहार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार।
कुर्सी को लेकर बढ़ी तकरार, स्पीकरों का नाटक बार-बार,
न जनता से कोई सरोकार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार।
अफसरों के लगे दरबार, जनता के नुमाइन्दे लगाएं कतार,
गुजरात मॉडल ने किया शर्मसार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार।
न कल्याण का कोई विचार, न मर्यादा, न संस्कार,
भाषा में छिटकता संस्कार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार।
प्रोपेगंडा को बनाये हथियार, असत्य और जुमलों की भरमार,
बन गया सर्कस, बनायी थी सरकार,
ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने बच्चों का बेड़ा गर्क करने का ठेका लिया है,
ऐसी निकम्मी सरकार।।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री गोपाल शर्मा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जो पर्ची सरकार है न...

श्री अध्यक्ष: हो गया माननीय डोटासरा जी। अब अंकित नहीं। अब अंकित नहीं। बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका, आप विराजें। 32 मिनट हो गये हैं 30 की जगह। हो गया आपका।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: आपको पांच मिनट दे दिये दो की जगह। कविता हो गयी। अब अंकित नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): सावधान।

श्री अध्यक्ष: अब अंकित नहीं होगा। आपका भाषण समाप्त हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): डोटासरा साहब, आप रहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): +++

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: दोनों बैठिये। डोटासरा जी और माननीय मंत्री, दोनों बैठिये। ...(व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे-कैसे मंत्री +++ की बात कह रहा है? कोई सुप्रीम पावर है क्या मंत्री? कानून से ऊपर है क्या मंत्री? जो मर्जी कहेगा? ऐसे-कैसे कह रहा है? ...(व्यवधान) ये बेलगाम हो रहे हैं। जो मर्जी बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपका हो गया। अब आप बैठिये। ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): धमकी दे रहे हैं क्या? +++...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवेरे से आपको ज्यादा करंट आ रहा है क्या? ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: +++

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह एक्सपंज कराएं, सर, ऐसी बातें कह रहे हैं ये। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: +++ ...(व्यवधान)

सदन कूप में

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश)

श्री अध्यक्ष: यह बर्दाश्त नहीं होगा। जाइये उधर। उधर जाओ। I will name You, Mr. Rohit Bohra. बाहर निकाल दूंगा अभी। वैल में से जाइये। वैल में से जाओ। ...(व्यवधान) नहीं जाओगे तो मैं भी निकाल दूंगा फिर। आसन का कहना नहीं मानोगे, मैं इलाज कर दूंगा। ...(व्यवधान) नहीं जाओगे? क्या घर की खेती है क्या ये? सदन की मर्यादा है। तमाशा कर रहे हैं। सब सदस्यों से निवेदन है कि अपनी सीटों पर बैठिये। मैंने नाम पुकार लिया है। ...(व्यवधान) मारने आये हो क्या? बैठिये, बैठिये। ...(व्यवधान) आपको इसलिए बोलने दिया था क्या? माननीय विपक्ष के नेता, कंट्रोल करिये। नहीं तो इनमें से एक भी नहीं बोल पायेगा आज। एक भी नहीं बोल पायेगा यदि यही हालत रही तो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, जिस प्रकार की बातें मंत्री जी यहां कह रहे हैं, मंत्री +++ कैसे भेज सकते हैं? ये कोई कानून से ऊपर हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: यदि यह हाल रहा तो एक भी नहीं बोल पायेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप एक्सपंज करवाइये।

श्री अध्यक्ष: चलिये, गोपाल शर्मा। शुरू करिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): विद्वान स्पीकर साहब, मैं आपका अभिनन्दन करता हूं कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका पूरा हो गया। मैं इसकी जांच करूंगा। आप बैठिये। यह मेरा काम है। मैं पूरी कार्यवाही को देखूंगा और न्याय करूंगा। ...(व्यवधान) आप नहीं बोलेंगे। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): सितम भी सहना, दुआ भी करना... ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तमाशा बना रखा है सदन को। यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह सदन है। ...(व्यवधान) यह मेरा काम है, मैं देखूंगा। मैं इसकी पूरी समीक्षा करूंगा और कोई भी असंसदीय शब्द या बात होगी, उसे हटा दिया जायेगा। गोपाल शर्मा, बोलिये। ...(व्यवधान)

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): हो गयी व्यवस्था। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा आपके सहयोगियों को। आपके नेता आगे खड़े हैं। आप नेताओं के भी नेता हो क्या? आपके नेता को आपने चुना है, मैंने नहीं। जब नेता को चुना है तो उसके कहने में रहो, उसके कंट्रोल में रहें। बहस करेंगे, उसके बाद फिर मैं भी नियमानुसार कार्रवाई करूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, हम आसन का भी सम्मान करते हैं, आपका भी करते हैं, मंत्री जी ने जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की है, जो असंसदीय है, वह आप हटावाइये।

श्री अध्यक्ष: जो भी होगी, कोई भी गलत बात होगी तो मैं उसे हटाऊंगा। कोई भी गलत बात होगी, हटाऊंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: मैं शाम से पहले दे दूंगा। मैं व्यवस्था, पढूंगा, उसको देखूंगा। असंसदीय अथवा अनियमित कोई भी बात होगी, उसे हटाऊंगा। जो भी नियमों में नहीं होगा, उसे हटाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: बोलिये, अब टाइम शुरू हो गया है।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय विद्वान स्पीकर साहब का अभिनन्दन, उन्होंने बोलने का अवसर दिया।

सितम भी सहना, दुआ भी करना,
गया बेकसी का वो जमाना,
अगर है जुर्रत, गिराओ बिजली,
बना रहे हैं हम आशियाना,
कुछ मासूम हैं और जिद है बिजलियां गिराने की,
उधर हमें भी है धुन विकसित राजस्थान बनाने की।
इन्होंने तो डाल दी थी काली चादर पूरे राजस्थान पर,
डाल दी थी काली चादर पूरे राजस्थान पर,
इस खुशनुमा बजट की सड़क सुहानी सुबह तक जाती तो है।।

अध्यक्ष महोदय के बहाने आदरणीय डोटासरा साहब से प्रार्थना है कि आपकी विद्वता पर नहीं जाऊंगा, इसलिए कृपया माफ करें। आय-व्ययक वित्त प्रबन्धन, उचित आवंटन और प्रगति के सोपान के ऊपर कदम, ये हैं राजस्थान के 2024-25 के बजट के निहितार्थ।

कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से असम अपनी आजानबाहु फैलाए

(श्री गोपाल शर्मा)

भारत माता के चरणों में यह अभिनन्दन पत्र भी है। यह अमृत बजट है। राजस्थान और देश की आजादी का ढिंढोरा पीटने वालों को पता नहीं होगा कि यह राजस्थान के निर्माण का 75वां वर्ष है। इस नाते यह जो बजट है, यह अमृत बजट है।

मैं आज के इस अवसर पर माननीय श्री नाथूराम जी मिर्धा को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने पहला बजट दिया था और कहा था, दूसरे पैराग्राफ में, मुझे तकलीफ है कि मैं सेवाओं की ज्यादा घोषणा नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तकलीफ है कि मेरा बजट नीरस है, मुझे तकलीफ है कि मैं जितना करना चाहता था, उतना नहीं बोल पाया हूं। दूसरी तरफ, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी इस नीरसता को मजाक में उड़ा रहे हैं और परिणाम क्या निकला कि नाथूराम जी एक बार बजट पढ़ पाये वित्त का, दूसरी बार वित्त मंत्री नहीं रहे।

(समय: 15.01 बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

अगली साल जय नारायण जी व्यास ने पढ़ा। जो आप कहना चाह रहे थे, उससे ज्यादा अच्छा कहूंगा, जो आप कह सकते हैं उससे ज्यादा अच्छा कहूंगा। दूसरी बार जय नारायण व्यास जी ने पढ़ा तो उनको नहीं पढ़ने दिया, अगली बार। जय नारायण जी कांग्रेस की बुराई के अन्दर से निकल पड़े। नाथूराम जी नये दल में शामिल हो गये। तीसरी बार टीकाराम जी पालीवाल ने पढ़ा तो हमारे शान्ती धारीवाल जी को याद होगा कि जनता पार्टी के वे अध्यक्ष बने थे। यह कहानी है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अब जो वित्त मंत्री हैं, उनका क्या होगा?

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): वह भी बताऊंगा, धारीवाल जी। मैंने 40-45 साल से आप लोगों को सुना है। आज आमना-सामना है। बजट पेश करने वालों की कहानी यह है, हीरालाल शास्त्री जी हटाये गये, जय नारायण जी व्यास हटाये गये, मोहन लाल जी सुखाड़िया हटाये गये, हरिदेव जोशी जी हटाये गये, एक खाली अशोक गहलोत जी निकले, जिन्होंने जादू दिखाकर अपने नौजवान नेता का पासा पलट दिया और इसके लिए धारीवाल जी को प्रणाम करता हूं।

इस बजट के अन्दर विश्व के नेता माननीय नरेन्द्र मोदी जी का

(श्री गोपाल शर्मा)

मार्गदर्शन है। हमारे कर्मठ, समर्पित, किसान पुत्र भजन लाल जी का नेतृत्व है और विजनरी उप मुख्य मंत्री वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी का संकल्प है। मातृ शक्ति के साथ पैरों में अंगद का बल लिये, राजस्थान राष्ट्र की आन-बान -शान का प्रतीक फिर बनने जा रहा है। यह जो बजट है, इसमें भारतीयता की खुशबू है और राजस्थान की परम्परा है। रूजवेल्ट, नेल्सन मंडेला, ये बजट के नाम ले रहा हूं, बजट पर चल रहा हूं, बजट पर बोल रहा हूं, आपको पता नहीं है, रूजवेल्ट, सिसरो, नेल्सन मंडेला, मिर्जा इस्माइल, कोफी अन्नान, ये कहां से गहलोत साहब पिछली बार बजट पढ़ते समय ले आये, जो अभी तक पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। जिस मिर्जा इस्माइल के कमरे में घुसकर एक नौजवान ने अपने को गोली मारकर आत्महत्या की। आपने बजट पढ़ा नहीं है, जैसे आपने वीर सावरकर को नहीं पढ़ा है। आपको पता नहीं है कि 1927 में गांधी जी ने जाकर सावरकर जी के पैर छुए थे, आपको पता नहीं है। कहेंगे तो पन्ना दिखा दूंगा, रिकॉर्ड दिखा दूंगा। आपको तो यह भी नहीं पता है, संविधान को लेकर नारे लगाते हैं, यदि ये बता दें कि संविधान सभा में राजस्थान से कौन-से सदस्य थे, तो मैं मान जाऊं कि इनको कांग्रेस का अध्ययन है। ये अशोक गहलोत जी के तीनों नाम बता दें तो मान जाऊं, ये राजेश पायलट जी का पूरा नाम बता दें तो मान जाऊं। मैं तो बिलकुल स्पष्ट रूप से एक-एक नाम लेकर आपसे कह रहा हूं, पूर्व शिक्षा मंत्री जी...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बजट के पेज नम्बर 30 पर, विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल द्वारा जयपुर की प्लानिंग से हम प्रेरणा लेकर शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास के लिए कटिबद्ध हैं। इनके बजट में है, यह दिया कुमारी जी के बजट में है।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): हां, इसको बदल देंगे। मिर्जा इस्माइल की जगह गोविन्द देव मार्ग रहेगा, बैठ जाइये। मिर्जा इस्माइल को निकाला गया था मैसूर से, आपको पता नहीं है।

श्री सभापति: कृपया बोलने दीजिये। आप विराजें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मैंने ये कहा आपसे। माननीय सभापति जी के माध्यम से कह रहा हूं, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं। जब से राजस्थान बना है, तब से शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान राजस्थान ने कब प्राप्त किया, किसके नेतृत्व में प्राप्त किया, अगर आप यह बता दें तो मैं मान जाऊं। आपको नहीं पता, बैठ जाइये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर देखिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): बैठ जाइये, आपको जानकारी नहीं है। आप राजनीति में निष्णात हैं और ज्ञान में अज्ञात हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर देखकर बोलें। साहब, आप शान्त रहें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बजट नहीं दिया है। इतिहास गवाह है कि उसने जनता के हक की सदैव लड़ाई लड़ी है। जब कानून बनाये जा रहे थे, जमीन के कानून, तो भारतीय जनसंघ ने नारा दिया था कि 'जमीन उसकी, जोते जिसकी'। जब देश के सामने अर्थव्यवस्था का संकट था, विदेशों से उधार ले लेकर काम चलाया जा रहा था, लोग अपनी सड़ी-गली चीजें हमको भेज रहे थे, तब जनसंघ ने नारा दिया, 'हर हाथ को काम, हर खेत को पानी'।

माननीय सभापति महोदय, जिस समय खाली खजाना, दौड़ रहे चूहे, पहली बार कहा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं और लास्ट में स्थिति यह आई कि क्या मैं जिला दे दूं, क्या मैं जिला दूं? तो हमारे एक नेता जी जो सामने बैठे हैं, दे दो साहब, दे दो साहब, दिया-दिया, न कोई फाइल, न कोई रिकॉर्ड, न कोई सर्वे, जिला दे दिया। हमारे दो विधायक पहुंचे और बोले कि लड़ाई में एक लड़का मर गया, बोले, मैं क्या करूं, हॉस्पिटल में दिखाओ। जूली जी आप सुनिये, आप लोग तो जूडो मास्टर हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपके पीछे शंकर जी बैठे हैं। एक बार उनसे जिले की पूछ लो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): जूडो मास्टर, जूली जी और डोटासरा जी। उन्होंने कहा अस्पताल में दिखाओ, तो हमारे एक वरिष्ठ विधायक ने कहा कि वह तो मर गया, बोले मर गया तो क्या करें, तो क्या करें, बोले कि 50 लाख रुपये दे दो, दे दिया, ले जाओ। किससे पूछा, कमाकर लाये थे? कोई खेती है आपके, कोई जादू के नोट थे दे दिया। राजस्थान के बजट का इस तरह से मजाक उड़ाया गया। जब अलमारियों में सोना रखा हो। सभापति महोदय, करोड़ों के नोट निकलते हों और आप ईमानदारी की बात करेंगे! आप बजट की बात करेंगे। बजट तो वहीं खत्म हो गया, जब सिर्फ खाना सीख गये और खाना ऐसा कि हर चीज हजम हो रही है।

सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं, आप किस बजट की बात करेंगे। पट्टे के पट्टे खत्म। एक पूर्व मंत्री, मैंने नाम नहीं लिया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 16 मिनट में एक शब्द बजट पर नहीं है। ये बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): उस पर भी आऊंगा। अभी आऊंगा, सुनिये। अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। बजट के ऊपर ही सारा चल रहा है। ऐसा हो बजट, समझ में आये झट।

डोटासरा जी क्या बोलेंगे, सभापति महोदय, जिस व्यक्ति ने राजनीति के अलावा कुछ पढ़ा नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बजट से इसका क्या लेना-देना है, इसीलिये सर्कस की सरकार है यह।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): जिसको ज्ञान नहीं हो, ... (व्यवधान) आप बैठिये तो सही। भजन लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में नया आत्मविश्वास आया है बजट के रूप में। यह उस धरती पुत्र की यात्रा की शुरुआत है जिनके नेतृत्व में कितने ही स्वर्णिम अध्याय लिखे जाने हैं। देखते जाइये। इस बजट में मुस्कुराता हुआ राजस्थान है जो मुस्कान धारीवाल जी से ही सीखी है हम लोगों ने। आशा और विश्वास से लकदक, सामर्थ्य और संकल्प से भरपूर। मैं जानना चाहता हूं, सभापति महोदय, कम से कम तीस बजट भाषण सुने हैं ऊपर से। आदरणीय धारीवाल जी भी रहे हैं, ये बतायें कभी इस तरह का प्रतिपक्ष देखा है, कभी देखा है? भैरोंसिंह जी खड़े होते थे तो लगता था कि कोई सिंह खड़ा है। आज खड़े होते हैं तो लगता है पता नहीं क्या बोलेंगे। उनको ही नहीं पता।

सभापति महोदय, खाटूश्याम जी की बात चार-पांच सदस्यों ने रखी। खाटूश्याम जी के आस-पास से आने वालों ने रखी है कि उनके लिए सौ करोड़ क्यों? उनको पूछिये, आप जानते हैं एफिल टावर पर साल भर में कितने लोग जाते हैं? नहीं पता आपको। आपको नहीं पता है, लेकिन खाटूश्याम जी में प्रतिदिन पांच हजार लोग जाते हैं, एकादशी को एक लाख लोग जाते हैं और मेले पर दस लाख लोग जाते हैं। ऐसा तीर्थस्थल अगर राजस्थान में हो और उसको हम तिरुपति बालाजी की तरह से नहीं बढ़ाना चाहें तो हमारा दुर्भाग्य है। आप कहें कि ठीक है, डोटासरा जी के घर के बगल में एक ऐसा भी आदमी रहता है जिसके पास रहने का पूरा ठिकाना नहीं है, लेकिन क्या वह कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता है, नहीं हो सकता। वह खाली यह कर सकता है कि इनको वोट नहीं देता और वह नहीं देता है।

माननीय विद्वान सदस्यों, 2023-24 में हमारी राजस्व प्राप्ति 2.33

(श्री गोपाल शर्मा)

लाख करोड़ थी जो 2024-25 में बढ़ करके 2.64 लाख करोड़ होने जा रही है और पहली तिमाही, यानी जनवरी से लेकर के मार्च तक उस राजस्व प्राप्ति के अन्दर बढ़ोतरी हुई है तो मैं प्रभु से यह कामना करता हूं सभी सदस्यों से मिल कर के कि हम लोग इस बार ऐसे बजट की सफलता की कामना करें कि जो राजस्व घाटे का अनुमान किया गया है जो कि 2023-24 के राजस्व घाटे के लगभग बराबर है, उसको पार करके हम राजस्व अधिशेष की तरफ बढ़ सकें। इसके लिए मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, कि जो भ्रष्टाचार में पैसा लगता आया है, जो रिश्वतखोरी और दलाली में लगता आया है, क्या उसका अनुमान लगा करके हम राजस्व की बढ़ोतरी में कुछ मदद राजस्थान की कर सकते हैं क्या?

सभापति महोदय, जो बजरी माफिया की बात करते हैं, मैं तो इन लोगों के नाम नहीं जानता, लेकिन इन लोगों का गिरेबान पकड़ कर क्या कुछ राजस्थान की मदद कर सकते हैं क्या? जब सरकार ने यह जिम्मेदारी ली है कि हम बजरी का कुछ खनन करेंगे तो उसको हम कहां तक ले जायेंगे। जैसे कि गणेश मन्दिर के ऊपर पैसा खर्च करने की बात आयी तो मैंने जानना चाहा कि कौनसा गणेश मन्दिर है।

सभापति महोदय, इसी तरह से मेरा यह निवेदन है कि विश्व की टॉप दस अर्थव्यवस्थाओं में शामिल फ्रांस और इटली की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या हमारे राजस्थान की है। इंग्लैंड और इटली से ज्यादा जमीन हमारे पास है। बहुत से विषयों में इजरायल से हम आगे हैं। यह बजट का विषय है। आदरणीय डोटासरा साहब, 350 बिलियन डालर की ...(व्यवधान) आदरणीय सदस्य हमारे गांव के होकर के वो विरोध कर रहे हैं, वोट नहीं मिलेंगे। मेरे गांव के हैं। मेरा विरोध करेंगे, वोट नहीं मिलेंगे। बैठ जाइये। ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये सब मजे ले रहे हैं आपके, आप समझ नहीं पा रहे हो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय सत्ता पक्ष के सदस्य और माननीय प्रतिपक्ष के विद्वान सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए कि हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था की नीति के मूलाधार बदलने जा रहे हैं। अपने राजस्थान के इकोनोमिक रिव्यू 2023-24 के मान्यता प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस समय राजस्थान का जो कृषि सेक्टर है उसका 26.72 प्रतिशत योगदान है। मतलब

(श्री गोपाल शर्मा)

पौने सत्ताईस प्रतिशत योगदान है हमारे कृषि सेक्टर का जिसकी वैल्यु 3.81 लाख करोड़ रुपये है और यह सिर्फ 9.64 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है। राजस्थान में हमारे कृषि क्षेत्र की जो स्थिति है वह यह है कि 9.64 प्रतिशत की दर से विकास, वैल्यु 3.81 लाख करोड़।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 2023-24 तो कांग्रेस का है ...(व्यवधान)

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): बैठिये-बैठिये। उम्र का प्रभाव आना स्वाभाविक है और...

श्री सभापति: अपनी बात दो मिनट में पूरी करें, माननीय सदस्य। आप विराजें, साहब।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): इतनी गम्भीर बात को नहीं बोलने देंगे ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 2023-24 का आंकड़ा है ...(व्यवधान)

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): क्या 2023-24 का आंकड़ा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। दो मिनट रह गये हैं, उनको बोलने दें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): चार दिन पहले आया है चार दिन पहले, आपको तो पता ही नहीं होगा, चार दिन पहले के आंकड़े बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं चार दिन पहले के।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): ...(व्यवधान) आपसे ज्यादा उम्र है, ज्यादा अनुभव है। ...(व्यवधान)

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): उसके लिए चरण छूने को तैयार हूं।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): अगर उम्र से अक्ल आती तो राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता नहीं होते, आपको बना देते। ...(व्यवधान) जूली जी प्रतिपक्ष के नेता नहीं होते। ...(व्यवधान) बैठिये।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है?

श्री सभापति: आप बोलिये। बस हो गया समय आपका।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): नहीं, ऐसा नहीं। मैं बात बोल रहा हूं। मेरे को टोका जा रहा है।

श्री सभापति: आप विराजिये। बस हो गया, उनका समय हो गया। आप विराजिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): बोलने ही नहीं दे रहे हैं, क्या बोलूं मैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस सदन की गरिमा है। आप कुर्सी पर बैठे हो। यह क्या है, कहां से आ गये, क्या बोल रहे हैं? सदन की गरिमा को तार-तार मत करो।...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपका समय पूरा हुआ। आप विराजिये प्लीज। आप विराजिये। आप भी विराजें। आपका समय पूरा हुआ। श्री शान्ती धारीवाल साहब।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मैं तो अपनी बात ही नहीं कह पाया। एक मिनट तो दे दें। ...(व्यवधान) एक मिनट बोलने दीजिये। धारीवाल साहब, एक मिनट।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): एक मिनट। केवल एक मिनट। 'कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते-गाते चिल्लाने लगे हैं। वो सलाखों के करीब आये तो, कायदे-कानून हमको समझाने लगे हैं। थोड़ा आराम करो, ...(व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ...(व्यवधान) कमल के फूल मुरझाने लगे हैं ...(व्यवधान)

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): थोड़ा आराम करो मेरे नाखुश दोस्तों, तुम्हारे चेहरे को देख कर ...(व्यवधान) लोग कुम्हलाने लगे हैं।'

श्री सभापति: विराजें। श्री शान्ती धारीवाल जी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, आपको इस आसन पर देख कर मन प्रसन्न होता है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जारी रखें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): और कुछ नहीं मिला तो कम से कम इस आसन को तो सुशोभित कर ही रहे हो।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय धारीवाल साहब, आप इनको अपना उत्तराधिकारी और घोषित कर दो।

श्री सभापति: आप तो अपना भाषण बोलें जो आप पढ़कर आये हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, इस बजट में 10 संकल्प लिये गये हैं और 10वां संकल्प गुड गवर्नेंस का है। गुड गवर्नेंस में आपने परफोर्म बता दिया, रिफोर्म बता दिया और ट्रांसफोर्म बता दिया। जहां तक परफोर्मेंस की बात है तो 8 फरवरी को पहला बजट आया, उसके ठीक तीन महीने बाद लोक सभा का चुनाव आ गया। उस लोक सभा के चुनाव में जो 11 सीटें आप पिछली दो बार से बराबर जीत रहे थे, वह 11 की 11 सीटें कांग्रेस ने आपके हाथ से छीन लीं, तो आपकी परफोर्मेंस तो दिख गई। मोदी की गारंटी भी हवा हो गई और आपका बजट भी हवा हो गया। एक मंत्री तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी खराब परफोर्मेंस की वजह से यहां आना ही बंद कर दिया। महाराष्ट्र में हमारे प्रधान मंत्री जी ने 17 रैलियां कीं और 17 रैलियों में 14 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई। राजस्थान में आठ जगह पहुंचे और आठ में से सिर्फ तीन सीट ले पाये, बाकी पांच सीट कांग्रेस की आ गईं। यह आपकी परफोर्मेंस रही। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: शांत रहो, यह महाराष्ट्र का बजट है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): बल्कि शरद पवार जी ने तो यह कहा कि प्रधान मंत्री जी कृपया महाराष्ट्र के विधान सभा के चुनावों में भी पधारना, ताकि हम आसानी से जीत जाएं और आपका सूपड़ा साफ हो जाये।

श्री सभापति: आप तो राजस्थान पर पधारें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): रिफोर्म में चीफ सेक्रेटरी साहब जगह-जगह जाकर हाजिरी रजिस्टर चैक करते हैं और मोबाइल से फाइल के फोटो खींचते हैं। नतीजा कुछ नहीं निकला, फाइलें पैंडिंग की पैंडिंग पड़ी हुई हैं और लोग धक्के खा रहे हैं, उनके कोई काम नहीं हो रहे, यह रिफोर्म आपने किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में जन सुनवाई चालू की थी, दो रोज चली और तीसरे रोज उन्होंने कहा कि कौन जूते खायेगा, हम तो नहीं जाएं, वह बन्द करनी पड़ी।

ठीक इसी तरह ट्रांसफोर्म की बात है। ट्रांसफोर्म में शासन की बागड़ोर मुख्य मंत्री के हाथ में होनी चाहिये, मंत्रियों के हाथ में होनी चाहिये, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। सारे ब्यूरोक्रेट जो यहां पर बैठते हैं, असल में शासन

(श्री शान्ती धारीवाल)

पति तो वह हो रहे हैं। सारे काम दिल्ली से हो रहे हैं। सी.एस. सीधा रिपोर्ट भेजता है और वहां से हुक्म आता है और उस हुक्म की पालना आप लोगों को झक मार कर करनी पड़ती है।

जैसा अभी डोटासरा साहब ने 70 हजार करोड़ रुपये का राजकीय घाटा बताया, उसको पूरा करने के लिये लोन लेना पड़ेगा। आप कहते हो ना कि लोन लिया, सन् 1952 से लेकर 2014 तक जितनी भी सरकारें रहीं, ज्यादातर कांग्रेस की रहीं, कुल मिलाकर देश पर 55 लाख करोड़ रुपये का कर्जा लिया था। 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों में आपने 112 लाख करोड़ रुपये का कर्जा लिया।

चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने एन.डी.टी.वी को इंटरव्यू दिया था ...(व्यवधान) मैं बिलकुल ठीक हूं, आपकी बड़ी मेहरबानी है और आपको देख कर तो वैसे ही प्रसन्नता आ जाती है, मजा आ जाता है। ऐसा खूबसूरत चेहरा कहां देखने को मिलता है। ...(व्यवधान) गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी ने 4 जून के लिये एक इंटरव्यू दिया कि 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है वह शेयर मार्केट को एक दम बूम करेगा, जिसको लगाना है, लगा दो। लोगों ने लगा दिये और लोग 30 लाख करोड़ रुपये के नीचे आ गये। ये दोनों तो शेयर ब्रोकर हो गये। शेयर ब्रोकर होकर जनता को लूट दिया, जनता को धोखा दे दिया।

वित्त मंत्री जी ने हैरिटेज पर 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। आदरणीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैंने 15 साल इस डिपार्टमेंट में काम किया है, 100 करोड़ रुपये में तो आपके चांदपोल, किशनपोल, त्रिपोलिया और जौहरी बाजार की सड़कें भी नहीं बनेंगी। स्वच्छ भारत के लिये 608 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा। 608 करोड़ रुपये में 12,300 घरेलू शौचालय बनाने के लिये आपने लिखा है जबकि हमने पिछले साल 1324 करोड़ रुपये के 40 हजार घरेलू शौचालय बनाने के लिये प्रोविजन किया था। ...(व्यवधान) अभी आप जानकारी लो, उसके बाद बताना।

वित्त मंत्री जी, आपने पंचायतों की आय और नगरपालिकाओं की आय किस प्रकार से बढ़ सकती है, उसके बाबत बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया, जो कि सबसे गंभीर बात है। आज अर्थ के अभाव में नगरपालिकाएं विकास नहीं कर पा रही हैं, पंचायतें विकास नहीं कर पा रही हैं। किस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़े, इस पर आपका सोच होना चाहिये था।

(श्री शान्ती धारीवाल)

इंदिरा रसोई को आपने अन्नपूर्णा बता दिया और नतीजा कुछ नहीं निकला। राजस्थान में आज 9 महीने से भी उनका पेमेंट नहीं हुआ है। बेरोजगारी कम करने के लिये 'इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना' अशोक गहलोत साहब ने चालू की थी। उसमें एक साल में 650 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा था, आपने 300 करोड़ रुपये कर दिया। एकदम 350 करोड़ रुपये घटा दिया। आजीविका मिशन में 2000 स्वयंसेवक समूह को रिवॉल्विंग फंड प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, हमने 3000 का लक्ष्य रखा था। स्ट्रीट वेंडर्स के बाबत आपने कुछ नहीं बताया कि क्या काम करोगे, कितना पैसा दोगे, इस बात का बजट में कोई उल्लेख ही नहीं किया।

एच.पी.सी.एल. की रिफाइनरी के लिये हमने 1244 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा था और आपने उसको घटाकर 1087 करोड़ कर दिया। 'मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' में 5200 व्यक्तियों के ब्याज के अनुदान के लिये आपने लिखा है, जबकि हमने पिछले साल 7000 का प्रोविजन रखा था। इसी तरीके से 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के बाबत डेढ़ लाख रुपये वे लोग देते हैं। पहली बार राजस्थान की सरकार ने 25 हजार रुपये देने का तय किया, पौने दो लाख रुपये हो गये। अब यह बता दो कि पौने दो लाख में क्या दो कमरे, एक बाथरूम, एक किचन बन जायेंगे? नतीजा यही है कि जिस प्रकार से यह आवास योजना चल रही है, उसी तरीके से धक्के से यह चलती रहेगी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इंदिरा आवास ध्यान है, कितना मिलता था?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): वह मुझे याद नहीं है, मैं प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहा हूं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 325 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, आपने उसको घटाकर 112 करोड़ कर दिया। 2020 में हमने एमएसपी पर कानून बनाया, उस कानून को केन्द्र सरकार ने आज तक मंजूरी नहीं दी। इसका जिम्मेदार कौन है? 700 किसान मर चुके, कुछ तो दया करो किसानों के प्रति। गेहूं खरीदने की बात कर रहे थे कि हम 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे, उससे मुकर गये। आप गोमाता की रक्षा की रक्षा की बात करते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): 2700 ही करेंगे, शुरुआत कर दी है। 2400 कर दिया है। पांच साल के लिए 2700 था। आप एक साथ मत मानें, 2700 करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैं एक साल की बात कर रहा हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्या यह लिखा है कि हम टुकड़ों में करेंगे? देखो, यह नोट हो रहा है। आप बता दो, आपने कहा कि चरणबद्ध रूप से.. ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): संकल्प है, पांच साल का। 2400 कर दिया है, 2700 करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने 2700 कहा था, 2400 ही किया। अब आप बैठ जायें, धारीवाल जी को बोलने दें, डिस्टर्ब मत करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मैं तो परमिशन से। ये हमारे सीनियर हैं, हमारे ऊपर इनकी बड़ी मेहरबानी है और रहेगी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 20 लाख टन गेहूं खरीदना था, सिर्फ 8 लाख टन गेहूं खरीदा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): उनको रोको, धारीवाल साहब, उनको रोको, उनको बीच में थोड़ी आदत है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वे तो धारीवाल जी के साथ ही हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): धारीवाल जी हमारे साथ हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): हम गोमाता की बात करते हैं। सरकार ने तो अपने बजट स्पीच में, गोमाता की रक्षा के लिए लोन देने के लिए भी कहा है। मैं इस बात की तारीफ करता हूं, लेकिन कत्लखाने तो चल रहे हैं, जगह-जगह कत्लखाने चल रहे हैं, उनको तो रोको। आप सुनें। बीजेपी के एक केन्द्रीय मंत्री +++ ने अपने लैटर हैड पर, तीन किलो गोमांस बांग्लादेश ले जाने के लिए अपने लैटर हैड पर परमिट जारी कर दिया, बीएसएफ के चीफ कमाण्डर के नाम पर। आप बताइये, एक तरफ गोमाता की रक्षा की बात करते हो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह फोटो कॉपी है। आप मदद करो, कत्लखाने का विषय गंभीर है। पक्ष-विपक्ष दोनों मिलकर करें तो इस पर गंभीरता से विचार-विमर्श भी हो सकता है। ...(व्यवधान)

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): हमारे करने से कुछ नहीं होगा। सरकार तो आप लेकर बैठे हैं। आप उनको बन्द करो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हम कर देंगे। बिलकुल कर देंगे।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): कर क्या देंगे, इसका क्या करेंगे? जो केन्द्रीय मंत्री बीएसएफ कमाण्डर को लिखकर दे रहा है, तीन किलो गोमांस..,

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह इसका भाग नहीं है, यह फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी बनावटी होती है। कहीं भी बन जाती है। ...(व्यवधान)

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): यह पत्र है, यह उनका लैटर हैड है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके पास कैसे आ गया? आपके पास किस सोर्स से आया? मंत्री जी ने लिखा, बांग्लादेश गया, आपके पास कैसे आ गया?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अब आप बैठो तो सही, कुछ बोलने तो दो। आपके पास इसका जवाब तो है नहीं कि मंत्री के खिलाफ कार्यवाही के लिए प्रधान मंत्री जी से कहेंगे। आपको कम से कम यह तो कहना चाहिए। अगर गौ रक्षक हो, गौ को माता मानते हो तो यह आपका धर्म बनता है कि आप प्रधान मंत्री जी से कहें कि इस मंत्री को बर्खास्त करें।

गोविन्द देव जी का मन्दिर। हमने 100 करोड़ रुपये पिछली सरकार में रखे थे और उसकी डीपीआर तैयार कर दी थी। सारे नक्शे बन गये थे, सब कुछ बनने थे कि 100 करोड़ रुपये में हम इसका सौंदर्यीकरण करेंगे और वहां पर कॉरिडोर बनायेंगे, उसको गायब कर दिया। गायब क्यों कर दिया? यह किसका दबाव है? वहां पर दुकानदारों पर दबाव डालकर खाली करा रहे हैं, कौन करवा रहा है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी जगह पर बैठें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सरकार में बैठे हुए लोग इस सरकार का उस तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं। कायदे से तो रिलीजियस पर्यटन को बढ़ाने के लिए हमें डिग्गी कल्याण जी, सालासर जी, रामदेवरा जी, इनको डवलप करना चाहिए।

सभापति महोदय, बालिका जन्म लेती है तो उसके लिए सशक्त कदम उठाने के लिए हम प्रतिबद्ध रहते हैं कि बालिका का अच्छी तरह से पालन-पोषण करें और उसको बड़ा करें, शिक्षा-दीक्षा देवें। यह बात आपने भी अपने बजट में कही है। आपको ध्यान होगा, बाबा साहेब अंबेडकर ने 25 जुलाई,

(श्री शान्ती धारीवाल)

1927 को मनु स्मृति को आग लगायी थी। क्यों लगायी थी, आग? उस मनु स्मृति को, जो उस वक्त के काफी सालों तक बड़ी पोपूलर होती थी, बड़ी चर्चा होती थी और लोग उसकी अनुपालना किया करते थे, उस मनु स्मृति को बाबा साहेब ने आग लगायी थी। कारण मालूम करना चाहिए, कारण मालूम हुआ कि किसलिए आग लगायी? आग इसलिए लगायी गयी थी कि उस मनु स्मृति में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए अपमानजनक शब्द लिखे हुए थे। मैं उसके कुछ अंश पढ़कर सुनाता हूं। दो-तीन ही अंश हैं, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वह तो लंबी किताब है, मोटी किताब है।

एक महिला को, जो आजाद नहीं रहना चाहिए। आजाद रहने वाली महिला अपने पति और पिता, दोनों के कुल को कलंकित करती है।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): अभी जो महिलाओं का फैसला आया है...(व्यवधान)

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पब्बाराम जी, आप विराजें। दूसरी बात, महिलाओं की पुरुष के प्रति चाहत, महिलाओं का जल्दी बदलने वाला मन और स्वाभाविक हृदय हिंसा की वजह से पति के प्रति वह धोखेबाज हो सकती है। ऐसे में उनको बहुत संभालकर या बहुत निगरानी में रखना चाहिए। तीसरी बात पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना भी महिलाओं का स्वभाव है। यह लिखा हुआ है। उस महिला से विवाह नहीं किया जावे, जिसके बाल कम हों और ऐसी महिला जो नीची जाति की हो, उससे विवाह नहीं किया जाये, यह है, उस मनु स्मृति में। इस मनु स्मृति का जिक्र मैंने इसलिए किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के लोग इकट्ठे हुए। जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने एक सामूहिक प्रस्ताव पास किया कि मनु स्मृति को कानून की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब कि लॉ की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। आप देखिये मनु स्मृति को पढ़ाना चाहते हैं। वे कौन लोग थे? हालांकि इसके लिए वाइस चासंलर ने मना कर दिया कि नहीं, मनु स्मृति नहीं पढ़ायेंगे। बल्कि शिक्षा मंत्री जी ने भी मना किया। मैं इस बात को अच्छा मानता हूं। ये लोग कौन थे, जिन्होंने इस तरह का प्रस्ताव पास किया?

श्री सभापति: माननीय वरिष्ठ सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): ये लेक्चरर और प्रोफेसर्स कौन थे? ये वे लोग थे जो संघ से रिलेटेड थे। संघ से रिलेटेड लोग आज इस मनु स्मृति को लागू करवाना चाहते हैं। आपको याद होगा, कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हेगड़े ने कहा था कि हम संविधान बदलेंगे। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप बजट पर बोलें, गलत बात है, जो इस सदन का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। ...(व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): डिस्टर्ब मत करो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मंत्री जी, डिस्टर्ब नहीं करें। उससे सारी जगह आग लग गयी थी, एक बार कहने से। यह जो शुरुआत है कि मनु स्मृति को हम लॉ की पढ़ाई में पढ़ायेंगे। यह तो शुरुआत है। कहीं ऐसा नहीं हो कि संविधान की आग ने सरकार को बहुमत नहीं लेने दिया, आप इससे निपट जायेंगे। सूपड़ा साफ हो जायेगा।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय,...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। आप समाप्त करें, साहब।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैं आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मनु स्मृति को अगर शिक्षा के सिलेबस में शामिल कर लिया गया तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि इस देश में आग लग जायेगी। मैं आखिर में एक निवेदन करना चाहता हूं। पोजिशन क्लीयर करना चाहता हूं। यूडीएच मिनिस्टर साहब।...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय,...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): यूडीएच मंत्री साहब।

श्री सभापति: आप अपनी बात समाप्त कीजिए, साहब।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): एक मिनट,...(व्यवधान) एक मिनट।

श्री सभापति: बैठिए, आप बैठिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): कालीचरण जी का एक काल अटेंशन मोशन था। माननीय यूडीएच मंत्री साहब, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, ये क्या बोल रहे हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप भी विराजिए ...(व्यवधान) आप भी बैठिए। आप विराजिए। आप समाप्त करें, साहब।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): हां साहब, एक मिनट। 1999 में जब ...(व्यवधान) ये सेन्ट्रल पार्क।

श्री सभापति: आप विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, इनको बैठाइए। ...(व्यवधान) ये क्या गदर मचा रखा है।

श्री सभापति: आप विराजिए। ...(व्यवधान) आप सुनते नहीं हैं क्या? विराजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी परमिशन लेकर बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) बैठ जाइए।

श्री सभापति: आप बोलिए, साहब। समाप्त करिए।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, ये बोल ...(व्यवधान) रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, इनको समझाइए। क्या गदर मचा रखा है? पिताजी से बड़ी उम्र के आदमी बोल रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजिए। आप भी विराजिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सन् 1999 में ये सेन्ट्रल पार्क सरकार के कब्जे में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जयपुर महाराजा हार गये। सुप्रीम कोर्ट ने हरा दिया उनको। हमने कब्जा कर लिया इस पर। जब हमने कब्जा किया, यूडीएच मंत्री साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, आप जरा करेक्ट हो जाओ, जो आपने जवाब दिया उससे। जब हमने कब्जा किया तो वहां पर पोलो का गेम भी चल रहा था और गोल्फ भी चल रहा था। अब उस खेल को हम छीन तो सकते नहीं थे, लेकिन हमने मीटिंग करके बाकायदा यह फैसला कर दिया, गोल्फ वालों को भी बुलाया और पोलो वालों को भी बुलाया। बुलाकर के उनसे सहमति ले ली इस बात कि की ये सारी जमीन जेडीए की रहेगी और पोलो क्लब भी जेडीए पोलो क्लब के नाम से चलेगा और गोल्फ क्लब भी जेडीए गोल्फ क्लब के नाम से चलेगा। यूडीएच सेक्रेटरी इसका प्रेसीडेंट रहेगा और जेडीसी इसका सेक्रेटरी रहेगा। यह बात सही है।

(श्री शान्ती धारीवाल)

आपने कहा कि साहब, एम.ओ.यू. नहीं किया। नहीं किया एम.ओ.यू., लेकिन समझौता हो गया था बाकायदा और समझौते पर दस्तखत है फाइलों पर। सब पर दस्तखत है, जिस पर गोल्फ क्लब वालों के भी दस्तखत हैं और पोलो क्लब वालों के भी दस्तखत हैं और अफसरों के भी सबके दस्तखत हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये गोल्फ क्लब वाले और पोलो क्लब वाले अतिक्रमण करने के आदी हैं। कई बार हमने इनके अतिक्रमण तोड़े हैं।

श्री सभापति: विराजिए, साहब। श्रीमती कल्पना देवी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): कई बार हटाएं हैं। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मुझे कम्प्लीट कर लेने दीजिए।

कई बार इनके हमने अतिक्रमण हटाएं हैं। आज आपने घोषणा की है। इन्होंने कहा कि वहां पर यूडीएच के जितने भी अफसर थे, वे सब मेम्बर बन गये। यह बात सही है। इसकी जांच करवाइए। जांच के लिए आपने कह दिया, बिलकुल जांच करवाइए। आप मेरी आखिरी बात सुन लीजिए। जांच करवा लेना आप और करवानी भी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप उन दोनों का।

श्री सभापति: विराजिए, सदस्य। मंत्री महोदय, आप कुछ कह रहे है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): न गोल्फ क्लब का बिगाड़ पाएंगे और न जेडीए पोलो क्लब का बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये आपको कुछ नहीं करने देंगे। याद रखना, कुछ नहीं करने देंगे।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अधिग्रहण की कार्यवाही के खिलाफ भी रिट याचिकाएं हुई हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब अधिग्रहण को वैधानिक मान लिया, उसके बाद वहां लगभग 40 हजार पेड़ और दूसरे कामों को लेकर जनहित याचिकाएं शुरू हुई। पोलो वाले भी गये और एक नहीं लगभग एक दर्जन के लगभग रिट याचिकाएं राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित रहीं, जिनमें से एक में डी.बी. ने फैसला सुनाया। उस फैसले पर आगे काम होता, उससे पहले वह मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया और सर्वोच्च न्यायालय में स्थगन हो गया। अब मुझे तो किसी से, 'न तो काहू से दोस्ती, न काहू से बैर', निष्पक्ष तो जांच हो जाए और भारत की न्याय व्यवस्था दोषी को जो दंड देना चाहे, वह दंड दे दे।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्रीमती कल्पना देवी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): वह तो ठीक है, आप कराइए, लेकिन फिर मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं आप कुछ नहीं कर पाओगे।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान) श्रीमती कल्पना देवी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: आप विराजिए, माननीय सदस्य। माननीय वरिष्ठ सदस्य, इस पर ध्यानाकर्षण में चर्चा हो चुकी है। अब बजट पर बहस का विषय है, इसको चलने दिया जाए।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजिए, माननीय सदस्य।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। कहते हैं कि-

'सपने नहीं हकीकत हैं बुनते,
इसलिए हम मोदी को चुनते।'

मैं हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं कि उन्होंने तीसरी बार केन्द्र में सरकार बनाकर इतिहास रचा है। यहां अभी बहुत सारी बातें हो रही थीं, इसमें मैं कहना चाहती हूं कि हम 'बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ' और महिला उत्थान की बात करते हैं, न कि महिला उत्पीड़न पर मुंह फेरते हैं। इस नारे पर 'बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ' हमें शायद यह भी जोड़ना चाहिए कि 'बेटों को सिखाओ'।

Sir, I want to start with a quote of Martin Luther King Jr., he said, "I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream." And in the same way, I didn't stop dreaming for Ladpura. 2019 में मैं जब पहली बार लाड़पुरा विधान सभा क्षेत्र से चुनकर यहां आयी थी, तब मैंने भी सपने देखे थे और मेरे क्षेत्र की जनता ने भी सपने देखें थे, परंतु पिछली सरकार की उदासीनता व राजनीतिक द्वेषता के कारण हमारे सपने अधूरे रह

(श्रीमती कल्पना देवी)

गये। मैं अपनी लाडपुरा की जनता-जनार्दन और कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने लाडपुरा से मुझे दूसरी बार नेतृत्व करने के लिए चुना और भरोसा जताया। I thank the Hon'ble Chief Minister Shri. Bhajan Lal Ji and Deputy Chief Minister Diya Kumari Ji for fulfilling some of my promises made to the people of Ladpura. हमारी सरकार आते ही आपने दो बड़ी सौगातें लाडपुरा को दी।

(समय: 15.48 बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

यहां बजट में इंटरिम बजट द्वारा ही सबसे पहले आपने 300 बेड का जिला अस्पताल दिया और एक महाविद्यालय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। यहां मैं कहना चाहती हूं कि ये दोनों अस्पताल एवं महाविद्यालय मेरे क्षेत्र में पहली बार आएंगे। इतने साल से एक भी कॉलेज नहीं था और एक भी हॉस्पिटल नहीं था।

इसी के साथ चम्बल किनारे बसे रंगपुर पंचायत के ग्राम गंगायचा का अस्तित्व बचाने के लिए आपने इस बजट में 10 करोड़ रुपये सुरक्षा दीवार में स्वीकृत करने की जो कृपा की, उसके लिए भी आपका आभार। इसके लिए मैं मेरे पत्रकार बंधु को भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिसने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए समय-समय पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया।

मैं पिछले पांच साल के कोटा के विकास कार्यों पर भी चर्चा करना चाहूंगी। पूर्ववर्ती सरकार ने कोटा के विकास को राजनीतिक रूप देकर पार्टी विशेष के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र की कार्ययोजना बनायी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र का काफी हिस्सा शहरी क्षेत्र में आता है। परन्तु इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई और जो भी कार्य किए गए वह मात्र केवल एक विधान सभा में किए गए।

मैं इस बजट की बात करूं। पेज 12 में हम देखते हैं कि इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर के महत्व को देखते हुए सड़क, पुलिया, फ्लाईओवर, एलीवेटेड रोड, आरओबी, आरयूबी के लिए लगभग 9 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। आपने इसमें लाडपुरा के खेडारामपुर में पुलिया के निर्माण के लिए भी 2 करोड़ 20 लाख रुपये दिए, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

(श्रीमती कल्पना देवी)

इसी के साथ, मैं एक मांग भी रखना चाहती हूं कि हमारी नोटाना की पुलिया है वह बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाती है। आपने पेज 29 में प्रावधान भी रखा है कि तूफान, अतिवृष्टि एवं समय पर रख-रखाव की कमी के कारण सड़क एवं पुलिया जो क्षतिग्रस्त हो गई है, उसके आपने 01 हजार 345 करोड़ रुपये रखे हैं, इसमें आपकी मेहरबानी होगी अगर आप नोटाना की पुलिया को भी इसमें जोड़ दें। जब बाढ़ आई थी तब यह क्षतिग्रस्त हो गई थी। बारिश के समय यह गांव टापू बन जाता है। वहां के लोग मेडिकल इमरजेंसी में भी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते और वहां काफी सारे ऐसे हादसे हो जाते हैं।

पेज 12 में ही आपने आरओबी की बात की है, मैं उसमें एक और मांग जोड़ना चाहती हूं। रोटेड़ा से सोगरिया पर बने रेलवे फाटक पर एक आरओबी की मांग करती हूं। यह फाटक जब बंद हो जाता है तो लोगों को लगभग 1 या 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है या बहुत लम्बा चक्कर काटना पड़ता है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे तो आपकी कृपा होगी।

अब बात करें बिजली पर। माननीय सभापति जी, अंग्रेज़ी में एक 'proverb' है, "As you sow, so shall you will reap", अर्थात जो बोएंगे वही काटेंगे। हमारे विपक्ष के सदस्य बिजली को लेकर जो शोर मचा रहे हैं, बोए पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। इन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कुछ भी खर्च नहीं किया। उल्टा डिस्कॉम को इतने घाटे में छोड़कर गए हैं, तो वह क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बिजली की स्थिति ठीक होगी। हमारी सरकार ने पहले बजट में विभिन्न क्षमता के जीएसएस की स्थापना के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें एक 400 केवी, तेरह 220 केवी, छत्तीस 132 केवी और सत्ताईस 35 के जीएसएस हैं। इसमें लाडपुरा क्षेत्र के अर्जुनपुरा नॉर्दन बाईपास के जीएसएस भी शामिल हैं। जिस ऊर्जा से ये कार्य होंगे, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बिजली की सारी समस्या दूर हो जाएगी और जनता को बिजली की समस्या से राहत मिलेगी।

It would be amiss of me, if I did not mention a special thank to the Hon'ble Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla Ji regarding the Airport. It is with his continued effort and perse-verance that the dream of an Airport for Kota is finally taking shape. This has been a long-long overdue requirement for Kota and as soon as our Government took over, within a month, मुझे

(श्रीमती कल्पना देवी)

लगता है कि शायद 20 दिन के अन्दर, the money for forest land diversion of 39 crores was deposited and power grid lines shifting was also sanctioned. पेज 45 के पांइट नम्बर 2 पर बजट में लिखा है, औद्योगिक नगरी कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। मुझे लगता है कि हम सब कोटावासियों के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इस बजट में होगी। इसी के क्रम में, I am proud to say that one of the biggest Krishi Mandi in Asia, Bhamashah Mandi is also located in Ladpura. On Pg. No. 101 another demand which has been pending since a long time has also been cleared. भामाशाह कृषि उपज मण्डी के विस्तार के लिए स्वीकृति मिली है।

अब आइये सिंचाई पर। हम किसान हित की बात करते हैं। हमारे विपक्ष के सदस्य चिल्ला रहे थे कि किसान के लिए क्या है, किसान के लिए कुछ भी नहीं है। किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और उत्पादन में लागत कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सिंचाई का पानी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावित किए हैं। आप पेज 94 में देखेंगे, चम्बल से लिफ्ट द्वारा सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाकर मण्डाना के लिए और आलानिया बांध से लाडपुरा के पंचायत अरण्डखेड़ा, गंदीफली, बनियानी, मवासा, जाखोड़ा पंचायत की सिंचाई के लिए, नहरों से पानी पहुंचाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए 2-2 करोड़ रुपये सैंक्शन करके माननीय मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी ने किसानों का हमदर्द बनकर दिखाया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मण्डाना एक डार्क जोन है। वहां बारिश के पानी पर निर्भर होने के कारण केवल एक ही फसल ले सकते हैं। वहां गर्मी के समय किसान फसल तो नहीं कर सकता, पर वहां पशुओं की क्या हालत होती है वह हमने देखा है। जब आलानिया बांध में बारिश की कमी से पानी कम होता है तो लगभग कोटा के 46 गांव ऐसे हैं जो सिंचाई के पानी से वंचित रह जाते हैं और पानी के लिए त्राहि-त्राहि मचती है। मैं धन्यवाद देती हूं पर मांग भी रखती हूं कि अभी भी लगभग 10 ऐसे गांव हैं जो सिंचाई के पानी से वंचित हैं, मेरी मांग है कि आप इनका भी ध्यान रखें। कालीसिंध पार्ट-टू या कोई भी दूसरे सिंचाई के पानी की योजना में इनको जोड़ा जाए। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्रीमती कल्पना देवी)

जल जीवन मिशन के बारे में क्या बोलूं। पिछली सरकार के समय इस योजना में कितने घोटाले सामने आए, यह सबको पता है। इस योजना के तहत पिछली सरकार ने केवल इस दुर्भावना से काम नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि अगर राज्य में हर घर में नल से जल मिलने लगेगा तो उसका श्रेय माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को मिलेगी। अगर राजनीति नहीं करते तो इस काम को टॉप प्रायोरिटी में रखते।

माननीय सदस्य अभी आंकड़ों में पता नहीं क्या कह रहे थे कि दूसरे नम्बर पर हैं। मैं उनको यह बताना चाहती हूं कि आज यह स्थिति है कि राज्य सूची में भी हम दूसरे नम्बर पर हैं, पर ऊपर से नहीं नीचे से। जल जीवन मिशन में हम सैकंड लास्ट आ रहे हैं। यह हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है।

अब एक और महत्वपूर्ण विभाग है चिकित्सा। मैं दोबारा 300 बैड हॉस्पिटल के लिए धन्यवाद देती हूं। आपने हर विधान सभा में मॉडल सीएचसी बनाने की घोषणा की है। कोटा के मेडिकल कॉलेज में स्पाइनल इंजरी सेंटर खोलने की भी घोषणा की है, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। एक गम्भीर समस्या है, जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूं। वर्तमान में केवल एक सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन मेडिकल कॉलेज में है, इसकी वजह से मरीजों में जांच कराने के लिए बहुत लम्बी वेटिंग होती है। ऐसी स्थिति है कि कई मरीजों की तो मृत्यु भी हो जाती है, तब तक उनका नम्बर आता है। मैं मांग करती हूं कि एमबीएस हॉस्पिटल में भी एक सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन दी जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): पेयजल की बात करे, जितना महत्वपूर्ण चिकित्सा है उतना ही महत्वपूर्ण शुद्ध पेयजल है। हमारे बजट में अमृत-टू योजना के अन्तर्गत 183 शहरों-क़स्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु लगभग 5 हजार 180 करोड़ रुपये के कार्य दो वर्ष में किए जाएंगे। 32 शहरी जल स्त्रोत जीर्णोद्धार के कार्य 127 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित हैं, इससे लाडपुरा के शहरी क्षेत्र के छावनी की पुरानी पाइप लाइन बदलने के कार्य एवं समस्त वॉर्ड में पानी की पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा।

अंत में मैं कहना चाहती हूं कि विपक्ष वाले इस बजट से क्यों इतना परेशान हैं। क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा व उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी इतना गजब का बजट पेश करेंगे, शायद उन्होंने इनको अंडर एस्टीमेट किया है।

(श्रीमती कल्पना देवी)

युवाओं को रोजगार के लिए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए, नौकरियों की बरसात की बात हो या महाविद्यालय खोलने की बात हो, हमारी संस्कृति को

(समय: 16.00 बजे)

बढ़ावा देने के लिए, धरोहर संरक्षण के लिए, हरियालो राजस्थान बनाने के लिए, एमएसएमई के लिए, डिफेंस मैनुफैक्चरिंग हब स्थापित करने के लिए, शहरी विकास हो या समाज और स्वास्थ्य हो, यहां हर वर्ग का और सबका ध्यान रखा गया है।

हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। हमारे मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन से राजस्थान एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए, यह जो बजट है, हमारी सरकार का जो रोड मैप है वह क्लियर है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान अग्रणी प्रदेश की श्रेणी में जल्द आयेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

सूचना

चांदीपुरा वायरस का राजस्थान में प्रवेश

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक वायरस है चांदीपुरा, जिसकी एंट्री गुजरात के रास्ते राजस्थान के अन्दर हो गयी है। दो संदिग्ध बच्चे, सुबह मिले हैं और उसमें से एक की डैथ हो गयी है। दूसरा गुजरात के अन्दर हिम्मत नगर हॉस्पिटल में एडमिट है।

मैं चाहूंगा कि आसन सरकार को निर्देश दे कि इस पर स्थिति स्पष्ट करे क्योंकि प्रदेश के अन्दर भय का माहौल है।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सभापति: श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के परिवर्तित अनुमानित बजट पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

(श्री श्रवण कुमार)

सभापति महोदय, 2-3 दिन से लगातार यह सुन रहे हैं और आपने भी यह भाषण में कहा था कि जो गुंडागर्दी करते थे, भू-माफिया थे, शराब माफिया थे, उन सबको खतम कर दिया है। मैंने जाकर गांवों में देखा तो एक भी मरा हुआ नहीं मिला। आपने कह दिया कि सबको खतम कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह इकतीसवां बजट पढ़ रहा हूं आज तक जिस भी सरकार ने, चाहे इस सरकार ने किया हो चाहे उस सरकार ने, इम्प्लीमेंट करने में 33 परसेंट से ऊपर नहीं पहुंचे हैं। आपके पास तो केवल महीने ही चार हैं, आप कहां से इम्पलीमेंट करोगे?

आपकी गुड गवर्नेंस के बारे में तो धारीवाल साहब ने बता दिया। मेरे पास 9 पास हैं। अभी कुछ देर पहले भाषण हो रहे थे कि पानी का बजट, बिजली का बजट, सड़क का बजट, अभी तक तो छह महीने में एक लोटा पानी का पिलाया नहीं। बातें करने से पेट भरता नहीं। अधिकारी आपकी बात मानते नहीं। तहसीलदार की पटवारी नहीं मानता, पटवारी की तहसीलदार नहीं मानता। कलेक्टर की एसडीएम नहीं मानता। मैंने मेरी 44 साल की राजनीति में इतना मुर्दा राज आज तक नहीं देखा, जिसमें कलेक्टर की एसडीएम नहीं माने, एडीएम नहीं माने। कलेक्टर खुद इस बात को स्वीकार करे कि भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है तो आप क्या कर रहे हो? What are you doing? बोलें, हम क्या करें?

मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि किसी के दिमाग में यह हो कि श्रवण कुमार भाषण देने के लिए खड़ा हो, नो, पीर पर्वत से भारी हो गई है, एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए, मेरा मकसद हंगामा मचाना नहीं है, मेरा मकसद है कि राजस्थान की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। यह पीड़ा आज आपको भी लगेगी। परसों आप इधर बैठे थे और यह लोग इधर बैठे थे। आज हम इधर बैठे हैं, आप उधर बैठे हो।

सड़कों की बात आती है, चाहे पानी की बात आये, चाहे बिजली की बात आये, चाहे ग्रामीण विकास की बात आये, आज छह महीनों में पंचायती राज की एक किस्त भी आपने नहीं भेजी। पंचायत समिति में एक किस्त भेजी नहीं। जिला परिषद् के कोटे में आपने कटौती कर दी। आप एक बात बताओ, जब गांव का विकास आपको करना चाहिए था उस पर तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अब भी शहरों का विकास ही कर रहे हो। शहरों का विकास करना है। शहरों का विकास तो अंग्रेजों के टाइम में हो गया था लेकिन गांवों के अन्दर

(श्री श्रवण कुमार)

आज जो गंदगी है, पानी के लिए जो लोग त्रस्त हैं, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिये। आज पानी के हालात यह हैं, गांवों के अन्दर, ईमानदारी से कह रहा हूं कि गांवों के लोग पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके कोटा में तो हो सकता है कि पानी की कमी नहीं होगी, पर हमारे यहां पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे यहां कुंभा लिफ्ट योजना के 7583 करोड़ रुपये मंजूर किये। उनका टेंडर भी हो गया। टेंडर होने के बाद में जब सरकार आई तो समीक्षा में कहा कि टेंडर का पैसा ज्यादा है, ठेकेदार को जो दिया, वह ज्यादा है, तो उसको कैंसिल कर दिया।

श्री सभापति: एक सैकंड, माननीय सदस्य। यह दोनों पुराने वरिष्ठ सदस्य क्या पुरानी बातें याद कर रहे हैं या नई बातों पर चर्चा चल रही है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दोनों क्या?

श्री सभापति: यह वरिष्ठ सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दोनों पुराने हैं, कोई खास बात नहीं है।

श्री सभापति: पुरानी बातें याद कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने उनके टेंडर कैंसिल कर दिये। जब हमने सेक्रेटरी को कहा तो सेक्रेटरी ने कहा कि टेंडर बहुत महंगे थे। मैंने कहा कि महंगे थे तो कम करके लगा दो ना। हम कब कह रहे हैं कि उस ठेकेदार को आप राजस्थान का धन लुटवा दो लेकिन आज तक वह टेंडर नहीं लगा है। मैंने कल भी सेक्रेटरी से बात की, सेक्रेटरी कह रहा है कि पीएचईडी मंत्री से बात करेंगे। पानी जैसी महत्वपूर्ण चीज के लिए आप मंत्री से क्या बात करोगे? प्रत्येक व्यक्ति को चाहे राज किसी का भी हो, सेवाएं तो आपको देनी हैं। यह तो इधर बैठे हैं, हम तो आपकी बुराई करेंगे, भलाई करेंगे, जो भी करेंगे, पर आपको राजस्थान की परवरिश करनी है।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी के 7583 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे, उनका टेंडर लगाया जाये और कम से कम दो साल के अन्दर गांव के लोगों को पानी पिलाने की इच्छा रखें। यह मेरा नंबर वन पाइंट है।

नंबर दो, पंचायतों के अन्दर किस्त आज तक नहीं आई और ना ही पंचायत समितियों में गयी है, ना ही जिला परिषद् में गयी है। मैं चाहूंगा कि

(श्री श्रवण कुमार)

पंचायतों को छोटा-मोटा काम करने के लिए गांव में सरपंचों के पास पैसा होता है, आज की तारीख में किसी पंचायत में एक पैसा भी नहीं है क्योंकि आपकी सरकार आने के बाद में, आप बातें करते हो, आपके पास बजट कहां है?

पहले एमएलए का बजट सीधा ट्रेजरी जाता था। अब आपको मालूम है, आपका बिल है, यात्रा का बिल है, वह भी पहले फाइनेंस में जाता है और वहां से फाइनेंस स्वीकृत करता है, तब आपका बिल ट्रेजरी में आता है। पैसा एक नहीं है। बातें करते हैं। अभी खड़े होकर के भाषण करने से पेट भर जायेगा क्या?

आप बड़े उत्तेजित हो रहे हो, "मत कर अपनी बुलंदियों पर इतना अभिमान, मैंने आसमान से सितारों को टूटते, जमीन पर गिरते देखा है। जो सुबह से शाम तक भिखारियों को भीख देते थे, उनको आठ बजे मैंने भीख मांगते देखा है। जो लोग अपने नाम से सूर्य उगाते थे और अपने नाम से सूर्य को छिपाते थे, समुद्र को सुखाते थे, उनको अर्थी पर जाते हुए देखा है। "शेरशाह सूरी जिसने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी, उसकी छठी पीढ़ी को मैंने स्टेशन पर रिक्शा चलाते देखा है। कहां अंधेरे में हो, कोई नहीं रहेगा। एक बार आओगे दूसरी बार हार जाओगे, फिर दस साल के बाद दोबारा नंबर पड़ेगा। जब तक हो, तब तक जनता की सेवा करो। जनता ने आपको इसीलिए भेजा है, आपको मेंडेट इसीलिए दिया है, बात सुनने की क्षमता रखो। बीच में हाथ क्या कर रहे हो? सिनेमा हॉल है क्या यह? सिनेमा हॉल है क्या? स्टेशन बना रखा है। आते ही खड़े हो जाते हैं। एक तो सुबह-सुबह मैंने देखा कि कितना सीनियर मंत्री बोल रहा था धारीवाल जी, उसके सामने खड़े थे। कहीं मानवता भी तो रखो ना। चीर-चीर कर दिया विधान सभा को।

श्री सभापति: धारीवाल जी अब मंत्री थोड़े ही हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्री नहीं हैं, लेकिन मंत्री का दर्जा आज भी हमने उनको दे रखा है।

श्री सभापति: वह पूर्व मंत्री हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपसे छोटे तो नहीं हैं ना?

श्री सभापति: नहीं, बहुत वरिष्ठ हैं वह तो, 84 साल के हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तभी हम इज्जत करते हैं। सीनियर्स की इज्जत करना सीखो।

इसलिए मैं कह रहा था कि बिजली की बात आती है, बिजली के बारे में कहते हैं कि राजस्थान में हम किसानों को दिन में बिजली देंगे। बड़ी खुशी की बात है। काम करोगे तो मना कौन करेगा?

श्री सभापति: विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारे जसवंत जी, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य भी मंत्री थे। हवा में उड़ते थे। मैंने इनको कहा भी था कि हवा में मत उड़ो।

श्री सभापति: श्री अंशुमान भाटी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या हो गया?

श्री सभापति: समय समाप्त, 10 मिनट।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): समय समाप्त हो गया? बोलना शुरू किया नहीं, उससे पहले समाप्त हो गया।

श्री सभापति: आपको 10 मिनट दे दिये। आपके दल ने आपको 8 मिनट का समय दिया है। मैंने आपको 10 मिनट तक बुलवाया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मुझे आप दो मिनट और दे दो।

श्री सभापति: ऐसे थोड़े ही होता है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मांग ही तो रहा हूं और क्या कर रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। श्री अंशुमान सिंह भाटी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं आपको बिजली की बात बता रहा हूं। बैठो, बैठो। सुन लिया, मंत्री नहीं बनायेंगे। चाहे कितनी भी चमचागीरी करो, नहीं बनायेंगे दोबारा आपको।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, आज परिवर्तित बजट 2024-25 पर विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, इस बार का बजट सही मायने में ऐतिहासिक और अद्वितीय बजट है। बजट के प्रावधानों में हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय का लक्ष्य भी देखा। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र जी मोदी का विकसित भारत 2047 का संकल्प भी देखा है।

(श्री अंशुमान सिंह भाटी)

इस बजट में सड़क, पेयजल, ऊर्जा, सिंचाई, कृषि, चिकित्सा, पशुपालन जैसे मुख्य विभागों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में प्रदेश के युवा, महिला, बालिकाएं, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता सेनानी, गरीब एवं वंचित वर्ग पर भी ध्यान दिया गया। इस बजट के अन्दर हमने देखा है एक तरफ औद्योगिक विकास की बात की है, साथ ही साथ वन और पर्यावरण संरक्षण की भी बात रखी गयी। इस बजट के अन्दर हमें हमारी ऐतिहासिक धरोहर व सांस्कृतिक केन्द्रों का ध्यान रखने का भी कहा गया है। इसके साथ ही साथ खुद के भविष्य का विजन भी स्पष्ट दिखता है। सही मायने में मैं मानता हूं कि यह एक पूर्ण बजट है।

माननीय सभापति महोदय, परिवर्तित बजट 2024-25 में मेरे कोलायत विधान सभा क्षेत्र को भी कई सौगातें मिली हैं। जैसे मेरे कोलायत में कपिल सरोवर में सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सौन्दर्यीकरण करने के लिये बजट घोषणा में लिया है। इसी प्रकार सीमांत क्षेत्र पर मौजूद हमारे बज्जू क्षेत्र के लिये जो हमारी सी.एच.सी. है, उसको क्रमोन्नत करते हुए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया। इसी के साथ कोलायत प्रोपर के अन्दर हमारी जो सी.एच.सी. है उसको क्रमोन्नत करते हुए सरकार ने हाल में ही बजट घोषणा के बाद 40 करोड़ का हमको फण्ड भी दिया है, इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में कोलायत विधान सभा क्षेत्र में डॉ. करणी सिंह लिफ्ट के अन्दर सरकार ने तकरीबन 270 करोड़ रुपये देकर 44,500 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का निर्णय लिया है। साथ ही वीर तेजाजी लिफ्ट के अन्दर तकरीबन 8,320 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिये 50 करोड़ का अतिरिक्त फण्ड दिया है। कुल मिलाकर नहरों पर हमारे क्षेत्र में 320 करोड़ का व्यय होने वाला है, इसके लिये भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

हमारा कोलायत विधान सभा क्षेत्र बिजली आपूर्ति से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। इसी को देखते हुए सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हमारे नोखरा गांव के अन्दर 220 केवी का जी. एस. एस. और सीमांत क्षेत्र बज्जू के अन्दर ग्राम खेड़ली के अन्दर 132 का जी. एस. एस. भी दिया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के अन्दर सीमांत क्षेत्र होने के कारण वहां पर जिप्सम की भी बहुत खनिज की उपलब्धता है। अवैध खनन

(श्री अंशुमान सिंह भाटी)

होने से पिछले पांच सालों के अन्दर एक हमारी भोलासर से रोड जाती थी, उस पूरी रोड को तहस-नहस कर दिया गया था। इस सरकार ने निर्णय लेते हुए उस रोड के लिये 16 करोड़ रुपये दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के अन्दर क्ले जैसे कि बॉल क्ले, चाइना क्ले और फायर क्ले, इनका अथाह भंडार है। इसी क्रम के अन्दर सरकार ने क्षेत्र में सिरेमिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिये बीकानेर में सिरेमिक हब बना है, जिससे हमारे क्षेत्र में निवेश आयेगा और निवेश के आने से क्षेत्र का विकास होगा ही, बाकी हमारे जितने भी ग्रामीणजन हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के अन्दर अतिरिक्त निदेशक, खान की भी घोषणा की गयी है, इसके लिये भी मैं तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कोलायत विधान सभा क्षेत्र की तमाम जनता की तरफ से और हमारी छत्तीसी कौम की तरफ से हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी और हमारी वित्त मंत्रीजी दिया कुमारी जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। पूरे मंत्रिमण्डल का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ में, मैं मेरे क्षेत्र की दो-तीन मांगें हैं, वह आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे कोलायत विधान सभा क्षेत्र में देशनोक में करणी माताजी का मन्दिर है। वहां पर एक उप तहसील है। मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले समय के अन्दर सरकार गंभीरता से लेते हुए इस उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करें। इसके साथ ही हमारे क्षेत्र के अन्दर कई पी.एच.सी. हैं, जैसे पीएचसी किलचू, पीएचसी आर.डी. 820, पीएचसी भीखमपुर, पीएचसी बसलपुर, इनको भी क्रमोन्नत करते हुए सी.एच.सी. का दर्जा दिया जावे तो एक बराबर विकास होगा और सबको चिकित्सा की सुविधा मिल पायेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसी क्रम के अन्दर हमारे भारत-पाक सीमा पर जितनी भी हमारी बालिकाएं रहती हैं, उनका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण से वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये उस स्थान तक नहीं पहुंच पातीं। इसको देखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि ग्राम गोकुल के अन्दर एक नया बालिका महाविद्यालय बनाया जावे जिससे हमारी बालिकाएं वह खुद के उच्च शिक्षा के अधिकार से वचित नहीं रहें।

(श्री अंशुमान सिंह भाटी)

विभागीय लापरवाही, हमारे क्षेत्र के अन्दर सीएडी ने आज से 35 साल पहले जो खाले बनाये थे, उनका ढंग से रख-रखाव और देखभाल नहीं हो पाया, विभागीय लापरवाही के कारण आज वह सभी खालें टूटने के कगार पर हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि 50 से 70 करोड़ का विशेष पैकेज हमारे क्षेत्र के लिये दिया जावे जिससे जितने भी क्षतिग्रस्त खालें हैं, उन सबकी मरम्मत हो सके और इस बड़े सीमांत क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्र को एक नई ताकत मिले और जितनी भी सुविधाएं हैं, वह संचालित होती रहें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के अन्दर पूरे बीकानेर संभाग की सर्वाधिक रोड्स हैं। 1710 किलोमीटर रोड के अन्दर से तकरीबन 241 किलोमीटर रोड आज की तारीख में नोन-पेचेबल श्रेणी में है। यह कुल सड़क का तकरीबन 14 प्रतिशत है। हर साल के अन्दर सरकार 10 से 15 किलोमीटर सड़क नोन-पेचेबल को पेचेबल में डालने के लिये री-कारपेटिंग के लिये देती है, परंतु इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण से यह 10-15 किलोमीटर हमारे लिये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हमारे क्षेत्र के अन्दर करीबन 34 सड़कें तो ऐसी हैं जिनमें 10 साल में एक बार भी नवीनीकरण का कार्य नहीं किया गया। हमारे छह सड़कें ऐसी हैं जिनमें 20 से 30 सालों के अन्दर एक बार भी री-कारपेटिंग का कार्य नहीं कराया गया। मैं यह चाहूंगा कि हमें इसमें भी री-कारपेटिंग के लिये एक विशेष बजट दिया जाये जिससे हम अपने जिले और अपने संभाग में एक लेवल तक आ सकें। उसके बाद जो विकास हो तो हम हाथ से हाथ मिलाकर आगे विकास में उन्नति कर सकें। इसी हिसाब से हमारे क्षेत्र में एम. डी. आर. 365 को भी चौड़ा करके तकरीबन 61 किलोमीटर रोड को अगर सात मीटर चौड़ा कर दिया जाता है तो हमारे निश्चित रूप से एन.एच. 11, जोकि जैसलमेर हाईवे है, वह सीधे ही बाप और खाजूवाला एन.एच. हाईवे 911 है, उससे कनेक्ट हो सकेगा।

इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र के अन्दर सिंचाई की काफी सुविधा उपलब्ध है चाहे वह नहरी सिंचाई हो, चाहे ट्यूबवैल से सिंचाई हो। सिंचाई का क्षेत्र अधिक होने के कारण से हम हमारे पूरे संभाग के अन्दर चना और मूंगफली के उत्पादन में सबसे रिकार्ड उत्पादन करते हैं। इसी को देखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि आर.डी. 820 पर एक गौण मंडी का निर्माण कराया जाये जिससे किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सके और एरिये का विकास हो सके।

इसी क्रम के अन्दर, इनके अलावा मैं राजस्थान की तीन-चार मुख्य

(श्री अंशुमान सिंह भाटी)

समस्याएं हैं, मैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, हमारे यहां तीन मुख्य समस्याएं हैं राजस्थान के अन्दर, जैसे कि गांव के अन्दर रहने वाले शहर की तरफ पलायन करना, दूसरा है, हर घर में जो कुटीर उद्योग था, उसको खतम करने से स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और लोग रोजगार के लिये पलायन कर रहे हैं। गांव के अन्दर रोजगार खतम होने के कगार पर है। आई.जी.एन.पी. पर आश्रित होने से आज जिस प्रकार से एक बहुत डार्क सर्कल में अपन पहुंच चुके हैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, अपन को यह बात समझनी पड़ेगी। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): हमारे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जिले हैं जैसे बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और बाड़मेर, इनमें बहुत ही बड़ा भू-भाग होने के कारण से हमारी जनता को बड़ी परेशानी और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमारे क्षेत्र के अन्दर रेगिस्तान का फैलाव है और पानी का अभाव है। हमारे क्षेत्र के अन्दर पूरी विद्युत आपूर्ति नहीं मिलती, शिक्षा और चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। भारत में गरीब जनता सरकार को अपना माई-बाप मानती है और वह हर काम के लिये सरकार पर आश्रित है, परंतु बड़े दु:ख के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि आज 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी हमारे ग्रामीणों को उनके पीने का पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, उनको पूरी बिजली नहीं मिल रही। इसी कारण से 70 साल बीतने के बावजूद भी उनको खुद का हक नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण से मजबूर होकर खुद का घर छोड़कर, खुद का गांव छोड़कर पलायन करके शहर में उनको जाना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा, यहां पर मौजूद सदस्यगण भी इस बात से वाकिफ होंगे कि खुद का घर, गांव और खुद का क्षेत्र छोड़ने के लिये कोई आदमी राज़ी नहीं होता। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये अपन को एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें हमारे जितने भी गांव हैं, गांवों को अपने को सुदृढ़ करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। सभापति महोदय, पुराने समय में आज से दौ सौ साल पहले विश्व का कुल निर्यात होता था, उसमें से 34 प्रतिशत हिस्सेदारी हमारे हिन्दुस्तान की होती थी।

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): एक मिनट और।

श्री सभापति: आपके समय से भी अधिक बुलवा दिया। विराजें।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): पिछली बार भी रह गया। एक मिनट और लूंगा। हमारे हर आंगन में कुटीर उद्योग से जितनी अलग-अलग जातियां जुड़ी हुई थीं चाहे वह सुनार हो, कुम्हार हो, सुथार हो, ये ही थे। इन्हीं समाज के सहयोग से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया गया था, पर हमने पाश्चात्य देशों की संस्कृति को अपनाते हुए कॉपी करते हमने हमारे जितने भी आंगन में कुटीर उद्योग थे, उनको खत्म करके हमने हमारे क्षेत्र के अन्दर जितनी भी बड़ी-बड़ी मिल्स और फैक्टरी डाल दीं। बड़ी फैक्टरी डालने के बावजूद आज पूरे विश्व के अन्दर 1.8 परसेंट योगदान उत्पादन के अन्दर है। हमें सोचने की जरूरत है, जहां हम पहले सोने की चिडिया कहलाये जाते थे, आज हमने खुद के सारे स्किल्स को खतम करते हुए हमारी जनता को लेबर बनाकर छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया जाये और जितने भी छोटे उद्योग हैं, उनको बराबर मान सम्मान बना रहे, जिससे हमारे देश का सम्मान बढ़े।

श्री सभापति: श्री यूनुस खान।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरे हाथ में बजट की यह कॉपी है। इनका प्रथम पॉइंट इनके संकल्प पत्र से शुरू होता है। इनके संकल्प पत्र की कॉपी मैं लेकर आया हूं। इसमें लगभग 400 पॉइंट इन्होंने बनाये हैं। अगर इसका 45 प्रतिशत निकालें तो आप भी देख लीजिये इसका 45 प्रतिशत कितना होता है, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी पिछले साढ़े तीन महीने से अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि हमने अपने संकल्प पत्र का 45 परसेंट हिस्सा पूरा कर दिया। इस संकल्प पत्र की मूल प्रतिलिपि का एक-एक पॉइंट मैंने रात को पढ़ा और इस बजट से मिलाया कि कौन-कौनसे काम हो गये। न तो उन्होंने जो 45 परसेंट बोले हैं, वे पूरे हुए और न ही माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें मैंशन किया है कि 45 बिन्दुओं पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है।

मुझे लगता है कि इनके बजट भाषण की स्टार्टिंग ही शायद गलत हो गयी। जो लोग लिखकर दे रहे हैं, उनसे पहले यह कहें कि हमारा संकल्प पत्र

(श्री यूनुस खान)

यह है, इसे पढ़ें, उसमें से जो काम हमने किये हैं, उन्हें टिक करें और उसके बाद हमारे भाषणों में डलवाएं, क्योंकि मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री दोनों बहुत बड़े पद होते हैं और जब वे सार्वजनिक स्थान पर बोलते हैं तो उनका असत्य होना ठीक नहीं है। अत: माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह रहेगा कि इस पर विशेष ध्यान दें।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री चले गये। उन्होंने कहा कि पांच साल में हम गेहूं की एमएसपी 2700 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर देंगे, जबकि इनके संकल्प पत्र में लिखा है कि हम 2700 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा एमएसपी देंगे। ऐसे में यह कहना उचित नहीं है, सदन को गुमराह करना है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सत्ताधारी दल पहले अपना संकल्प पत्र पढ़ ले, क्योंकि इसमें एक त्रुटि और है। इसमें जो इनका संयोजक है, उस सहित 25 आदमी हैं, उन 25 आदमियों में से एक भी व्यक्ति इस हाउस में नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति माननीय किरोड़ी लाल जी थे, उन्हें भी इन्होंने छुट्टी पर भेज दिया। यानी अब इनके पास संकल्प पत्र बनाने वाला तो एक व्यक्ति है नहीं, इम्प्लीमेंट करने वाले यहां बैठे हैं, इन्होंने अभी तक इसे पूरा पढ़ा नहीं। अत: यह गैप कैसे पूरा हो, इस पर पहले इनको ध्यान देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरा समय कम है, बोलना तो और ज्यादा चाहता था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आपने हमारे संकल्प पत्र को इतनी श्रद्धापूर्वक पढ़ा, उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सर, मैं तो आप ही का हूं, लेकिन यह जो हाउस है, इसमें बोलने का अधिकार है। मैं तो आप ही का हूं, मैं कहां जाऊंगा?

माननीय सभापति महोदय, मैंने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी करेंगे। मैंने प्रधान मंत्री जी के बहुत सारे भाषण सुने। वे हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री हैं। वे कहते हैं कि इंडिया का रुपया मजबूत हो गया। जब इंडिया का रुपया इतना मजबूत हो गया तो फिर आपको डॉलर में काम करने की जरूरत कहां है? आपको इंडियन रुपीज में बोलना चाहिये था। मैंने पूरा गूगल छान मारा, 350 बिलियन डॉलर में कितने इंडियन रुपीज होते हैं। अभी आदर्श नगर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, वे कह रहे थे कितनी बिन्दी लगती हैं। मैंने कहा, मैं तो गांव का आदमी हूं, मुझे पता नहीं है।

(श्री यूनुस खान)

मेरा वित्त मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि पहले हाउस को यह तो बताएं कि अभी राजस्थान की इकोनॉमी कितने रुपये की है और अब इनके बजट से कितने रुपये की हो जायेगी, क्योंकि बिलियन डॉलर न तो इधर बैठने वाले सदस्यों को समझ में आयेगा, न उधर बैठने वाले सदस्यों को समझ में आयेगा। अत: जितना व्यवहार करेंगे, कम से कम इंडियन रुपीज में करें, क्योंकि हमारा रुपया बहुत सुदृढ़ है और हमारे नेता माननीय नरेन्द्र मोदी जी भी विश्व के नेता है, इसलिए रुपये में बात करें। यह मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र डीडवाना में भी 33 केवी का जीएसएस दिया है। उसके लिए भी आपका धन्यवाद। इन्होंने मोलासर को 30 शैयाओं से 50 का किया, उसके लिए भी धन्यवाद।

जो काम किये हैं, उनके लिए तो धन्यवाद, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं यह देख रहा था कि जो हमारा एफआरबीएम एक्ट है, उसका वायलेशन इनके इस बजट में है। बात की जा रही थी कि हम आते ही इकोनॉमी को सुधार देंगे, कांग्रेस वालों ने कर्जे के नीचे दबा दिया। आपका 25 हजार करोड़ रुपये तो अभी बजट में डेफिसिट दिखा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, हम तो यह उम्मीद कर रहे थे कि जब आप राज में आएंगे और संसदीय कार्य मंत्री होंगे तो वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी के सलाहकार होंगे। पहला बजट जो आयेगा वह सरप्लस का आयेगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चाहे वह कैपिटल का मामला हो, चाहे रेवेन्यू का मामला हो, दोनों ही घाटे के बजट आपने प्रस्तुत किये हैं और इससे राजस्थान पर ऋण भार और बढ़ेगा। मेरा निवेदन है कि जो बोलें उसे कम से कम पहले बजट में तो करें, बाद में तो भले ही नहीं करें।

श्री सभापति: श्री अमीन कागजी। विराजें, साहब, समय छह मिनट हो गया आपका।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सर, मैं तो बैठ जाऊंगा, दो मिनट तो मुझे दें।

श्री सभापति: सबका इतना ही समय है। अध्यक्ष जी की व्यवस्था है। विराजें, साहब। श्री अमीन कागजी।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): बजट पर तो शुरू ही नहीं हुआ मैं। सभापति महोदय, चलिये मैं आपके अनुशासन में ही रहूंगा, एक मिनट में यह कहूंगा। चलें कोई बात नहीं, यह बात मानें न मानें, मेरी इतनी तो मान लें, इन्होंने खाटूश्याम जी को 100 करोड़ रुपये देकर कॉरिडोर बनाने की बात कही, तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी यात्री बाहर से खाटूश्याम जी आता है वह सालासर भी जाता है, इस कॉरिडोर में सालासर को भी जोड़ लें। उसके साथ-साथ पाढाय माता को भी जोड़ लें, नागौरी मन्दिर को भी जोड़ लें। यह मेरा उनसे आग्रह रहेगा।

श्री सभापति: विराजें।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सभापति महोदय, कांग्रेस वालों के लिए ये कहते हैं कि ये लोग गायों के खिलाफ हैं। इन्होंने छह महीने के अनुदान को बढ़ाकर 9 महीने किया, मेरा आपसे आग्रह है, आप तो गौमाता को मानने वाले हैं, इस 9 महीने को बढ़ाकर 12 महीने कर दें। इससे लोग आपको याद रखेंगे।

श्री सभापति: श्री अमीन कागजी।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट चर्चा में बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट जमीनी वास्तविकताओं और समस्याओं से दूर है। यह बजट पूर्ण रूप से दिशाहीन और लोगों की अपेक्षाओं के विपरीत है। राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया पहला बजट पूर्ण तरह से आमजन के खिलाफ है। इसके जो की-पॉइंट्स हैं, इनमें 70 हजार करोड़ रुपये के बजट घाटे की आपने बात की है। छह महीने पहले 8 फरवरी को जब इनका अन्तरिम बजट आया था, उसमें इन्होंने जो घोषणाएं की थीं और हर विधान सभा क्षेत्र को पांच करोड़ की सड़कें देने की बात की थी, यह बात अलग है कि इन्होंने स्थानीय विधायकों से चर्चा न करके वहां से बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों की अनुशंसाएं लेकर काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि आज तक किसी भी विधान सभा क्षेत्र में उनके टेंडर नहीं हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं जब पहले साल में 70 हजार करोड़ रुपये का बजट ये आज लेकर आये हैं तो परिकल्पना कीजिये कि पांच साल में साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये के नजदीक कर्जा लेकर इस प्रदेश को और नीचे ले जाने की इनकी प्लानिंग है क्योंकि यह डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने बजट में एमएसपी की बात नहीं की, इनका भी वही ढर्रा है, जिस तरह से नरेन्द्र मोदी जी ने 750 किसानों की मृत्यु होने के बाद भी आज तक बजट पर बात नहीं की। न ही इन्होंने ईआरसीपी की बात की, न केन्द्रीय बजट की बात की। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि इनके

(श्री अमीन कागजी)

पास समय है, 23 तारीख को देश का बजट आने वाला है, ये सारे के सारे लोग दिल्ली जाएं और प्रधान मंत्री जी, जिन्होंने यह वादा किया था कि ईआरसीपी लेकर आएंगे, उनसे बात करें। यह हमारी अशोक गहलोत जी की सरकार लेकर आयी थी, जिसमें 9500 करोड़ के टेंडर हो चुके थे और काम शुरू हो चुका था। अब इनका दायित्व बनता है कि ये ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना में लेकर आएं।

महलों, मन्दिरों और हवेलियों का यह बजट, जिसमें जयपुर के लिए 100 करोड़ रुपये की इन्होंने प्लानिंग की बात की, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 2017-18 के बजट में जयपुर के परकोटे को रिपेयर करने के लिए 18 करोड़ रुपये दिये थे और आज तक उस 18 करोड़ का कोई काम नहीं हुआ और जयपुर का परकोटा ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है।

माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि बजट में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 20-20 हैंडपम्प और 10-10 ट्यूबवैल की बात की है। आप यहां पर बैठे हैं। शहर का जल स्तर बिलकुल गिर चुका है। जहां शहर में आप लोगों ने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में ट्यूबवैल की बात की है, 20-20 हैंडपम्प की बात की है, शहर में हैंडपम्प काम नहीं कर सकते हैं, जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। उसकी जगह शहर की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में उनको ट्यूबवैल में कन्वर्ट करें ताकि हैंडपम्प न मिलकर, उन विधान सभा क्षेत्रों में ट्यूबवैल मिलें, जहां का जल स्तर नीचे चला गया है।

(समय: 16.30 बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

साथ ही, इस बजट में वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। यह बात आप देख लीजिये। आपने पूरे बजट में कहीं भी पानी बचाने की बात नहीं कही है। जयपुर में पानी की किल्लत है। जब बीसलपुर का गला घुटता है तो जयपुर के लोग प्यासे रह जाते हैं और हमने यह दो महीने में देखा है। बीसलपुर की सप्लाई प्रभावित होती है तो जयपुर की चारदीवारी में पानी की किल्लत होती है। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी हैंडपम्प जो खराब हो गये हैं, डिस्कार्ड हो गये हैं, आप बैठे हैं, संसदीय मंत्री जी, आपकी कैबिनेट के लोग भी नहीं हैं, अधिकारी भी नहीं हैं लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप हार्वेस्टिंग पर ध्यान दें, जितने भी ट्यूबवैल खराब हैं, उनको शहर में हार्वेस्टिंग में कन्वर्ट करवा दें।

(श्री अमीन कागजी)

साथ ही, आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की है। जयपुर में ग्रेटर और हैरिटेज में तकरीबन दो हजार टन कचरा रोज वेस्ट में बदल रहा है। लीगेसी वेस्ट, जिसका अम्बार लग चुका है। 20 लाख टन से ज्यादा जयपुर में कचरा पड़ा हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। लीगेसी वेस्ट के लिए राज्य सरकार को कई बार एनजीटी ने नोटिस दिये हैं, कई बार पेनल्टी की बात की है। साथ ही, यह भी कहना चाहता हूं कि सॉलिड वेस्ट में अगर आप बात करते हैं तो आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात नहीं की है। एक तरफ आप उद्योगों को बढ़ाने की बात करते हैं, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज आ रहे हैं लेकिन बजट में आपने कहीं भी यह प्रावधान नहीं किया है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनमें से जो वेस्ट निकलेगा, उसका निस्तारण कैसे करेंगे। चाहे मकराना चले जाएं, चाहे किशनगढ़ चले जाएं, चाहे भिवाड़ी चले जाएं, चाहे जयपुर के सीतापुरा चले जाएं, वीकेआईए चले जाएं, वहां जिस तरह का प्रदूषण हो रहा है और जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, उसके लिए प्लानिंग आपके इस बजट में कहीं नहीं दिखी, जबकि इसके लिए भारत सरकार आपको मोटा पैसा देती है लेकिन आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया है।

जयपुर में आप बात करते हैं कि 50 क्लस्टर बनायेंगे। तीन वर्ष में प्लानिंग करके 150 करोड़ रुपये हैंडीक्राफ्ट के लिए खर्च करेंगे, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे। जयपुर में जलमहल के सामने एक हाट बाजार बनकर तैयार है, 2017 में बनाया था वसुन्धरा जी के टाइम पर। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान के जितने भी हस्तशिल्प हैं, उनको लाकर वहां बैठाइये, उनका वहां प्रमोशन करिये, उनकी प्रदर्शनी लगातार चलती रहे। चूंकि जो एरिया है, जहां यह हाट बाजार बना है वहां डेली दस से बीस हजार टूरिस्ट आते हैं। इससे एक्सपोर्ट प्रमोशन को बल मिलेगा।

जयपुर में वॉल सिटी को लेकर आपने एक घोषणा की है कि जयपुर वॉल सिटी हैरिटेज डवलपमेंट प्लान बनाकर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। अभी शान्ती धारीवाल जी बोल रहे थे कि हमारे टाइम पर हमने भी बहुत प्रयास किये और यह वही जयपुर, जिसको 5 फरवरी, 2020 को हमारे अथक प्रयास से यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। क्या 100 करोड़ रुपये से आप उस धरोहर को बचा पायेंगे? मैं बिलकुल नहीं समझता और यह बजट आपको पता है 100 करोड़ का बजट, मुझे डर है इस बात का कि सरकार में बैठे लोग कहीं इस बजट को महलों में और मन्दिरों में और अपने

(श्री अमीन कागजी)

किलो को सजाने में नहीं व्यर्थ कर दें, इसकी मुझे आशंका है। इसको आप डिटरमाइन कर लीजिएगा कि ये जयपुर शहर की चौकड़ियां हैं, जिसकी नियत से आपने ये 100 करोड़ रुपये की घोषणा की है, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठें और आपके अधिकारियों को कहिये कि किस तरह से यह विश्व धरोहर आप सुरक्षित रख पायेंगे। इसमें मुझे डाउट है।

आप मेडिकल की बात कर रहे हैं। आरयूएचएस का आप हाल देख लीजिये। आरयूएचएस में अभी चार दिन पहले, एक बहुत ही प्रतिष्ठित अख़बार ने कहा कि 700 बेडेड हॉस्पिटल, जिसको माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, उसमें न डॉक्टर हैं, 12 फैकल्टीज में न मेडिसिन है, न सर्जरी है, न आर्थोपेडिक्स है, न बच्चों के लिए डॉक्टर है। यह बताइये, आप करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं। बजट का प्रावधान नहीं है, डॉक्टरों की पोस्टिंग नहीं है, डॉक्टरों का अभाव है और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि ये एक तरफा काम, जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में वहां के लिए डॉक्टरों का इंतजाम नहीं करेंगे, वहां पर पद सृजित नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि आप सक्सेस हो पायेंगे।

इसी तरीके से जयपुर में आपने आयुक्तालय के अन्दर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स बनाई है। सिक्योरिटी पुलिस फोर्स की एक अलग से बात की है, लेकिन आज जयपुर शहर में बड़ी चुनौती है, वह बेतहाशा बढ़ता नशे का कारोबार है, जिसमें हमारे युवा बिगड़ रहे हैं, हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि राजस्थान में सात जिला सम्भागों में नशे के लिए चौकियां बनाई गई हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सात में से एक चौकी जिसके अन्दर पांच से छह पुलिस वाले हैं और पूरा जयपुर नहीं, पूरा सम्भाग वे सम्भालते हैं, नशे के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप पता कर लें, उसके अन्दर क्या कार्यवाही कर रही है, आपकी नारकोटिक्स की फोर्स बनाई है, जिसका एसओजी में दफ्तर है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। आवारा पशुओं को लेकर।

श्री सभापति: श्री श्रीचन्द्र कृपलानी साहब।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): सभापति जी, एक मिनट, समाप्त कर रहा हूं। सभापति जी, आपने बोलने के लिए वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हरिमोहन जी, डोटाटसरा जी और जूली जी दोनों नहीं हैं, आपको जिम्मेदारी दे गये हैं। सभापति महोदय,

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

राजस्थान सरकार के परिवर्तित आय-व्ययक बजट 2024-25 पर आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि डोटासरा जी और जूली जी यहां पर नहीं हैं, क्योंकि डोटासरा जी दो-तीन दिन से यहां पर नहीं थे, जब बजट पर चर्चा चल रही थी। यहां पर जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, आधे से ज्यादा लोग इस बजट की तारीफ कर रहे थे। जूली जी खुद कर रहे थे, आपके भाटी जी ने की। आपके भाटी जी ने की है, वे खड़े हैं। डोटासरा जी के आने के बाद। ये सारे मंत्री बैठे हैं। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि विपक्ष में बैठकर ऐसे क्यों फड़फड़ाते हो, अच्छे बजट पर क्यों तालियां नहीं बजाते हो। आपको भी ताली बजानी चाहिए, आप कल बजा रहे थे लेकिन आज आप बदल गये।

सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि यह आय-व्ययक बजट, आंकड़े मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने यहां पर कहे हैं लेकिन ईमानदारी से हम विचार करें तो इस देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गये हैं। हरिमोहन जी, आप इस बात को सुनना। हिन्दुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने 50-55 साल तक राज किया है। ये जोगाराम जी कह रहे हैं कि कम सुनते हैं, सही बात है क्या, वास्तव में नहीं सुन रहे हैं, तभी सुखी हैं। आजादी के 75 साल में 50 साल से ज्यादा आपने राज किया हिन्दुस्तान में। राजस्थान में पंचायत से लेकर प्रधान मंत्री तक आपका था लेकिन ईमानदारी से दिल पर हाथ रख कर आप विचार करो इस बात का कि हिन्दुस्तान में विकास की नींव का पत्थर अगर सबसे पहले किसी ने रखा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा जिन्होंने इस देश के विकास की शुरुआत की। पचास साल में आप गांवों में सड़कें नहीं बना सके। पचास साल में आप गांव के किसानों की समस्याओं की जो आप बार-बार बात करते हो, फसल बीमा योजना उन्होंने बनाई, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था उन्होंने की। हिन्दुस्तान को परमाणु ताकत वाला मुल्क उन्होंने बनाया। ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं भी बड़ाई करता हूं जिन्होंने सड़कों का संचार किया लेकिन उनके जाने के बाद में आपने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप नोट कर लो। आपके नेता, प्रतिपक्ष नहीं हैं, उनके आने के बाद बता देना। आपका नम्बर आये तब बोलो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): भ्रष्टाचार, आतंकवाद के अलावा

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

दिया क्या है आपने। ...(व्यवधान) और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विकास की शुरुआत अगर किसी ने की तो राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री और देश के पूर्व उप राष्ट्रपति माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने शुरुआत की जिन्होंने अन्त्योदय योजना बना कर राजस्थान के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा, जिन्होंने बारानी जमीन पर लगान माफ किया, जिन्होंने पहली बार पंचायतों को सड़कों से जोड़ा। पंचायतों में मिडल स्कूल उस समय खुले, उससे पहले आपने नहीं खोले थे। वो भैरोंसिंह जी ने खोले थे। उसके बाद उस विकास को आगे बढ़ाया राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने जिन्होंने भामाशाह योजना अपनाई, गांव-गांव में गौरव पथ बनाये और हर पंचायत पर दसवीं का स्कूल खोला, उसके बाद दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बारहवीं तक के स्कूल खोले। करोड़ों-अरबों के काम उन्होंने शहरों में और गांवों में कराये।

आप इस बात का विचार करो कि आज जो यह बजट यहां पर प्रस्तुत हुआ है यह बजट वो ही बजट है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो विकास की नींव रखी थी और भैरोंसिंह जी शेखावत ने जो विकास की नींव रखी थी, जो वसुन्धरा जी ने रखी थी, यह उस बजट का आगे वाला हिस्सा है। आने वाले समय में मैं आज दावा कर रहा हूं, बार-बार श्रवण जी कह रहे थे न कि पांच इधर के और पांच साल उधर के, वह अब नहीं होगा। अब की बार भाजपा बार-बार है हिन्दुस्तान में और राजस्थान में। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अब नहीं आनी है आपकी, क्योंकि आपने ...(व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): लोक सभा के रिजल्ट ने बता दिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बता दिया, सही है। अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे। कहां जा रहे हो, रफीक खान जी, बैठो न। अशोक गहलोत जी के खिलाफ हो क्या आप? अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, इस राजस्थान के लिए क्या किया उन्होंने? आप बार-बार यहां पर कह रहे हो, इस बजट में ऐसी चीजें हैं कि क्रियान्वित नहीं होंगी, इतना बड़ा बजट बना है। ...(व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सौ यूनिट बिजली फ्री, चिरंजीवी योजना ...(व्यवधान) बात करोगे तो आपका समय खतम हो जायेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): राजस्थान में आप ढूंढोगे, ये एमएलए बैठे हैं राजस्थान के सारे, एक लाख से ज्यादा पत्थर आपके शिलान्यास के लगे हुए हैं जिसमें कोई योजना ही स्वीकृत नहीं हुई, यह गहलोत साहब के राज के हैं।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

मेरी खुद की कांस्टिट्यूएन्सी में लगे हुए हैं 300 पत्थर तो। खाली बजट पर बोलते गये, बोलते गये, काम का कोई लेना-देना नहीं। आप यह बार-बार जो कह रहे हो न सीटें कम-ज्यादा, तो यह तो राजनीति में चलता रहता है लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हिन्दुस्तान में मोदी जी प्रधान मंत्री बने। आपके पास क्या है, आपके पास राहुल गांधी है। ...(व्यवधान) आप तो मुझे बताओ, वह शोले का डायलोग नहीं है, कितने आदमी थे, जो गब्बर सिंह बोलता है तो, रफीक जी, यह बताओ 2014 में कितने जीते थे? कांग्रेस के 42, 2019 में कितने आदमी थे आपके? 52 और अभी संविधान के नाम पर लोगों को असत्य बोल-बोल कर, पता नहीं लोगों में भ्रम पैदा करके अम्बेडकर जी के नाम पर, अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता थे। अम्बेडकर जी को हराया किसने? आप लोगों ने हराया 1952 में बॉम्बे में। ...(व्यवधान) ये भूल गये उसको। अब आपकी सीटें कितनी आ गई? अब आपकी सीटें आई 99 ...(व्यवधान) सुनो तो सही। आप तो 2014 की 2019 की और 2024 की तीनों को मिलाओ कितनी सीटें होती हैं? तीनों मिला कर उतनी सीटें नहीं आई ...(व्यवधान) 199 सीटें। ...(व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपका समय खतम हो जायेगा। ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरा समय कभी खतम नहीं होगा। मेरा समय तो शुरू हुआ है, कहां से खतम होगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): समय तो आपका खतम हो गया, हमारा तो अब शुरू हुआ है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): और आपको ये सीटें मिली कैसे, यूपी में सपा से गठबन्धन कर लिया, वहां उद्धव ठाकरे जी मिल गये, कहीं आम आदमी पार्टी मिल गई। इन पार्टियों को मिला कर आपको इतना जोश खाने की जरूरत नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, ये मंत्री जी उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरे को मंत्री बनाया कि नहीं बनाया उसकी चिन्ता मत करो, चिन्ता इस बात की करो कि यह देश कैसे आगे बढ़ेगा। चिन्ता इस बात की करो राजस्थान कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे मुख्य मंत्री जी भजन लाल जी शर्मा और राजस्थान की हमारी उप मुख्य मंत्री हमारी

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट दिया है न, यह कांग्रेस को खतम करके रख देगा। देख लेना आप, क्योंकि मुझे पता है यह पहली बार हुआ होगा इस बजट में कि कांग्रेस का एमएलए हो चाहे यह 'बाप' पार्टी के भी बैठे हैं, निर्दलीय भी बैठे हैं, यूनुस खान जी, चन्द्रभान जी, जीवाराम जी, आपको कसम है, अशोक जी, आपको इस बजट में कुछ नहीं मिला? सबको मिला है। पहली बार ऐसा बजट आया है। भाटी जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? ...(व्यवधान) आप बोले हो। आप भाषण में बोले हो। ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान) एक मुस्लिम था उसकी आपने बेइज्जती करके टिकट तो नहीं दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, आप विराजिये। आपका नम्बर आये तब बोलना। माननीय सदस्य, आप बोलिये। आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): श्रवण जी, एक बात बताओ, अगर मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री नहीं होते तो क्या अयोध्या में राम का मन्दिर बनता? ...(व्यवधान) नहीं बनता। इस समस्या का अगर किसी ने समाधान किया है तो नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, फिर आप बोलेंगे तब ये नहीं बोलने देंगे, फिर क्या होगा। आपके नेता, प्रतिपक्ष बोलेंगे न तो ये सब बोलेंगे। आप विराजिये। आपका नम्बर आयेगा तब बोल देना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, अभी तो पहली झांकी है, मथुरा-काशी बाकी है। देखते जाओ आगे क्या होगा। ...(व्यवधान) अयोध्या में हम नहीं हारे हैं, फैजाबाद में हारे होंगे।

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, एक जमाना था जब मनमोहन सिंह जी इस देश के आपकी पार्टी के प्रधान मंत्री थे। हिन्दुस्तान के बाहर अमेरिका, जापान, जर्मनी कब मनमोहन सिंह जी जाते थे कब वापस

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

आते थे, पता ही नहीं लगता था लोगों को कि हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री वो है क्या। हालांकि उनकी हालत तो यह थी कि हमारे प्रधान मंत्री जी को...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अमेरिका ने मनमोहन सिंह जी को सलाह लेने के लिए बुलाया है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, खतम करिये आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं?

श्री सभापति: आप अपनी बात कहें। आप उधर देखो ही मत, आप आसन को सम्बोधित करो और समाप्त करो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मनमोहन सिंह जी को तो जुकाम होता था न तो सोनिया जी को फोन करके पूछते थे कि गोली लूं कि नहीं लूं मैं। यह हालत थी उनकी लेकिन आज हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी अमेरिका की धरती पर उतरते हैं, चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं तो लोग कहते हैं हिन्दुस्तान का शेर आया है। यह है नरेन्द्र मोदी का प्रभाव। आज देश में धारा 370 कभी हटाने के बारे में सोच सकते थे क्या?

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मैं कुछ बोला ही नहीं अभी तो। मुझे पांच मिनट तो बोलने दो।

श्री सभापति: ...(व्यवधान) प्लीज, दो मिनट रविन्द्र जी भाटी को बोलने दें।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): आदरणीय सभापति महोदय, मेरे से पहले आदरणीय कृपलानी जी ने कहा कि बजट में क्या मिला है।

श्री सभापति: एक मिनट, भाटी जी। ...(व्यवधान) आप समाप्त कीजिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मैं पूरा बजट आपको पढ़कर बता दूं, पूरे बजट में शिव कांस्टीट्युएंसी का नाम कहीं लिखा हो तो मैं आपके लिये चार बार टेबल बजाता, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि इसमें एक शब्द तक आपने नहीं लिखा। ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, एक मिनट।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

सभापति महोदय, मेरा कहना है कि हरीश चौधरी जी अभी यहां नहीं हैं, अभी 2-3 दिन पहले वह बजट पर बोल रहे थे। जब मैंने कहा कि कोरोना में आप 5 स्टार होटलों में थे, लोगों की सेवा नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक बात बड़े दम से कही थी कि हम पहले गरीब होंगे, लेकिन आज हमारी इतनी ताकत है कि हम 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में रुक सकते हैं। उन्होंने कहा था, लेकिन यह 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में रुकने का अधिकार भी नरेन्द्र मोदी जी ने सम्मान निधि प्रारम्भ की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: क्लोज कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मैं भजन लाल शर्मा जी एवं दिया कुमारी जी को धन्यवाद देता हूं और मेरी 5-6 मांगों को बोल कर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय, निम्बाहेडा से मंगलवाड़ रोड जो हमारी बहुत बड़ी समस्या है, वह स्वीकृत की जाये। छोटी सादड़ी में ए.डी.जे. कोर्ट, निम्बाहेड़ा में राजकीय कन्या महाविद्यालय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: इनका समय कट रहा है, आप चिन्ता मत कीजिए, आपको पूरा मिलेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ...(व्यवधान) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी सादडी, उप जिला चिकित्सालय, छोटी सादड़ी, राष्ट्रीय राजमार्ग महुडिया से बागदरी। निम्बाहेड़ा क्षेत्र में निम्बोदा लघु सिंचाई परियोजना स्वीकृत की जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सभापति महोदय, आज आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं अपनी बात की शुरुआत मेरे क्षेत्र के एक छोटे-से गांव पादरिया से करना चाहूंगा। मैं उस गांव की बात कर रहा हूं जहां का हर दूसरा सदस्य आज के समय में फ्लोराइड पानी की वजह से दिव्यांग है। मैं मेरी बात की शुरुआत उस डी.एन.पी. एरिया से करना चाहूंगा जहां पर आजादी के 75 साल बाद भी सड़क, पानी और शिक्षा की भारी कमी है। मैं मेरी बात की शुरुआत उन तमाम पशु पालकों को याद करते हुए करूंगा, जिन्हें अभी तक किसी तरीके की कोई चिकित्सा सहायता नहीं मिली, पशुओं के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं हुई। मैं मेरी बात की शुरुआत उन युवाओं की उम्मीदों के साथ करूंगा जिन्हें कहा गया था कि आने वाले समय में बाड़मेर, जैसलमेर को दुबई बनायेंगे, लेकिन धीरे-धीरे उनके सपने चूर-चूर हो गये,

(श्री रविन्द्र सिंह भाटी)

आज की तारीख में उनको कोई रोजगार नहीं है। मैं मेरी बात की शुरुआत उन तमाम किसान भाइयों को याद करते हुए करूंगा ....

श्री सभापति: प्लीज, हिन्दी में, हिन्दी में बोलिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): बिलकुल। उन तमाम भाइयों को याद करते हुए करूंगा जिनको कहा था कि कृषि कनेक्शन देंगे..

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, हिन्दी में बोलिए तभी आपका भाषण नोट होगा। हमारे यहां पर नोट नहीं होगा तो आपका भाषण क्या काम आयेगा? हिन्दी में बोलोगे तो आपकी एंट्री हो जायेगी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): बिलकुल, बिलकुल। आज भी हमारे वह किसान भाई हाथ में पर्चियां लेकर घूम रहे हैं। पिछली सरकार ने तो कुछ नहीं दिया, जिसकी वजह से वह इस तरफ बैठे हैं। मेरा निवेदन तमाम भाइयों से, समस्त मंत्रीगणों से है कि उन किसानों की आवाज को सुनो। बिजली की वजह से वह इस स्तर पर परेशान हैं कि वह आत्महत्या करने के कगार पर आ गये हैं। आपने अभी कहा कि हम राजस्थान की इकोनॉमी को 350 बिलियन डालर तक ले जायेंगे। मेरी यह समझ में ही नहीं आ रहा कि आप 350 बिलियन की बात तो कर रहे हो, लेकिन यह सीमांत क्षेत्र छोड़ दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका रिकार्ड में लेना है या क्या करना है? रिकार्ड में लेने के लिये हिन्दी में बोलोगे तो आपका हर शब्द नोट हो जायेगा। ...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): आज भी मेरा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर का एक्सटेंशन का इंतजार कर रहा है। ...(व्यवधान) माननीय, अब मैं हिन्दी में ही बात रखूंगा।

इस बार के बजट में मैंने तमाम वह मांगें रखीं, प्रदेश की सरकार के आगे रखीं। इन्होंने सुझाव मांगे, भर-भर के सुझाव मैंने भेजे, लेकिन बजट में एक भी जगह शिव विधान सभा का नाम नहीं डाला गया। मेरे शिव विधान सभा की तमाम जनता ने पूछा, उन भाइयों ने पूछा, उन बुजुर्गों ने पूछा कि क्या हुआ, शिव का नाम क्यों नहीं आया? मैंने कहा कि इनको बहुत बुरा लगा कि मैंने एम.पी. का चुनाव लड़ा। मैं आप से ही था, मैं कोई और नहीं था, कहीं और से नहीं आया था। कोई गुस्सा हो तो मेरे से निकालो, मेरे लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। इस बजट में आपने सीमांत के उन लोगों को नकार कर

(श्री रविन्द्र सिंह भाटी)

उनके साथ एक कुठाराघात किया है। हम किसके लिये मांग रहे थे, उन लोगों के लिये जो आजादी के बाद तक उन अभावों में जी रहे हैं और बदले में उनको क्या मिला? मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, अभावों में जी रहे उन लोगों की ओर आप देखें। देश मजबूत तब होगा, बॉर्डर मजबूत तब होगा जब सीमांत क्षेत्र के लोग मजबूत होंगे। उन युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन किसान भाइयों को बिजली मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी, लेकिन आज के समय में बात करने के लिये कोई तैयार नहीं है। अगर कोई भी बात है, कोई भी चीज आप हमसे करें।

(समय: 16.57 बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

उन सीमांत के लोगों को किसी भी चीज की कोई सज़ा ना दें। 2-4 बार आपने सीटी बजाई है ...(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि एस.बी.जी. पर काम करने का समय आया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में उन सीमांत के लोगों का आप विशेष ध्यान रखें।

साथ ही साथ, शिक्षा और चिकित्सा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सारी सीटें खाली पड़ी हैं। पानी की कमी इस स्तर पर है कि जो नर्मदा स्कीम 2017 में पूरी होनी थी, वह अभी तक पेंडिंग चल रही है। जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं, जल जीवन मिशन अभी तक धरातल तक पहुंच ही नहीं पाया है, काम आधा-अधूरा है। कोई मॉनिटरिंग किसी स्तर की नहीं है।

भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक गडरा ब्लॉक की अगर मैं बात करूं जो सीमांत का आखिरी ब्लॉक है, वहां पर डिस्कॉम में ए.ईएन., जे.ईएन. से लेकर नीचे स्टोर कीपर तक, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। किसान आज खून के आंसू रो रहा है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मेरा निवेदन है कि उस गडरा ब्लॉक में जो कहीं न कहीं सीमांत क्षेत्र पर है, वहां पर एक बस स्टैण्ड की जरूरत थी। मैंने कई बार आपकी सरकार से निवेदन किया कि वह देश का आखिरी बस स्टैण्ड है, आप बनवाएं। हमारे लोग छोटी-छोटी चीजें मांग रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, आपका समय पूरा हो गया है।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): लेकिन आप वर्तमान बजट में दे नहीं

(श्री रविन्द्र सिंह भाटी)

पाये। मुझे लगता है कि यह हमारे लिये निराशाजनक बजट रहा। मैं कहना चाहूंगा हमारे लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि उस सदन में जाकर कहियेगा जरूर। मैं जब विद्‌यार्थी परिषद् में था, उस समय कहा करते थे

'कदम-कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम-कदम पर लड़ेंगे तुम से।

दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे।'

वह तमाम लोग आज भी तैयार हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि सड़क से सदन तक की इस लड़ाई को आगे न बढ़ायें।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण। अंकित न हो।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): 000

(समय: 17.00 बजे)

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, यह बजट दिया कुमारी जी के द्‌वारा पेश नहीं किया गया, बल्कि उनके द्‌वारा मात्र पढ़ाया गया बजट है, क्योंकि जब दिया कुमारी जी बजट पढ़ रही थीं तो न तो उनके चेहरे पर खुशी थी, न उनके चेहरे पर मुस्कान थी और न ही उनके अन्दर यह आत्मविश्वास था कि वह राज्य सरकार की वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश कर रही हैं, क्योंकि उनसे मात्र बजट पढ़वाया गया है।

आज इस बजट के अन्दर 'घोषणा' शब्द से ज्यादा 'प्रस्तावित' शब्द ज्यादा हैं और वे विकास के ज्यादा कार्य हैं जिसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने उन कार्यों की या तो घोषणा की या उनके लिए बजट स्वीकृत किया, उनको तोड़-मरोड़कर इस बजट में पेश करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

हम पिछले तीन दिनों से पक्ष व विपक्ष की इस बजट बहस के अन्दर चर्चा सुन रहे हैं। माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्‌वारा बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं। संविधान की बात की जा रही है। लोकतंत्र की रक्षा की बात की जा रही है। देश के प्रधान मंत्री की की जा रही है, लेकिन शायद उनको यह पता नहीं कि इस चुनाव में देश की जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया है। अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र उस दिन कहां चला गया था, जब देश की लोक सभा के अन्दर 100 से अधिक सांसदों का

(श्री अमित चाचाण)

निलंबन एक साथ किया गया था? क्योंकि कोई सांसद आपके खिलाफ कोई आवाज न उठा सके। उस दिन देश का लोकतंत्र कहां चला गया था जब देश का अन्नदाता, देश का पेट भरने वाले हमारे किसान दिल्ली की सड़कें घेरकर बैठे थे? साढ़े सात सौ किसानों ने शहादत देने का काम किया था। उस दिन देश का लोकतंत्र कहां चला गया था जब देश के दो-दो मुख्य मंत्रियों को आपने जेल में डालने का काम किया और आपकी ईडी उनके खिलाफ किसी भी तरह दोष तय नहीं कर पायी? उस दिन देश का संविधान कहां चला गया था जब हमारे देश का नाम रोशन करने वाली हमारी बहन-बेटियां दिल्ली की सड़कों पर बैठकर आपके भाजपा सांसद के खिलाफ आवाज उठा रही थीं? उस दिन देश का लोकतंत्र कहां चला गया था जब चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो रहा था? उस दिन देश का लोकतंत्र कहां चला गया जब कोटा में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, हमारे राजस्थान की जनता की आवाज को उठाया जा रहा था? आपके ही द्वारा विधायकों के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमे करवाये गये, तब लोकतंत्र कहां चला गया था? उस दिन देश का लोकतंत्र कहां चला गया था जब 8 जुलाई को पूरे राजस्थान की जनता ने लोकतंत्र का वह काला दिन देखा कि पार्षदों को नगरपालिका में बैठाकर रखा और आपने चुनाव कराने का काम नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं कि उस दिन देश का लोकतंत्र कहां चला गया जब ईडी/सीबीआई के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी पत्रकार, कोई भी साहित्यकार, आपके खिलाफ आवाज उठाता है, महंगाई के खिलाफ बोलता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है तो आप उसको जेल में डालने का काम करते हैं? वह लोकतंत्र कहां चला गया? आपके मुख से संविधान की बातें, आपके मुख से लोकतंत्र की बातें अच्छी, शोभा नहीं देती क्योंकि आप तो वे लोग हैं जो मुंह में राम रखते हैं, बगल में छुरी रखते हैं। आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं।

चुनाव के दौरान देश के प्रधान मंत्री, जो 140 करोड़ की जनता के प्रधान मंत्री थे, जब चुनावी रैलियों में जा रहे थे, जब वे चुनाव में जा रहे थे, तब देश का किसान, देश का युवा, देश का मजदूर उनके मुख से यह सुनना चाहता था कि हमने किसानों के लिए क्या किया, हमने युवाओं के लिए क्या किया, हमने बेरोजगारों के लिए क्या किया। तब हमें शर्म आयी कि हमारे देश का प्रधान मंत्री, देश में भय पैदा करने के लिए, देश में भाईचारा खतम

(श्री अमित चाचाण)

करने के लिए यह कह रहा था कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस चोरी कर लेंगे। हिन्दू-मुस्लिम के नाम पर पूरे देश में भय पैदा किया जा रहा था। उस दिन पूरे देश की जनता शर्मसार हुई। आप लोग जो राम का नाम लेते हैं, राम की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, आपने अयोध्या चुनाव क्या हारा, यूपी की सीटें आपने क्या गंवाईं, आप के ही नेता प्रधान मंत्री जी ने राम शब्द का नाम लेना ही छोड़ दिया और उन्होंने उसी दिन जय जगन्नाथ कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ओडिशा से आपको सीटें मिली थीं और उसका आईना देश की जनता ने आपको दिखाया।

धार्मिक जगह पर, आपने जो धर्म, हिन्दू धर्म का, जाति का राजनीतिक एजेंडा इस बार देश में बनाया है, उस धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो वोट लेना चाहते थे, इस बार देश की जनता जाग चुकी है, देश का युवा जागरूक हो चुका है और आपको आईना दिखाने का काम किया। मात्र 240 सीटों पर सिमेटने का काम किया, वे सीटें भी ज्यादातर गड़बड़ी कर जीतने का काम किया। जो 14 उप चुनाव हुए उसमें आप सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र दो सीटें मिलीं। महादेव जी ने भी पर्चा दिया, बद्रीनाथ की सीट भी आपके हाथ से निकली। आप ज्यादा सिद्धांतों की, आप ज्यादा संविधान की और आप ज्यादा लोकतंत्र की बातें न करें, क्योंकि देश की जनता ने आपके दोहरे चरित्र को पहचान लिया है और आने वाले समय में, हमारे पूर्व मंत्री आप कह रहे हैं कि अभी झांकी बाकी है, झांकी तो देश की जनता अभी आपको दिखायेगी जब आपके चार राज्यों के उप चुनाव होंगे। राजस्थान में उप चुनाव होंगे तब आपको देश की और राजस्थान की जनता आईना दिखाने का काम करेगी।

आज कुछ सदस्य कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने तो रेवड़ी बांटने का काम किया है, क्योंकि आपको, आपके चश्मे से, आपकी नजर से, आपको गरीब नजर नहीं आता, दलित आपको नजर नहीं आता, युवा आपको नजर नहीं आता, बेरोजगार आपको नजर नहीं आता। आपको तो चंद पूंजीपति घराने नजर आते हैं। अगर घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली दी गयी, जिस गरीब व्यक्ति का बिजली का कनेक्शन कट जाया करता था, उसको राहत देने का काम मुख्य मंत्री ने किया, आपको यह रेवड़ी लगती है। उस किसान का, जब बरसात न हो या ज्यादा हो तो फसल बर्बाद हो जाती है, उस किसान को 2 हजार यूनिट बिजली नि:शुल्क देने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया है, वह

(श्री अमित चाचाण)

आपको रेवड़ी नजर आती है। आज गरीब व्यक्ति का, इस बढ़ती महंगाई में चूल्हा नहीं जल पाता था, यह तो मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लेकर आये, गरीब का चूल्हा जलाने का काम किया, वह आपको रेवड़ी नजर आती है। हमारे युवा बच्चों का सपना था कि हम भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जायें, उस बच्चे के सपने को साकार करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया, वह आपको रेवड़ी नजर आती है। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने पेंशन राशि की बढ़ोतरी करने का काम किया, वह आपको रेवड़ी नजर आती है। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने शहरों के अन्दर भी नरेगा चालू करने का काम किया, वह आपको रेवड़ी नजर आती है क्योंकि आप किसान विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं, आप युवा विरोधी हैं।

आप देश में कहते हैं कि हमने बुलेट ट्रेन चला दी, हमने वंदे भारत ट्रेन चला दी, हमने एयरपोर्टों का विकास करवा दिया, तो आप यह भी तो बतायें कि गांव के अन्तिम छोर पर जो दलित बैठा है, बेरोजगार बैठा है, जिसके घर की जिम्मेवारी इसके कंधे पर है, उस युवा बेरोजगार के लिए आपने क्या किया है? आज भी 70 सालों के बाद गरीब जो अंतिम छोर पर बैठा है, जो बगैर बिजली के बैठा है, बगैर पानी के बैठा है, उसके लिए आपने क्या किया? यह तो आप बतायें। आपने एक काम किया है, सरकार बनने के बाद पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बन्द करने का काम किया, उनके नाम को बदलने का काम किया और जो-जो जन-कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलायी गयी थीं...। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज मैं, मेरे क्षेत्र की बात करूं। हमारे सदन के नेता...सभापति महोदय, मेरा 15 मिनट का टाइम है। संसदीय कार्य मंत्री के इशारों पर आप घंटी बजाने का काम न करें। यह मेरा आपसे निवेदन है, संरक्षण है। आप मेरा टाइम देख लीजिये, मुझे 15 मिनट का टाइम दिया गया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपने क्या कहा?

श्री अमित चाचाण (नोहर): मैंने सही कहा, हम लगातार देख रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बजट पर बोलो...(व्यवधान)

श्री अमित चाचाण (नोहर): आप बैठें, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा 15 मिनट का टाइम है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप पहले बजट पर एक लाइन बोलकर बतायें।

श्री अमित चाचाण (नोहर): मुझे 15 मिनट का टाइम दिया गया है, मैं 15 मिनट बोलूंगा, पूरा बोलूंगा। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप बजट पर एक लाइन बोलकर बता दें।

श्री अमित चाचाण (नोहर): आप चुप रहिये, आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, जो भी कहेंगे मुझे सभापति कहेंगे, आप नहीं कह सकते। आप नीचे बैठिये।

इस सदन के नेता लोक सभा चुनाव के दौरान नोहर में गये थे। वे क्या कहकर आये, क्या आपको पता है? हमारा विधायक अभिषेक मटोरिया है। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि अगर वह आपका विधायक है तो सदन में बैठाइये और बैठाकर मुझे दिखाइये और आप बोलकर दिखाइये कि आपका विधायक है, क्योंकि जनता विधायक चुनती है और जनता ही इस सदन में भेजती है। आपने उसका परिणाम भी देखा है। जनता ने साढ़े सत्रह हजार वोटों से नोहर से भारतीय जनता पार्टी को हराकर भेजा और आपके उस विधायक को घर पर बैठाने का काम किया है।

श्री सभापति: श्री सुभाष मील।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, मेरा अभी टाइम नहीं हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। अंकित नहीं होगा।

श्री अमित चाचाण (नोहर): 000

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय सभापति महोदय, परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा और हमारी उप मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री माननीया दिया कुमारी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए एक शानदार और समावेशी बजट, जो हर वर्ग के लिए बहुत कुछ इस बजट के अन्दर दिया है, उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, बजट पर बहस के लिए मुझे बोला गया है। मैं बजट पर बोलूंगा।

(श्री सुभाष मील)

माननीय सभापति महोदय, पिछले तीन दिन में हमने देखा है कि जब बजट पर बहस चल रही थी, यह पहला बजट है इतिहास के अन्दर जब विपक्ष के साथी बजट पर बहस करने के लिए खड़े हुए, इन्होंने बेशक विरोध किया होगा, लेकिन अंत में हर सदस्य ने यह जरूर बोला है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए इतना बजट देने के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। ऐसा कोई सदस्य नहीं रहा जिसने यह बात न बोली हो, तो अपने आप में यह बात बहुत कुछ कहती है कि विपक्षी लोग भी इस बजट की वाहवाही कर रहे हैं। एक सदस्य ने तो यहां तक कहा कि सरकार ने जो बजट दिया है, आमतौर पर जो सरकारें अंतिम साल में देती है, वह बजट इस सरकार ने पहले साल में दिया है। इसके बाद बचता ही क्या है जब विपक्षी सदस्य यह बात बोल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे कार्यकाल के अंत में जब सरकार बजट देती है तो इस बात को सोचकर देती है कि अगर कोई बड़ी घोषणा करेंगे, बड़े काम की घोषणा करेंगे तो हो सकता है कि अपनी सरकार रिपीट हो जाए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने ऐसा शानदार बजट दिया कि आजादी के बाद पहली बार एक परिपाटी को तोड़ते हुए जो बजट सरकारें आमतौर पर अंतिम साल में देती है, वह कार्यकाल की पहली साल में, पहले वर्ष में देने का काम किया। मैंने अख़बार में एक विपक्षी सदस्य का कोट पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि यह सिर्फ विकास का सपना दिखाने वाला बजट है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जरूरी है विकास के लिए विकास के सपने देखना। किसी काम को पूरा करने के लिए पहले उसके सपने देखने पड़ते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने विकसित राजस्थान का सपना देखा है, तभी ऐसा शानदार बजट उन्होंने पेश किया। यह मैं कहना चाहता हूं।

पिछली कांग्रेस की सरकार में पांच साल सरकार को केवल राजनीतिक अस्थिरता के सपने आते रहे। विकास के सपने अगर आते तो आज सरकार के जो माननीय सदस्य थे, उनको आज विपक्ष में नहीं बोलना पड़ता। मैं देख रहा था जब बजट हमारी वित्त मंत्री जी पढ़ रही थीं, कई विपक्ष के साथी बीच-बीच में विरोध भी कर रहे थे। हो सकता है कि उनको ये लग रहा था कि हमें बजट में कुछ मिला या नहीं मिला। लेकिन जब सत्र समाप्त हुआ और हम वापस जा रहे थे, सबको बजट की कॉपी दी गयी। सब एक-एक कॉपी ले गये और

(श्री सुभाष मील)

दूसरे दिन जब बहस में हिस्सा लेने के लिए आए तो सब लोगों ने, विपक्ष वालों ने भी प्रशंसा की कि हमें बजट में बहुत कुछ मिला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा-

'करीब आने से चलता है हमारी शख़्सियत का पता,

दूर से तो चाँद भी छोटा-सा दिखाई देता है।'

इसलिए जब इन्होंने बजट को पढ़ा तब इनको वास्तविकता का पता लगा। आज बहस में एक विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे, वे एक बात कह रहे थे कि उप-मुख्य मंत्री का पद नहीं होता, उस पर कई तरह के सवाल उठा रहे थे। हमारे साथी उस बात का फिर विरोध भी कर रहे थे। मैं हमारे साथी से भी, आप विरोध कर रहे थे, लेकिन आप उनकी पीड़ा को नहीं समझते।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इनको पीड़ा बता ही दो आप।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय सभापति महोदय, पिछले पांच साल में अगर कांग्रेस की सरकार को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला कोई शब्द था, कोई पद था तो उप-मुख्य मंत्री का था, इसलिए माननीय सदस्य ने अपनी पीड़ा जाहिर करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं एक उन्होंने कविता भी पढ़ी थी कि ये जो निकम्मी सरकार है, उन्होंने कविता के माध्यम से एक बात कही थी, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि

"नहीं है ये निकम्मी सरकार,

आपने किया था युवाओं के सपनों को तार-तार

और आज पेपर लीक के आरोपी हो रहे हैं गिरफ्तार।

मैं कहना चाहता हूं कि

आपने किया था जल जीवन मिशन में खुलकर भ्रष्टाचार,

ये सरकार करेगी हर-घर, हर-नल का सपना साकार।

माननीय सभापति महोदय, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि

आपने तो किया था अपने ही उप-मुख्य मंत्री पर प्रहार,

और यहां पर सब लोग मिलकर चला रहे जनता की सरकार।"

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बजट सत्र शुरू होने के बाद में विपक्ष के साथी कई बार लोकतंत्र की बात कह रहे थे। बीच में कई बार नारे भी उन्होंने लगाए, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। मैं

(श्री सुभाष मील)

इस सम्बन्ध में एक बात आपको कहना चाहता हूं। हमारे यहां की बहुत मशहूर घटना है। एक दंपत्ति किसी गांव में रहते थे। बहुत गरीब परिवार से थे। उनके घर की माली हालत खराब थी। उनका जो आदमी था, वह कोई काम-धाम करता नहीं था। आलतू-फालतू में पूरा दिन गुजारता था और घर वाली कहती थी कि काम करो। उसने सोचा कि क्या करूं, इससे पिंड कैसे छुड़ाऊं, तो उन्होंने फैला दिया। उसने फैला दिया गांव में कि मैं थोड़े बहुत तंत्रमंत्र, जादू-टोना जानता हूं। किसी को दुख-दर्द हो जाए तो मुझको बुला लेना, मैं इलाज कर दूंगा। गांव वाले उसको बुलाने लग गये। वह अपने मंत्र बोलता, गांव वालों को खुश करके या जैसे भी आ जाता। उसकी घरवाली ने देखा कि ये पूरे दिन करता क्या है। लोग इसको बुला-बुला कर लेकर जा रहे हैं। उसने सोचा कि एक दिन इसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये करता क्या है। उसका पति एक जने के घर में बैठा-बैठा झाड़ा फूंक कर रहा था और उसकी घरवाली पीछे छिपकर सुन रही थी कि क्या करता है। उसके पति ने बोलना शुरू किया कि आकाश बांधू, पाताल बांधू, बांधू सारे जग को। पत्नी भी सुनकर हैरान रह गयी। फिर दोबारा बोला कि आकाश बांधू, पाताल बांधू, बांधू सारे जग को। तीसरी बार जब उसने बोला आकाश बांधू, पाताल बांधू, तब घर वाली सामने आकर खड़े होकर बोली कि पहले जाकर घर का छपरा बांध ले, आकाश-पाताल बाद में बांध लेना। लोकतंत्र की रक्षा तो बाद में हो जाएगी, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की कुछ रक्षा कर लो तो आपका भी भला हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, संविधान की रक्षा करने वाले, अभी एक सदस्य बोल रहे थे, लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे थे। थोड़ी देर पहले नारे भी लगा रहे थे। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस की सरकार में जब जालौर के अन्दर एक बच्चे की केवल जाति के नाम पर पानी पीने से पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी, तब लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग कहां थे? जब थानागाजी में एक महिला का उसके पति के सामने रेप किया और सात दिन तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई, तब लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग कहां थे? मैं कहना चाहता हूं कि उदयपुर में जब कन्हैयालाल दर्जी की गला काटकर हत्या कर दी गयी, तब लोकतंत्र की रक्षा करने वाले कहां थे? भीलवाड़ा में दस साल की मासूम बच्ची से सामूहिक बलात्कार करके टुकड़े-टुकड़े भट्टी में जला दिए, तब लोकतंत्र की रक्षा करने वाले कहां थे?

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, कई विपक्ष के

(श्री सुभाष मील)

साथियों ने कहा कि इस बजट के अन्दर रोजगार की बात नहीं की गयी। मैं इनको कहना चाहता हूं कि यह पहला बजट है जिसमें पांच साल के लिए चार लाख सरकारी नौकरी की घोषणा की गयी और इस वर्तमान वर्ष के लिए एक लाख नौकरियों की घोषणा की गयी है। जो भी नौकरियां होंगी, वह भी कांग्रेस सरकार की तरह नहीं, बिलकुल पारदर्शी तरीके के साथ में होंगी, वरना तो पिछली सरकार के अन्दर 19 पेपर, एक के बाद एक पेपर लीक होते गए और हमारे नौजवान हताशा में चले गये।

मैं कहना चाहता हूं कि भजन लाल सरकार के अन्दर 100 से अधिक पेपर लीक के आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी। 10 जुलाई को एक तरफ यहां पर बजट पढ़ा जा रहा था, उसी समय कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, उनके करीबी को पेपर लीक के अन्दर गिरफ्तार किया जा रहा था। माननीय, एक अख़बार ने उनका नाम भी छापा था, लेकिन मैं सदन की गरिमा को देखते हुए वह नाम यहां पर नहीं बोलना चाहता।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री सुभाष मील (खंडेला): सभापति महोदय, मेरा तीन मिनट का समय अभी बच रहा है। मैं समय देख रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिए। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री सुभाष मील (खंडेला): सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वह पेयजल की समस्या है। जो जे जे एम मिशन था, जो पानी के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की थी, उस योजना को बर्बाद करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया।

श्री सभापति: कन्क्लूड कीजिए।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये पहली बार है जब राजस्थान के अन्दर छह बड़ी वृहद पेयजल योजनाओं के माध्यम से सरकार ने 20 हजार 370 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। लोगों के पानी के लिए समुचित व्यवस्था करने का प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, खेलों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि खिलाडियों के लिए पिछली सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिट की घोषणा की थी, लेकिन आज तक नहीं बनी।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री सुभाष मील (खंडेला): हमने खेल नीति 2024 बनाने का फैसला लिया।

श्री सभापति: आप विराजें, प्लीज। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री सुभाष मील (खंडेला): झुन्झुनूं के अन्दर स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का..

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या। आप विराजे, प्लीज।

श्री सुभाष मील (खंडेला): सर, एक मिनट लास्ट में। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि बहुत ही शानदार बजट दिया। जब हमारी वित्त मंत्री बजट पढ़ रही थीं, मैं देख रहा था, विपक्ष के कुछ साथी तालियां तो बजाना चाहते थे लेकिन यूं हाथों को पकड़ लिया, क्या पता कौनसी घोषणा पर टेबल पर हाथ चला जाए। 100 करोड़ की घोषणा खाटूश्याम मन्दिर के लिए हुई। कई सदस्य मेज़ थपथपाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष में बैठे थे इसलिए नहीं थपथपाई।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री सुभाष मील (खंडेला): ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, मैं मेरे क्षेत्र की पांच बात बताना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री सुभाष मील (खंडेला): मेरे क्षेत्र में सरकार ने एक उप जिला अस्पताल दिया।

श्री सभापति: प्लीज।

श्री सुभाष मील (खंडेला): एक सरकारी कॉलेज दिया। एक 33 ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान जी। आपको पांच मिनट बोलना है।

श्री सुभाष मील (खंडेला): जी.एस.एस. दिया। चार पंचायतों के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: चन्द्रभान जी, आप प्रारम्भ करो। आपको पांच मिनट बोलना है, चन्द्रभान सिंह जी। समय प्रारम्भ हो गया। आप प्रारम्भ करो।

श्री सुभाष मील (खंडेला): सभापति महोदय, मैं एक मांग करना चाहता हूं।

श्री सभापति: विराजे, माननीय सदस्य। प्लीज।

श्री सुभाष मील (खंडेला): एक मिनट।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय..

श्री सुभाष मील (खंडेला): चन्द्रभान जी, एक मिनट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजे। अंकित नहीं होगा।

श्री सुभाष मील (खंडेला): 000

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नीम का थाना को हटाएंगे या रखेंगे? यह तो पूछ लो, सरकार रिव्यू करा रही है ज़िलों का।

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि समय बहुत सीमित है, अपनी सीमाओं में हमें बोलना है, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं। आप प्रारम्भ करें, अपने समय में अपनी बात रखें। आपके पांच मिनट हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। वास्तव में भजन लाल जी सरकार ने राजस्थान में जो बजट दिया है वह बहुत ही अच्छा बजट दिया है। मैं चित्तौडगढ़ ज़िले की बात करूं या चित्तौडगढ़ विधान सभा की बात करूं, चुनावी समय का लास्ट साल होता है और बजट देते हैं उस प्रकार का बजट इस सरकार ने फर्स्ट साल में दिया है, तो वास्तव में तारीफ के लायक बजट है। ऐसे बजट का अनुमान सत्ता पक्ष को भी नहीं था और विपक्ष को भी नहीं था कि ऐसा बजट इस साल मिलेगा। जो बजट मिला है वह सराहनीय बजट है। यह बजट धरातल पर लगे, सभी मंत्री भी गए, वहां के प्रशासन को भी अलर्ट किया और ज़मीनों को चिह्नित करने के बारे में भी चर्चा की है। बजट बहुत ही जल्दी धरातल पर लगेगा और काफी अच्छा काम होगा।

मंत्री जी बैठे हैं, संसदीय मंत्री जी भी बैठे हैं, नगरीय विकास मंत्री भी बैठे हैं और काफी मंत्री महोदय विराज रहे हैं। छोटी-छोटी बातें नीचे से उठकर आ रही हैं। सबसे बड़ी बिजली की समस्या उठकर आ रही है। रात को 3-3,4-4 घंटे बिजली जा रही है, उसके बारे में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। किसान हो या गांव का आदमी हो, एक घंटे भी बिना बिजली रहता है, परेशान हो जाता है। पूरे दिन काम करके रात को आता है, रात को जब आदमी सोता है, किसान सोता है, मजदूर सोता है या आम आदमी सोता है, बिजली नहीं आने पर उस पर क्या बीतती है? सिंगल फेज 24 घंटे बिजली देते हैं। आप

(श्री चन्द्रभान सिंह चौहान)

कारख़ानों की थोड़ी कम कर दो या दूसरी कोई बिजली कम कर दो, एग्रीकल्चर की कम कर दो, परन्तु जो घरेलू बिजली है उसको आप 24 घंटे देने की कोशिश करें। अगर काटना भी है तो दिन में काट दें, परन्तु रात को भोजन करते समय या सोते समय बिजली नहीं कटे, इसके बारे में आप एक बार सोचें।

युवाओं की बात करूं। सरकार यह भी रही है, वह भी रही है, दोनों सरकार रही हैं। पेपर लीक होता है तो युवाओं के साथ अन्याय होता है। साल-दो साल उन लोगों ने तैयारी की है। उनके मां-बाप उनको पढ़ाने के लिए ज़मीनें बेच देते हैं, रकम गिरवी रख देते हैं। बच्चे को पढ़ाने के लिए जयपुर भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं या कोई बड़ा शहर होता है वहां भेजते हैं, उसको बाहर भेजते हैं और पेपर आउट हो जाता है। इसमें पहले भी कानून बनाया है। ऐसा सख्त कानून बने कि जो लोग इस प्रकार का गुनाह करते हैं उनको सख्त से सख्त फांसी की सज़ा मिले, युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, जहां भी बड़े-बड़े कारखाने हैं, चित्तौडगढ़ में सीमेंट के बड़े-बड़े कारखाने हैं। हिन्दुस्तान जिंक है, काफी बड़े-बड़े कारखाने हैं। सरकार से एक विनती करता हूं कि वहां काफी युवा बेरोजगार हैं, उनका लोकल 50 परसेंट कोटा फिक्स हो। वहां के बच्चे योग्यतानुसार कैसे नौकरी लग सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करें। धूल मिट्टी वहां के लोकल लोग खाते हैं। काफी दु:ख वहां के लोकल लोग देखते हैं। वहां के बेरोजगार युवा काफी हैं, उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी कैसे लगे, उसके बारे में भी सरकार चर्चा करे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट हुए हैं। सभापति जी, ऐसे मत करो।

श्री सभापति: पांच मिनट का समय था।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, गोशालाओं के लिए अनुदान की बात की है। गोशालाओं को 9 महीने अनुदान देने की बात कर रहे हैं, उसको साल भर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, सभी लोग जब वोट लेने जाते हैं तो हम सब गायों की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, पर गायों के बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष सभी मिलकर, मुख्य मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करें, सरकार से भी रिक्वेस्ट करें कि गायें काफी दु:खी हैं, उसके लिए 12 महीने गोशालाओं को अनुदान मिले।

श्री सभापति: विराजिए। कुमारी रीटा चौधरी।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, दो मिनट का समय दीजिए।

श्री सभापति: पांच मिनट तो कुल आपको मिले हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): मेरे वहां गोचर ज़मीनें ..

श्री सभापति: विराजिए। आपको छह मिनट दे दिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): जब आर.एस. गठाला साहब कलेक्टर थे, उन्होंने सारी ज़मीनें, एक बिलानाम जमीन थी, उन सबको गोचर कर दी। उन ज़मीनों को वापस कैसे कर सकते हैं। पिछली सरकार में हमने चर्चा भी करी कि उनको वापस बिलानाम करें क्योंकि मेरे वहां यू आई टी है। काफी दिक्कत है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। कुमारी रीटा चौधरी।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरी दो-तीन मांग हैं।

श्री सभापति: आप विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़):000

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): आपके लिए रुक तो जाते पर आप हमारा साथ नहीं देते हो।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़):000

श्री सभापति: ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे वक्ता हैं। यह समय की व्यवस्था है, इसको नहीं बढ़ा सकते। आप बोलिए, आपका समय प्रारम्भ है। आपको दस मिनट बोलना है।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): सभापति महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पहला बजट पूर्ण बजट दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं। सभापति महोदय, सरकार जब बजट रखती है तो वह पूरे साल की एक तस्वीर होती है कि किस तरीके से सरकार राज्य के अन्दर काम करेगी, क्या नीति लेकर आएगी, किस तरीके से बजट के अन्दर जो काम दिए हैं उसको क्रियान्वित करेगी।

हमारी पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस सरकार ने लगातार पांच साल तक बहुत शानदार बजट दिया। मैं समझती हूं कि इस बार यह बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, यह बजट उन पांच साल का बजट था, उसी बजट की रूपरेखा के ऊपर यह बजट तैयार किया है।

(कुमारी रीटा चौधरी)

सभापति महोदय, मैं कुछ बिन्दुओं पर बात करना चाहूंगी। हमारे बहुत से साथी बोल चुके हैं। मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगी। मैंने सुना था, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि यह बजट स्वास्थ्य को समर्पित होगा। पिछली जो गहलोत सरकार थी, उन्होंने चिरंजीवी योजना चालू की, 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना चालू की, 10 लाख की दुर्घटना बीमा योजना चालू की। जब यह बजट आया, इसमें जब स्वास्थ्य का पाइंट आया, तो कहीं पर भी उस चिरंजीवी योजना के बारे में किसी भी प्रकार की बात नहीं कही गयी। उस पर वह मौन रहे। आयुष्मान भारत की बात की, लेकिन जनता के अन्दर असमंजस की स्थिति है। उस चिरंजीवी योजना के अन्दर हम स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। कृपलानी जी, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना था, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं आपको कहां डिस्टर्ब कर रहा हूं?

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): आप कर रहे हो, आपस में बोलकर।

हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैंने बजट के अन्दर देखा कि बहुत सारे अस्पतालों को आपने क्रमोन्नत किया। सबसेंटर दिये, पी एच सी खोली, सी एच सी खोली, उसको मॉडल के रूप में भी ला रहे हैं। आप सी एच सी, उप जिला अस्पताल भी बना रहे हैं। वर्तमान में जो स्वास्थ्य केन्द्रों का ढांचा है, गांव के अन्दर हो, चाहे शहरों के अन्दर हो, हम लोग जब बजट लेकर आये, उससे पहले हमें देखना चाहिए था कि वहां पर डॉक्टर्स हैं या नहीं हैं, वहां पर स्वास्थ्यकर्ता हैं या नहीं हैं। आप लोगों ने घोषणा की और उसको अमलीजामा पहनाने के लिए इस बजट में किसी भी प्रकार का बजटीय प्रावधान नहीं किया है।

सभापति महोदय, मैं शिक्षा पर आऊंगी। हमारे शिक्षा मंत्री यहां नहीं हैं और अच्छा है कि वे यहां पर नहीं हैं। शिक्षा का जो बजट अलॉट किया है, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, वह सिर्फ 'ऊंट के मुंह में जीरा' देने जैसा है। हमारी पूर्व की सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। लेकिन इस बजट में इंग्लिश मीडियम जो स्कूलें हैं, उसके बारे में किसी भी तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। उस पर सरकार मौन है।

मैं अपनी विधान सभा की बात करती हूं। बाडेट ग्राम पंचायत है, दूर की पंचायत है। ग्रामवासियों के कहने से वहां के ग्राम चिमनपुरा के अन्दर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली। अब वहां पर आवेदन जो आये हैं, 110 आवेदन वहां पर आये हैं, लेकिन वहां पढ़ाने के लिए टीचर नहीं हैं। मैं आपके माध्यम

(कुमारी रीटा चौधरी)

से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि एक गरीब का बच्चा भी सपना देखता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का। आप लोगों को इस बजट के अन्दर प्रावधान करना चाहिए था। उन इंग्लिश मीडियम स्कूलों को जीवित रखें। उसमें अगर स्टाफ की कमी है तो उन स्टाफ को वहां पर नियुक्त किया जाये ताकि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश माध्यमिक विद्यालय में पढ़ सके।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी शिक्षा के अन्दर प्राइवेट स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जायेगा, उस पर भी कोई प्रावधान इसके अन्दर नहीं किया है।

अब मैं रोजगार की बात करूं। रोजगार में महानरेगा के अन्दर रोजगार की गारंटी दी हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 125 दिन की। ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र के अन्दर भी रोजगार की गारंटी दी। मैं समझती हूं कि एक गरीब व्यक्ति की लाइफ लाइन के रूप में यह नरेगा योजना है। इसके ऊपर भी कि वह 125 दिन चालू रहेंगे या नहीं, इस बजट के अन्दर कोई प्रावधान नहीं है। उस पर भी सरकार मौन है। शहर के लिए भी नरेगा एक लाइफ लाइन है। बीजेपी सरकार को चाहिए कि जॉब क्रियेशन की तरफ वह ध्यान दे। यह नहीं कि जो जॉब क्रियेशन किये थे उनको खतम करने का काम करें।

कहां तो तय था कि उजाला हर घर के लिए,

कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।

सभापति महोदय, युवा विकास और कल्याण के ऊपर इस बजट के अन्दर बहुत कुछ कहा गया। मैंने उस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ा। इसमें चिंता जाहिर की कि युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार बहुत संवेदनशील है। जब मैंने बजट में इस पाइंट को पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप चार लाख भर्तियां अगले पांच साल के अन्दर करने जा रहे हैं। मैंने पूरा बजट पढ़ा। बार-बार पढ़ा। मैंने देखा कि उस बजट के अन्दर कहीं पर भी किसी तरह की कैसे नौकरी दी जायेगी, ना वैकेंसी का कोई अलाटमेंट है, ना उसके लिए कोई बजट है, ना कोई प्रावधान किया है। फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि यह बजट नहीं है, यह तो मोदी चालीसा पढ़ी जा रही है। चालीसा हम पढ़ते हैं, गणेश चालीसा होती है, हनुमान चालीसा होती है, उसके अन्दर ईश्वर ने, हनुमान जी ने, गणेश जी ने क्या बड़े काम किये हैं, उसके माध्यम से पढ़ा जाता है।

सभापति महोदय, मैं पांच मिनट लूंगी। मैं अपने आप बैठ जाऊंगी अपनी बात खतम करके।

श्री सभापति: आपका जो समय है, उसमें आपको समाप्त करना है। आपका एक मिनट शेष है।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधान मंत्री हैं उन्होंने बहुत तरीके बता दिये नौकरियों के। उन्होंने कहा कि नाले की गैस से पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। मैं समझती हूं कि चार लाख में वह भी होगा। उन्होंने हैलीकॉप्टर को रोड पर चलाने का काम करा, तो बहुत सारे हमारे युवा उस हैलीकॉप्टर को धक्का देने के अन्दर काम करेंगे, शायद चार लाख नौकरियों की वह बात आपने की है।

सभापति महोदय, मैं सड़क के लिए बात करूंगी। जो अंतरिम बजट दिया था, चार महीने का लेखानुदान पास किया था हमारी वित्त मंत्री ने, उसके अन्दर पांच करोड़ की सड़क की घोषणा की थी।

श्री सभापति: श्री जेठानन्द।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): मैं समझती हूं कि यह हमारा विशेषाधिकार है कि प्रत्येक जन प्रतिनिधि विधायकगण से पूछकर सड़क दी जाती। वह 5 करोड़ की सड़क हमारी विधान सभा के लिए किसके कहने से दी?

श्री सभापति: विराजिये।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): आप विराजें, मैं अपनी बात खतम करके बैठूंगी।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): मुझे तो उन्होंने पुकार लिया इसलिए खड़ा हुआ हूं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): आपके कहने से ना तो खड़ा होऊंगा और ना बैठूंगा।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): 000

श्री सभापति: आप बोलिये। आपका समय प्रारंभ हो चुका है, जेठानन्द जी। 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2024-25 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, यह जो बजट है, वह जब हमारी वित्त मंत्री दिया

(श्री जेठानन्द व्यास)

कुमारीजी पढ़ रहीं थीं, उस समय हमारे जितने भी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य हैं, विपक्ष वाले भी बैठे-बैठे कुछ ताली बजा रहे थे, कुछ मेज बजा रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि यह ऐतिहासिक बजट जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, उसमें सब खुश हैं। जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, उनको विपक्ष की भूमिका निभानी है, इसलिए उनको विरोध तो करना ही है। जब वह बजट के विरोध में बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पिछली सरकार की गाथा सुना रहे हैं। पिछली सरकार ने अंत में जो बजट पेश किया, वह केवल जनता को लूटने का काम था।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सितम्बर के बाद जिनको पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन और वह, उस समय उनकी पेंशन भी इन्होंने बंद कर दी। उनको उस समय पेंशन नहीं मिली। वह पेंशन भी जनवरी, फरवरी में जाकर उनको मिली है। यानी उनका जो बजट था, इन्होंने चुनाव में लुटा दिया।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है। यह कहते हैं कि बजट में कुछ नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूं कि छह महीने में से तीन महीने तो आचार संहिता के रहे। उसके बाद भी जितना काम इस भजन लाल जी सरकार ने किया है, उतना अगर किसी सरकार ने किया हो तो तुलनात्मक देख लीजिये। आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। केवल भजन लाल सरकार ने ही यह काम किया है।

मैं बताना चाहता हूं कि जब कोरोना का समय था, तब जो हमारे सामने बैठे हैं कांग्रेस के भाई, वह सब होटलों में थे। जनता मौत से जूझ रही थी और यह होटलों में आनंद ले रहे थे। यहां तक कि बीकानेर का तो मुझे पता है, राजीव गांधी ब्रिगेड चंदा करने में लगी हुई थी। जैसे यह संघ का नाम ले रहे हैं। संघ का हर व्यक्ति उस समय मैदान में था। कई जगह भोजनालय चले और सेवाएं कीं। मैं बीकानेर की बात करता हूं, यह बता दें, कांग्रेस का व्यक्ति बता दे कि उसने सेवा की है। चंदे के अलावा कुछ काम नहीं किया। दान दाता जो सामग्री भेजते थे, उस पर अशोक जी की फोटो लगाकर बांट रहे थे।

माननीय सभापति महोदय, यहां एक साथी ने कहा यह थोथी घोषणाएं हैं। अभी तो पहल हुई है और पहल होते ही इन्होंने थोथी घोषणा कह दी। ऐसा लगता है कि इनके पास पूरे पांच साल की एक्स-रे की मशीन है, जो इन्होंने निकाल लिया कि थोथी घोषणाएं हैं। पांच साल बाद देखना यह सरकार कितना

(श्री जेठानन्द व्यास)

काम करती है और राजस्थान में कितना विकास होता है, यह आप सबको पता चल जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, यह कहते हैं आप बार-बार मोदीजी का नाम लेते हो। मैं इनको बताना चाहता हूं और मैं तो लगातार देख रहा हूं कि भारत का प्रधान मंत्री जब विदेशों में जाता था तो विदेशों के प्रधान मंत्री से मिलने के लिये हाथ जोड़कर पीछे खड़ा होता था। आज भारत का प्रधान मंत्री जब विदेशों में जाता है तो विदेशों के प्रधान मंत्री उनसे मिलने के लिये लालायित रहते हैं और कुछ प्रधान मंत्री तो उनके पैर भी छूते हैं। यह हमारे मोदीजी का चरित्र है। भारत का मान बढ़ाने वाला अगर कोई प्रधान मंत्री है तो वह नरेन्द्र भाई मोदी है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वह देश के प्रधान मंत्री हैं। कांग्रेस के प्रधान मंत्री नहीं थे, देश के हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): वह शेरे हिन्दुस्तान है।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): आप अगर देश का प्रधान मंत्री मानते, न तो उनकी निन्दा नहीं करते, आपके नेता विदेशों में जाकर उनकी निन्दा नहीं करते। इसलिये आप अपने नेता को समझाओ कि यह देश का प्रधान मंत्री है, इसलिये वह विदेश में जाकर भारत की बेइज्जती नहीं करे।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्व सरकार के कुप्रबन्धन और रेवड़ी बांटने के चक्कर में महत्वपूर्ण बिजली विभाग को गर्त में पहुंचा दिया था। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय ने प्रदेश को बिजली संकट से उबारने के लिये आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिये हैं और यह कह रहे हैं कि बिजली में कुछ नहीं हुआ। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो कदम उठाये हैं वह आने वाले समय में राजस्थान में बिजली की कमी नहीं रहेगी और राजस्थान दूसरों को बिजली देने लायक बन जायेगा। 3325 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित परियोजनाओं हेतु MOU किया जा चुका है। उत्पादन को गति देने के लिये पूगल, छतरगढ़, बीकानेर आदि में सोलर पार्क विकसित किये जाने का प्रस्ताव सराहनीय है। सम्पूर्ण राजस्थान में विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान सौर ऊर्जा की दृष्टि से अत्यन्त संभावनाओं से भरा हुआ है। पी.एम.सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये 40 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है, इसके लिये माननीय वित्त मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि

(श्री जेठानन्द व्यास)

प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को भी समयबद्ध रूप से सौर ऊर्जा से जोड़ने के बारे में पहल की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की विकास की गति का पैमाना सड़कों का विस्तार होता है। माननीय प्रधान मंत्री महोदय के भारतमाला प्रोजेक्ट का फायदा निश्चय ही राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को मिल रहा है। अब प्रदेश की जब बात होती है, मैं बीकानेर से सम्बन्धित हूं, बीकानेर में हमारे कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री ने पत्थर लगाये हैं, वहां आज तक सड़कें नहीं बनीं, आप जाकर वहां देख लीजिये। चुनावी समय में इन्होंने जो सड़कें बनायीं, वह सड़कें भी राजनीतिक रूप से बनायी गयीं। जहां भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहते थे, वहां बीच में 100 मीटर की सड़क छोड़कर आगे बनायी और पीछे बनायी। वह सड़कें भी छह महीने में बह चुकी हैं, टूट चुकी हैं। हम जो सड़कें बनाने जा रहे हैं वह राजनीतिक नहीं, हम जो सड़कें बनाने जा रहे हैं वह लम्बे समय तक सड़कें चलेंगी। यह ध्यान रखना। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के लिये प्रति विधान सभा क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये की सड़कें व तीन करोड़ रुपये के अन्य आधारभूत संरचना के कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं, जिसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री भजन लाल जी शर्मा और माननीन उप मुख्य मंत्रीजी दिया कुमारी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बीकानेर के पवनपुरी, नागराज जी मन्दिर, माताजी मन्दिर के सामने आर.ओ.बी. के निर्माण की घोषणा से बीकानेरवासियों को बहुत लाभ होगा। इसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूं।

शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के क्रम में बीकानेर में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिये चरणबद्ध रूप से जी.सी.सी. मॉडल आधारित इलेक्ट्रिक बसों की क्रय की घोषणा से लोगों को अवश्य ही राहत मिलेगी। साथ ही ई-बसों के सुगम संचालन हेतु मॉडल शेल्टर होम, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। विभिन्न इकाइयों में बिजली की लाइनों को भूमिगत करने हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा इतना निवेदन है कि मेरे बीकानेर में गलियों, मोहल्लों में जहां पर भी ऐसे बिजली के टावरों का जाल है, उससे हर समय दुर्घटना की संभावनाएं व डर बना रहता है, उसके लिये उनको चिह्नित करके वहां अंडरग्राउंड किया जाये। गौशाला का जो मुद्दा है वह भी गायों के लिये सरकार ने बहुत कुछ किया है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर। (अनुपस्थित) श्री रामकेश मीणा। आज विराजें। समय हो गया। विराजें।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): एक मिनट और।

श्री सभापति: एक मिनट नहीं, विराजें। श्री रामकेशजी।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, बजट 2024-25 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। निदा फाजली की शायरी से शुरू करके और अटल जी की कविता से इस बजट का समापन किया था। वित्त मंत्रीजी ने 2 घंटे 53 मिनट तक इस बजट को सदन में पढ़ा। महोदय, बजट में सबसे जो खास बात देखी कि एक साल की योजनाएं गिनाकर और 2047 तक का विजन माननीय वित्त मंत्रीजी ने सदन में बताया। बजट में रोजगार, शिक्षा, उद्योग, कृषि, महिला, मजदूर, किसान सब पर फोकस किया। सब बिन्दुओं को बजट में छूने की कोशिश की गयी। बजट का प्रावधान किसी न किसी रूप में कम या ज्यादा रूप में किया है लेकिन माननीय सभापति महोदय, हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। आज भी 5.7 लाख करोड़ रुपया सरकार पर कर्जा है और इस बजट में 2.64 लाख करोड़ हमारी आमदनी दर्शायी गयी है और 2.90 लाख करोड़ सरकार का खर्चा और 25 हजार करोड़ रुपया सरकार कर्ज लेने के लिये अभी भी इसमें विचार कर रही है। तब जाकर आपके इस बजट की घोषणाएं पूरी होंगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे लोकतंत्र की खूबी है, संविधान के आर्टिकल 202 से 207 तक लोकतांत्रिक सरकारों को, चुनी हुई जो सरकारें हैं उनको अपना राजस्व इकट्ठा करने की छूट दी गयी है और राजस्व इकट्ठा करने के बाद में उसको किस तरह सरकारें व्यय करेंगी, आय और व्यय का यह जो लेखा है, इसको हम बजट कहते हैं। संविधान निर्माताओं ने यह सोचकर कि लोकतांत्रिक सरकारें जनकल्याण के काम करेंगी और जो राजस्व उनको प्राप्त हो रहा है, उस राजस्व का बंटवारा भी कल्याणकारी योजनाओं में करेंगी, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि जिस तरह की नीतियां और प्राथमिकताएं अभी सरकार ने तय की हैं, उससे सरकार की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है।

बिन्दु संख्या 33 में माननीय वित्त मंत्री जी ने 5 हजार करोड़ रुपये के काम के लिए किले, महल और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रावधान किया है। बजट के बिन्दु संख्या 85 में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं की शिक्षा, रोजगार, बालिका सम्बल और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए मात्र 150 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

(श्री रामकेश)

इसी तरीके से अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी, सफाई कर्मचारी, अल्पसंख्यक समुदाय को भी रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बहुत कम बजट अर्थात् 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये हैं। बिन्दु संख्या 80 में अगर हम देखते हैं तो टीएसपी क्षेत्र में निवासरत जनजाति के परिवारों को मात्र 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे हम लोगों में यह साफ जाहिर हो रहा है कि इस बजट में जो राजस्व प्राप्त होगा, उसका बंटवारा कमजोर वर्ग यानी वीकर सैक्शंस को नहीं करके किले और महलों पर इसका जो फोकस किया है, यह किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है।

मैं अपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथियों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों ने भी अभी अखबारों में देखा होगा, टीएसपी एरियाज में अपने बच्चों को बेचने की भी घटनाएं घटी हैं। साथियों, अपने बच्चों को कौन बेचता है? यह तब होता है जब उसके घर में खाने के भी लाले पड़ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा कोई गरीबी की स्थिति होती है, तब जाकर भी अपने बच्चों को बेचने की कोई बात नहीं करता है। ऐसी स्थिति जब टीएसपी एरियाज में गरीब और मजदूरों के यहां पर बन रही है तो उस वर्ग, क्षेत्र के लिए हमें बजट में निश्चित रूप से बड़े स्तर पर प्रावधान करना चाहिये। यह नहीं करके हम लोगों ने एक बहुत बड़ी भूल की है।

मैं सरकार से, वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा कि हमारे आदिवासियों के लिए, टीएसपी क्षेत्र के लोगों के लिए, जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बजट में प्रावधान उनकी जनसंख्या के अनुसार करना चाहिये। चूंकि अभी जो चल रहा है, 2021 की जो जनगणना है, इसीलिए हमारे राहुल गांधी जी ने मांग की है कि अब जो जनगणना हो, वह जाति के आधार पर हो। जब जाति के आधार पर जनगणना होगी तो निश्चित रूप से हमारे वीकर सैक्शंस के लोग, आदिवासी और गरीब लोगों की सही संख्या पता लगेगी और उसी आधार पर उनके लिए बजट का एलोकेशन होगा।

महोदय, हमारे शासन और सुशासन के सम्बन्ध में पिछली सरकार ने राजस्थान में नये जिलों की घोषणा की थी। पूरे राजस्थान के लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि उन जिलों में अभी बजट मिलेगा, वहां का विकास होगा, क्षेत्र का विकास, जिसके लिए लोग लालायित थे, वहां पर आज सरकार ने एक कमेटी बनाकर समीक्षा के नाम पर जिलों का जो मामला था वह रोक दिया। इस तरह से विकास को अवरुद्ध कर दिया।

(श्री रामकेश)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी ईआरसीपी की योजना है, वह बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है। मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बजट में ईआरसीपी योजना को चालू करने का प्रावधान किया है।

मेरी मुख्य मंत्री जी से मांग है कि ईआरसीपी के लिए उन्होंने जो मध्य प्रदेश से समझौता किया है, जो एग्रीमेंट किया है, जो एमओयू किया है, उस एमओयू की कॉपी हमने पहले भी मांगी थी और अब मैं फिर सदन के माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा, मध्य प्रदेश से आपने क्या समझौता किया और कितनी डिपैंडेबिलिटी पर आपने यह समझौता किया है, 21 जिलों को आप पानी कैसे दे पाएंगे, यह सारी की सारी रूप-रेखा आपको सदन में बतानी चाहिये। आपने पहले भी एमओयू नहीं रखा। अब जब भी आप बजट पर रिप्लाई करेंगे, मैं आपसे मांग करता हूं, क्योंकि यह कोई एक-दो जिलों का मामला नहीं है, 21 जिलों का मामला है, 21 जिलों की पूरी की पूरी जनता आपको देख रही है, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि जब आप अपना जवाब दें तो इसे जरूर सबके सामने रखें।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री अर्जुन लाल।

श्री रामकेश (गंगापुर): हमारे शिक्षा मंत्री जी, जिन्होंने अभी आदिवासियों के सम्बन्ध में एक ऐसा वक्तव्य दिया, आदिवासियों के पिता की जानकारी वे लेना चाहते थे...

श्री सभापति: विराजें। आपका समय पूरा हो गया है। अंकित नहीं होगा।

श्री रामकेश (गंगापुर): 000

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर

सामान्य वाद-विवाद

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 के इस बजट भाषण पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं आपको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं।

श्री रामकेश (गंगापुर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): महोदय, मैं सदन के नेता हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा और हमारी उप मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में जिन्होंने बजट पेश किया, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सर्वजन कल्याणार्थ व समावेशी विकास में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बजट दिया। साथ ही साथ, समस्त क्षेत्र के आधारभूत विकास के लिए उन्होंने जो बजट समर्पित किया है, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवद्द ज्ञापित करता हूं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के संकल्प ''आपणो अग्रणी राजस्थान'' को चरितार्थ करने के लिए ''सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय'' और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर उनके हित में राज्य के सम्पूर्ण विकास हेतु इस बजट को प्रस्तुत किया। मैं इस बजट का स्वागत और अभिनन्दन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा 10 संकल्प बताये हैं- HIS SEAT IQG. H for Human Resource Development; I for Infrastructure Development; S for Sustainable Development; S for Social Securities; E for Economy को बढ़ाने के लिए और A for Agricultural growth and welfare for farmers; T for Tourism, art and cultural promotion; I for Industrial Development & Investment Promotion; Q Quality Life के लिए और G, जो इन सब नौ संकल्पों के साथ चलने के लिए Good governance का जो सपना दिया है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि विकसित राजस्थान का जो 2047 का मुख्य मंत्री जी ने सपना देखा है, यदि इन संकल्पों का सही क्रियान्वयन हो गया तो राजस्थान 2047 के पहले इस सपने को साकार कर देगा।

(श्री अर्जुन लाल)

सभापति महोदय, जैसा कि बजट में कहा गया कि गत सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी थी, साथ की साथ, राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी आ गया था, लेकिन हमारे देश के यशस्वी

(समय: 18.00 बजे)

प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस ध्येय को लेकर हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में और उप मुख्य मंत्री जी एवं वित्त मंत्री महोदय के कठोर परिश्रम जनकल्याण, जन-विश्वास, स्नेह पर खरा उतरने का इन्होंने जो सार्थक प्रयास किया।

महोदय, जिन हालातों में प्रदेश की बागडोर हमें सौंपी गई थी, उस पर मैं यह कहना चाहूंगा-

"कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें,
लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मझधार हमें,
फिर भी दिखाया है हमने और दिखा देंगे सबको,
इन हालातों में भी आता है दरिया पार करना हमें।"

सभापति महोदय, मैं प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर के बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्या है, पेयजल की है। वहां पर वैसे विकास हुआ, लेकिन जो मूलभूत विकास होना चाहिए था वह गत सरकारों ने नहीं किया। हमारी यशस्वी भूतपूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने 308 करोड़ की एक माणकलाव-दांतीवाड़ा योजना बनाई थी, उससे दो नगरपालिकाएं और 119 गांवों को जोड़ने का साकार रूप दिया था। गत सरकार ने उसमें से पेयजल को अन्यत्र ले जाने के प्रयास किये, लेकिन वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इससे निजात दिलाने के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, उसमें 90 से 100 एमएलडी पेयजल मिलना था, लेकिन आज 10 साल बाद भी स्थिति यह है कि वहां 25 से 30 एमएलडी पानी मिल रहा है, इस बदौलत से वहां पर पेयजल की बहुत-बड़ी समस्या बनी हुई है। इसलिए मैं हमारे मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारा जसवंत सागर बांध है, जहां से जोधपुर को निरन्तर तीन साल तक पेयजल की सप्लाई दी गई थी, अन्यथा हो सकता है जोधपुर हो जाता। अब उसकी स्थिति यह हो गई है कि अब वहां पर एक बून्द भी पानी नहीं है। जो भरा रहता था, जवाई की तरह वहां से सप्लाई दी जाती थी, लेकिन उसकी

(श्री अर्जुन लाल)

वजह से वहां पर पानी की कमी हो गई और अब इन्दिरा गांधी नहर से जोधपुर में पानी लाया जा रहा है। अभी इस बजट के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा भी की है कि जवाई से जोधपुर तक 194 किलोमीटर, जो पुरानी जवाई नहर थी, उसका जीर्णोद्धार करके हम जवाई से भी सप्लाई देंगे।

जोधपुर शहर के अन्दर कायलाना, सुरपुरा बांध, उम्मेद सागर बांध सभी भरे रहते हैं। उसकी बदौलत शहर के भीतरी भाग में करीब सभी तहखाने और अंडरग्राउंड में पानी आ जाता है। सरकार को बड़ी-बड़ी क्षमता के पम्पिंग सैट लगाकर उस पानी को बाहर निकाला जाता है तो मेरा निवेदन है कि अब तृतीय चरण की जो पेयजल की पाइप लाइंस, स्वीकृत हुई हैं उसको यदि जोधपुर से नहीं ले जाकर जसवन्त सागर बांध में डाला जाता है तो जोधपुर को ग्रेविटी से भी पानी मिल जायेगा। हमारा यह निवेदन है कि इस प्रोजेक्ट में संशोधन करके जसवन्त सागर बांध में उस पाइप लाइन से आने वाले पानी को पहुंचा दिया जाये तो हमारे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की और आसपास के क्षेत्र की भी मांग पूरी हो जायेगी।

सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री जी भी विराजे हैं। इनका भी मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि आपने गरीब विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री दी है और दो जोड़ी पोशाक भी दी है। गरीब बच्चों को आगे प्रमोट किया। मेरा आपसे निवेदन है कि एक चीज की कमी रख दी गई है, उनको दो जोड़ी जुराब और दो जोड़ी जूते भी साथ में दे दें तो उन बच्चों में एकरूपता आ जायेगी। जो निजी विद्यालय के बच्चे होते हैं, उस तरह राजकीय स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं, उनको भी यह सुविधा उपलबध हो जायेगी। उनके मन की हीन भावना खतम हो जायेगी और उनका मनोबल बढ़ेगा।

श्री सभापति: साहब, विराजें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मुख्य मंत्री महोदय को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने युवा वर्ग को इस बजट में बहुत कुछ दिया है। उसके तहत मेरे बिलाड़ा में नया कन्या महाविद्यालय दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्री उमेश मीणा।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): साथ ही साथ, दो मिनट। हमारा जो अम्बेड़कर राजकीय महाविद्यालय है, उसके अन्दर विज्ञान संकाय खोल दिया

(श्री अर्जुन लाल)

जाये। मेरी दूसरी मांग है, बोरूंदा में जो उप तहसील है, उसको तहसील में क्रमोन्नत किया जाये। ये मेरी डिमांड्स हैं। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री उमेश मीणा।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): जय जौहार। इस सदन को धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने बजट 2024-25 पर बोलेने के लिए मौका दिया, इसके लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र आसपुर की जनता और भील प्रदेश की ओर से, मेरी ओर से आपको खूब-खूब धन्यवाद, जौहार कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं अभी यहां पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ से चर्चाएं सुन रहा था और इस बजट पर बात हो रही थी, कई आरोप-प्रत्यारोप भी हो रहे थे। पक्ष के सदस्यों की तरफ से एक बात आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान के अन्दर सभी विधान सभा क्षेत्रों में कुछ न कुछ बजट दिया है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को कहना चाह रहा हूं कि आसपुर विधान सभा क्षेत्र को, इस बजट को मैंने तीन दिन पढ़ा, एक भी लाइन आसपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए नहीं आई है। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, आदिवासी एरिया में विकास चाहती ही नहीं है।

आज मैं बिजली की बात करूं। आज इस सदन के अन्दर सदस्य बता रहे थे कि तीन घंटे, चार घंटे बिजली नहीं आ रही, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे आसपुर विधान सभा क्षेत्र और डूंगरपुर-बांसवाड़ा के अन्दर ये हालात हैं कि दो घंटे की कटौती के नाम पर सात-सात, आठ-आठ घंटे कटौती की जा रही है और चार-चार, पांच-पांच दिन तक हमारे कई गांवों के अन्दर लाइट नहीं मिल रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। सभापति महोदय, आज मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने एक मांग की थी, 220 केवी जीएसएस की मांग की थी, लेकिन हमारी मांग नहीं मानी गई।

आज सड़कों की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन ब्लॉक हैं, आसपुर, दोवडा, साबला और पाल लेम्बरवाड़ा और निठारों की सड़कों की स्थिति यह है, देश को आजाद हुए 75-76 साल हो गये हैं, लेकिन आज भी वे सड़कें नहीं बनी हैं। वहां पर सड़क नहीं होने की वजह से कोई बीमार हो जाता है तो 6 से 7 किलामीटर खाट पर पेशेंट को बिठाकर वहां दूर लेकर वाहन में बिठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं ऐसी स्थिति मेरे विधान सभा क्षेत्र की है।

(श्री उमेश मीणा)

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत से कहना चाहता हूं कि मैंने यहां पर मुख्य मंत्री और मंत्री महोदय से भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मांग दी थी, लेकिन उनमें से एक भी सड़क इस बजट में नहीं दी गई। बड़े दु:ख की बात है।

आज मैं मेरे यहां बेणेश्वर की बात करूं, मैंने नियम 295 के अन्दर भी लगाया था और मैंने इस सदन में आवाज रखी थी। आज बेणेश्वर धाम जो आदिवासियों की आस्था का केन्द्र है और चार राज्यों के श्रद्धालु वहां आते हैं, लेकिन इस बेणेश्वर के अन्दर भी हमें एक रुपया भी बजट में नहीं दिया गया। बड़े दु:ख की बात है। चार राज्यों की दु:ख की बात है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए।

सभापति महोदय, मेरे एरिया में शिक्षा की बात करूं तो वहां पर जो स्कूलें हैं वे क्रमोन्नत की गई हैं, प्राथमिक स्कूल उच्च प्राथमिक स्कूल में की गई है और माध्यमिक स्कूल उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुई है, लेकिन नियमानुसार इन विद्यालयों में जो कमरे होने चाहिये, वे आज भी कक्षा-कक्ष नियमानुसार नहीं हैं। आज निठावा की एक स्कूल की हालत बताऊं आपको, जहां सीनियर स्कूल बनायी गई है उसमें मात्र तीन कमरे हैं। इन तीन कमरों में बारह क्लास के बच्चे कैसे बैठ पायेंगे? सभापति महोदय, बड़े दु:ख की बात है।

आज मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि यहां के हमारे शिक्षा मंत्री जो वहां पर कक्षा-कक्ष विद्यालयों में नहीं है इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। स्कूलों में स्टाफ नहीं है, इसके लिए बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आदिवासियों के डीएनए पर बात करने के लिए ये तैयार हैं। मां-बाप को, मेरे बाप को गाली देने के लिए तैयार हैं। हमारी मांओं को गाली देने के लिए तैयार हैं। मैं शिक्षा मंत्री को कहना चाह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हो, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। 5 जनवरी, 2011 के कैलाश बनाम महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। यह सौ साल, दो सौ साल नहीं, आठ हजार साल पुराना इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है।

श्री सभापति: विराजिये। श्री हमीर सिंह।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट मुझे दीजिये।

श्री सभापति: आपका समय हो गया। विराजिये। अंकित नहीं हो।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): 000

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2024-25 की वाद-विवाद चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, हर सरकार आती है वह विकास का कार्य करती है चाहे भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, पर आजादी के बाद में अगर अपन देखें तो भारत सरकार में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री बने। गांव, गरीब, किसान से लगा कर पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण से लगा कर इस भारत को देखने का और हर वर्ग तक विकास पहुंचाने का जो कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। राजस्थान में गांव, गरीब और किसान, ढाणी तक अगर विकास कार्य करने का काम किया तो भाजपा की सरकार के स्वर्गीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने किया है। आजादी के बाद शिक्षा, चिकित्सा में अगर गांव और ढाणी तक कार्य किया तो पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा राजे जी ने किया और यह 2024 का बजट जो 10 तारीख को रखा है इस बजट का रोड मैप देख कर विपक्ष क्या राजस्थान की पूरी जनता ने इसकी सराहना की है।

(समय: 18.14 बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, सभी वर्गों को छूते हुए राजस्थान के मुख्य मंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी ने और उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी ने जो यह बजट राजस्थान के हर वर्ग के विकास के लिए दिया है मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा और राजस्थान की पूरी जनता तारीफ तो क्या, अभी जो हमारे साथी कह रहे थे विपक्ष में विराजे हुए भी मन में तो गुदगुदाते हैं कि अच्छा कार्य है और हमारे सबके लिए अच्छा किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी के लिए कहूंगा कि 'काम करो तो ऐसा कि एक पहचान बन जाये, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाये। यह जिन्दगी तो हर कोई काट लेता है, जिन्दगी जीओ इस क़दर कि एक मिसाल बन जाये।' विगत सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी से उतार दिया था। मैं इस सदन में था 2018 से 2023 तक, कई माननीय सदस्य और मंत्री विराजे हैं, कैसा विकास हुआ, क्या हुआ, मैं इस

(श्री हमीर सिंह भायल)

बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि हमारे साथ में भेदभाव किया है। मैं बाड़मेर-जैसलमेर से इकलौता विधायक था, मेरे साथ में क्या किया आपने, कोई कसर छोड़ी थी क्या? सैंक्शंड कार्य आपने होने नहीं दिया। इससे बढ़ कर क्या हो सकता है पर मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हर विभागवार और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करती हुई विकास करेगी, इसमें कोई दोराय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक मैं निवेदन करूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को कि जैसे पूर्व में ईआरसीपी योजना जो राजस्थान के पूर्वी इलाके में बनी हैं, सबसे ज्यादा अगर पेयजल की दिक्कत है तो मैं ईमानदारीपूर्वक कह सकता हूं कि जोधपुर डिविजन में और उसमें भी बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जोधपुर से लगा कर पश्चिमी राजस्थान में। मैं, मुख्य मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि पेयजल की हमारे चार स्कीम्स से जो पानी की योजना चालू हुई थी, पर आज तक पानी सब जगह पहुंचना अत्यंत दूर रह गया है और पेयजल की इतनी तकलीफ होती है। पोकरण-फलसूंड बाड़मेर कैनाल, नर्मदा, उम्मेद सागर पर अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया है, इसलिये योजना बना कर पश्चिमी राजस्थान को पानी देने के लिए अत्यंत आवश्यकता है और पानी की तकलीफ कैसी होती है ...(व्यवधान) उसका नाम आप जोड़ देना।

अध्यक्ष महोदय, पानी की तकलीफ क्या होती है, पेयजल की कमी को लेकर, पानी की अहमियत बड़ी कमाल की होती है। 'अगर दरिया में हो तो गहराई छुपाती है, अगर आंचल में हो तो दिल के राज छुपाती है।' यह पानी की तकलीफ होती है। यह मैंने इसलिये निवेदन किया है आपको कि बहुत अति आवश्यक है। बजट खूब दिया और आगे के लिए भी बजट के लिए एक मेरे साथी पाली से विराजे हैं, सबसे बड़ी पश्चिमी राजस्थान में मैं यह कह रहा हूं कि उद्योग भी चाहिये पर इसके साथ में हमारी मरुदायिनी जो मरु गंगा के नाम लूणी नदी थी, उसको पाली, जोधपुर और बालोतरा ने, उद्योग चलना चाहिये, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर हमारी स्थिति मरु गंगा को बिगाड़ कर पोल्यूशन से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जब तक उसको नहीं सुधारेंगे, आदरणीय भाटी जी भी इस पर बोले थे। मतलब यह सारी तहसीलों से लगाकर किसान बरबाद हो गये, पशु-पक्षी बर्बाद हो गये। यह स्थिति बन गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरी मांग रहेगी कि भूजल, एनिकट जो मेरी एक अरावली श्रंखला विधान सभा में है उसके अन्दर एनिकट

(श्री हमीर सिंह भायल)

गोयनाभाकर और क्षेत्र में भाकरड़ा बेल्ट, रमणिया, भागवा, धीरा, सेला, बांगी, काकी, धारणा, सीमोल, नालगुढ़ा, हिमराणा, थापण, फूलण, दंताला, गोलिया, पीपलोद, गूमरोट, अन्नपूर्णा, मोकलसर, देवन्दी, मोगड़ी, अर्जियाणा ये सारे एनिकट बन जायें तो किसानों के लिए और सबके लिए पानी की सहूलियत हो जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में खूब दिया है, इसके लिये धन्यवाद, पर कल रिप्लाई है और 29 तारीख तक आस बंधी हुई है और सिवाना को पांच साल में इन्होंने प्रताड़ना दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमें हमारी सरकार और मुख्य मंत्री जी खूब बजट देंगे। कुछ मांगें हैं, वे भी निवेदन करना चाहूंगा। राजकीय बालिका महाविद्यालय, छाडो की ढाणी, सिणधरी; सार्वजनिक निर्माण विभाग, अधिशाषी अभियंता कार्यालय, सिवाना जिला बालोतरा; जल संसाधन विभाग, अधिशाषी अभियंता कार्यालय, सिवाना; सांचोर से लगा कर भटिण्डा तक जो रोड़ जाती है हमारी, गुजरात से लगा कर, महाराष्ट्र से लगा कर सिणधरी होकर, वहां कई कैजुअल्टीज होती हैं। एक्सीडेंट होने के बाद, अगर वहां ट्रोमा सेन्टर हो जाता है तो जिन्दगियां बच सकती हैं, इसलिये ट्रोमा सेन्टर खोलने के लिए निवेदन करूंगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चाडो की ढाणी; 33 केवीए के सब स्टेशन, रामपुरा, जटन्तरी, समदड़ी, ओड़ू सिणधरी, रमणिया, बादरू, कूंडल, यह कार्य करवाने के लिये मैं निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा और चिकित्सा जब तक नहीं सुधरेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., सबको आरक्षण मिला है और मिलना भी चाहिये। ई.डब्ल्यू.एस. को भी मिला है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री अनिल कुमार शर्मा।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको भी मिलना चाहिये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: हो गया। सब लोग सात-सात मिनट में पूरा करेंगे।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट से प्रदेश की जनता को बहुत आशाएं थीं, लेकिन जो यह बजट माननीय उप मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किया गया, यह प्रदेश की जनता को बहुत ही निराश करने वाला बजट था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं

(श्री अनिल कुमार शर्मा)

थीं, प्रदेश की जनता को आशा थी कि उनको राहत देने वाली योजनाएं यह सरकार देगी। जैसे कि चिरंजीवी योजना में 25 लाख के इलाज की योजना थी, उसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली के क्षेत्र में 200 यूनिट घरेलू कनेक्शन और 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन की भी कोई चर्चा नहीं की गई। गत सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को जो फूड पैकेट वितरित किये गये थे, उसके बारे में भी इस बजट में कोई चर्चा नहीं की गई। आज भी लोगों के घरों में गहलोत जी की फोटो लगे हुए थैले टंगे हुए हैं और लोग आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह चाहे ओ.पी.एस. का जिक्र करूं, ओ.पी.एस. के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। कोविड काल में अपनी जान जोखिम में डाल कर जिन कोविड हैल्थ असिस्टेंट ने काम किया, उनके रोजगार के बारे, उनको नौकरी देने के बारे में भी इस बजट में कोई चर्चा नहीं की गई।

बिजली के क्षेत्र में बड़े-बड़े दावे किये गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज की स्थिति में प्रदेश में बिजली की व्यवस्था सबसे खराब है और चरमराई हुई है। माननीय सदस्यों ने तीन दिनों में अपनी-अपनी राय रखी, प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की अपनी-अपनी बात रखी। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के जोधपुर डिस्कॉम की बात करूं, मुश्किल से चार घंटे भी लगातार किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिली। गर्मी के समय में तो बहुत भयंकर हालात थे। आज जब बिजली की खपत कम है, लोड कम है, लेकिन वो के वो हालात अब भी बने हुए हैं। विभाग के पास डी.पी. नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, ओवर लोड होकर रोजाना ट्रांसफार्मर, डी.पी. जल रही हैं। बारिश-अंधड़ में पोल गिर रहे हैं। मेरी कल भी अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों का एक ही जवाब है कि मैटेरियल नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है और जब आने का पूछा जाये तो कहते हैं कि अभी कोई संभावना भी नहीं है। बिजली के क्षेत्र में यह स्थिति है, इसको सुधारने की जरूरत है। अभी मैं कई माननीय सदस्यों के सुझाव सुन रहा था। पूर्ववर्ती सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल का 18-20 परसेंट कार्यकाल हो गया, पूरा साल होने को आया है, गत सरकार पर आरोप लगाने के बजाय प्रदेश की जनता को राहत देने का काम करें, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा 2023 में मेरे विधान सभा

(श्री अनिल कुमार शर्मा)

क्षेत्र में 200 के.वी. जी.एस.एस. पातलीसर, 132 के.वी. दल्लूसर और 132 के.वी. घड़सीसर स्वीकृत हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पातलीसर और घड़सीसर का कार्य चालू है, लेकिन बड़ी धीमी गति से चल रहा है और दल्लूसर का अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। ठेकेदार से, कम्पनी से सम्पर्क करने पर कहते हैं कि डेढ़-दो साल लगेंगे। एक-डेढ़ साल हो गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनको तुरंत शुरू करवा कर जनता को राहत देने का काम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरदारशहर में विद्युत लोड को देखते हुए, चूंकि पूरे चूरू जिले में सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कृषि कुएं हैं, सबसे ज्यादा वहां डिमांड है, लोड है, इसलिए सरदारशहर में 132 के.वी. जी.एस.एस. को 220 के.वी. में क्रमोन्नत करने की मैं सरकार से मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत बी.जे.पी. की सरकार में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई थी, जो कि गांव-ढाणियों में बसे हुए कृषकों के कनेक्शन के लिये योजना थी, उसको बंद कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके दीनदयाल उपाध्याय जी संघ के संस्थापकों में से थे, उनका नाम खराब हो रहा है और जो हजारों पीड़ित हैं, जिन्होंने आवेदन कर रखे हैं, वे रसीदें लेकर घूम रहे हैं, इस दीनदयाल उपाध्याय योजना को शुरू कर जनता को राहत देने का काम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी के बारे में दो मिनट में आपको कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में कहें।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): मेरे विधान सभा क्षेत्र में बारिश के समय में पानी की भयंकर समस्या है। गत सरकार में अगेंस्ट फेल्योर 12 ट्यूबवैल मैंने स्वीकृत कराये और नई सरकार के आते ही समीक्षा के नाम पर उनको रोक दिया गया। आज बारिश के समय में सक्षम व्यक्ति तो टैंकरों से पानी मंगवा लेता है, लेकिन आम मजदूर, किसान को बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह ट्यूबवैल तुरंत शुरू कराएं।

(श्री अनिल कुमार शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में कहना चाहूंगा कि शोले फिल्म का हव्वा भाजपा के सभी माननीय सदस्यों को चढ़ा हुआ है। अभी माननीय कृपलानी साहब कह रहे थे कि कितने आदमी थे? माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी राहुल गांधी जी की तुलना उन्होंने शोले के जय-वीरू से की और खुद गब्बर सिंह। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गब्बर सिंह का खातमा भी जय-वीरू ने ही किया था।

श्री अध्यक्ष: अंकित न हो, हो गया। श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): 000

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग आज भी इस सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं कि भजन लाल सरकार की उप मुख्य मंत्री और राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने इतना बढ़िया बजट पेश कर दिया। जनता के सामने, जनता के बीच में बोलने के लिये कुछ नहीं छोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये हमारे मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निवेदन करता हूं कि यह अपूर्व बजट राजस्थान की ग्रोथ का इंजन बनेगा और हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, मैं समझता हूं उसको पूरा करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा और लोक सभा चुनाव में आम जनता ने भाजपा की नीति-रीति, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास किया है। इस बजट को देखें तो हम पांच भागों में बांट सकते हैं। मेरे हिसाब में जब मुझे लगा, मैं यहां सदन में रखना चाहूंगा। पहला है, मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास। दूसरा है, सुशासन और निरन्तरता में विश्वास। तीसरा है, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास। चौथा, सरकार की गारंटी डिलीवरी में विश्वास और पांचवां, विकसित राजस्थान के संकल्प में विश्वास। मुझे आशा है कि यह बजट भाजपा सरकार द्वारा लिये जन कल्याणकारी फैसलों को पूरा करेगा। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा के तुरन्त बाद दूसरे दिन ही मंत्रियों की बैठक बुलायी और मंत्रियों को टास्क दे दिया कि जो घोषणा हुई है, इसको समयबद्ध तरीके से पूरा करें। मंत्रियों को भी कह दिया और अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर कह दिया कि निश्चित रूप से यह जो बजट पेश किया गया है, वह धरातल पर आना चाहिए।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय कम है। मेरे पास कई बातें रखने को थीं, पर आपने दस मिनट का समय दिया है।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): इसलिए मैं आपको दो-तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा। एक तो राजस्थान में कैंसर की बीमारी जबर्दस्त तरीके से फैल रही है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता को अगर हम देखें तो करीब दस प्रतिशत के करीब कैंसर फैल गया है। इस हिसाब से इसकी रोकथाम के लिए मुख्य मंत्री जी ने और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने आर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ, राजस्थान पत्रिका के सम्पादक श्री गुलाब जी कोठारी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि वे अपने समाचार पत्र में अग्रलेख के मार्फत इस मामले में सरकार का और जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और लोग भी जागरूक हुए हैं। श्रीअन्न की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है। निश्चित रूप से आर्गेनिक फार्मिंग होने की वजह से बीमारियों में कमी आयेगी, मैं इस प्रकार का विचार रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें आपके बीच में रखना चाहता था। समय का अभाव है इसलिए मैं सीधे-सीधे मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांगों के सम्बन्ध में कुछ कमियां रह गयी हैं, बजट में छूट गया है, उसके ऊपर निवेदन करना चाहूंगा। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कोटा और सीकर कोचिंग का हब है और कोचिंग के छात्र आये दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैंने भास्कर में एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें बड़ा मार्मिक जिक्र इन आत्महत्याओं का किया गया है। मैं समझता हूं कि जिनके परिवार में कोई बिछड़ जाता है, अपन उनको संवेदनाएं प्रकट कर सकते हैं, उस दु:ख को अपन बांट नहीं सकते। इसलिए सरकार को प्रभावी कदम उठाकर कोचिंग सेंटर्स और हॉस्टल मालिकों के साथ बैठकर कोई इस प्रकार रीति-नीति बनानी चाहिए ताकि जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर कहीं न कहीं रोक लग सके। (समय-समाप्ति सूचक घंटी)

साथ ही, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि बजरी माफियाओं का राजस्थान में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। बजरी माफियाओं पर लगाम नहीं लगायी तो निश्चित रूप से हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रोक लगेगी। हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बढ़ता जा रहा है, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए, वह नहीं बढ़ पा रहा है। यही नहीं, आप बनास के किनारे..

श्री अध्यक्ष: बैठिये, दो मिनट ज्यादा हो गये, विराज जायें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): तो मैं मेरे क्षेत्र की बात तो कर दूं।

श्री अध्यक्ष: पहले वही करते, बाकी बातें बाद में आतीं। अब अगली बार।

श्री जाकिर हुसैन।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट 2024-25 के वाद-विवाद में मैं अपनी बात विस्तारपूर्वक कहूंगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही आहत हूं। मैं शेरशायरी के थ्रू आपको बताना चाहता हूं।

न मांझी है, न रहबर है, न हक में हवाएं हैं,
है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है,
जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में पहली बार दो नयी परम्पराएं हुई हैं। पहली परम्परा यह हुई है कि केन्द्र के बजट के पहले सरकार ने राज्य का बजट पेश किया। +++

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्षीय व्यवस्था के विरुद्ध कोई बात नहीं कही जा सकती है।

श्री अध्यक्ष: यह मेरी व्यवस्था थी, व्यवस्था पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप जनरल भाषण करिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): इसमें लोकतंत्र की हत्या हुई ना।

श्री अध्यक्ष: लोकतंत्र यह थोड़े ही कहता है, अध्यक्षीय व्यवस्था पर टिप्पणी करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): लोकतंत्र और हत्या में अभी फर्क करना समझो।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): मैं यह समझता हूं, +++

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था दे दी। ...(व्यवधान) इन्होंने जो अध्यक्षीय व्यवस्था का कहा है, उसे एक्सपंज किया जाये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, सात महीने आपने कोई उपलब्धि नहीं की, +++ और आप कहते हैं कि हमने पिछले बजट के 53 परसेंट कार्य पूरे कर दिये। मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं कि 53 परसेंट कार्य हो जाते तो +++ ये कह रहे हैं कि कार्य पूरे हो गये।

श्री अध्यक्ष: +++, इसकी व्यवस्था दे दी।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): तीन महीने आचार संहिता लगने के बाद भी यदि 53 परसेंट काम हो जाता है तो सरकार तो बहुत हवा में उड़ रही है। आप एक बात बतायें कि आपने जो पांच-पांच करोड़ रुपये बजट में दिये थे, उनके टेण्डर तक नहीं हुए। आप पूछ लें। हमारी पिछली सरकार में 10-10 करोड़ का गांवों में सड़कों का विकास, नगरपालिका में 7-7 करोड़ का, उनके अधूरे काम पड़े, अर्थव्यवस्था खराब हो रखी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यह बजट दिशाहीन प्रतीत होता है। इस बजट में दलित, अल्पसंख्यक, किसान, छोटे व्यापारी, युवा, महिला आदि के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं दिया गया है। यह बजट मात्र प्रस्तावना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर आपने दस संकल्प की घोषणा की है। इस बजट में विकसित राजस्थान 2047, सर्वजन हिताय के लिए पांच वर्षों में दस संकल्प, इसमें पानी, बिजली, सड़क, शहरी एवं ग्रामीण विकास, किसान, उद्योग, धरोहर संरक्षण, स्वास्थ्य, गरीब एवं वंचित और सुशासन की बात की है। मुझे लगता है कि ये बातें केवल मात्र आंकड़ों के जाल में फंसी हुई प्रतीत हो रही हैं, धरातल में ऐसा कुछ भी नहीं है।

आपको यह कहना चाहता हूं कि सरकार को बने सात महीने हो गये हैं, पर प्रदेश की जो हालत हो रखी है, लूटमार, आगजनी, महिला के साथ बलात्कार, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। सात महीने होने के बाद भी सरकार का कोई मैसेज नहीं है कि राज बदल गया। आज भी हमारी पूर्ववर्ती अशोक गहलोतजी की सरकार को याद करते हैं। अशोक गहलोतजी की सरकार जब-जब थी, पांच वर्षों में बजट दिया, हर बजट भाषण में, हर विधान सभा क्षेत्र, हर जिला, ग्रामीण, हर तहसील को कुछ न कुछ घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है। अगर वे यहां पूरी कर दें तो राजस्थान का पूरा विकास हो जायेगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने महंगाई के नाम से वोट मांगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने महंगाई राहत कैम्प लगाये थे, 25-25 लाख रुपये की चिरंजीवी योजना में लोगों के इलाज हो रहे थे। आम गरीब आदमी की जेब के अन्दर 25 लाख रुपये का कार्ड डाल दिया था, जाओ हास्पिटल में इलाज कराओ। आज कोई पैसे वाला 25-25 लाख रुपये नहीं लेकर जाता है। समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

अध्यक्ष जी, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: छह-छह मिनट हैं। आपकी सूची 45 लोगों की आयी है।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): अभी मेरी मांग ही पूरी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: पहले वह बोलिए, फालतू की बातें, +++ पर बोलिए आप। टाइम तो वो ही है।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): पांच मिनट ही हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: फटाफट एक मिनट में रखिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): मुख्य मंत्री जी ने पेंशन के लिए।

श्री अध्यक्ष: सुश्री नौक्षम। आप तो फिर वही बोल रहे हैं।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): अध्यक्ष जी, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: सात मिनट हैं, आप लोग तो दूसरी सब बातें कर रहे हैं। एक मिनट में करिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): इसमें मकराना का नाम कहीं नहीं आया। मकराना के विकास का नाम 125 पेज के अन्दर कुछ भी नहीं आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मकराना के अन्दर 25 करोड़ रुपये नगरपालिका में सौन्दर्यीकरण के लिए देने की घोषणा करें। गच्छीपुरा उप-तहसील को तहसील बनाने की घोषणा करें। रानीगांव, बेसरोली, मनाणा पीएचसी को सीएचसी बनाने की घोषणा करें। कोला डूंगरी, सरनावड़ा, रामसिया, इन्दौखा में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को पीएचसी बनाने की घोषणा करें मकराना क्षेत्र को रीको बनाया जाए। किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे को फोर लेन की घोषणा करें। और जो पिछली सरकार में दस-दस ट्यूबवैल स्वीकृत हुए थे, समीक्षा के नाम पर वह पेंडिंग पड़े हैं, उन्हें स्वीकृत किया जावे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। कंजूसी की है आपने।

श्री अध्यक्ष: सुश्री नौक्षम।

सुश्री नौक्षम (कामां): औरों के खयालात की लेते हैं तलाशी,

अपने गिरेबां में झांका भी नहीं जाता,

तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए,

(सुश्री नौक्षम)

जूली साहब, जनाब, आपका और हमारा फासले का रास्ता है।

तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए,
साहिल पे खड़े हो तो डूबा भी नहीं जाता है।"

Hon'ble Speaker Saheb, since I am a first timer, if there is a mistake here in the most dignified prayer, House, kindly forgive me. My sincere apology at first. I take my pride in honour to congratulate the Hon'ble Chief Minister Shri BhajanLal Sharma Ji and the Deputy Chief Minister, who is also the Finance Minister of the State, Sushri Diya Kumari Ji for promoting one of the most iconic ever budget presented in the Assembly. I stand by here taking references…

श्री अध्यक्ष: हिन्दी में बोलें तो सबकी समझ में आयेगा।

सुश्री नौक्षम (कामां): हिन्दी में भी अभी आएंगे। I take my pride in also congratulating the entire team who has sat down on the financial terms of 2024-25, by logically implementing one of the finest ever written budgets in the first six months of the Government. India is the largest democratic country in the World, not just the largest democratic country in the World, but one of the biggest financial Hubs developed in the Nation of ever across the Globe (…interruptions…)

मैं आपको हिन्दी में भी समझाऊंगी।

श्री अध्यक्ष: एक ही भाषा में बोलिए, पांच मिनट बोलना है, जो विषय रखना है, पहले रख दीजिए। बाद में और टाइम के लिए कहेंगी।

सुश्री नौक्षम (कामां): हम आपको इस बजट की एक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। आप लोग हमारे सम्मानित साथी हैं। सदन में सबने बहुत बातें रखी। कुछ हमारे विपक्ष के सम्मानित नेताओं के मैंने बयान पढ़े अख़बार में कि ये तो डायरेक्शनलेस है, विजनलेस है, निराशाजनक है। अगर आप सरकार की शुरुआत के छह महीने में इस बजट को निराशाजनक कहते हैं तो जब आपकी सरकार ढहने लगी थी, उस समय के बजट को क्या कहेंगे? आपने तो खानापूर्ति की। जब सरकार के चले जाने का समय आ गया तो मुफ्त, सारे खाते खोल दिए, कितने तो जिले बना दिए, आपको खुद भी याद नहीं होगा। पंचायत स्तर को आपने जिला साबित कर दिया और आप इसको निराशाजनक बता रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कामां विधान सभा से आती हूं इसलिए मैंने जूली साहब को याद किया, क्योंकि वे हमारे हमसाये हैं, पड़ौसी हैं, जूली साहब,

(सुश्री नौक्षम)

आपके यहां पर पांच मंत्रालय वहां चल रहे थे। एक-एक सड़क तीन-तीन बार सेंक्शन हो गयी। डी.एम.एफ.टी. से पैसा लग गया, क्योंकि खनन जोन में है तो कम से कम संगमरमर की सड़क होनी चाहिए थी, जहां एक तिनका भी बजरी नहीं गिरी है। एक तिनका भी बजरी नहीं गिरी तो संगमरमर की सड़कों को, जिनको आपने तीन-तीन बार सेंक्शन किया, वह गया कहां? मेवात विकास बोर्ड से आपके पास इतना फंड आया, अलग से कामां विधान सभा क्षेत्र में लगना चाहिए था। आपकी पिछले 50 साल की जो दशा थी, ऐसी की ऐसी दशा आपने हमको दे दी। एक रुपया कहीं नहीं लगा किसी भी डिपार्टमेंट में। पंचायत में एक जगह साहबजादी थी, एक जगह साहबज़ादा था। एक जगह बेटी थी, एक जगह बेटा था। दूसरी बात, आपकी नगरपालिका में, आपके पीडब्ल्यूडी में, मैं चाहती हूं, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, ये जितने महकमे हैं जिसमें गत सरकार का वहां पर राजकीय धन लगा हो, उनकी एक कमेटी जानी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। पता तो चले लगा कहां है? आप हमसे सवाल जवाब करते हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) हमें तो ये ही समझ नहीं आता कि आपका मोशन किस साइड जा रहा है कि आप हम से सवाल-जवाब कैसे करते हैं?

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी का गृह जिला भी है, गृह लोक सभा क्षेत्र भी है, उनके वहां पर जिस तरीके से पिछले 50 साल की एक मांग पूरी नहीं हुई, जैसे मेवात विकास बोर्ड था, ऐसे ही जैसे ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना का किया है, उसको 50 करोड़ का बजट दिया है, उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ब्रज योजना के तहत एक ब्रज नगरी को आगे बहुत उत्साहित करने का दिया जाना है, मैं उसी तरीके से यह चाहती हूं कि कामां में जहां जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किया गया है, एक आधारभूत, भौतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक विकास की पूर्ण संभावनाएं हैं। मैं आपके माध्यम से इस ब्रज विकास क्षेत्र योजना के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मनीष यादव।

सुश्री नौक्षम (कामां): अध्यक्ष जी, एक सेकण्ड। कन्क्लूड कर रहे हैं। ब्रज रज तज बैकुण्ठ न जाए, ये वही प्राचीन कामवन धाम है जहां अपने माता -पिता के तीर्थस्थल के लिए स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री को प्रकट किया, जो आज विद्यमान हैं। कामां

(सुश्री नौक्षम)
जिसका प्राचीन नाम कामवन है, काम्यवन है, जो ब्रज का पंचमोन्मुख है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट ज्यादा हो गये।

सुश्री नौक्षम (कामां): एक बात और रखना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: बस दस सैकण्ड में रख दीजिए। नहीं। श्री मनीष यादव। आपको एक मिनट एक्स्ट्रा दे दिया। अगली बार।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): अध्यक्ष जी, परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अभी सदन में एक माननीय सदस्य की बहस सुन रहा था, वे कह रहे थे कि अमृत बजट है। मैं पूछना चाहता हूं सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से, साथियों से कि पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, जो बीपीएल परिवारों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं, उनके लिए बनायी गयी थी। उस योजना में गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को जो नौवीं से बारहवीं तक के बच्चे हैं, उनको 1200 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती थी, अगर कोई परिजन की, मुखिया की जान चली जाती थी, 30 हजार रुपये उनको मिलता था, अगर कोई शारीरिक अपंगता हो जाती थी, हादसे में मौत हो गयी तो 75 हजार रुपये दिये जाते थे। आप गरीब के उत्थान की बात करते हैं, आपने इस बजट में इस पन्नाधाय जीवन अमृत योजना को खतम करने का काम किया, उसको कैंसिल करने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से शुरुआत करना चाहूंगा। आज पेयजल की ऐसी स्थिति हो गयी। आज किसान को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, खड़े होकर कोई बात नहीं करेगा। सब बैठिए।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): मैं मेरे क्षेत्र के किसान, जो हर वर्ग का व्यक्ति है, किसान है, किसान सिंचाई के पानी के लिए इंतजार करता रहता है। गर्मी के मौसम में जिस तरीके से मेरे क्षेत्र की जनता परेशान रही है, पानी के लिए दर-दर भटकना पडा। इस गर्मी के मौसम में सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी कि ऐसी आपात स्थिति में लोगों को पानी कैसे पिलाया जाए।

इस जल जीवन मिशन में भी हमारे 95 राजस्व गांव हैं। सात महीने

(श्री मनीष यादव)
सरकार में आने के बाद भी हमारा एक भी गांव जल जीवन मिशन से नहीं जुड़ा। 41 राजस्व गांव में हमारे वहां अभी भी स्टे है। जिस प्रकार यह गर्मी का मौसम रहा, कह रहे है कि टैंकर की व्यवस्था शुरू की है, टैंकर की व्यवस्था में अव्यवस्था रही। अपने-अपने लोगों के घर में डलवाने का काम अधिकारियों के इशारे पर भाजपा के नेता कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने आपको सरकार में लाकर खड़ा किया। सरकार आई तब से राजस्थान की जनता पानी के लिए तरस रही है।

मैं ईआरसीपी की बात करना चाहूंगा। ईआरसीपी का एमओयू हुआ, अभी तक आपने टेबल नहीं किया। चर्चा है कि 3400 एमसीएम पानी राजस्थान को मिलना था, 1788 एमसीएम पानी मिल रहा है, इसलिए आप इसको टेबल नहीं कर रहे हैं, इस एमओयू को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र के बांधों को भी आपने नहीं जोड़ा। आपने बजट में शाहपुरा बांध का जिक्र किया, जबकि शाहपुरा नाम से ऐसा कोई बांध मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं है। विधान सभा क्षेत्र में चार बांध आते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो पंचायती राज के अन्तर्गत आते हैं और दो बांध जल संसाधन में आते हैं, उनको जोड़ा जाए।

बिजली की अव्यवस्था इस गर्मी के मौसम में रही। राजस्थान की जनता जानती है कि हीटवेव की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, लेकिन एक मंत्री या मुख्य मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि राजस्थान में हीटवेव की वजह से जनता मर रही है। माननीय उच्च न्यायालय को कहना पडा कि हीटवेव से अगर कोई मरा है, उन लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा। बड़े शर्म की बात है कि अभी तक मौतों का आंकड़ा सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। पीडित परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैं कानून-व्यवस्था की बात करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिए।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): आज राजस्थान में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, हालात खराब हैं। हर जगह पर जाओ तो महिला अत्याचार। हर जगह पर दिन-रात चोरी, डकैती, लूट, अपहरण के मामले आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा भरतपुर में चिकसाना थाना क्षेत्र के नोगया गांव में दलित दूल्हे की बिंदोरी पर पथराव किया गया। इस सरकार में 6 महीने में 20 हजार 766 महिला अत्याचार के मामले सामने आए हैं। मैं आपका ध्यान

(श्री मनीष यादव)

आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार हर जगह पर विफल है। इस सरकार ने नौजवानों के लिए बड़े-बड़े वादे किए। आपने एक लाख नौकरी का वादा तो किया लेकिन आपने वर्गीकरण करके नहीं बताया कि कौनसी भर्ती किस समय कराएंगे, किस डिपार्टमेंट की भर्ती होगी। न्यायालय का स्टे होता है, वहां किस प्रकार की व्यवस्था होगी?

श्री अध्यक्ष: समाप्त करिए। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़क की अव्यवस्था है। हर जगह इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, उनको ठीक किया जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। बहुत बढ़िया।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजस्व में हम चाहते हैं कि.

श्री अध्यक्ष: अर्जुन लाल जी, बोलिए। आपका टाइम कटेगा। बोलिए। ...(व्यवधान) 6-7 मिनट ही हैं सबके लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सब अच्छे वक्ता हैं, सब अच्छा बोल रहे हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): परिवर्तित बजट 2024-25, मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने पढ़ा। इस बजट की गांवों, ढाणियों, शहरों में, चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के विधायक भी गुपचुप तरीके से प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान को बीमारू प्रदेश से निकालकर विकसित राज्य बनाने की संकल्पना, रामराज्य की परिकल्पना के आधार पर इस राजस्थान को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं पिछली सरकार के बारे में आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। लगातार आप विपक्ष वाले प्रहार कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रहार से हम रुकने वाले हैं, कुछ अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। आपकी सरकार में आपने राजस्थान का अनाथ करने का काम किया।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

कुर्सी के चक्कर में दो-दो बड़े नेता लड़ने लगे। गहलोत साहब कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और पायलट साहब व उनके सहयोगी साथी विधायक गहलोत साहब को कुर्सी पर देखने को तैयार नहीं थे। यानी कि किस्सा कुर्सी का चलने लगा। कुर्सी के चक्कर में राजस्थान की जनता पिछले पांच सालों में परेशान हो गई। कबीरदास जी ने सही कहा था, 'अंधेर नगरी चोपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा'। 'चलती चाकी देखि कै दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई'। इस प्रकार से राजस्थान की जनता पिसती रही। कांग्रेस राज में कोई सुनने वाला नहीं था। अंधेर नगरी हो गई थी।

कांग्रेस राज में क्या-क्या नहीं हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस राज में जितना भ्रष्टाचार हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार भी इस क़दर कि आपके खजाने में सचिवालय में करोड़ों रुपये मिल रहे हैं, किलो-किलो भर सोना मिल रहा है। चोरी, नकबजनी में राजस्थान प्रथम रहा। भ्रष्टाचार में प्रथम रहा। लूट-डकैती में प्रथम रहा। हत्याओं में प्रथम रहा। कन्हैयालाल की उदयपुर में हत्या हुई। चित्तौड़ में हत्या हुई। भीलवाड़ा में हत्या हुई। नाबालिग बच्ची से बलात्कार करके भट्टी में झौंककर उसको मारने का काम आपने किया। बालिकाओं का अपहरण और हत्याओं में प्रथम रहा। बदमाशों की सीमा यहां तक भी कम नहीं रही और राजस्थान के अन्दर नकल गिरोह पनपाने का काम आपने किया। पेपर लीक के माफियाओं को पनपाने का काम आपने किया। बजरी माफियाओं को पनपाने का काम आपने किया। जमीन घोटाला करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। जोधपुर जिला प्रशासन में पीएमओ को भेजी असत्य रिपोर्ट, गलत नक़्शे से 30 बीघा जमीन गायब कर दी। यह जोधपुर में जादूगर जी रहते हैं, 30 बीघा जमीन गायब कर दी। शराब माफियाओं को आपने पनाह दी। जमीन माफियाओं को आपने पनाह दी। जमीन माफिया में, तहसीलदार के आदेश से पहले ही 1500 बीघा जमीन का म्यूटेशन खोल दिया। यह सारे आपके कारनामे हैं। मानव तस्करी, अवैध हथियार का कारोबार, नशीले पदार्थों की सप्लाई के कारोबार में आप प्रथम रहे हो। मिलावट के माफियाओं को पनपाने का आपने काम किया। जनता पांच साल तक डरकर जीवन बिताने के लिए तैयार थी और सरकार होटलों में रहकर मौज-मस्ती कर रही थी। जादूगर बंसी बजा रहा था और

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

राजस्थान की जनता भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रही थी। ...(व्यवधान) रोम वाला नहीं, यहां जादूगर वाला मामला हो गया।

इतना ही नहीं, प्रशासन के अन्दर, सरकारी महकमों के अन्दर कोई भी फाइल अगर एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाती तो भ्रष्टाचार के बिना नहीं जाती थी, हर फाइल पर पैसा देना पड़ता था। सचिवालय के अन्दर करोड़ों रुपये के घोटाले हुए। घोटालों में कोयला घोटाला, उस घोटाले को आपने देखा होगा, किस प्रकार से घोटाला हुआ। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो-तीन मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपने डिस्कॉम अजमेर में एक हैदराबाद की कम्पनी को ठेका दिया, उसने 149.54 करोड़ का टेंडर लिया। टेंडर तो ज्यादा का लिया, लेकिन 149.54 करोड़ का टेंडर लेने के लिए इतनी बैंक गारंटी दी। जब उस बैंक गारंटी की जांच हुई तो यह बैंक गारंटी फर्जी निकली। आपके शासन में लगातार, उन्होंने कोयला सप्लाई किया और अनेकों काम उन्होंने किए, जब पता चला तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम भी हो रहा हे।

आपने जल जीवन मिशन का घोटाला किया। आपने फूड पैकेट में घोटाला किया, यह भी अख़बार में छपा। यह आपने देखा होगा, 1700 रुपये करोड़ का मिड डे मील में घोटाला हुआ है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट और। मोबाइल घोटाला हुआ। आधे को बांटे, आधे को नहीं दिए, कहां गए कहां नहीं गए। जमीन घोटाला, स्टाम्प घोटाला, बिजली के ठेकों में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, घोटालों की सरकार चली थी और आप कह रहे हो कि हमने अच्छा शासन दिया। आपने पेपर लीक करके ऐसा काम किया कि आपने किसी को नहीं छोड़ा। 17-17 बार पेपर लीक हुए। अंत में एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री चुन्नीलाल। चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट हो गए और।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: एक वाक्य कह दो, जो कहना है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: इतनी देर में कह ही देते।

(समय: 19.00 बजे)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): पिछली सरकार बिना काम किये, किया विलासी व्यवहार, कोरोना में भी खूब कमाया, लाखों का व्यापार सजाया। कुछ तो लाज-शर्म करते, क्यों 17 बार पेपर लीक करवाते ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): इसीलिए हमने कहा था कि कांग्रेस राज की कब्र खुदेगी। आपने समय दिया और राजस्थान का बजट बड़ा ही सराहनीय रहा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट 2024-25 पर अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: बोलिये, बोलिये।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के माध्यम से अपनी केशोरायपाटन विधान सभा के बारे में बताना चाहता हूं, उसमें पाटन, कापरेन, लाखेरी, इन्द्रगढ़, चार नगरपालिकाएं आती हैं, जो राजस्थान की किसी भी विधान सभा में नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फिर भी वहां पर कोई कॉलेज नहीं है कोई पंचायत समिति नहीं है।

आपने पिछले सत्र में, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, उप मुख्य मंत्री जी ने कॉलेज की घोषणा की थी, लेकिन इस बजट में आपने वह घोषणा भी नहीं की है। मेरी विधान सभा में कोई घोषणा नहीं की जबकि पहले सत्र में आपने घोषणा की थी, उसके बावजूद भी आपने बजट में नहीं लिया।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अशोक गहलोत जी ने राजस्थान को बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं दीं। हमारे कैम्प लगाये। राजस्थान की जनता को सुख-सुविधाएं देने का प्रयास किया लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम हार गये, आप उधर बैठ गये, हम इधर बैठ गये।

(श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा)

मोदी जी ने इस बात का वादा किया था लोक सभा में कि हम 400 सीटें जीतकर आयेंगे, लेकिन नतीजा यह हुआ कि आप 240 पर ही रह गये। अभी-अभी जो इलेक्शन हुए, सात राज्यों में चुनाव हुए आपने देखा होगा कि आपकी मात्र दो ही सीटें आयीं। आपकी दो ही सीटें आयी हैं इसलिए आप घमंड मत करो। आज हम यहां हैं, कल वहां होंगे। आप यहां होंगे और हम वहां होंगे। आपकी दो सीटें आयी हैं। आप अयोध्या में हार गये और बद्रीनाथ में हार गये। आप हिन्दुत्व की बात करते हो, आप दोनों ही जगह हार गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा शहर में कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। कोटा औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था, बाद में उसको एजुकेशन नगरी के नाम से जानने लगे, लेकिन वहां रोज कोई न कोई आत्महत्या होती है। पूरे भारतवर्ष के लोग ही नहीं, इंडिया से बाहर के लोग भी कोटा में पढ़ने आते हैं। कोटा की स्थिति यह हो गयी है कि वहां का प्रशासन, वहां का एसपी, कलेक्टर देखते रहते हैं और रोज आत्महत्याएं हो रही हैं। यह कोटा के लिए दुर्भाग्य की बात है। वहां बड़े-बड़े हॉस्टल बन रहे हैं, उनमें लड़कों से मनमानी फीस ली जा रही है, मनमाना किराया लिया जा रहा है। आज यह स्थिति है कि एक ऑटो वाला कोटा जंक्शन से अपने निवास स्थान पर आने के लिए 500 रुपये ले रहा है। जो लोन लेकर बड़े-बड़े मकान बना रहे हैं, जो लड़कों को रखते हैं वह 15-15, 20 -20 हजार रुपये किराया लेकर उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। इस बारे में अंकुश लगना चाहिए। कोटा के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए राजस्थान में 2000 से अधिक महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले गये थे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को सुधारने के लिए यह सरकार की ओर से महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत गहलोत सरकार ने की थी, लेकिन आप लोगों ने, आपकी सरकार ने, भजन लाल जी की सरकार में उनको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। मैं मानता हूं कि गांवों में हमने इन 2000 स्कूलों को खोला है। राजस्थान ग्रामीण परिवेश का प्रदेश है, 80 परसेंट जनता गांवों में रहती है। क्या गांव के लड़के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते? क्या उनको अंग्रेजी की शिक्षा नहीं दी जा सकती?

श्री अध्यक्ष: आपका टाइम हो गया। पूरा करें।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): अध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं आपको बताऊं, हमने वन टाइम पेंशन स्कीम लागू की थी, आपने बंद कर दी।

श्री अध्यक्ष: हो गया। श्री भागचन्द।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): चिरंजीवी योजना जिसमें हम 25 लाख रुपये देते थे।

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका टाइम ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट भाषण 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

आपने मेरी विधान सभा में बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं। मेरी विधान सभा में एक आरओबी की आपने घोषणा की, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की घोषणा की, नगरपालिका को क्रमोन्नत किया। एक उपभोक्ता कोर्ट की अभी आपने घोषणा की है। एक 220 जीएसएस की घोषणा, एक 33/11 जीएसएस की घोषणा की है। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब की भी घोषणा की है, जो कि पूरे राजस्थान में आठ हैं। उसके लिए वित्त मंत्री जी को दिल की गहराइयों से बांदीकुई की जनता की ओर से धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जिला ही बचा है, वह भी ले लो।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): वह भी लेंगे। मिलना चाहिए। मेरी कुछ मांगें हैं। ईआरसीपी के अन्दर मेरी विधान सभा का एक भी बांध नहीं जोड़ा गया है। सदन के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा के बांध जोड़े जायें। बांदीकुई शहर के अन्दर एक बाईपास दिया जाये, शहर के अन्दर भीड़-भाड़ रहती है। आभानेरी और झाझीरामपुरा, सांवलिया धाम करणावर, ननदेरा व बिवाई डूंगरी को हैरिटेज घोषित किया जाये और वहां विकास कार्य करवाये जायें।

अभी मेरे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि हमारी जो घोषणाएं हैं, वह धरातल पर हैं। मैं विपक्ष के नेता को यह अवगत कराना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने मेरी विधान सभा में एक ट्रोमा सेंटर की घोषणा की थी जो आज भी वह जमीन अलॉटमेंट में है। एक महिला आईटीआई की घोषणा की थी, वह

(श्री भागचन्द टांकड़ा)

भी जमीन अलॉटमेंट में है। आप थोड़ा-सा इस चीज का ध्यान रखें। आपकी थोथी जो घोषणाएं थीं, इसी का कारण है कि आप उस ओर बैठे हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सभी खड़े रहोगे 5-5 एक जगह पर। नियमों का पालन नहीं करते। यह मैं तीसरी बार कह रहा हूं। वहां भी यही करते हो, यहां भी यही कर रहे हो।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): 2017 में एक आरओबी का सैंक्शन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पूरे पांच साल में उस आरओबी का निर्माण पूर्ण नहीं कर पाये आप। ऐसी इनकी सरकार थी। लगातार 5 साल तक उस काम को बंद रखा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वह काम दोबारा चालू हुआ है। इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं कि जिस काम की हम शुरुआत करते हैं उसका अंत भी हम करते हैं, जिसका जीता-जागता उदाहरण मेरी विधान सभा में आप ओवरब्रिज देख लेना, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शुरू हुआ और जिसका समापन, लोकार्पण भी होगा। जीता-जागता उदाहरण बांदीकुई में आपको देखने को मिल जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभा चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवर्तित बजट 2024-25 पर मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

वर्ष 2047 का विजन संकल्प लिये सर्वजन हिताय कार्यों के समावेश के साथ प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बेहतरीन एवं उत्कृष्ट बजट हमारी भाजपा सरकार ने पेश किया है। इस परिवर्तित बजट में हमारी सरकार ने जन कल्याण की भावना को 10 संकल्प के साथ अमृत काल खंड विकसित राजस्थान 2047 का आईना प्रस्तुत किया है।

इस बजट की विशेषता के बारे में कई वरिष्ठ जनों ने मुक्त कंठ से दिल खोलकर प्रशंसा की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी जिन पर ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार देश की जनता ने विश्वास जताकर एक बार फिर से देश के नेतृत्व की बागडोर सौंपी है, उनके मार्गदर्शन में माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा इस बजट में संपूर्ण राजस्थान के हर वर्ग यथा गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ा,

(श्रीमती शोभा चौहान)

महिला, किसान एवं युवा वर्ग के साथ हर क्षेत्र के विकास के सभी पहलुओं का समावेश किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस परिवर्तित बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत को बहुत कुछ मिला है। मेरे क्षेत्र की जनता को चिकित्सा हेतु विधान सभा क्षेत्र में ही जिला अस्पताल की सारी सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिये सोजत शहर स्थित आचार्य श्री रघुनाथ जैन स्मृति उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किये जाने पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी भजन लाल जी शर्मा, उप मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी एवं चिकित्सा मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार ज्ञापित करती हूं।

महोदयजी, कोरोना काल के समय जब अस्पताल में अतिरिक्त संसाधनों और उपकरणों की आवश्यकता थी, तब विधायक कोष से मेरे द्वारा 75 लाख की राशि जारी की गयी ताकि मेरे क्षेत्रवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। उप जिला चिकित्सालय के मापदंड तय हुए तभी से इस अस्पताल को क्रमोन्नत किये जाने का मेरा प्रयास जारी रहा है। वर्तमान में कई विशेषज्ञ, डॉक्टर एवं आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण इमरजेंसी में रोगियों को जिला अस्पताल हेतु रेफर कर दिया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार की बदौलत अब ऐसा नहीं होगा। रोगियों को जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं इसी सोजत हॉस्पिटल में मिल सकेंगी। इसका फायदा सोजत शहर सहित आस-पास की ढाणियों, गांवों और कस्बों की देवतुल्य जनता को मिल सकेगा। जिला अस्पताल की सौगात के साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र के बगड़ीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 30 रोगी भर्ती पलंग व्यवस्था में बढ़ोतरी कर दिये जाने पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, उप मुख्य मंत्रीजी का एवं चिकित्सा मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं। महोदयजी, मगरा क्षेत्र से जुड़ी वंचित जनता के लिये सी.एच.सी. सरकार द्वारा प्रदान की गयी, इस सुविधा का बहुत लाभ मिल सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के मध्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 162 गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंडावल नगर पुलिस चौकी संचालित है। राजमार्ग की घटनाओं एवं अपराधों की रोकथाम के साथ आस-पास के क्षेत्र की समुचित कानूनी व्यवस्था का जिम्मा इसी पुलिस चौकी पर है। कई बार आवश्यक दायित्वों के सामने अपर्याप्त संसाधन छोटे पड़ जाते हैं। इस कारण मेरी मांग पर सरकार द्वारा इस पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत

(श्रीमती शोभा चौहान)

कर दिया गया। इसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कोटि-कोटि आभार व्यक्त करती हूं। पुलिस थाना संचालित होने से क्षेत्र में निश्चित रूप से अपराधों में कमी आयेगी और क्षेत्र में सुशासन देने में मदद मिलेगी।

(समय: 19.11 बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से माननीय मुख्य मंत्रीजी का एवं उप मुख्य मंत्रीजी एवं नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी झाबर सिंह जी खर्रा साहब का कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत रोड ग्राम पंचायत को भी नगरपालिका में क्रमोन्नत कर दिया गया और आबादी के हिसाब से बड़ी ग्राम पंचायतें, नगरपालिका बन जाने से कस्बे के विकास को एक नई दिशा मिल सकेगी और शहरी सुविधाएं मिलने से आमजन के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

पाली, जैतारण शहर सहित मेरे विधान सभा क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने के लिये 23 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि स्वीकृत किये जाने पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का और जलदाय मंत्रीजी का मैं कोटि-कोटि आभार प्रकट करती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्री एवं उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रायपुर ग्राम पंचायत कहने को तो ग्राम पंचायत है लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहरी श्रेणी में आने के कारण विगत कई वर्षों से डॉक्टर पदस्थापित नहीं है। उप खण्ड मुख्यालय पर स्थित यह अस्पताल मगरा और मैदानी क्षेत्र के लिये जीवनदायिनी है लेकिन डॉक्टर नहीं होने के कारण कई बार मरीजों को ब्यावर और सोजत अस्पताल ले जाते समय रास्ते में घायल दम तोड़ देते हैं। एक-दो डॉक्टरों के भरोसे चलने वाले इस अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के समय तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से रायपुर सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने हेतु आग्रह करती हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पूर्व में भी रायपुर उपखण्ड की वैसे 25 हजार जनसंख्या है। पहले वह नगरपालिका थी, लेकिन कुछ समय बाद ही नगरपालिका को भंग करके उसके

(श्रीमती शोभा चौहान)

स्थान पर ग्राम पंचायत बना दिया गया। महोदयजी, उपखण्ड कार्यालय, तहसील, पंचायत समिति सब होते हुए भी, नगरपालिका के सभी मापदण्ड भी पूरे करती है, विगत सरकार की उपेक्षा के कारण रायपुर ग्राम पंचायत को नगरपालिका नहीं बनाया जा सका लेकिन लोक कल्याणकारी भाजपा सरकार से उम्मीद है कि इस ग्राम पंचायत को भी नगरपालिका की सौगात मिलेगी। अत: रायपुर ग्राम पंचायत नगरपालिका बनाये जाने हेतु सरकार से मैं आग्रह करती हूं और महोदय जी, रायपुर उपखण्ड पर पुलिस थाना संचालित है। एन. एच. 162 पर आपराधिक घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी...(व्यवधान)..

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): एक मिनट, सर। पुलिस आपराधिक घटना स्थल पर समय पर नहीं पहुंच पाती। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं थाने में दर्ज अपराधों की संख्या को देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय स्वीकृत किया जाये। साथ ही कुशालपुरा ग्राम पंचायत में स्थित पुलिस चौकी, जिसकी तहसील उपखण्ड कार्यालय रायपुर लगते हैं, लेकिन पुलिस थाना जैतारण लगता है, पुलिस थाना एवं उपखण्ड कार्यालय की अधिक दूरी होने के कारण पुलिस कार्यवाही प्रक्रिया निस्तारण में काफी समय लगता है, अत: कुशालपुरा पुलिस चौकी को रायपुर थाने में क्रमोन्नत किया जाये।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, रमीला जी।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट भाषण के ऊपर बोलने का आपने मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैंने सत्तापक्ष के लोगों का भी भाषण अच्छी तरह से सुना और विपक्ष के लोगों का भी भाषण सुना है। ..(व्यवधान).. आप बोलते हैं उस समय मैं बीच में नहीं बोलती इसलिये आप सुनें।

श्री सभापति: बीच में कोई नहीं बोलें।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): सब लोगों का मैंने भाषण सुना है और बजट भाषण को भी अच्छी तरह से सुना है। जब करोड़ों का बजट आया तो इस बजट के अन्दर मैंने सोचा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मेरे कुशलगढ़ का कहीं न कहीं नाम आयेगा, पर इस कुशलगढ़ का नाम ही कहीं नहीं आया। मैं जब निर्दलीय सदस्य के रूप में सदन में बैठती थी तब कुशलगढ़ को करोड़ों का बजट मिलता था। मंत्री महोदय हमारे पीछे ही बैठते थे। कांग्रेस सरकार का

(श्रीमती रमीला खड़ीया)

जब बजट आता था तो उस समय विपक्षी भी टेबलें अच्छी तरह से थपथपाते थे। यह मैंने अच्छी तरह से देखा है। जिस तरह से उनके चेहरे पर, हमारे मंत्रीजी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से खुश होते थे और हंसते थे, हम पास में बैठते थे। ..(व्यवधान).. इसी तरह से मुझे एक पत्रकार महोदय ने फोन किया, जिस दिन बजट आया उसी शाम को कि, विधायक महोदय, कुशलगढ़ को क्या मिला? मैंने यही जवाब दिया कि जब मैं निर्दलीय थी तब तो कांग्रेस सरकार ने मुझे जो मांगा वह भी दिया और नहीं मांगा वह भी मुझे दिया, आज मैं हाथ के पंजे पर जीतकर गयी हूं इसलिये मैं विपक्ष में बैठी हूं इसलिये मुझे कुछ भी नहीं मिला।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार का जब बजट आता था तो सबके मन में और सबके दिलों में यह था कि आज तो कुछ न कुछ हमको मिलेगा और वास्तव में जब बजट पढ़ते थे तो सभी माननीय सदस्यों के लिये छोटी-मोटी घोषणा जरूर होती थी और बहुत खुश होकर हम यहां से निकलते थे। इसी तरह से आज जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, जिस तरह से मेरा विधान सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात से लगता हुआ है, बिलकुल इसी तरह से मैं आज यह कहना चाहती हूं कि हमारा इलाका आदिवासी इलाका है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, कम से कम महिलाओं का ख्याल रखो। आदिवासी का नाम लेते ही आपने घंटी बजा दी। शिक्षा मंत्रीजी की तरह आप भी कर रहे हो क्या?

इसी तरह से हमारे आदिवासी क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़कों की काफी समस्या है। आप देना चाहते हैं, हमारे मंत्री महोदय बैठे हुए हैं पीडब्ल्यूडी के, मैं आशा करती हूं और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय जरूर मुझे करोड़ों के काम...

श्री सभापति: श्री हरलाल सहारण। विराजें, माननीय सदस्य, समय समाप्त हो गया आपका। सबको 5-5 मिनट मिले हैं।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): सर, प्लीज मैं बोलती ही नहीं हूं। ऐसे क्या कर रहे हैं?

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): 000

श्री हरलाल सहारण (चूरू): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे 2024-25 के बजट पर अपनी बात रखने का मौका दिया। सभापति महोदय, सरकार द्वारा पेश बजट को मैंने अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश की। मैं सदन में पहली बार आया हूं। मुझे उम्मीद थी कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य उप मुख्य मंत्री के द्वारा सदन में प्रस्तुत बजट की पैरावाइज तथ्यों के आधार पर आलोचना करते तो सार्थक बहस होती। सभापति महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि सदन में बजट की बहस में प्रतिपक्ष तर्क नहीं, कुतर्क कर रहा है, क्योंकि हमारी सरकार ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है वह इतना शानदार है कि उसकी आलोचना करने का कोई अवसर नहीं है। शायद इसीलिए प्रतिदिन सदन में प्रतिपक्ष के साथियों के बजट पर सराहनीय भाषण सुन रहा हूं।

सभापति महोदय, आज के सात महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी। बजट में जिस तरह राजस्थान की जनता के साथ करार होता है, उस पर प्रतिपक्ष को चर्चा करने का नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में जितने बजट प्रस्तुत किये, उल्लेखनीय कार्यों में बजटीय प्रावधान नहीं किया, इसलिए प्रतिपक्ष के सदस्यों के पास बजट पर बहस करने का नैतिक अधिकार नहीं है। बजट घोषणा में "करो और भूल जाओ" की नीति में कांग्रेस ने चुनावी वर्ष के आखिरी बजट में फोन ले लो, बिजली फ्री ले लो, आटा ले लो, दाल ले लो, यह सब करके राजस्थान को पीछे धकेल दिया।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान बजट के पैरा 188 पर आकर्षित करना चाहूंगा। 44 हजार 200 करोड़ के पूंजीगत व्यय की इस वित्तीय वर्ष में घोषणा की है। जब इतना रुपया एक वर्ष में राजस्थान में आधारभूत संरचना पर खर्च होगा तो आप सबको राजस्थान की प्रगति दिखने लगेगी। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस मद में किये गये प्रावधानों पर हमारी सरकार 65 प्रतिशत पैसा खर्च कर रही है। सभापति महोदय, मैं बजट के पैरा 179 पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किसान और किसानी पर एक साल में 96 हजार 787 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इतनी विशाल राशि राजस्थान में किसी सरकार ने आज तक खर्च नहीं की। किसान हूं, इसलिए किसान के हित की बात समझता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार किसानों की कर्ज माफी के

(श्री हरलाल सहारण)

नाम पर, इनके बनाये नेता आज +++ के नाम से पुकारे जाते हैं, उन्होंने एक, दो, तीन, दस कहकर किसानों के साथ अन्याय किया था। भजन लाल जी की सरकार...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, फिर मैं कह रहा हूं, ऐसे आप टारगेट करके इंगित करेंगे, यह बात सही नहीं है। किसको +++ कह रहे हैं आप? खुद को कह रहे हो आप। जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उस पर टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): आप किसान की बात करने वाले हैं न। इन्होंने कहा, किसान, किसान, किसान। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार की परिपाटी गलत है। यह परिपाटी गलत है। आगे जवाब दूंगा मैं आपको। संसदीय मंत्री जी, समझाइये अपने सदस्यों को। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपके प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं न, आप विराजिये।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): मैं एक बात कहना चाहता हूं, विपक्ष के सदस्य कह रहे थे, किसान, किसान, किसान। 75 साल की आजादी के बाद 60 साल राज करने वाले किसान की बात करने वालों ने एक पैसा नहीं दिया। प्रधान मंत्री जी ने छह हजार रुपये सम्मान निधि दी और भजन लाल सरकार ने दो हजार रुपये सम्मान निधि देकर किसान का भला किया है। जो किसानों पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, यहां आने वाले लगभग आधे से ज्यादा किसान होंगे, किसान की कभी बात नहीं की आपने, आप बात करते न किसान की तो कर्ज का मारा किसान कभी आत्महत्या नहीं करता। आपने कहा, एक, दो, तीन, दस कहकर कर्जा माफ कर देंगे, किया क्या?

सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, यमुना जल समझौते के तहत 577 एमसीएम पानी हरियाणा से समझौता अनुसार ताजेवाला हैड से पाइप लाइन चूरू आयेगी। ...(व्यवधान) क्या गलत बोल दिया मैंने। 577 एमसीएम पानी, दोबारा लिख लो। चूरू, झुंझुनूं और सीकर में पानी आयेगा, किसानों की खुशहाली होगी। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) सभापति महोदय, मेरे अभी पांच ही मिनट हुए हैं, दस मिनट हैं मेरे।

यह बजट चूरू के लिए खुशहाली लेकर आया है। पिछले पांच साल तक कृषि कनेक्शंस इस कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ पैसा भर लिया, एक नहीं दिया। हमारी सरकार ने यह कहा है कि 2024 में सारे किसानों को बिजली दी जायेगी। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

(श्री हरलाल सहारण)

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो मैंने मांगा, वह दिया। कृषि महाविद्यालय, सरकारी हॉस्पिटल खोलने का...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): और तो और, 200 करोड़ की रिंग रोड दी है। मैं मुख्य मंत्री जी को, वित्त मंत्री जो धन्यवाद दूंगा।

श्री सभापति: श्री शंकरसिंह जी रावत।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): सभापति महोदय...

श्री सभापति: विराजें। 5-5 मिनट का समय दिया है।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि दो जीएसएस नाकरा से ढाढरिया और 10 करोड़ चूरू शहर की जनता को पैसे देने की मांग कर रहा हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, आपने मुझे आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। महोदय, 10 जुलाई को जब प्रदेश की उप मुख्य मंत्री महोदया और वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, उसके शुरू में ही हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा के विकसित भारत के, विकसित राजस्थान के संकल्प की झलक देखने को मिली। यह बजट जानदार, हर वर्ग के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट से प्रदेश के चहुंमुखी विकास को पंख लगेंगे।

सभापति महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा आमजन की सेवा, हर वर्ग का सम्मान स्वरूप विकास हो, ऐसा संकल्प लेकर चलती है। हमारी पार्टी सत्ता का सुख भोगने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है, हमारी पार्टी राष्ट्रहित में जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ती है। यही कारण है कि आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री बने हैं और देश की जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से एवं राजस्थान की आम जनता की तरफ से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत माता के अवतारी पुरुष के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने पर बहुत-बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं।

(श्री शंकरसिंह रावत)

महोदय, लोक सभा चुनाव 2020 में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने खूब प्रोपेगेंडा चलाया, 55 साल के युवा +++, जिसने कभी संविधान पढ़ा नहीं, वह भी संविधान की दुहाई देकर सत्ता हासिल करना चाहता था, लेकिन देश की जनता ने उसे सिरे से नकार दिया। मैंने नाम नहीं लिया। जिस पार्टी ने देश में बेवजह आपातकाल घोषित कर दिया हो, उस पार्टी के नेता ''संविधान खतरे में है'' की दुहाई देते फिर रहे हैं। शर्म आनी चाहिये ऐसे नेताओं को।... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अब देश की जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि आज देश किन हाथों में सुरक्षित रह सकता है। हमरी विदेश नीति का लोहा दुनिया मानती है।

हमारी उप मुख्य मंत्री महोदया आदरणीय दिया कुमारी जी ने जब बजट पेश किया तो प्रदेश की जनता-जनार्दन ने तिजोरी के ताले खोल दिये थे। उन्होंने ''सबका सम्मान, सबका विकास'', इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे प्रदेश की जनता को विकास की सौगातें दीं, जिसकी पूरे राज्य में प्रशंसा हो रही है।

कांग्रेस राज में प्रदेश में अफीम, तस्करी, गांजा, चरस का धंधा पनपा। युवा आज इनके नशे में गर्त में डूब रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रदेश की युवा पीढ़ी को इस नशे से मुक्त कराने के लिए विशेष कानून बनाये जाएं। मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले गिरोह और उनके साथ लिप्त अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाये।

दूसरा, कांग्रेस सरकार में प्रदेश जंगलराज की चपेट में आ गया था। चौरी, डकैती, लूट, बहन बेटियों के साथ गैंगरेप की घटनाएं आम बात हो गई थीं। बहन, बेटियां रात में ही नहीं, दिन में भी सुरक्षित नहीं थीं। अब हमारी सरकार ने इन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चालू कर दिया है। प्रदेश में आने वाले समय में अपराधियों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मेरा सरकार से आग्रह है कि विभिन्न आपराधिक गैंगों के सफाए के लिए, पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाएं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): सर, दो मिनट। प्रदेश में गोमाता का

(श्री शंकरसिंह रावत)

बुरा हाल है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये भूख, प्यास में दर-दर भटकती हैं, दूध निकालने वाले निकालकर इसको रवाना कर देते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश में गोशाला खोलकर विधायक कोष में बजट बढ़ाया जाये। मेरी एक एरिया की मांग है।

(माननीय सदस्य श्री शंकरसिंह रावत के शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। सोहन लाल नायक।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र पाकिस्तान का बॉर्डर है, सीमान्त क्षेत्र से आता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों ने मुझे चुना और उनकी आवाज को मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। इस वक्त हमारे यहां सिंचाई पानी की बहुत बड़ी किल्लत है और गंगानगर जिले से एक हजार किसान यहां आकर धरना दिये हुए हैं, जयपुर में बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि उनकी बात सुनें और उनकी समस्या को दूर करें। वे यहीं जयपुर में धरने पर बैठे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पंजाब के अन्दर जब भी राइस की, धान की बुवाई होती है तो हमारे हिस्से का पानी काट लिया जाता है। यह राज्य सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करवाकर वह पानी हमें दिलवाया जाये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आईजीएनपी की सैकंड फेज के अन्दर 430 करोड़ का बजट इस बजट के अन्दर दिया गया है और हमारे फर्स्ट फेज को नकारा गया है, एक भी बजट नहीं दिया गया है, जबकि वहां से आपकी सत्ता के विधायक भी चुने गये हैं।

मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि गंग कैनाल के सीएडी का एमओयू जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार माननीय अशोक जी की सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजा, वह एमओयू आज तक नहीं हुआ है, जिस कारण से सीएडी के खाले नहीं बन रहे हैं। हमारा किसान वहां पानी के लिए परेशान हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग के अन्दर डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, नर्सिंग कर्मचारियों के पद रिक्त हैं, वह भी मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे विजयनगर ब्लॉक के अन्दर सीएचसी में 600 से 700 ओपीडी है और मात्र दो डॉक्टर काम कर

(श्री सोहन लाल नायक)

रहे हैं। यह बहुत दुख की बात है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पीएचसी और सीएचसी के अन्दर डॉक्टरों की व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, बड़े दु:ख की बात है कि कृषि यंत्रों पर केन्द्र सरकार और स्टेट सरकार जीएसटी लेती है। उधर, अभी इस बजट में दिया गया था कि आप इंग्लिश शराब और बीयर पर 20 परसेंट छूट दे रहे हैं और किसानों के संयंत्रों पर जीएसटी, जो कि 12 और 18 परसेंट लगी हुई है, उसको कम किया जाये। यह बहुत दुख की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डिग्गियों को अनुदान बढ़ाया जाए, क्योंकि सीमेंट, बजरी और पॉलिथीन की कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन जो अनुदान है वह पुराना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए आप से निवेदन करूंगा कि विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं, विषय नहीं है और क्रमोन्नत करने की व्यवस्था भी करवाई जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय का कई बार सरकारीकरण किया जा चुका है। पहले माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार ने किया था। वसुन्धरा जी सरकार ने उसको कैंसिल किया। फिर दोबारा किया, फिर कैंसिल किया। उसकी कोई संस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय, कोई संस्था नहीं है, एसडीएम प्रशासक है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है।

मैं ज्यादा न कहते हुए पुन: आपसे निवेदन करूंगा कि बीएसएफ, रायसिंहनगर फायरिंग रेंज के अन्दर 2023 में, फायरिंग का बिना अनाउंस किये हुए वहां एक महिला की डैथ हो गई थी और जिला कलेक्टर के यहां प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने यह कहा कि इस परिवार को मुआवजा देंगे। इस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। माननीय सभापति महोदय, आज तक उसमें कुछ नहीं किया गया है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बजट के अन्दर हमारे क्षेत्र के अन्दर जो सड़कें हैं, उसमें राजियासर से रायसिंहनगर एमडीआर है, उसको आप स्टेट हाईवे बनाने की बात करें। कृषि विपणन बोर्ड के अन्दर, कृषक कल्याण कोष से कोरोना के टाइम में एक टैक्स लगा था 0.50 परसेंट और वह आज तक चला आ रहा है और कोरोना की स्थितियां खत्म हो चुकी हैं फिर भी, किसानों को पूरा मूल्य नहीं मिलता। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री समाराम, पांच मिनट में अपनी बात पूर्ण करें।

श्री समाराम (पिंडवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, आज परिवर्तित बजट 2024-25 पर आपने बोलेने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी विपक्षी कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है। मैं तो यह समझ रहा हूं कि शायद पहली बार इस प्रकार का बजट दिया है जो बहुत शानदार, जानदार और हर आम वर्ग को छूने वाला बजट है। पांच साल के अन्दर जनजाति-आदिवासी एमएलए होने के नाते एक भी हैंडपम्प कहीं दिया हो तो बता दें, अगर एक छात्रावास खोलकर दिया हो तो बता दें।

धन्यवाद देता हूं, यशस्वी मुख्य मंत्री के नेतृत्व में उप मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पढ़ा, पूरा राजस्थान खुश है। विपक्ष भी तो थपथपा रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कम से कम एकाध काम दिया होता। जनजाति के पूर्व मंत्री जी अभी हैं नहीं। हमने सोचा, कम से कम दो-दो हैंडपम्प दे दो, दस-दस हैंडपम्प, एक हैंडपम्प नहीं दिया।

शिक्षा विभाग का तो ढर्रा ही बिगाड़ दिया। शिक्षा विभाग में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली गई, अध्यापक तो इंग्लिश मीडियम के हैं ही नहीं, फिर खोल दी। नाथी की बाड़ा तो बना ही रखा था, पेपर लीक करके युवाओं के साथ में धोखा किया।

यशस्वी मुख्य मंत्री के नेतृत्व में मैं धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का बजट, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर उप स्वास्थ्य केन्द्र को हॉस्पिटल में क्रमोन्नत किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र देवदर से टांकिया का रोड था 25 करोड़ का, वह भी स्वीकृत हुआ। मेरे जनजातीय आवासीय बालिका छात्रावास स्वीकृत हुआ। बहुत बड़ी बात है कि पहले बजट के अन्दर, चुनावी बजट में तो हर कोई घोषणा करते हैं, आपके तो कई पत्थर लगे हुए हैं, एक घोषणा भी अगर पूरी की होती। कम से कम एक साल का आबू पर्वत पर, जो डीपीआर 2016-17 में ढाई सौ करोड़ की बनी थी, लेकिन सालगांव बांध का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है जबकि घोषणा करने में काफी समय लगा था। आपने लिलुड़ी बड़ली शहीद स्मारक की दो-दो बार घोषणाएं की थीं, 2011 में की, उसके बाद मैं विधान सभा में चिल्लाते-चिल्लाते रहा, फिर भी आधा-अधूरा काम आप लोगों ने किया है। बाकी फिर भी कांग्रेस सरकार के अन्दर, पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ।

हमारी पूर्व यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिन्धिया थीं, उस समय पर हर पंचायतों को गौरव पथ दिया था, पंचायतों में गौरव बढ़ाया। आपने

(श्री समाराम)

कहा हम किसी की योजना से नहीं करेंगे। एक विकास पथ दे देंगे, सभी पंचायतों के अन्दर। एक-एक विकास पथ भी नहीं दिया। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। एक दिया था, आप सही कह रहे हैं, पर वह पूरा नहीं किया, आधा-अधूरा किया, आपके पास पैसा ही नहीं था। आपस में किसी प्रकार से कोई काम नहीं दिया था। जिस प्रकार से आप लोगों ने पांच साल में रेवड़ियां बांटने का काम किया। आदिवासी क्षेत्र के अन्दर हालात देखें तो अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। पूरे राजस्थान की बात करूं तो यह जो पहली बार बजट दिया, यह हर वर्ग को, जिस प्रकार आते ही गैस के सिलेंडर को 450 रुपये में किया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपने तो घोषणा की थी कि हम करेंगे लेकिन किया कुछ नहीं। चिरंजीवी-चिरंजीवी क्या, आयुष्मान भारत योजना भारतीय जनता पार्टी की थी, आप लोगों ने राजस्थान में लागू नहीं होने दिया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हमारे सारे आदिवासी गुजरात में जाते थे, कम से कम वहां पर इलाज तो होता था। हमारे स्टेट में ही इलाज हो जाता लेकिन आपने इसको लागू नहीं होने दिया और जिस प्रकार से जेजेएमवाई में जो जल शक्ति मंत्री, केन्द्र सरकार ने बजट पास किया था, आपने पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार के अलावा क्या किया? पाइपलाइन का, पूरे राजस्थान में मुझे लगता है कि इसकी जांच करवायी जाये।

पूरे राजस्थान में मैं कह सकता हूं कि जहां पर सड़कें खोदी थीं ठीक नहीं की और जहां भी अगर पाइपलाइनों की हालत भी देखी जाये तो ठीक प्रकार से कांग्रेस सरकार में काम नहीं हुआ। अब धीरे-धीरे हमारे प्रभारी मंत्री जी आने के बाद में सिरोही जिले में स्थिति काबू करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन काम तो आप लोग सारा बिगाड़ चुके हैं, उसको सम्भालना बहुत मुश्किल है। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री विक्रम सिंह जाखल। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मुझे लोकतंत्र के मन्दिर में बात करने का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद एवं तहेदिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा का और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का, छह महीने के भीतर ही प्रदेश के आपके

(श्री विक्रम सिंह जाखल)

नेतृत्व में आज शानदार बजट जिसमें युवा, महिला एवं किसान सहित प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते बजट पेश किया। इस बजट में गत सरकार द्वारा धरती पुत्र किसानों के साथ किये खिलवाड़ को मुंहतोड़ जवाब दिया।

सभापति महोदय, नवलगढ़ और यहां की जनता 1952 आम चुनाव से ही आज तक राजनेताओं की तानाशाही से जूझती रही है। यहां की जनता ने 2023 के विधान सभा चुनाव में पहली बार भाजपा को पुरजोर बहुमत देकर भ्रष्टाचार एवं कुशासन को विराम दिया। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि शेखावाटी को तीन दशक से यमुना जल समझौते का इंतजार था जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने मात्र दो महीने के भीतर शेखावाटी की जनता को एक खूबसूरत तोहफा दिया।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के लिए इस लोक कल्याणकारी बजट में मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि झुंझुनूं जिले के प्रसिद्ध धार्मिक लोहार्गल धाम के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहां पर लोहा भी गल जाता है। प्राचीन मत है कि पाण्डवों को महाभारत के युद्ध के बाद यह अहसास हो गया था कि कहीं न कहीं उन्होंने अपने भाइयों को युद्ध में मारा है, तो महाभारत के युद्ध के बाद मुक्ति के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें कहा था कि भारतवर्ष के सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन करने पर जहां भी आपका लोहा अर्थात् शस्त्र गल जायें, आपको पापों से मुक्ति मिल जायेगी। यह वही लोहार्गल धाम है जिसके विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री महोदय द्वारा तीर्थराज लोहार्गल में बरखण्डी पर्वत तक रोपवे की स्वर्णिम सौगात दी है। साथ ही, इस पावन भूमि में मालखेत 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का विकास कर वहां पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की समस्या का समाधान किया है, जिसके लिए मैं आभारी हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ ही, झुंझुनूं शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए 161 करोड़ रुपये की सौगात दी है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। नवलगढ़ शहर से सीमेंट फैक्ट्रियों में आने-जाने वाले भारी वाहनों से होने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए 36 करोड़ रुपये की स्वीकृति, 12 किलोमीटर तक के बाईपास की सौगात दी है। मुकुन्दगढ़ कस्बा जब से बसा है गन्दे पानी से परेशान है, दस करोड़ रुपये स्वीकृत कर ड्रेनेज प्रोजेक्ट की सौगात दी है। आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय के लिए देवीपुराबणी की जनता को पुलिस थाने की सौगात दी है। ग्राम डूंडलोद एवं

(श्री विक्रम सिंह जाखल)

जाखल में नगरपालिका की सौगात के लिए आपका मैं विशेष आभारी रहूंगा क्योंकि वहां की जनता काफी वर्षों से नगरपालिका की मांग कर रही थी जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आज पूरी की है।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): ग्राम जाखल में प्रथम श्रेणी के चिकित्सालय की सौगात दी है। साथ में, मैं आज सदन के सामने सिर्फ एक सैकंड का समय ले रहा हूं।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं सदन के सामने मेरे क्षेत्र की ज्वलंत समस्या रख रहा हूं। जैसे पूरे राजस्थान में पुष्कर का, परबतसर का, भैरूतालाब का, बालोतरा का पूरे प्रदेश में मेला भरता है वैसे ही पशु मेला बदराना जोहड़ का नवलगढ़ में भरता था, जो पिछली सरकार के पूर्व विधायक ने अपनी ताकत से उस बदराना जोहड़ का भू-परिवर्तन करवाया। रिकार्ड होनी चाहिये यह बात। बदराना जोहड़ में शेखावाटी का किसान, पूरे प्रदेश का किसान, पूरे भारत के किसान उस पशु मेले में नवलगढ़ आते थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि नगरपालिका और वहां के राजस्व के रिकार्ड को और यहां के देवस्थान विभाग की बिना एनओसी के भू-परिवर्तन कर दिया उस चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो मैं चाहूंगा कि इसकी जांच हो और जल्दी से जल्दी यह बदराना जोहड़ का मेला भरवाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। वित्त मंत्री महोदया ने जो 2024-25 का बजट दिया है अगर मेरे शेखावाटी क्षेत्र के सन्दर्भ में देखूं तो बहुत ही निराशाजनक बजट दिया है। सबसे ज्यादा उपेक्षा किसी क्षेत्र की हुई है तो वह शेखावाटी है। बहुतसी घोषणाएं ऐसी इस बजट में हैं कि जिनका पूरा होना सम्भव नहीं है। बजट प्रावधान इतना कम उनमें किया गया है, वो कैसे पूरी होंगी? हर तहसील को जिला मुख्यालय से जोड़ने की बात की है कि जिसमें टू लेन से उनको जोड़ा जायेगा और प्रावधान 306 करोड़ का। तीन तहसीलें भी टू लेन से जुड़ जाये तो बहुत बड़ी बात है।

सभापति महोदय, नगरीय क्षेत्रों में अण्डरग्राउंड बिजली की लाइन करने की बात की है कि नगरीय क्षेत्रों के मुख्य मार्गों में अण्डरग्राउंड बिजली केबल डाली जायेगी और प्रावधान डेढ़ सौ करोड़ का। दो का होगा कि तीन का होगा, कैसे सम्भव होगा? स्कूल रिपेयर की बात की है, बजट नाम मात्र का,

(श्री मनोज कुमार)

कैसे होगा? स्कूलों के क्षेत्र में पिछली सरकार ने जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया था, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें हों, नये स्कूल खोलने की बात हो, क्रमोन्नति की बात हो और इस बार देखें तो "ऊंट के मुंह में जीरा"। पचास स्कूल नयी खोलने की बात की है, अब किस-किस के हिस्से पांती आयेगी और कौन रहेगा? सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी आपस में लड़ते रहेंगे, हमारा तो नम्बर पता नहीं कब आयेगा।

सभापति महोदय, सौ स्कूल की बात की है कि हम क्रमोन्नत करेंगे। सौ स्कूल हैं और दो सौ विधान सभा क्षेत्र हैं, आधी-आधी काट कर होगी या कैसे होगी, समझ से बाहर है। कम से कम हर विधान सभा क्षेत्र में एक-एक तो करते। आज टैक्नोलोजी का जमाना है, हर बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है। साइंस स्कूल फैकल्टी खुले पर नये विषय खोलने की बात गौण है। नयी फैकल्टी कब खोलेंगे, इसमें कोई प्रावधान नहीं है, तो कैसे शिक्षा का स्तर आगे बढ़ेगा? इसलिये मुझे नहीं लगता कि जो घोषणा ये कर रहे हैं यह धरातल पर आ भी पायेंगी या सिर्फ कागजों में रहने वाली हैं, क्योंकि जब तक बजट प्रावधान नहीं होगा, पैसे का प्रबन्ध नहीं होगा ये होने वाली हैं नहीं।

बाकी बिजली के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आवश्यक है। आपने बात की है कि हम 2024 तक की पेंडेंसी खतम करेंगे कृषि कनेक्शनों की, पर डेडलाइन दी नहीं कि कब तक खतम करेंगे। क्या वह गेहूं की 2400 से 2700 रुपये वाली योजना, उसी तरह से वह पंचवर्षीय योजना रह जायेगी? इसकी कोई डेडलाइन नहीं है।

सभापति महोदय, घरेलू कनेक्शन देने की बात की है पर ढाणियों में व्यक्ति रहते हैं जो उन्होंने क्या गुनाह कर दिया कि उनकी कोई बात नहीं? बिजली उनको भी चाहिये। उनको भी मोबाइल चार्ज करने के लिए जरूरत पड़ती है, उनको भी जरूरत है। उनकी कोई बात नहीं की गई। कम से कम घरेलू कनेक्शन की बात हो तो ढाणियों, शहरों, गांवों सबकी समानता से हो। सबको समानता मिले।

बाकी और बहुत-सी योजनाएं हैं जिनका कोई जिक्र नहीं है। नन्दीशाला, गोशाला में पिछली सरकार ने बहुत से प्रावधान किये थे। उनको आगे बढ़ाने की बात थी पर इस बजट में कहीं कोई नाम नहीं आ रहा है।

एक इन्होंने स्टांप ड्यूटी की बात की कि कृषि भूमियों के पारिवारिक

(श्री मनोज कुमार)

सैटलमेंट में छह परसेंट से दो परसेंट ली जायेगी, लेकिन उसमें दो प्रोपर्टी का बैरियर लगाया है, उससे वह हो नहीं पायेगा। उस परिवार की जब तक सारी सम्पत्ति हिस्सेपांती नहीं होगी, तब तक उनका हो नहीं पायेगा। मेरी मांग है कि इसको कम से कम पूरा किया जाये।

आप ऊर्जा एमनेस्टी लेकर आये हैं। ऊर्जा एमनेस्टी पिछले डेढ़-दो साल से चल रही है, पर आज भी बड़े कनेक्शनों की वह इसलिए नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ प्रावधान है नहीं। मेरी मांग है कि उसमें जो फ्यूल सरचार्ज है, स्पेशल फ्यूल सरचार्ज है, उसको भी जब तक एमनेस्टी में नहीं लेंगे तब तक आपके यह बड़े बकायदार खतम नहीं होंगे। इसको आप विशेष तौर से ध्यान करके इस एमनेस्टी में इनको भी शामिल करने की बात करें।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। श्री संजीव कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सदस्य, एक मिनट में मेरे क्षेत्र की बात करना चाहूंगा।

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, दिनांक 10 जुलाई, 2024 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश की वित्त मंत्री माननीया दिया कुमारी जी ने इस सदन में राजस्थान सरकार का परिवर्तित बजट 2024-25 पेश किया है, इस बजट का हम वैलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इनका बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। राजस्थान प्रदेश की जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की अवधारणा को लागू कर राजस्थान को देश के एक अग्रणी विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का मौका दिया और उसी भावना से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने यह बजट पेश कर आमजन को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है, आमजन को राहत पहुंचाने की दिशा में एक कदम बढ़ाने का काम किया है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास राजस्थान की सरकार ने किया है। आज राजस्थान प्रदेश की जनता तहेदिल से इस बजट का वैलकम करती है, स्वागत करती है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार बनने के बाद जिस तरीके से गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपये में एल.पी.जी. सिलेण्डर की व्यवस्था

(श्री संजीव कुमार)

कर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाकर 8000 रुपये कर, गेहूं के एमएस.पी. पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देकर, पेयजल और सिंचाई के लिये ई.आर.सी.पी. परियोजना के प्रथम चरण के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर के वर्क ऑर्डर जारी करना, इनकी पिछली सरकार के समय पेपर लीक की जो घटनाएं होती थीं, युवा वर्ग के साथ जो खिलवाड़ होता था, उसको रोकने के लिये पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिये एस.आई.टी. का गठन करके इनमें शामिल लोगों को जेल में पहुंचाने का काम करके राजस्थान की वर्तमान सरकार ने शानदार तरीके से इस कार्यकाल को शुरू करने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि आपने समय कम दिया है, पांच मिनट की समय सीमा में आपने बांधा है तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा के लिये भादरा से डुंगराना बोझला मलसीसर तक 13 किलोमीटर लंबी सड़क के लिये 20 करोड़ 18 लाख रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। भादरा-साहवा सड़क से भादरा-राजगढ़ सड़क तक 8 किलोमीटर बाईपास निर्माण के लिये 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र के युवा वर्ग और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये, खेल क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने के लिये भादरा में खेल स्टेडियम की घोषणा करके एक शानदार कदम इस सरकार ने खिलाड़ियों के लिये उठाया है।

इसके साथ-साथ भादरा एस.डी.एच, उप जिला चिकित्सालय के नवीन भवन के निर्माण कार्य को कंटीन्यू करने का फैसला भी इस बजट के तहत किया गया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री संजीव कुमार (भादरा): यह जो सारे काम भादरा के लिये किये गये हैं, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीया वित्त मंत्री जी का आपके माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

(श्री संजीव कुमार)

मेरे क्षेत्र में जो बाईपास दिया है, वह बाईपास तब जाकर कामयाब होगा, उसको तब सार्थक कर पायेंगे जब इस बाईपास पर एक आर.ओ.बी. निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करने की कृपा करेंगे।

इसके साथ-साथ मंदिरों के जीर्णोद्धार व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये इस बजट में भरसक प्रयास किया गया है। मेरे भादरा विधान सभा क्षेत्र में पूरे उत्तरी भारत से लोग लोक देवता गोगाजी की पवित्र स्थली गोगामेड़ी पर माथा टेकने के लिये आते हैं।

श्री सभापति: विराजिए। श्री आदू राम मेघवाल।

श्री संजीव कुमार (भादरा): मैं कहना चाहता हूं कि गोगामेड़ी के इस मन्दिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम आप करें। एक मिनट निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री संजीव कुमार (भादरा): 000

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आपणो अग्रणी राजस्थान ...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): लोक कल्याणकारी प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिये समर्पित परिवर्तित ऐतिहासिक बजट ...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाय।

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर

सामान्य वाद-विवाद

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। ...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): कला-संस्कृति और साहित्य की दृष्टि से भारतवर्ष में अग्रसर भक्ति और शक्ति के प्रदेश राजस्थान को समर्पित गौरवशाली बजट का मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं।

'सोने री धरती अठै, चांदी रो आसमान,

रंग रंगीलो रस भर्‌यो अनोखो म्हारो राजस्थान'।

माननीय सभापति महोदय, मैं मैथिली शरण गुप्त की उन पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा:-

'अंधा सखा सांध का मारा क्या जाने इतिहास बिसारा,

साखली है जिसकी महिमा सूर्य चन्द्र खगोल भूगोल।

जिनके हाथ में कलम है उसकी बोल जय।'

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि जब आपके हाथ में कलम आई थी, पांच साल तक आपने राज किया, राजस्थान की जनता को क्या दिया? सभापति महोदय, प्रदेश की इसी ऐतिहासिक वैभवशाली प्राचीन संस्कृति, सभ्यता को समर्पित राजस्थान प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट में बहुआयामी परियोजनाओं का उपहार देने एवं प्रदेश को सर्वोच्च शिखर तक ले जाने हेतु प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान लोकप्रिय मुख्य मंत्री, राजस्थान की उप मुख्य मंत्री प्रेरणा पुंज माननीय उप मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, लोकप्रिय हितैषी माननीय उप मुख्य मंत्री डॉक्टर प्रेम चन्द बैरवा को आभार एवं धन्यवाद देता हूं।

(समय: 20.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से सदस्य चुनकर आया हूं, वह भारत-पाक सीमा पर स्थित प्रदेश का पहला क्षेत्र चौहटन विधान सभा है, जहां आज भी मानव जीव के लिए मूलभूत सुविधाओं का

(श्री आदू राम मेघवाल)

अभाव है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की आम जनता की भावना के अनुसार वित्तीय वर्ष..

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): वित्तीय वर्ष 2024-25 की घोषणा में महाभारतकालीन अति प्राचीन चौहटन कस्बे को नगरपालिका बनाने एवं उप खण्ड मुख्यालय पर जिला अस्पताल बनाने, बासड़ऊ में 132 केवी जीएसस बनाने, नेत्राण में पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने जैसे अनेकों बहु आयामी, जन हिताय, परिकल्पनाओं का विशेष उपहार देने पर क्षेत्र की आम जनता में खुशी है व उल्लास भी है, लहर भी है। इसके लिए मैं राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी भजन लाल जी शर्मा और उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी और डॉ. प्रेम चन्द जी बैरवा का विशेष आभार प्रकट करता हूं कि अब निश्चित रूप से राजस्थान में बहु आयामी विकास परियोजनाएं खुलेंगी तथा विकास के नये प्रतिमान स्थापित होंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: विराजें। रामनिवास गावड़िया।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में सुशासन को समर्पित, मैं सदन के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि बाखासर के रणक्षेत्र नमक उद्योग को लेकर.

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजें। पांच मिनट का समय है।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैंने बजट कॉपी को बारीकी से पढ़ा तो उसमें देखा कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र का कहीं नाम नहीं था। हो सकता है कि आपकी सरकार को मेरे से पीड़ा हो सकती है, लेकिन क्या मेरे क्षेत्र की जनता से पीड़ा है? वोट तो आपको भी दिया है, थोड़ा कम दिया होगा तो थोड़ा कम बजट दे देते, लेकिन बड़ी खुशी होती कि इस बजट की कॉपी में परबतसर का नाम होता। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि परबतसर वह धरती है जहां वीर तेजाजी महाराज का पशु मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वह रानाबाई जी धरती है जिसने ऐसे शूरवीरों को पैदा किया है, जिन्होंने पूरे देश में नाम रोशन करने का काम

(श्री रामनिवास गावड़िया)

किया है। अगर इस बजट में आप लोग कुछ काम नहीं दे सकते थे तो कम से कम हमारी सरकार द्वारा जो काम चालू हैं, उनको समीक्षा के नाम पर आप लोगों ने बन्द कर दिया। मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि 41 करोड़ के उप जिला अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया, जिसको आपने रोक दिया। जे.जे.एम. का काम, 1800-1800 रुपये की रसीदें काटकर उनके घर में पाइप लगा दी, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि उस किसान को, गरीब को पीने के लिए पानी मिले।

मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हम कौनसे आर्थिक नियोजन की बात कर रहे हैं? इस प्रदेश में जन्म लेने वाला हर बच्चा 70 हजार 800 रुपये का कर्ज लेकर पैदा होता है। हम कैसे अग्रणी राजस्थान की कल्पना कर सकते हैं?

सभापति महोदय, आज इस देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री के रूप में आप लोगों ने ऐसे शख्स को बैठा रखा है। कहते हैं ना कि जब बाड़ ही खेत खाने लग जाये तो कौन रखवाली करेगा? इस गरिमामयी सदन में उनके द्वारा यह असत्य बोला जाता है कि प्रदेश में किसी भी स्कूल के अन्दर बिना छत के बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है और दूसरे दिन पत्रिका के अन्दर हम लोग देखते हैं कि उनके खुद के जिले की दर्जनों भर स्कूलों में बिना छत के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में नामांकन कम हो गया। मेरे परबतसर विधान सभा क्षेत्र में जहां पिछले साल 34 हजार नामांकन था, वह इस बार घटकर 21 हजार हो गया। हम किस राजस्थान की बात कर रहे हैं जब हमारी आने वाली पीढ़ी को हम लोग ऐसी सुविधा नहीं दे सकते जिससे वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके, वह आने वाले समय में उन पूंजीपतियों के बच्चों के बराबर सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज यही कहना चाहूंगा कि आज इस प्रदेश के नौजवान की यह दशा है, वह यह कहता है कि जो लोग पेपर लीक के नाम पर, जो लोग कानून व्यवस्था के नाम पर यहां रोज घड़ियाली आंसू बहाते थे, सरकार में आने के बाद वे लोग क्या कर रहे हैं? इस प्रदेश और देश में आज भी छत गिर जाती है, पुल बह जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं स्थगित हो जाती हैं, पूंजीपतियों के खजाने भर जाते हैं। महलों और किलों में रौनक आ जाती है, लेकिन उस गरीब के घर, झोपड़ी में बल्ब आज भी नहीं जल रहा है। जब ये सारी दशाएं, सारी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जब इस प्रदेश और देश में सारे हक छीन लिये जाते हैं, चाहे वह

(श्री रामनिवास गावड़िया)

शिक्षा का हक हो, चाहे चिकित्सा का हक हो, चाहे न्याय का हक हो, चाहे संवैधानिक अधिकार हो, चाहे अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार हो, उन सब हक को जब छीन लिया जाता है तो एक व्यक्ति परेशान होकर, विवश होकर चप्पल और थप्पड़ का प्रयोग करता है। थप्पड़ से कुछ याद आया? आप लोगों को मेरी मुफ्त में सलाह है कि बड़े-बड़े दुपट्टे सिलवा लो, क्योंकि आपकी सरकार पिछले छह महीने में पूरे प्रदेश में विश्वास खो चुकी है। बाबा रामदेव की तरह यह दुपट्टा मुंह ढक कर आपकी जान बचाने के काम आयेगा।

श्री सभापति: विराजिये। श्री रमेश खींची।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि नौजवान छात्र संघ राजनीति करके यहां आये हैं, मेरे साथ ऐसे सैकड़ों छात्र नेता हैं जो इस सदन में और इस प्रदेश व देश की संसद में भी..

श्री सभापति: आप विराजें। श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़। अंकित नहीं होगा।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): 000

श्री सभापति: विराजिये। आपका अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): 000

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने 2024-25 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, यह बजट 10 संकल्प के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर अग्रसर होते हुए राजस्थान की एक रूपरेखा है। इस बजट में बुनियादी सुविधाओं हेतु सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य को समर्पित किया गया है। यह बजट गांवों में, शहरों में संतुलित विकास हो, इस तरह का यह बजट हमारे सामने आया है। यह बजट महिला, युवा विकास और मजदूरों को समर्पित है। मैं इस अवसर पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी, उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसा ऐतिहासिक बजट यहां पेश किया है। 75 साल से यहां बजट आ रहे हैं लेकिन इस सोलहवीं विधान सभा में, यदि पहला बजट किसी सरकार का ऐसा ऐतिहासिक बजट आया है, उसमें इस बजट को शायद हमेशा के लिए याद किया जायेगा कि ऐसा पहला बजट यहां प्रस्तुत हुआ था।

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

सड़क, चिकित्सा, पानी, बिजली की मैं लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप मुझे पांच मिनट का ही समय देंगे। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में, जब से मैंने मार्बल का व्यवसाय प्रारंभ किया, उस दिन से राजसमन्द जिले में मार्बल मण्डी बनाने की एक आवाज चल रही थी, लेकिन मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि राजसमन्द को इस बार मार्बल मण्डी की बहुत बड़ी सौगात मिली है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में आमेट सीएचसी उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत हुई है। सरदारगढ़ पीएचसी, सीएचसी में क्रमोन्नत की गयी है। केलवाड़ा में 132 केवी का जीएसएस स्वीकृत किया गया है। आगरिया फीडर, जिसका मैंने यहां पर कई बार जिक्र किया था, उसको स्वीकृत किया गया है। सबसे बड़ी योजना, यहां चित्तौड़ से और भी सदस्य विराजमान हैं, माही-जाखम परियोजना, जिसके ऊपर 3 हजार 5 सौ करोड़ रुपये पेयजल के लिए इस सरकार ने यहां मंजूर किये हैं। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप सुनें। यह माही-जाखम परियोजना की 3 हजार 5 सौ करोड़ की बात है, 2008 से 2013 तक आपकी जो सरकार थी, 2013 में भी यहां घोषणा की गयी थी कि 5 करोड़ की डीपीआर बनायेंगे। फिर आपकी जो 2018-2023 की सरकार थी। 2023 के बजट में भी आपने यहां कहा था कि, जाखम-माही का जिक्र आया तो आपने कहा कि हम डीपीआर तैयार करेंगे। मैं आदरणीय भजन लाल जी और दिया कुमारी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि 3 हजार 5 सौ करोड़ में राजसमन्द जिले के लगभग साढ़े चार सौ गांव, चित्तौड़ के, उदयपुर के और प्रतापगढ़ के गांव मिलकर, लगभग एक हजार गांवों में शुद्ध पेयजल जाखम योजना से पहुंचेगा।

मैंने गत बजट में भी यहां मांग रखी थी और यह कहा था कि कुम्भलगढ़ का नाम नहीं आया है। बहुत धन्यवाद दूंगा कि कुम्भलगढ़ का नाम इस बजट में करीब चार-पांच जगह पर आया है। मुझे आशा है कि आगे भी जो बेड़च नाका पेयजल परियोजना हमारी 20 सालों से विचाराधीन है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बेड़च नाका और हीरालाल जी देवपुरा, जो आपके सदन के नेता थे, उनके नाम से आमेट में कॉलेज है, उसको क्रमोन्नत करना पीजी में। चारभुजा में सीसी की सड़क, चारभुजा में नया कालेज, सियाणा और जीलवाड़ा में पीएचसी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें आगे और भी मिलेगा।

अब मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यहां बहुत चर्चाएं हुईं, एससी, एसटी, इन सबको कम मिला। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50 साल तक कांग्रेस जीतती आयी है। 50 साल तक वहां की जनता ने कांग्रेस का विधायक दिया है, लेकिन वहां महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मनाई जाती थी। जब मैं पहली बार विधायक बना तो भैरोंसिंह जी शेखावत जब मुख्य मंत्री थे, तब हमने महाराणा प्रताप की जयंती मनाना प्रारम्भ किया था।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): यही नहीं, केलवाड़ा के चौराहे पर महाराणा प्रताप की और राणा पूंजा की मूर्ति एक साथ लगायी।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): एक मिनट में कर रहा हूं। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, एक मिनट। इन्होंने साजिश रचकर असामाजिक तत्वों द्वारा महाराणा प्रताप की व राणा पूंजा की मूर्ति तुड़वाई ताकि वातावरण खराब हो। ...(व्यवधान) और नयी मूर्तियां लगाकर, उसको पुन: आबाद किया। इसलिए पहले से ज्यादा वोटों से जीतकर आया हूं, नेता प्रतिपक्ष महोदय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। इस बजट से किसानों और नौजवानों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। बोलने के लिए बहुत मुद्दे हैं लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का और प्रदेश का है, वह है किसानी का है, इसलिए मैं किसानी पर बात करूंगा, नहीं तो आप घंटी बजा देंगे।

श्री सभापति: पांच मिनट में आपकी बात आपको पूर्ण करनी है।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं श्रीगंगानगर जिले से आता हूं, जिसको अन्न का कटोरा कहा जाता है। श्रीगंगानगर के लोग पूरी तरह किसानी पर निर्भर हैं। सबसे पहले मैं गंगानगर के भागीरथ कहे जाने वाले महाराजा गंगासिंह जी को नमन करता हूं, जिन्होंने आज से 100 साल पहले मात्र दो साल में गंगनहर का निर्माण करवाया और गंगानगर की बंजर भूमि को हरा-भरा किया। आज किसानों के हालात बहुत बुरे हैं। पिछले दो महीने से किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है सरकार को इससे अवगत भी करवा दिया, लेकिन उसे

(श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर)

उसके हक का पानी नहीं मिला। किसान आज शहीद स्मारक, जयपुर में अपने हक के पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, वह अपने हक का पानी मांग रहे हैं। 2500 क्यूसेक्स हमारे हक का पानी है, हमें मिल रहा है 1200-1300 क्यूसेक्स। इसकी वजह से हमारी नरमे की फसल और अन्य फसलें बर्बाद हो गयी हैं। हैरानी की बात तो ये है कि हरिके बैराज पर पानी बहुत है और लगभग 11 से 13 हजार क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान छोड़ा जा रहा है और हमें राजस्थान के किसानों को 2500 क्यूसेक्स पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने एक वादा किया था कि पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं जाने दूंगा, राजस्थान को हक का पानी दूंगा। आज किसान अपने हक के पानी के लिए वंचित हैं। उनकी फसलें बर्बाद हो गयी हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में फिरोजपुर फीडर के लिए 200 करोड़ रुपये का जिक्र किया गया है, जो पूर्व में माननीय अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी। उसकी डीपीआर भी बना कर दिल्ली भेज दिया था, लेकिन डीपीआर को फुटबाल बना दिया। कभी उसको पंजाब भेज दिया गया, कभी दिल्ली। इसी चक्कर में हमारी फिरोजपुर फीडर का निर्माण नहीं हुआ। फिर भी भजन लाल सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 200 करोड़ का प्रावधान रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन इसमें और भी काम होने वाले हैं। जो हमारी पुरानी बीकानेर कैनाल है, हुसैनीवाला हैड से 45 आरडी के लिए नहर की सफाई के लिए अलग से बजट जारी किया जावे। 45 आरडी से खाखावाले हैड तक नहर की री-लाइनिंग व आरसीसी का निर्माण करवाया जाए ताकि किसानों को हक का पानी समयानुसार मिलता रहे। दोनों पटडे जो नहर के कच्चे हैं, जहां से पंजाब में पानी की चोरी हो रही है और हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा, उस नहर को पक्का किया जावे।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में दस करोड़ पक्के खालों के लिए प्रावधान किया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 10 करोड़ में तो सिर्फ एक ग्राम पंचायत के खाले पक्के बन पाएंगे। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बजट को बढ़ाकर कम से कम 300 करोड़ का बजट जारी किया जावे ताकि किसानों के खाले पक्के हो सके।

गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के किसानों के हालात अच्छे नहीं हैं।

(श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर)

पिछले साल भी गुलाबी सूंडी का प्रकोप था, ओलावृष्टि से किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसान कर्जाई हो चुका है। मेरा सरकार से निवेदन है कि गुलाबी सूंडी से और ओलावृष्टि से जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनको भी मुआवजा देने का सरकार काम करे।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): किसानों की लगातार फसल खराब होने से किसान कर्जाई हो चुका है। भू-माफियाओं और बैंकों के कर्मचारियों की मिलीभगत से किसानों की बैंकों की ऑनलाइन नीलामी हो रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उनकी ऑनलाइन नीलामी बंद कर किसानों का कर्जा माफ किया जाए।

नशा मुक्त राजस्थान बनाने की बात की है। आज नशामुक्त राजस्थान की बात क्यों हो रही है? मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो नशा मुक्त राजस्थान बनाना है, वह कैसे बनेगा? नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए, उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, उनको खेलों से जोड़ा जाए।

श्री सभापति: विराजिए। श्री विरेन्द्र सिंह।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): सरकार का धन्यवाद करना है, साहब, मुझे स्टेडियम दिया है एक।

श्री सभापति: श्री विरेन्द्र सिंह। आप विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): 000

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, बजट प्रस्ताव 2024-25 पर जो मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री और उपमुख्य मंत्री ने राजस्थान के लिए जो बजट दिया, वह सभी वर्ग के लिए, पूरे राजस्थान के लिए एक खुशहाली लेकर आयेगा।

माननीय सभापति महोदय, दस संकल्पों के माध्यम से जो बजट पेश किया, उसमें वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही अल्प अवधि में 53 प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाओं, संकल्प पत्र के 45 बिंदुओं पर कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। गरीब महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेण्डर, पीएम किसान सम्मान निधि में दो हजार रुपये बढ़ाकर किसानों को आठ हजार रुपये देने

(श्री विरेन्द्र सिंह)

का, जिसकी पहली किस्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक हजार रुपये जारी कर दी है। ईआरसीपी परियोजना के प्रथम चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

माननीय सभापति महोदय, हर क्षेत्र में आधारभूत संरचना हो। पेयजल के रूप में मेरी मसूदा विधान सभा में पेयजल बहुत बड़ी समस्या है। 2003 से 2008 के बीच में बीसलपुर परियोजना की पानी की टंकियां बनीं, पाइप लाइन बिछी, लेकिन विगत पांच सालों में आधी से ज्यादा टंकियां खाली पड़ी हुई थीं। पानी के लिए ईआरसीपी योजना, जल जीवन मिशन के माध्यम से, जो राजस्थान को प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने सौगात दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऊर्जा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में प्रदेश में पांच वर्षों में 53 हजार किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क लगभग 60 हजार करोड़ रुपये व्यय कर विकसित करने की घोषणा की है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं।

युवाओं को रोजगार, पिछली सरकार में केवल पेपर लीक होते थे, हमारी सरकार ने 70 हजार पदों पर भर्तियां किए जाने के क्रम में 20 हजार नियुक्तियां दी हैं। आने वाले पांच वर्षों में चार लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है।

चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मसूदा विधान सभा में सीएचसी से उप जिला चिकित्सालय की घोषणा की गई है। मसूदा ग्राम पंचायत को नगरपालिका की सौगात दी है। विजयनगर से केकड़ी तक 20 करोड़ रुपये की सड़क की स्वीकृति प्रदान की है। मसूदा ग्राम पंचायत पर खेल स्टेडियम की घोषणा की है। मैं उसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मसूदा विधान सभा क्षेत्र में बाकी के काम हैं। भिनाय में सीएचसी, पुराने समय में विधान सभा क्षेत्र में थी, लेकिन 2008 में परिसीमन में वह खतम हो गई, तो उस सीएचसी को 50 बेड बढ़ाने की मैं सरकार से मांग करता हूं। भिनाय में पीडब्ल्यूडी का एईएन कार्यालय खोलने की भी मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बादनबाड़ा में 132 केवी जीएसएस के लिए जमीन आवंटन हो चुकी है। वहां चारदीवारी भी बनी हुई है। मैं मांग करता हूं कि वहां 132 केवी जीएसएस देने की कृपा करें।

गोशाला में 9 महीने के लिए अनुदान मिलता है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि गोशालाओं में 12 महीने तक अनुदान दिया जाए। गायें सड़कों पर घूमती हैं, दुर्घटना में घायल होती हैं, गोशालाओं में उनका भरण पोषण हो सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): युवाओं के खेलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए खेल स्टेडियम की आवश्यकता है, भिनाय में एक खेल स्टेडियम बनाया जाए। मेरे क्षेत्र में जालिया, मसूदा पंचायत समिति में दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा कस्बा है, वहां पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए।

भिनाय में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय है, उस विद्यालय में बालक और बालिका एक ही विद्यालय में हैं। पूरे गांव की, विधान सभा क्षेत्र की मांग है कि बालिकाओं के लिए एक अलग सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय की घोषणा की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री विद्याधर चौधरी।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): सभापति महोदय, 2024-25 के बजट के वाद-विवाद पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सरकार के वित्त मंत्री द्वारा 2024-25 का बजट मैंने पढ़ा और समझा। उसमें मुझे यही समझ में आया कि एक असत्य को 100 बार अगर बोलने की बात की जाए और उसको सच साबित करने का प्रयास किया जाए तो उस सम्बन्ध में वित्त मंत्री द्वारा असत्य जुमलों का यह बजट रखा गया है। मैं क्यों कह रहा हूं, समझना। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो यही जुमले लेकर आए थे। यही घोषणाएं कि हम काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपये ड़ालेंगे। उस पैसे की कोई सीमा उस समय निर्धारित नहीं की गई, क्योंकि उस टाइम इनके मन में काला था। ऐसे ही हमारी वित्त मंत्री जी ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की कि कब कौनसा काम, किस-किस तारीख में, कैसे-कैसे होगा, उसका कोई विजन नहीं दिया।

हरित क्रांति के बारे में मोदी सरकार ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। सरकार के वित्त मंत्री द्वारा कोट करके यह कहा जाना कि स्वामीनाथन जी ने यह कहा है किसान के बारे में, तो मैं उनको यह पूछना चाहता हूं कि उनको यह दर्द तो पैदा हुआ, लेकिन किसान का दर्द क्यों नहीं दिखा? किसान जब सड़कों पर था, आप यहां बैठे हैं, कोई आदमी हाथ खड़ा करके यह बता दे कि किसान के समर्थन में कौन आया था। बता सकता है कोई? हरलाल जी बैठे हैं, ये किसान की बात कर रहे थे, इनसे पूछा जाए कि किसान जब डेढ़ साल तक कोरोना काल में सड़क पर बैठा था, आपकी सरकार ने वहां सूलें गाड़ रखी थीं, आपने दिल्ली

(श्री विद्‌याधर सिंह)

जाने के रास्ते बंद कर रखे थे, तो कौन लोग गए थे, किसने किसान का दु:ख दर्द में साथ दिया? जेठाराम जी कह रहे थे कि जब कोरोना आया था तो सरकार होटलों में मजे कर रही थी और हम लोग सेवा कर रहे थे। अगर आप थाली बजाने व ताली बजाने को सेवा कहते हो तो आपका यह बहुत अच्छा विजन है। ...(व्यवधान) हम बता रहे हैं। हमने छह महीने तक किसानों का साथ दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री विद्‌याधर सिंह (फुलेरा): किसानों ने सड़क पर रातें गुजारी हैं। ...(व्यवधान) मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज किसान यह कह रहा है मेरे खेत की मिट्टी से भरता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव अब भी उलझा है किस्तों में। ...(व्यवधान) आप लोगों का कोई विजन नहीं है। ...(व्यवधान) पहले सुनने का माद्दा रखो। यह कहावत कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते और काम की फिक्र और जिक्र करते हैं। यह आपकी सरकार वह सरकार है जो काम करने में नहीं काम का जिक्र और फिक्र करने में है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, काम का जिक्र नहीं करते।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री विद्‌याधर सिंह (फुलेरा) : श्रीमान जी, मैं तीन घंटे से यही देख रहा हूं कि हमारे विपक्ष वालों का माइक बंद कर देते हैं और उधर 5-5 मिनट तक बोलते रहते हैं। मैं बोलूंगा, चाहे आप मना करें। आपकी डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार में है। प्रजातंत्र के रूप में डबल इंजन की सरकार हुई। डबल ही आपके यहां भ्रष्टाचार पनपा है। मैं आपके माध्यम से अपने कागज पेश करना चाहता हूं, आप देख लीजिएगा अपने ऑफिस में कि यह सही है या असत्य का पुलिंदा है।

मैं मेरे यहां पानी की बात करता हूं। फुलेरा को 6.59 एमएलडी पानी अलॉट है। वर्तमान में 4.70 एमएलडी मिल रहा है।

श्री सभापति: विराजें। श्री ताराचन्द।

श्री विद्‌याधर सिंह (फुलेरा): गांव में, 163 गांवों में 12 एमएलडी पानी है और 7 एमएलडी दिया जा रहा है ...(व्यवधान) यहां जलदाय मंत्री हों तो नोट कर लें।

श्री सभापति: विराजिए। सबको 5-5 मिनट। विराजें।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने परिवर्तित बजट 2024-25 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं।

श्री सभापति: विराजें। अंकित नहीं हो।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): 000

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा के निर्देशन में उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा पठित बजट की सराहना करते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। आपणो अग्रणी राजस्थान के ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): दृष्टिगत रखते हुए अमृत कालखण्ड में विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को साकार करते हुए आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य सर्वजनहिताय, समावेशी है। हमने जिसमें 10 संकल्प लिए हैं ...(व्यवधान) सभापति जी, कांग्रेस काल का अंतिम बजट 2023 मेरे सामने आ रहा है, निवर्तमान मुख्य मंत्री ने दिया था। जनता ने परिणामस्वरूप आज उनको उधर बिठा दिया है। अपने अंतिम बजट में गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता को भ्रमित करते हुए फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए ऐसा पिटारा खोला, बिना अध्ययन के किया कि इन योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा। कांग्रेस नेताओं की फौज ने तब तक बजट को बचत राहत और बढ़त का बजट बताया, जबकि बजट का हाल क्या हुआ, पूरे देश ने देख लिया। बजट के नाम पर प्रदेश की 8 करोड़ जनता को कर्ज में धकेल दिया। आज प्रदेश के हर व्यक्ति पर 71 हजार रुपये का कर्ज है। राजस्थान अपनी सर्वाधिक कर्ज की सीमा को भी पार कर चुका है। राहत के नाम पर दलित, किसान, महिला, युवा, बेरोजगार आदि वर्ग त्राहिमाम-त्राहिमाम करने लगे। भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। बढ़त ऐसी मिली कि प्रदेश की समझदार जनता ने भ्रम और असत्य वादों की शिकार हुए बगैर प्रदेश की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्टतम सरकार को उखाड़ फेंका।

प्रदेश में अब भाजपा सरकार है। मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार शानदार कार्य कर रही है। अभी तक हम इनके खोदे हुए खड्डे भर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्य मंत्री और राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है, यह स्पष्ट लक्ष्य

(श्री ताराचन्द)

आधारित, प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ सभी वर्गों के सपनों को साकार करेगा। ऐसे बजट को लोक कल्याण का बजट कहेंगे तो उपयुक्त रहेगा।

पंडित दीनदयाल जी के सपने, जिसमें प्रदेश के गरीब, पिछड़े, दलित आदि के कल्याण की चिन्ता करते हुए उन्हें राज्य की मुख्य धारा से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस बजट से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। राजस्थान एक बार फिर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो जायेगा।

कांग्रेस ने अपने पांच वर्षों के शासन काल में जिस प्रकार से भ्रष्ट तंत्र को खड़ा किया था, उससे लगता था कि भजन लाल सरकार को एक बार तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन केन्द्र में मोदी की सरकार है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता के आशीर्वाद से राजस्थान तेजी से उठ खड़ा हुआ है।

पूर्ववर्ती सरकार के कारनामों और वित्तीय असफलता पर कुछ लाइनें प्रस्तुत करूंगा-

कश्ती चलाने वालों ने जब हारकर दी पतवार हमें,
चंद दिनों में दिखाया है हमने, फिर से दिखा देंगे सबको
कि इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने राजस्थान के सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को दिल खोलकर दिया है। मोदी सरकार की मंशा अनुसार किसानों की बजट में चिंता की गयी है।

इसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए बेहतर और आधुनिक इलाज की बड़ी योजना की कल्पना की गयी है। 1,500 नये चिकित्सकों की भर्ती से चिकित्सकों की कमी की पूर्ति हो सकेगी।

पेयजल पूर्ति के लिये 15 हजार करोड़ की राशि के आवंटन से प्रदेश के अधिकांश घरों में नल से जल का लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए बजट से निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा। 18-18 परीक्षाओं में पेपर लीक से पीड़ित युवा निराश हैं। अब वित्त मंत्री दिया कुमारी जी की चार लाख नौकरियों की घोषणा के चलते उत्साह जगा है। इसी प्रकार महिलाओं के कल्याण के साथ-साथ रोज़गार उन्मुख योजनाओं से महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा।

केन्द्र की तर्ज पर राजस्थान में 15 लाख लखपति दीदी योजना से राजस्थान में व्यापक लाभ दिखेगा।

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य।

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में बेहतर सुविधा, शौचालय आदि के निर्माण से बेहतर वातावरण बनेगा।

श्री सभापति: श्री ललित यादव।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के,
जिसे बुरा लगे वह सामने से हट जाये।

अब मैं मेरा आखिरी का पन्ना पहले पढ़ूंगा। बाद में तो फिर क्या है कि जल्दी खतम कर देंगे। अब मैं उलटा चलूंगा।

जिंदगी के हालात खराब हैं मेरे प्रदेश में,
झील में पानी बरसता है मेरे प्रदेश में,
खेत पानी को तरसता है मेरे प्रदेश में,
गरीब के घर अंधेरा बसता है मेरे प्रदेश में,
श्मशानों में लाइट जलती है मेरे प्रदेश में
और दूध महंगा खून सस्ता है मेरे प्रदेश में।

ये हालात आज राजस्थान में बने हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं छात्र जीवन से राजनीति में आया, मैं पहले बोलना चाहता था लेकिन बोलने की व्यवस्था नहीं थी। मेरा अनुरोध है कि छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई हुई है, उन छात्र संघ चुनावों को भी तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाये। बहुत सारे हमारे नौजवान साथी इस चाह में हैं, पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में छात्र सेवा में लगे हुए हैं, वे चाहते हैं कि हमें अवसर मिले और हम भी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर अपने इलाके की सेवा कर सकें। मेरा अनुरोध है कि उस पर भी आप लोग रोक हटाने का काम करें।

सभापति महोदय, बजट विश्लेषण में यह लगा कि बजट में सारा खोखलापन है। कुछ भी प्रदेश के लिए नहीं हो पाया। पर्ची सरकार कुल बजट का 9 प्रतिशत पूंजीगत व्यय करेगी, अर्थात् यह सरकार 44,216 करोड़ के असेट्स निर्माण करेगी।

कृषि के क्षेत्र में 2023-24 के बजट में 1031 करोड़ का प्रावधान

(श्री ललित यादव)

किया था और इस बार आपने 802.22 करोड़, जो कम करने का काम किया है। यह किसान के प्रति आपकी किस प्रकार की सोच है, क्या आप किसान को देना चाहते हो, यह इस बजट में दर्शाता है। जो किसान 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्मी में, कड़कड़ाती सर्दी में पेट और पीठ को एक करके इस पूरे मुल्क का पेट भरने का काम करता है, उस किसान के बारे में कोई चिंता नहीं की गयी है। मेरा सरकार से अनुरोध है, निवेदन है, मांग है कि किसानों की ऋण मुक्ति हेतु पालिसी बनायें। उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए सभी किसानों को उर्वरक, बिजली, पानी नि:शुल्क उपलब्ध कराकर कृषि जिंसों की खरीद हेतु एकीकृत एजेंसी बनाकर राज्य की खरीद प्रणाली को विकसित करने का काम करें।

सभापति महोदय, एमएसपी के बारे में भी बहुत-सी बात हुई। देश में भी हुई। हजारों किसानों ने शहादत दे दी, शहीद हो गये लेकिन यह एमएसपी वाली बात पूरी नहीं हो पायी। यहां भी ज्वार पर, बाजरे पर कोई एमएसपी की, लेकिन पूरे प्रदेश में खरीददारी कहीं नहीं हो पायी। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसान सम्मान निधि में भी आपने 12 हजार रुपये की बात की, उसमें भी आपने 500-500 रुपये दो बार बढ़ाने की बात की है। असत्य बात आप लोग कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि उद्योगों के अन्दर भी आपने नई उद्योग नीति, 2024 लागू करने की बात की है। थीम बेस पार्क बनाने की बात की है। आप जिस किसान से भूमि अधिग्रहण करोगे, उस किसान के बारे में कुछ आपने इसमें नहीं सोचा है। उसका कोई सलेक्शन नहीं किया गया है। उसके बच्चों को ना उसमें रोजगार मिलेगा, ना ही उनको कोई और सुविधा देने का काम आप करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर भी ध्यान देने का काम करें। मैं हिन्दुस्तान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बजट में बाबा साहेब को कम से कम याद तो किया है।

मेरे नीमराणा क्षेत्र की, अलवर क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं। वहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे इलाके में लोकल नौजवानों को कल-कारखानों में रोजगार मिले। मैंने उन नौजवान साथियों को रोते हुए देखा है। मैंने उन नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिलने पर मौत को गले लगाते भी देखा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार कोई कानून बनाये और लोकल आदमी को

(श्री ललित यादव)

रोजगार देने का काम करे ताकि जो स्किल्ड नौजवान है, उनको रोजगार उपलब्ध हो पाये।

मैं बड़ी पीड़ा के साथ एक बात कह रहा हूं कि इस बात पर उनको वापस भेज दिया जाता है कि आप लोकल हो, इसलिए आपको कारखाने में नहीं लगाया जायेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार इस पर भी ध्यान देवे।

श्री सभापति: श्री रामबिलास। विराजें, माननीय सदस्य।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): मैं आपसे एक मिनट चाहूंगा।

श्री सभापति: एक मिनट नहीं। आप विराजें। अपना हो गया।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ओपीएस पर भी सरकार अपना पक्ष रखने का काम करे।

श्री सभापति: श्री रामबिलास।

श्री रामबिलास (लालसोट): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय भजन लाल शर्मा जी का एवं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदया श्रीमती दिया कुमारी जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा प्रस्तुत यह बजट प्रदेश को निरंतर विकास और खुशहाली के पथ पर अग्रेषित करने वाला है।

इस परिवर्तित बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट में पांच वर्षों की कार्ययोजना बनाकर भविष्य के लिए जो संकल्प निर्धारित किया है, उन्हें यह सरकार निश्चित रूप से पूर्ण करेगी। सम्माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, ऐसा मेरा मानना है।

सभापति महोदय, इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास सम्बन्धी सभी मांगों को लगभग पूर्ण किया गया है। चाहे वह रावास उपखंड कार्यालय खोलने का हो या रामगढ़-पचवारा कृषि उपज मंडी की घोषणा करने का हो। लालसोट नगरपालिका को नगरपालिका से नगरपरिषद् में क्रमोन्नत करने की घोषणा हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र की उपरोक्त मांगें काफी लम्बे समय से चली आ रही थीं। विगत सरकार में मेरे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित

(श्री रामबिलास)

विधायक सरकार में कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी इन मांगों को पूर्ण नहीं करवा पाये थे, परंतु हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री भजन लाल जी शर्मा एवं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदया श्रीमती दिया कुमारी जी ने अपने पहले बजट में ही उक्त घोषणाएं कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। इसके लिये मैं तथा लालसोट विधान सभा क्षेत्र की समस्त जनता आपकी आभारी है।

इस क्रम में जैसे अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे। पिछली सरकार ने किसानों के साथ और नौजवान, दोनों के साथ अन्याय किया था। किसानों के कर्ज माफी की घोषणा करके पिछली सरकार बनायी थी और नौजवानों को नौकरी और बेरोजगारी भत्ते की भी घोषणा करके सरकार बनायी थी। बेरोजगार युवाओं को नौकरियां देना दूर की बात थी, बल्कि इन्होंने तो पेपर का व्यापार किया था। कई दफा पेपर लीक हुए थे। किसान उस असत्य आश्वासन से, जो आज से पांच साल पहले जिसके एक लाख रुपये की KCC थी, उस पांच साल में ब्याज से बढ़कर वह दो लाख रुपये की KCC हो गयी उनकी। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो पिछली सरकार है जिन्होंने किसानों को असत्य आश्वासन दिया और जब से भजन लाल जी मुख्य मंत्री बने तो मुख्य मंत्रीजी बनते ही उन्होंने किसानों के सम्मान में सम्मान निधि भी बढ़ायी और बेरोजगारों को नौकरी के लिये, रोजगार के लिये आने वाले पांच साल में चार लाख नौकरी देने की घोषणा की। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को पुन: धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें हैं जो पेंडिंग रह गयी थीं। एक तो हमारे लालसोट विधान सभा क्षेत्र के लिये मैंने पहले भी आग्रह किया था कि लकड़ी का एक बड़ा मार्केट है, अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान देती है और लालसोट में वुड पार्क के नाम से अगर इसको विकसित किया जाये तो हैण्डीक्राफ्ट का एक बड़ा काम वहां से निकलकर आयेगा जिसमें हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। दूसरी, लालसोट में कन्या महाविद्यालय है, उसको मैं सरकार से पी.जी. में क्रमोन्नत करने की भी मांग करता हूं। तीसरी, हमारी कोथून रोड बैल्ट है, जो काफी बड़ा एरिया है, उसमें कॉलेज की सख्त आवश्यकता है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वहां पर कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की जाये। पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजें। माननीय सदस्य श्री चेतन पटेल।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बजट में सिर्फ खानापूर्ति की गयी है। यह बजट प्रभावहीन है, दिशाहीन है। हमारे पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं के बिलकुल विपरीत हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब मैं बजट पढ़ रहा था तो मैंने सिक्योरिटी पुलिस फोर्स के बारे में पढ़ा। एंटी गैंगस्टर फोर्स, 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, इन सबके बारे में पढ़ा और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, माननीय, कि जब सरकार की मानसिकता संविधान विरोधी हो, आरक्षण विरोधी हो, दलित विरोधी हो, आदिवासी विरोधी हो तो फिर इन फोर्सों का कोई मतलब नहीं निकलता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद आदिवासी समुदाय से आता हूं। हमारी बहन +++ जो 11 साल की है, मूक-बधिर है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो उसके साथ जब अन्याय होता है, रेप होता है तो वह उम्मीद करती है कि मेरी आवाज यह समाज बने, सदन में मेरी आवाज उठे और मुझे यह सरकार सुने और मुझे न्याय दिलाये। ...(व्यवधान)..

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। बिना वजह क्यों बोल रहे हो? बार-बार क्यों उठाते हो? गिरफ्तार कर लिया, जांच पूरी हो गयी, चालान पेश होने वाला है। ...(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप मंत्री हैं, आप अपनी सीट से बोलें। बड़ी मुश्किल से पांच-पांच मिनट मिले हैं, इनको आप डिस्टर्ब करते हो।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय सदस्य अपनी आवाज इस सदन में रखते हैं, सी.बी.आई की मांग करते हैं। जब इतनी-सी मांग रखते हैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य कि क्या सी बी आई की जांच होगी या नहीं होगी? इसमें भी किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया। जब हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य द्वारा सदन में चर्चा का यह विषय रखा गया कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में बच्चों को बेचने की खबर चल रही है। छह-छह हजार रुपये में छह-छह महीने के बच्चे बेचे जा रहे हैं, तो उस पर हमें सरकार द्वारा जवाब मिलता है कि अब मां-बाप ही अपने बच्चों को बेचने लग जायें तो इसका हम क्या कर सकते हैं? यह बड़ी ही शर्म की बात है, माननीय, जबकि ऐसा कर्म करने पर मजबूर हुए परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी लेकर, लक्षित कर योजनाएं बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करना चाहिये था।

(श्री चेतन पटेल कोलाना)

माननीय सभापति महोदय, हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने आदिवासियों के लिये बहुत आवाज उठायी पर मैंने यही महसूस किया कि उनको दबा दिया गया। हमने सदन से वाक-आउट किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि हमारी विपक्ष में संख्या कम हो, हम शरीफ जरूर हैं, पर कमजोर कहीं से कहीं तक भी नहीं हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह आदिवासियों के खिलाफ जो वायरस चल रहा है, यह यहां से ही नहीं, पूरा ऊपर से चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आदरणीय नेताजी राहुल गांधीजी का, जो मणिपुर में हमारे आदिवासी भाई-बहनों की संभाल करने, उनका मनोबल बढ़ाने दो बार नहीं, तीन-तीन बार वहां पर पहुंचे हैं और आज मोदीजी कहते हैं कि हालात बहुत सामान्य हैं। मणिपुर में हालात बहुत सामान्य हैं, जबकि मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि न तो हालात मणिपुर में सामान्य हैं, न हालात इस प्रदेश राजस्थान में सामान्य हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां के हालात यह हैं कि यहां के शिक्षा मंत्रीजी आनन-फानन में आकर, बड़े जोश में, हो सकता है कि उनके विभाग के अधिकारी उनको गलत सूचना दे देते होंगे कि आपका विभाग बहुत अच्छा चल रहा है, तो वह जोश-जोश में ऐसे अनर्गल बयान दे देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आपको बताने में कोई संकोच नहीं है कि शिक्षा विभाग की यह स्थिति है कि आपके ही द्वारा पूछा गया सवाल, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा पूछा गया सवाल कि एक भी कक्षा खुली जगह पर लगती है या नहीं लगती? इनका जवाब आता है कि एक भी कक्षा खुली जगह में नहीं लगती, जबकि वास्तविकता यह है कि शिक्षा मंत्रीजी के गृह जिले में ही कई स्कूलों में कमरे नहीं हैं और बरामदे में और पेड़ों के नीचे कक्षाएं लग रही हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा पूछा गया कि 60 साल से चल रहे किशोरपुरा की हकीकत के बारे में जब सदन में प्रश्न पूछा गया तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी द्वारा जवाब में बताया गया कि स्कूल भवन में 10 कमरे बताये गये हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि 8 किलोमीटर दूर किराये के परिसर में संचालित है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात को एक मिनट में समाप्त करें।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, आपको

(श्री चेतन पटेल कोलाना)

बताना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा में साढ़े तीन लाख में से 1.24 लाख पद खाली हैं। शिक्षा विभाग की भर्ती के लिये अलग से कोई घोषणा नहीं की गयी। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र के सुल्तानपुर ब्लॉक में शिक्षकों के 1,309 पदों में से 203 पद ही भरे हुए हैं जिसमें से 17 स्कूलों में तो प्रिंसिपल तक नहीं हैं। चार लाख नौकरियों की घोषणा तो कर दी लेकिन यह वर्गीकरण नहीं किया कि किसमें नौकरी देंगे। संविदा में लगायेंगे, नरेगा में लगायेंगे, यह कुछ भी नहीं बताया। यह चार लाख नौकरियां सिर्फ और सिर्फ मोदीजी की घोषणा जैसे ही साबित होंगी, जैसे दो करोड़ सालाना उन्होंने बतायी थी और बाद में पकोड़ा तलने को भी उन्होंने रोजगार बता दिया। यही हालत आपकी चार लाख नौकरियों की होगी। और, तो और प्रदेश के युवाओं को यह भरोसा हो चुका है कि यह दिल्ली से बनकर बजट आया है तो 100 प्रतिशत मोदीजी हमें जुमले पर जुमले देकर भरमाने लगे हैं। यह रंग इतना बदलते हैं कि अब तो गिरगिट भी शरमाने लगे हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामावतार बैरवा।

श्री रामावतार बैरवा (चाकसू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का तथा विधान सभा क्षेत्र चाकसू के आमजन की आवाज को सदन में उठाने का जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पहला बजट पेश किया, जो कि समाज के सभी वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, युवा, महिला, गरीब, किसान आदि के लिये सर्वश्रेष्ठ तथा इस बजट सत्र में चाकसू विधान सभा क्षेत्र के लिये जो घोषणाएं की हैं और वहां के आमजन को जो सौगात दी है, उसके लिये मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी भजन लाल शर्मा जी तथा राजस्थान की उप मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री महोदया श्रीमती दिया कुमारी जी एवं उप मुख्य मंत्री डॉ. प्रेमचन्द जी बैरवा एवं हमारे सभी मंत्रीगणों के लिये मैं दिल से आभार और धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान बजट 2024-25 में विधान सभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों के लिये 14 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर चाकसू की जनता पर जो उपकार किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(श्री रामावतार बैरवा)

अब मैं खेल की बात पर आता हूं और चाकसू विधान सभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम की घोषणा किये जाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा माननीय वित्त मंत्री महोदया का मैं आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं। तदुपरांत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कोटखावदा में सहायक अभियंता कार्यालय खोलने तथा माधोराजपुरा उपखण्ड में आर.एस.ई.बी. कार्यालय खोलने की घोषणा की है, उसके लिए भी मैं चाकसू की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, जर्जर भवन वाले 15 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों के पुनर्निर्माण हेतु 45 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं वित्त मंत्री महोदया का मैं आभार प्रकट करता हूं। इसमें चाकसू विधान सभा क्षेत्र को भी जोड़ा गया है। सभापति महोदय, मैं बजट भाषण में आगे की ओर बढ़ते हुए कुछ पंक्तियां विकास को समर्पित करता हूं।

अग्निपथ पर चलते जाना है,
विकास में जन-जन को भागीदार बनाना है,
संदेश यही है, संकल्प यही है,
हर व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है।।

सभापति महोदय, अब मैं बजट भाषण में विकास को प्राथमिकता देते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र चाकसू की आमजन की विभिन्न समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदया को उन समस्याओं से अवगत कराते हुए निम्नलिखित समस्याओं का निराकरण करते हुए बजट में जोड़ने का आपसे अनुरोध करता हूं।

विधान सभा क्षेत्र चाकसू के कोटखावदा में उप-खण्ड कार्यालय कृषि उपज मण्डी एवं कन्या महाविद्यालय, चाकसू में कृषि महाविद्यालय और चाकसू में एडीजे कोर्ट, चाकसू के उप-खण्ड माधोराजपुरा में महाविद्यालय एवं खेड़ापति बालाजी को पर्यटन स्थल में शामिल किये जाने की घोषणा करने हेतु मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय, जो अभी हमारे सामने विराजमान विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह जो बजट है यह केवल कागजों की घोषणा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह बजट कागजों की घोषणा नहीं, धरातल का बजट है। आप देखते रहना, जो हमारे मोदी जी का सपना है, जो

(श्री रामावतार बैरवा)

कहते हैं वह करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। जिस प्रकार आपने पिछली बार मेरे विधान सभा क्षेत्र चाकसू में उप जिला अस्पताल की घोषणा की थी, वह आज भी कागजों में ही है। जो आपने पट्टियां लगायी थीं, उन पट्टियों का पता ही नहीं है।

श्री सभापति: श्रीमती गीता बरवड़। विराजिये, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री रामावतार बैरवा (चाकसू): 000

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने 2024-25 बजट पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, सदन के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन में पेश किया गया बजट बहुत ही निराशाजनक एवं दिशाहीन है। मैं भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र की बिलकुल अनदेखी की गयी है। क्षेत्र की जन सुविधाएं एवं जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा समय रहते सड़क निर्माण, प्राथमिक चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बावड़ी, ट्रॉमा सैंटर, विद्यालय खोलने, क्रमोन्नत करने, विद्युत विभाग के सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय खोलने, ग्राम पंचायत जोइंतरा में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी निर्माण, ट्यूबवैल निर्माण, हैंडपम्प आदि प्रस्ताव बजट में शामिल करने हेतु भेजे गये, जिन्हें बजट में शामिल नहीं कर मेरे विधान सभा क्षेत्र की अनदेखी कर दी गयी।

बजट में भोपालगढ़ को मिसिंग लिंक सड़कें मिलने की आस थी, लेकिन एक प्रतिशत भी सौगात नहीं मिली, जिससे जनता में मायूसी है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा ग्राम पंचायत जाजीवाल कलां से रतकूडिया तक क्षतिग्रस्त सड़क के लिए डबल डामर रोड की मांग करती हूं। ग्राम पंचायत आसोप, बासनी छापला, ग्राम पंचायत खारिया खंगार तक डबल डामर रोड की मांग करती हूं। श्रीमान् यह उप-खण्ड भोपालगढ़ से उप-खण्ड पीपाशहर विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा को जोड़ती है। ग्राम पंचायत गरासनी, दाड़मी, शिवनाथ नगर, बासनी बुद्धा, ग्राम पंचायत रतकूड़िया तक डबल लेन रोड बनाकर जिला सड़क घोषित किये जाने की मांग करती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कें, जो मैंने पहले दस सड़कें दीं, उसमें से एक भी सड़क मेरी स्वीकृत नहीं हुई।

(श्रीमती गीता बरवड़)

सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग में हमारी निम्न मांगें हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की मांग करती हूं। स्व. सेठ नेनूराम राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की मांग करती हूं। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हवासपुरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की मांग करती हूं। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोयला को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्न्त करने की मांग करती हूं। भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में उप-स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की मांग करती हूं- रामड़ावास कलां, पालड़ी रणावता, सियारा, बुचेटी। सभापति महोदय, प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाने में काफी दूरी होती है, रोगी को समय पर प्रारम्भिक उपचार नहीं मिलता। अत: इन ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता है- ग्राम पंचायत ढंढोरा, बुरछा, नागलवास। भोपालगढ़ में कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां डॉक्टर्स, एएनएम, जीएनएम आदि की पोस्टें खाली पड़ी हैं, मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि इन्हें भरा जाये ताकि जनता को सुविधा हो सके।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, कृपलानी जी के सांइलेंसर लगवा दें, इनकी आवाज यहां तक आ रही है।

श्री सभापति: कृपलानी जी की आवाज बुलन्द है।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): भोपालगढ़ क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी और बिजली की है। मेरे क्षेत्र में रात-दिन लोग पानी और बिजली की समस्या से परेशान रहते हैं। बिजली बारह-बारह घंटों तक काट दी जाती है। जब अधिकारियों को फोन किया जाता है तो बोला जाता है कि जयपुर से किया हुआ है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं आपको कहना चाहती हूं कि जब आदमी को एक दिन पानी नहीं मिलता तो उसकी क्या परेशानी होती है, जब 15-15 दिनों में एक दिन पानी आता है तो मेरे क्षेत्र की जनता की क्या कंडीशन होती होगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि भोपालगढ़ क्षेत्र में पानी और बिजली की समस्या खतम करने के लिए जो मैंने डिमांड्स दीं, उन्हें पूरा किया जाये।

श्री सभापति: विराजें।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): सभापति महोदय, मेरे भोपालगढ़ क्षेत्र में कई ढाणियां ऐसी भी हैं जिनमें अभी तक बिजली के कनेक्शंस नहीं हैं,

(श्रीमती गीता बरवड़)

वे अन्धेरे में रहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि जो लोग आज भी अन्धेरे में बैठे हैं, उनके यहां कनेक्शंस करवाने की आप कृपा करवाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2024 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.57 बजे मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों का तारांकित प्रश्नोत्तर

जहाजपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवार

64. श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में उक्त योजना से वंचित परिवारों के नाम जुड़ने के पश्चात् अब तक राशन सामग्री नहीं मिलने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 5303 पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोड़ने हेतु विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उपखण्ड जहाजपुर में 5309 एवं उपखण्ड कोटड़ी में 3708 आवेदन लंबित हैं।

(2) जी नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों को उचित मूल्य दुकानों के द्वारा निर्धारित प्रावधानानुसार पोस मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन पश्चात् गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उपभोक्ता संरक्षण के लिए युवाओं को पुरस्कार

72. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या उपभोक्ता मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2020 से माह जनवरी, 2024 तक उपभोक्ता संरक्षण हेतु प्रशंसनीय कार्य करने वाले कितने युवाओं को पुरस्कृत किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह पुरस्कार प्रतिवर्ष नियमित रूप से दिए जा रहे हैं? यदि हां, तो विगत चार वर्षों में किस वर्ष पुरस्कार नहीं दिए गए तथा पुरस्कार की राशि कितनी है एवं पुरस्कृत युवाओं को सरकार क्या-क्या सुविधा प्रदान करती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रशंसनीय कार्य करने वाले युवाओं को पुरस्कार देने की योजना में वर्ष 2020 से माह जनवरी, 2024 तक किसी भी युवा को पुरस्कृत नही किया गया।

(2) यह पुरस्कार प्रतिवर्ष नियमित रूप से नहीं दिए जा रहे हैं। पुरस्कार की राशि निम्नानुसार है:-

पुरस्कार	**राशि (रुपये)**
प्रथम	15,000/-
द्वितीय	10,000/-
तृतीय	5,000/-

पुरस्कृत युवाओं को सरकार अन्य कोई सुविधा प्रदान नही करती है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जोधड़ास ग्राम (डेगाना) में शहीद स्मारक हेतु भूमि का आवंटन

82. श्रीमती अनिता जाटव (हिन्डौन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम जोधड़ास में शहीद स्मारक हेतु भूमि का आवंटन नहीं किया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब कब तक भूमि आवंटित कर दी जायेगी?

उत्तर

ग्राम जोधड़ास में शहीद सैनिक श्री नेमीचंद के शहीद स्मारक के लिए भूमि आवंटन नहीं किया गया।

ग्राम जोधड़ास के खसरा नं. 27/1 रकबा 1.18 बीघा गै.मु. गोचर में से 5 बिस्वा भूमि आवंटन का प्रस्ताव राजस्व विभाग में प्राप्त हुआ था, जो कि शहीद स्मारक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूमि की किस्म गै.मु. गोचर होने के कारण विधिसम्मत नहीं था।

नियमों के अन्तर्गत आवंटन योग्य अन्य भूमि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

वनों के संरक्षण हेतु कार्ययोजना

83. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वनों के संरक्षण व संवर्धन के लिए योजना बनाई गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वन अधिकारियों की मिलीभगत से वन क्षेत्र में वृक्षों की कटाई एवं खनन का अवैध कारोबार होता है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वन क्षेत्रों से अवैध खनन को रोकने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान वन नीति 2023 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, वन)

(2) जी नहीं। वन क्षेत्रों में अवैध कटाई एवं खनन की शिकायतें प्राप्त होने पर रोकथाम हेतु समय-समय पर वन विभाग द्वारा पुलिस, खान, राजस्व विभाग के सहयोग से कार्यवाही की जाती है।

पिछले पांच वर्षों में विभाग अन्तर्गत अवैध कटान एवं अवैध खनन के प्रकरणों का वन मण्डलवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान वन नीति 2023 के बिन्दु संख्या 6.2 में अवैध खनन को रोकने के प्रावधान सम्मिलित है। सरकार द्वारा वन क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के लिए संभागीय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर गश्ती दलों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्टाफ द्वारा अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्रों में होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने का सतत प्रयास किया जाता है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पाली के किसानों को उपलब्ध अनुदान राशि

84. श्री भीम राज भाटी (पाली): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किसान अनुदान राशि प्रत्येक पात्र किसान को उपलब्ध करवाई जाती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र पाली में वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक कितने किसानों के खातों में कितनी राशि जमा करवाई गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अनुदान राशि से वंचित कृषकों की अनुदान राशि कब तक जमा करवा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

धौला (जमवारामगढ़) में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना

85. श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में 132 केवी जीएसएस नहीं होने से उचित वोल्टेज नहीं मिल रहा है तथा सरकार को टी एण्ड डी का नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार धौला में 132 केवी जीएसएस बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के धौला में 132 केवी जीएसएस हेतु प्रस्ताव अध्ययन उपरान्त तकनीकी रूप से दिनांक 17.06.2024 को स्वीकृत कर दिया गया है।

वर्तमान में उक्त जीएसएस हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर व बालोतरा जिलों में रीको द्वारा भूमि का अधिग्रहण

65. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर व बालोतरा में रीको द्वारा किस-किस स्थान पर भूमि चिन्हित या अधिग्रहण की गई है जहां उद्योग संचालित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र सिवाना में भारत माला हाईवे के पास रीको द्वारा भूमि चिन्हित की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या रीको द्वारा मोकलसर व समदड़ी में उद्योगों हेतु जो भूमि आवंटित या चिन्हित है, उन सभी में उद्योग स्थापित हो गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि रीको द्वारा आवंटित भूखंड पर तय समय सीमा में उद्योग नहीं लगाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाता है? यदि हां, तो समदड़ी व मोकलसर रीको क्षेत्र में ऐसे कितने भूखंडों का आवंटन निरस्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर और बालोतरा में रीको द्वारा चिन्हित या अधिग्रहित भूमियों पर जहां उद्योग संचालित किये जा रहे हैं, उनका विवरण "परिशिष्ट अ" पर संलग्न है।

(2) रीको द्वारा सिवाना विधान सभा क्षेत्र में भारतमाला हाईवे से लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर ग्राम सिणधरी चौसीरा की चरागाह एवं राजकीय (गै.मु. उद्योग) भूमि, लगभग 25 कि.मी. की दूरी पर ग्राम बामसीन की भूमि तथा लगभग एक कि.मी. की दूरी पर ग्राम मुठली की चरागाह भूमि चिन्हित की गई है। विवरण "परिशिष्ट ब" पर संलग्न है।

(3) औद्योगिक क्षेत्र मोकलसर में रीको द्वारा कुल 57 भूखण्ड नियोजित हैं, जिनमें से 31 भूखण्डों का आवंटन किया गया है। आवंटित भूखण्डों में से 13 भूखण्डों पर उत्पादन दर्ज किया जा चुका है। 07 भूखण्डों की उत्पादन समयावधि वर्ष 2023-24 में पूर्ण हुई है जिनको उत्पादन संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जा चुका है। 03 उद्यमियों की निर्धारित

(उद्योग मंत्री)

समय सीमा शेष है। 05 आवंटियों को निर्धारित समय सीमा में उत्पादन शुरू नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। शेष 03 भूखण्ड तरमीम शुद्धि का वाद लम्बित होने के कारण उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर पा रहे हैं।

औद्योगिक क्षेत्र समदड़ी में कुल 50 भूखण्ड नियोजित हैं जिनमें से 45 भूखण्डों का आवंटन किया गया है। इनमें से 36 भूखण्डों का उत्पादन दर्ज किया जा चुका है एवं शेष 09 भूखण्डों में से 02 की उत्पादन प्रारम्भ करने की समयावधि शेष है। 03 भूखण्ड वर्तमान में निर्माणाधीन है। 02 आवंटी विभिन्न कारणों से निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे हैं। 02 आवंटियों को उत्पादन प्रारम्भ नहीं करने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया जा चुका है।

(4) रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों पर उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु आवंटन तिथि/औद्योगिक क्षेत्र को विकसित घोषित करने की तिथि से तीन वर्ष में उत्पादन शुरू करने का प्रावधान है। निर्धारित समय सीमा में उत्पादन शुरू नहीं करने पर आवंटी द्वारा नियमानुसार धारण प्रभार शुल्क जमा करवाकर समयावधि बढवाई जा सकती है। इसके पश्चात् भी उद्यमी द्वारा उत्पादन प्रारम्भ नहीं करने पर भूखण्ड आवंटन निरस्त किये जाने का प्रावधान है।

निर्धारित समय सीमा में उत्पादन गतिविधि शुरू नहीं करने पर औद्योगिक क्षेत्र समदड़ी में 02 भूखण्डों के आवंटियों को तथा औद्योगिक क्षेत्र मोकलसर में 05 भूखण्ड आवंटियों को भूखण्ड निरस्तीकरण की कार्यवाही से पूर्व "कारण बताओ नोटिस" जारी किये गये हैं।

राजस्थान राज्य खेल परिषद् में रिक्त पद

66. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान राज्य खेल परिषद् में कितने पद रिक्त हैं? सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् में कुल 324 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् में सीधी भर्ती के रिक्त पदों में से प्रशिक्षक ग्रेड-तृतीय के 128 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।

युवा विकास एवं कल्याण कोष से लाभान्वित युवा

67. श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में युवा विकास एवं कल्याण कोष स्थापित किया गया था? यदि हां, तो कितनी राशि का व किस-किस कार्य के लिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कोष की स्थापना के पश्चात् किन-किन जिलों में कितने-कितने युवाओं को कितनी-कितनी राशि के संसाधन उपलब्ध करवाए गए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कोष से शिक्षा एवं छात्रवृत्ति प्रदान की गई है? यदि हां, तो किन-किन जिलों में कितने-कितने युवाओं को कितनी राशि दी गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बजट वर्ष 2023-24 में युवा विकास एवं कल्याण कोष की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा के क्रम में विभाग द्वारा युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन नहीं किया गया तथा उक्त संबंध में कोई राशि स्वीकृत भी नहीं की गई है।

(2) उक्त संबंध में अब तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(3) जी नहीं। उक्त संबंध में अब तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

लालगढ़ जाटान (सादुलशहर) में हैण्डबॉल एकेडमी की स्थापना

68. श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के गांव लालगढ़ जाटान में हैण्डबॉल एकेडमी के निर्माण के लिए पूर्व में आवंटित बजट को जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

इस विभाग के पत्र दिनांक 28.02.2023 द्वारा भारत सरकार के खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लालगढ जाटान, श्रीगंगानगर में हैण्डबाल/ वॉलीबाल/ बास्केटबॉल Mud Court खेल सुविधाओं के विकास हेतु राशि रुपये 5.75 करोड के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाये गये हैं। खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत उक्त स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकृति अनुरूप निर्माण कार्य करवाये जावेंगे।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

वर्ष 2018 में लालगढ़ जाटान में हैण्डबाल एकेडमी हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष से राशि रुपये 70.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई जो राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् के खाते में जमा है। इस राशि से अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है और ना ही राशि का उपयोग किया गया है। उक्त राशि का खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत कार्य निर्माण होने के पश्चात आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खेलो के विकास हेतु उपयोग किया जावेगा।

जैसलमेर में वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित परिवार

69. **श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला जैसलमेर में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक वृद्धावस्था, विधवा तथा निःशक्त पेंशन योजना में कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त में से कितने आवेदन निरस्त किए गए एवं कितनों में पेंशन जारी की गई? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जैसलमेर जिले में वर्ष 2019 से 2023 तक वृद्धावस्था, विधवा तथा निःशक्त पेंशन योजनान्तर्गत आवेदनों की वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः-

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	प्राप्त आवेदन	निरस्त	स्वीकृत आवेदन
वृद्धावस्था पेंशन	32975	1925	31950
विधवा पेंशन	4140	190	3950
निःशक्त पेंशन	2245	122	2123
कुल	**39,360**	**2,237**	**38,023**

जैसलमेर जिले के पेंशन लाभार्थियों का वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र की वैधता

70. **श्री मनीष यादव** (शाहपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मनीष यादव)

क्या यह सही है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र जारी होने के छह माह में उसका नवीनीकरण का प्रावधान है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश क्रमांक 54159 दिनांक 09.09.2015 एवं परिपत्र दिनांक 08.08.2019 (Annexure A) के अनुसार ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि एक वर्ष की होती है, परन्तु क्रिमीलेयर में नहीं होने के संबधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी गयी है। अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाता है, ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में पालनहार योजना से लाभान्वित परिवार

71. श्री लक्ष्मण (बस्सी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पालनहार योजना के क्या मापदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पालनहार योजनान्तर्गत विगत एक वर्ष में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त में से कितने आवेदन किन कारणों से लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजनान्तर्गत कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पालनहार योजनान्तर्गत निम्न पात्रता श्रेणियों में लाभान्वित किया जाता है:-

1. अनाथ बालक/बालिका
2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के सभी बच्चे
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

4. पुनर्विवाहित विधवा माता के सभी बच्चे
5. एड्स पीड़ित माता/पिता के सभी बच्चे
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के सभी बच्चे
7. नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
8. विशेष योग्यजन माता-पिता के सभी बच्चे
9. तलाकशुदा/परित्यकता महिला के सभी बच्चे
10. सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित माता/पिता के सभी बच्चे

(सुलभ सन्दर्भ एवं विस्तृत जानकारी हेतु पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम 2022 परिशिष्ट-अ पर संलग्न)

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पालनहार योजनान्तर्गत विगत एक वर्ष में कुल 186 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से कुल 18 आवेदन आक्षेपित होकर प्रार्थी स्तर पर लंबित हैं। उक्त आक्षेपित आवेदनों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल 1320 पालनहारों के 2428 बच्चे उक्त योजना का लाभ उठा रहे हैं। उक्त विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(नियम, सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

उचित मूल्य की दुकानों पर भौतिक सत्यापन

72. श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में उचित मूल्य की दुकान पर सभी राशन कार्डधारकों के बायोमैट्रिक मशीन द्वारा भौतिक सत्यापन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सत्यापन कार्य ई-मित्र कियोस्क पर भी करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। प्रदेश की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों की माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पोस मशीनों के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन करवाया जा रहा है।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नागौर में खाद्य सुरक्षा योजना में लाभान्वित परिवार

73. श्री अजय सिंह (डेगाना): खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रताधारियों की संख्या का प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो कितना प्रतिशत कब से बढ़ाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2022-23 की बजट घोषणानुसार नये परिवारों को उक्त योजना में जोड़ा गया है? यदि हां, तो संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों के नाम जोड़ने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयन सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत निर्धारित की गई है। एनएफएसए पात्रधारियों 69.09 प्रतिशत सीमा को बढ़ा कर 100 प्रतिशत किये जाने हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किये गये प्रस्ताव क्रम में वित्त विभाग की आईडी नं 132000012 दिनांक 03.04.2020 द्वारा सीमित वित्तीय उपलब्धता के कारण आगामी वर्षों में वित्तीय उपलब्धता होने तक परीक्षणाधीन रखा गया है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2022-23 की बजट घोषणानुसार कुल 4029 नये परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया है।

(3) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को चयनित करने की सीलिंग 4.46 करोड़ की गई है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार सुसंगत प्रकाशित जनसंख्या अनुसार सिलिंग तय है। राज्य के कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद संभव हो सकेगा।

बालोतरा व बाड़मेर जिलों में टाडा-माडा योजना में व्यय राशि

74. श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अरूण चौधरी)

(1) क्या जिला बालोतरा व बाड़मेर में टाडा एवं माडा योजना लागू है? यदि हां, तो उक्त योजना में क्या-क्या कार्य किये जा सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में टाडा एवं माडा के तहत विगत पांच वर्षों में कितनी राशि कहां-कहां पर किस-किस मद में व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला बालोतरा व बाड़मेर में टाडा व माडा योजना के तहत कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बालोतरा व बाड़मेर में टाडा एवं माडा योजना लागू नहीं है। जिला बालोतरा व बाड़मेर में बिखरी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित योजनाएं लागू हैं। विभाग द्वारा बिखरी क्षेत्र अन्तर्गत संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जिला बालोतरा व बाड़मेर में बिखरी क्षेत्र अन्तर्गत संचालित योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2020 से 2023 तक विभाग द्वारा राशि रु. 893.03 लाख स्वीकृत कर राशि रु. 787.38 लाख व्यय की गई। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) योजना लागू करने के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, क्षेत्र विशेष की आवश्यकता, संसाधनों तथा बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

उदयपुर ग्रामीण में मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की कार्ययोजना

75. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कितनी ग्राम पंचायतों व फला मगरों आदि में मां-बाड़ी केंद्र संचालित नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में जहां बच्चों की संख्या अधिक है या विद्यालय दूर हैं, वहां मां-बाड़ी केंद्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में 51 ग्राम पंचायतों में से 14 ग्राम पंचायतों में से मां-बाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इनके अतिरिक्त अन्य ग्राम पंचायतों में मां-बाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है। संचालित मां-बाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाने के विभाग को प्राप्त प्रस्तावों, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, क्षेत्र विशेष की आवश्यकता तथा मां-बाड़ी केन्द्र खोलने के मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थानों पर मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा में स्वयंसेवकों की भर्ती

76. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में स्वयंसेवकों की भर्ती का जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला कोटा में विगत तीन वर्षों से स्वयंसेवकों की भर्ती नहीं हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अवधि में उक्त जिले में कितनी बार कितनी भर्ती के आदेश जारी किये तथा भर्ती नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कोटा जिले में उक्त अवधि में स्वयंसेवकों की विभिन्न विभागों में ड्यूटी लगाने के मामले में अनियमितता हुई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) स्वयंसेवक को सेवा से डिस्चार्ज करने के क्या नियम है? विगत तीन वर्षों में जिला कोटा में कितने स्वयंसेवकों को डिस्चार्ज करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं कितनों को डिस्चार्ज किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

सादुलपुर में दर्ज राजस्व प्रकरण

77. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मनोज कुमार)

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में विगत दो वर्षों में कितने राजस्व संबंधी प्रकरण दर्ज हुए तथा कितनों का निस्तारण किया गया एवं शेष का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क के तहत दर्ज प्रकरणों सहित निस्तारित प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त प्रकरणों के निस्तारण की कोई समय सीमा निर्धारित की है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में विगत 02 वर्षों में 2318 राजस्व संबंधी प्रकरण दर्ज हुए तथा 1366 प्रकरणों का निस्तारण किया गया एवं शेष का नियमानुसार कार्यवाही कर निस्तारण किया जा रहा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क के तहत 41 प्रकरण दर्ज किये गये तथा इनमें से 12 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।

(3) जी हां। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क के तहत दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की समयावधि 90 दिवस नियत है।

निवाई की दत्तवास उप-तहसील का क्रमोन्नयन

78. श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा उप तहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत करने के क्या नियम एवं मानदंड निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई की उप तहसील दत्तवास तहसील में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नियम एवं मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला टोंक की तहसील निवाई में स्थित उप-तहसील दत्तवास के

(राजस्व मंत्री)

क्षेत्राधिकार अन्तर्गत 04 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं 16 पटवार मंडल सम्मिलित हैं।

उप-तहसील दत्तवास को तहसील में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बीकानेर में राजस्व व उपनिवेशन विभाग में रिक्त पद

79. श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर में राजस्व एवं उपनिवेशन के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी के कितने पद रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों के कितने हलकों में किस-किस पटवारी को कितने हलकों व क्षेत्र का अतिरिक्त पदभार दिया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

पदनाम	राजस्व विभाग के रिक्त पद	उपनिवेशन विभाग के रिक्त पद
तहसीलदार	03	01
नायब तहसीलदार	13	01
गिरदावर	37	01
पटवारी	69	03

(2) उक्त रिक्त पटवार मण्डलों (हलकों) का अतिरिक्त पदभार पटवारी के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्तमान में राजस्व विभाग में पटवारियों के रिक्त 1963 पदों पर भर्ती हेतु राजस्व मण्डल के पत्र दिनांक 19.06.2024 द्वारा अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को भिजवायी हुई है, साथ ही

(राजस्व मंत्री)

उपनिवेशन विभाग में पटवारियों के रिक्त 42 पदों पर भर्ती हेतु आयुक्त, उपनिवेशन बीकानेर के पत्र दिनांक 01.07.2024 द्वारा अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को भिजवायी हुई है। भर्ती कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

मेड़ता की नवीन तहसील व उप-तहसीलों के भवन

80. श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में कितनी तहसीलें व उप-तहसीलें खोली गयीं? उक्त में से कितनों के भवन निर्माण हो चुके हैं व कितने प्रगतिरत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में उक्त अवधि में खोली गयी तहसीलों व उप-तहसीलों में से किसी का भी भवन निर्माण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के भवन निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश मे विगत पांच वर्षो मे खोली गयी तहसीलों व उप तहसीलों का जिलेवार विवरण संलग्न है (परिशिष्ट 'अ')। उक्त में से निर्मित एवं प्रगतिरत भवन निर्माण कार्यों का विधानसभा वार विवरण संलग्न है (परिशिष्ट 'ब')।

(2) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में उक्त अवधि में उप तहसील कार्यालय गोटन खोली गयी है जिसमें भवन निर्माण नही हुआ है तथा राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भवन रहित तहसील एवं उप तहसील कार्यालयों मे निर्माण किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बून्दी में पौधारोपण पर व्यय राशि

81. श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बून्दी में विगत पांच वर्षों में वन विभाग ने कितने पौधे लगाये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा)

(2) सरकार द्वारा उक्त पौधारोपण के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पौधारोपण की निविदा किस-किस फर्म को जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पौधारोपण में से कितने पौधे जीवित हैं तथा कितने पौधे खराब हो गये हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बून्दी में विगत पांच वर्षो में विभाग द्वारा वृक्षारोपण में रोपित पौधों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पौधारोपण के लिए किये गये भुगतान राशि का विवरण परिशिष्ट-अ में समाहित है।

(3) सभी वृक्षारोपण कार्य विभाग में प्रचलित नियम अुनसार ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/पारिस्थितिकी विकास समिति द्वारा किये गये है।

(4) जीवित तथा खराब हो गये पौधों का विवरण परिशिष्ट-अ में समाहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों की भूमि की कुर्की

82. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा विगत छह माह में किसानों की भूमि नीलाम व कुर्की करने के आदेश जारी किए हैं? यदि हां, तो कितने, कहां-कहां व कब-कब? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा भी भूमि नीलामी व कुर्की के संबंध में निर्देश दिए गए थे? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश की 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकों में से दो प्राथमिक बैकों द्वारा विगत छह माह में किसानों की भूमि नीलामी/कुर्क करने के आदेश जारी किये गये हैं। जिलेवार विवरण निम्नानुसार हैः-

(राज्य मंत्री, सहकारिता)

क्र. सं.	जिले का नाम	जिले में कार्यरत सहकारी भूमि विकास बैंक का नाम	ऋणियों की संख्या जिनके नीलामी/कुर्क के आदेश जारी किये गये हैं			माह जिसमें आदेश जारी किये गये
			कृषक	उद्यमी	कुल	
1.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	12	8	20	मई, 2024
2.	दौसा	दौसा	35	0	35	अप्रेल, 2024

(2) जी हां। दिनांक 20-05-2024 को सहकारिता विभाग स्तर से किसी भी सहकारी बैंक में बकाया कृषि ऋणों की वसूली हेतु नीलामी की कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखे जाने हेतु निर्देश जारी किए गये। (प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है)

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सौर एवं विंड पावर हेतु भूमि का आवंटन

83. श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में सौर ऊर्जा एवं विंड पावर के लिये किस-किस कम्पनी व संस्था को किस-किस किस्म की कितनी-कितनी भूमि किन शर्तों पर कहां-कहां आवंटित की गई है? स्थानवार व कम्पनियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवंटित भूमि पर कम्पनियों व संस्था द्वारा कितनी समय सीमा में उक्त प्रोजेक्ट लगाये जाने थे तथा किस-किस कम्पनी व संस्था द्वारा प्रोजेक्ट का कार्य तय समय पर प्रारम्भ नहीं किया? सरकार द्वारा तय सीमा में प्रोजेक्ट प्रारम्भ नहीं करने वाली कम्पनियों व फर्मों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किस-किस कम्पनी व संस्था को प्रोजेक्ट के लिये कितनी-कितनी भूमि आवंटित करने का प्रावधान था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सौर ऊर्जा एवं विंड पावर के लिये भूमि आवंटन का विवरण क्रमश: परिशिष्ट "अ" व "ब" पर उपलब्ध है। विकासकर्ता/निवेशक द्वारा संयंत्र स्थापना हेतु भूमि का आवंटन हेतु आवेदन किया जाता है। अक्षय ऊर्जा नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत निगम की अनुशंषा पर राजस्व विभाग द्वारा अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि आवंटन, राजस्थान भू-राजस्व नियम, 2007 संलग्न परिशिष्ट "स" के नियमानुसार आवंटित की जाती है।

भूमि की किस्म का विवरण आवंटन आदेश परिशिष्ट "द" व परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(2) सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु समय निर्धारण आवंटन अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि आवंटन, राजस्थान भू-राजस्व नियम नियम, 2007 के अनुरूप होता है। उक्त भू-राजस्व नियम के अनुसार वैध कारणों से समयावधि बढ़ायी जा सकती है। इसके साथ ही यदि विकासकर्ता द्वारा परियोजना स्थापित नहीं करने पर निरस्त करने का भी प्रावधान है। सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु आज दिनांक तक निरस्त की गई भूमि की सूची परिशिष्ट "य" तथा परिशिष्ट "र" पर उपलब्ध है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

खाजूवाला में घरेलू बिजली कनेक्शन

84. डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में विगत तीन वर्षों में घरेलू बिजली कनेक्शन के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त में से कितनों के डिमाण्ड नोटिस जारी कर कितनों को कनेक्शन दिए गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कनेक्शन किस योजना के तहत दिये गये तथा डिमाण्ड नोटिस जारी करने के बाद कितने कनेक्शन शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में विगत तीन वर्षों में घरेलू विद्युत

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)
कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों व उनके सापेक्ष में जारी मांगपत्रों व जारी किए गए घरेलू विद्युत कनेक्शनों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में बिन्दु सं. (1) में वर्णित जारी किए गए घरेलू विद्युत कनेक्शनों का योजनावार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है तथा माह जून 2024 के अंत तक मांगपत्र जमा वाले लंबित घरेलू विद्युत कनेक्शन के आवेदनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। उक्त मांगपत्र जमा वाले लंबित आवेदनों के सापेक्ष में वरीयतानुसार घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने का कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाना लक्षित है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरदारशहर में अभियन्ता कार्यालयों में रिक्त पद

85. श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के अन्तर्गत अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का कार्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यालयों में कौन-कौनसे संवर्ग के पद कहां-कहां व कब से रिक्त हैं? कार्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्रान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में अधिशाषी अभियंता व सहायक अभियंता कार्यालयों में अभियांत्रिकी व मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध हैं तथा कनिष्ठ अभियंता कार्यालयों हेतु अलग से कोई भी पद स्वीकृत नहीं है। तकनीकी कर्मचारियों के पद अधिशाषी अभियंता व सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता कार्यालयवार स्वीकृत न किए जाकर जिलेवार स्वीकृत किए गए हैं। कार्यरत पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

उक्त विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रा.रा.वि.प्रा.निगम में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत एंव रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

(2) उपरोक्त समस्त कार्यालयों में कहां-कहां कब से रिक्त पदों का विवरण कार्यालयवार विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में स्थित अधिशाषी अभियंता व सहायक अभियंता कार्यालयों में रिक्त पदों को निगम नियमानुसार पदोन्नति, स्थानान्तरण एवं विभागों में सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम द्वारा भरा जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

सीधी भर्ती कोटे की रिक्तियों को राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर शीघ्र भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

किशनपोल में लम्बित विद्युत कनेक्शन

86. श्री अमीन कागजी (किशनपोल): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में घरेलू एवं व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन के कितने आवेदन पत्र माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2023 तक प्राप्त हुए? उक्त में से कितनों के डिमांड नोटिस जारी किए गए तथा कितने लम्बित हैं? जोनवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन के कितने आवेदन-पत्रों पर डिमांड नोटिस जारी होने के उपरांत भी कनेक्शन जारी नहीं किए गए? सरकार द्वारा लंबित विद्युत कनेक्शन कब तक जारी कर दिए जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कितनी लाइनें अंडरग्राउंड हो चुकी हैं व कितनी शेष हैं? शेष कार्य को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्षेत्र में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2023 तक कितने-कितने जीएसएस स्वीकृत हुए तथा उक्त में से कितने-कितनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है व कितनों का शेष है? शेष का निर्माण कब तक पूर्ण हो जाएगा? जोनवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के अन्तर्गत जनवरी, 2019 से

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

दिसंबर, 2023 तक घरेलू एवं व्यावसायिक श्रेणी के प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष, जारी डिमांड नोटिस, जारी विद्युत कनेक्शनों एवं लंबित आवेदनों का उपखण्डवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में बिन्दु संख्या (1) के सापेक्ष कोई भी विद्युत कनेक्शन लम्बित नहीं है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकार की अंडरग्राउंड केबलिंग की कोई योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2023 तक सहायक अभियन्ता ई-2 के क्षेत्र में एक 33 केवी सब-स्टेशन रामगंज-2 स्वीकृत किया गया था, जिसे 30.11.2021 को चालू कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर सामान्य वाद-विवाद के समय माननीय सदस्यगण का सदन पटल पर रखा गये वक्तव्य

[श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर)**]**

(1) जवाजा को तहसील घोषित किया जावे।

(2) बराखन पंचायत पर विद्युत विभाग की G.S.S.

(3) जस्साखेड़ा से बराखन तक सड़क की एस्टीमेट 43 करोड़ का था और अपने 15 करोड़ ही दिए है।

(4) विधान सभा भीम से कामली घाट चौराहा तक के एरिया को ब्यावर जिले में शामिल किया जावे।

(5) सुरेह घाटा फीडर पर 05 करोड़ रु. का बजट स्वीकृत कराकर राजियावास के तालाब को भरा जावे।

(6) जवाजा तालाब की चादर को तीन फीट की ऊंचाई को बढ़ाई जावे।

(7) ब्यावर शहर के लिए मेगा रोड फोर लेन छह लेन रोड के लिए प्रस्तावित 72 करोड़ का बजट दिया जावे।

(8) अमृतकौर अस्पताल का 80 करोड़ बजट किया जावे।

(9) बराखन एक पुलिस चौकी हो।